

भारतीय रिज़र्व बैंक  
**बुलेटिन**



जुलाई 2024

खंड 78 अंक 7

अध्यक्ष

माइकल देवब्रत पात्र

संपादक समिति

मनीष कपूर

अजीत आर जोशी

रेखा मिश्र

प्रज्ञा दास

सुनिल कुमार

स्नेहल हेरवाडकर

पंकज कुमार

वी. धन्या

श्वेता कुमारी

अनिर्बन सान्याल

सुजाता कुंडू

संपादक

जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2024

सर्वाधिकार सुरक्षित।

सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,

बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को

<https://bulletin.rbi.org.in> पर देखा जा सकता है।

# विषय-वस्तु

## भाषण

18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण*	
श्री शक्तिकान्त दास	01
वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी रखना*	
श्री शक्तिकान्त दास	03
भारत की मौद्रिक नीति की भावी तैयारी*	
माइकल देवब्रत पात्र	07
उभरते वित्तीय परिदृश्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका*	
एम राजेश्वर राव	13
साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारियाँ: बैंकिंग पर्यवेक्षण में अग्रिम आश्वासन*	
स्वामीनाथन जे.	19
भविष्य के निर्माण हेतु कमियों को दूर करना: समावेशी विकास में एसएलबीसी की खास भूमिका*	
स्वामीनाथन जे.	23

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति*	27
महामारी के बाद के साक्ष्य के साथ भारत के लिए ब्याज की आधार दर के अनुमान को अद्यतन करना	77
भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाना	91
भारत में सकल मूल्य संवर्धन में श्रम संरचना के योगदान का आकलन – मानव पूंजी दृष्टिकोण	103
हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन	115

**वर्तमान सांख्यिकी** **131**

**हाल के प्रकाशन** **185**

## परिशिष्ट

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, जून 2024



## भाषण

18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण\*

श्री शक्तिकान्त दास

वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी रखना\*

श्री शक्तिकान्त दास

भारत की मौद्रिक नीति की भावी तैयारी\*

माइकल देवब्रत पात्र

उभरते वित्तीय परिदृश्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका\*

एम राजेश्वर राव

साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारियाँ: बैंकिंग पर्यवेक्षण में अग्रिम आश्वासन\*

स्वामीनाथन जे.

भविष्य के निर्माण हेतु कमियों को दूर करना: समावेशी विकास में एसएलबीसी की खास भूमिका\*

स्वामीनाथन जे.



## 18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में उद्घाटन भाषण\*

श्री शक्तिकान्त दास

मुझे रिजर्व बैंक के अठारहवें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए खुशी हो रही है। यह वार्षिक कार्यक्रम हमें सांख्यिकीय प्रणाली की वर्तमान और विकसित स्थिति पर विचार करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सार्वजनिक नीति के क्षेत्र में सांख्यिकीय तरीकों और प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग में सुधारों का जायजा लेने में भी मदद करता है।

विभिन्न क्षेत्रों में निष्कर्ष निकालने के लिए एक पसंदीदा उपकरण के रूप में सांख्यिकी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। यह अनुशासन तथ्यों के संग्रह से आगे बढ़कर अनिश्चितता के स्तर को ध्यान में रखते हुए व्याख्या और निष्कर्ष निकालने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा है। इस बदलाव ने सांख्यिकी को अन्य प्रमुख विषयों के एक अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया है। मानव ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने में दक्षता में सुधार और अंतिम-उपयोगकर्ता अनुभव को समृद्ध करने के लिए सांख्यिकीय तरीकों के संयोजन में कंप्यूटिंग शक्ति में वृद्धि का अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

भारत में सांख्यिकी दिवस का जश्न प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के साथ मनाया जाता है। भारत में आधुनिक आधिकारिक सांख्यिकी की नींव रखने में उनका योगदान अग्रणी रहा है। उनके काम से प्रेरित होकर, भारतीय सांख्यिकीविद् घरेलू और वैश्विक स्तर पर पारंपरिक और सांख्यिकी के नए अनुप्रयोगों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि में, मैं उन क्षेत्रों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जिनमें रिजर्व बैंक का अत्याधुनिक सूचना प्रबंधन सार्वजनिक नीतियों के निर्माण और भारत में समग्र आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है। एक साल पहले, हमने सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में अपनी अगली पीढ़ी का डेटा वेयरहाउस, यानी

\* सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई द्वारा 28 जून, 2024 को आयोजित 18वें सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास का उद्घाटन भाषण

केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) की शुरुआत की थी। कई नई सुविधाएँ<sup>1</sup> नई प्रणाली<sup>2</sup> में पेश की गईं। नए पोर्टल पर रिपोर्टिंग के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी), शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) को पहले ही शामिल किया जा चुका है। रिजर्व बैंक ने विनियमित संस्थाओं के 15,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है। कई वन-टू-वन हैंडहोल्डिंग सत्र भी आयोजित किए गए हैं। मैं, इन पहलों के लिए रिजर्व बैंक के सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग को बधाई देना चाहता हूँ। सभी नियमित सांख्यिकीय प्रकाशन अब सीआईएमएस से उत्पन्न होते हैं। इसके साथ ही, हम सांख्यिकी की गुणवत्ता में लगातार सुधार करने के अपने लक्ष्य के एक अभिन्न अंग के रूप में सीआईएमएस को और अधिक विस्तृत और परिष्कृत करने का मंशा रखते हैं। नया सीआईएमएस भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में अनुसंधान की सुविधा भी दे रहा है, रिपोर्टिंग बोझ को कम कर रहा है, तकनीकी प्रगति का फायदा उठा रहा है और डेटा प्रदाताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के अनुभव को बढ़ा रहा है। इस प्रयास में हमें बाहरी विशेषज्ञों के मार्गदर्शन से भी लाभ हुआ है। हमारा महत्वाकांक्षी लक्ष्य सूचना को सार्वजनिक हित के रूप में स्थापित करना है।

<sup>1</sup> इसमें बहुत अधिक प्रोसेसिंग गति और स्केलेबिलिटी के साथ डेटा लेक और इंटीग्रेटेड एनालिटिक्स जैसी नए युग की विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं। डेटा लेक की कल्पना सीआईएमएस के एक भाग के रूप में की गई है, जो कई प्रणालियों (आरबीआई के अंदर और बाहर), डेटा भंडारण (संरचित और असंरचित जानकारी दोनों) और डेटा प्रोसेसिंग (मानक और गतिशील क्वेरी आधारित रिपोर्ट) से डेटा प्राप्त करने के मामले में सामान्य डेटाबेस प्रणाली की तुलना में अधिक लचीला है।

<sup>2</sup> सीआईएमएस में लागू किए गए नवाचारों में शामिल हैं: (ए) डेटा और मेटाडेटा के आदान-प्रदान में सुधार करने के लिए, एक सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा ईएक्सचेंज (एसडीएमएक्स) आधारित रिपॉजिटरी लागू की गई है, जिसमें एसडीएमएक्स तत्व और संबंधित मानवी कार्यकुशलता की उपज शामिल हैं, जो व्यावसायिक अवधारणाओं वाले तत्वों को संरेखित करके डेटा मानकीकरण करती हैं और तत्वों का अभ्यास करके पठनीयता के वांछित स्तर पर विजुअलाइजेशन की सुविधा प्रदान करती हैं; (बी) विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत आवधिक डेटा से एसडीएमएक्स समय श्रृंखला उत्पन्न करने के लिए एक नया एसडीएमएक्स डेटा रूपांतरण उपकरण विकसित और कार्यान्वित किया गया है; (सी) सभी रेटेक और सुपरटेक डेटा संग्रह सुविधाओं को सर्वर-टू-सर्वर डेटा ट्रांसमिशन और डेटा गवर्नेंस में एसडीएमएक्स आर्टिफैक्ट्स/मेटाडेटा के निर्माण के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है; (डी) क्रॉस डोमेन डेटा को जोड़ने वाले सांख्यिकीय विश्लेषण करने के लिए एक उन्नत विश्लेषणात्मक प्लेटफॉर्म को एकीकृत प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ कार्यान्वित किया गया है; (ई) एक एसडीएमएक्स डेटा क्वेरी कार्यक्षमता आम जनता के लिए इंटरैक्टिव मेटाडेटा संचालित खोज और डेटा विजुअलाइजेशन विश्लेषणात्मक मंच प्रदान करती हैं; (एफ) पावर उपयोगकर्ता क्षमता जिसे सामान्य डेटा प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाता है, लागू किया गया है; और (छ) नियमित सूचना प्रस्तुत करने की कार्यक्षमता को विनियमित संस्थाओं के लिए डैशबोर्ड, सिस्टम संचालित अलर्ट और डेटा सबमिशन निगरानी उपयोगिताओं के साथ समृद्ध किया गया है।

भविष्य पर नजर डालें तो दुनिया भर में आधिकारिक आंकड़ों के संकलन के लिए वर्ष 2025 का विशेष महत्व है। विशेष रूप से राष्ट्रीय खातों और भुगतान संतुलन के लिए, समष्टि आर्थिक आंकड़ों के संकलन के लिए, नए वैश्विक मानकों<sup>3</sup> में वैश्विक प्रयासों की ऊंचाई तक पहुंचने की उम्मीद है। रिजर्व बैंक में हमारी टीम इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रही है।

हम वैकल्पिक डेटा स्रोतों से प्रत्याशाओं, सेंटिमेंट इंडिकेटर्स और नीति विश्वसनीयता उपायों का विश्लेषण करने के लिए बहुत बड़ी कंप्यूटिंग शक्ति की उपलब्धता और बढ़ते डिजिटल फुटप्रिंट का उपयोग करने का भी प्रयास कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि कोविड-19 संबंधित लॉकडाउन और प्रतिबंधों के सबसे गंभीर चरणों के दौरान वैकल्पिक और अपरंपरागत डेटा स्रोतों का उपयोग अमूल्य साबित हुआ। वास्तव में, उनकी उपयोगिता संकट के बाद भी व्यापक रूप से बनी हुई है। डेटा प्रबंधन प्रणालियों को नीतिगत इनपुट के रूप में अपरंपरागत डेटा स्रोतों के उपयोग के साथ तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसा करते समय, हमें अफवाओं को खत्म करने और उच्च आवृत्ति संकेतकों से संकेतों को पकड़ने के महत्व के प्रति सचेत रहना होगा। हम जानते हैं कि हम डेटा की कमी के युग से डेटा प्रचुरता के युग की ओर बढ़ रहे हैं। संग्रहीत डिजिटल डेटा<sup>4</sup> की मात्रा के

साथ-साथ भंडारण क्षमता<sup>5</sup> भी तेजी से बढ़ रही है, जिससे नए अवसरों के साथ-साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आ रही हैं।

अब ध्यान स्वाभाविक रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) तकनीकों में क्षमता बढ़ाने और असंरचित पाठ्य डेटा का विश्लेषण करने पर है। ऐसा करते समय, नीतिपरक विचारों पर ध्यान देने की जरूरत है और एल्गोरिदम में पूर्वाग्रहों को खत्म करने की जरूरत है। रिजर्व बैंक में, हमने कई क्षेत्रों में एआई/एमएल एनालिटिक्स में कदम रखा है। आरबीआई@100 के लिए रिजर्व बैंक के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के तहत, हमारा लक्ष्य उच्च आवृत्ति और वास्तविक समय डेटा निगरानी और विश्लेषण के लिए अत्याधुनिक प्रणाली विकसित करना है।

जैसा कि प्रसिद्ध सांख्यिकीविद् और प्रोफेसर महालनोबिस के करीबी सहयोगी प्रोफेसर सी.आर.राव ने कहा था: “सांख्यिकी डेटा से सीखने का विज्ञान है। आज डेटा क्रांति का युग है।”<sup>6</sup> मुझे यकीन है कि रिजर्व बैंक में हमारे सांख्यिकीविद् उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना जारी रखेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था के विकास के उच्च स्तर की यात्रा में उभरती सूचना और अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करेंगे।

मैं, आज के विचार-विमर्श की सफलता की कामना करता हूँ।  
धन्यवाद।

<sup>3</sup> राष्ट्रीय खातों और भुगतान संतुलन के आंकड़ों के लिए नए मानक, क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रीय खातों पर अंतरसचिवालय कार्य समूह (आईएसडब्ल्यूजीएनए) और भुगतान संतुलन सांख्यिकी पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) समिति (बीओपीकॉम) द्वारा समन्वित हैं जिसके लक्ष्य हैं - सीमा नीति विश्लेषण और सामाजिक कल्याण एवं पर्यावरणीय स्थिरता के एकीकृत तत्वों की निगरानी आवश्यकता को पूरा करना; वास्तविक और वित्तीय क्षेत्र के संचालन में वैश्वीकरण और नवाचार को शामिल करना; डिजिटल परिवर्तन को शामिल करना; जलवायु परिवर्तन पर नजर रखना; स्टॉक और प्रवाह के बीच स्थिरता; अधिक विस्तृत विवरण; अन्य मानकों के साथ स्थिरता; और नए डेटा स्रोत और विधियाँ विकसित करना।

<sup>4</sup> मूर का नियम

<sup>5</sup> क्राइडर का नियम

<sup>6</sup> राव, बी.एल.एस. प्रकाश (2020)। ‘सी.आर.राव: ए लाइफ इन स्टैटिस्टिक्स’, भावना - दी मैथेमैटिक्स मैगज़ीन।

# वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी रखना\*

श्री शक्तिकान्त दास

प्रोफेसर शेरी मार्कोस<sup>1</sup>; डॉ. हिरोको ओउरा<sup>2</sup>; उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन; श्री अरिजीत बसु, अध्यक्ष, अकादमिक परिषद, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; डॉ. रबी एन. मिश्रा, निदेशक, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; विशिष्ट वक्ता और पैनलिस्ट; अकादमिक परिषद के सदस्य, कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स; रिजर्व बैंक के मेरे साथियों; देवियों और सज्जनों। नमस्कार।

मुझे भारतीय रिजर्व बैंक के कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस) द्वारा आयोजित वित्तीय आघातसहनीयता पर वैश्विक सम्मेलन के दूसरे सत्र का उद्घाटन करने के लिए यहां उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। सम्मेलन का पहला सत्र पिछले वर्ष अप्रैल में आयोजित किया गया था और मैंने उसमें भी भाग लिया था। वर्ष 2020 में अपनी स्थापना के बाद से, सीओएस ने न केवल रिजर्व बैंक, बल्कि कुछ अन्य देशों के पर्यवेक्षकों की पर्यवेक्षी क्षमता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनके जिन्होंने कॉलेज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों<sup>3</sup> में भाग लिया है। संगठन के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में उनके समर्पण के लिए टीम सीओएस को मेरी बधाई।

मुझे यह जानकर भी प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन में विश्व भर के प्रख्यात वक्ताओं, पैनलिस्टों और शिक्षाविदों ने भाग

\* श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 20 जून 2024 - कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स (सीओएस), आरबीआई, मुंबई द्वारा आयोजित वित्तीय आघात-सहनीयता पर दूसरे वैश्विक सम्मेलन में उद्घाटन भाषण।

<sup>1</sup> डॉ. शेरी मरीना मार्कोस, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, एसेक्स विश्वविद्यालय, कोलचेस्टर, यूके और सीबीडीसी अकादमिक सलाहकार समूह, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूके एचएम ट्रेजरी।

<sup>2</sup> डॉ. हिरोको ओरा, प्रमुख, वित्तीय क्षेत्र आकलन और नीति प्रभाग, मिशन प्रमुख, एफएसएपी, भारत, आईएमएफ, वाशिंगटन डीसी, यूएसए।

<sup>3</sup> प्रशिक्षण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सेमिनारों और सम्मेलनों के संयोजन के माध्यम से, कॉलेज पर्यवेक्षकों को अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और विधाओं से लैस करता है।

लिया है। यह तीन दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक वित्तीय समुदाय के हित के विभिन्न विषयों को कवर करेगा।

सम्मेलन का विषय, 'वित्तीय प्रणाली को आघातसहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट-प्रतिरोधी रखना', वह है जो कभी भी प्रासंगिकता नहीं खोएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आर्थिक चक्र के किस पक्ष में हैं। वास्तव में, भविष्य के लिए तैयार होने और संकट के खिलाफ आघातसहनीय होने के लोकाचार को हर वित्तीय संस्थान में निर्मित करने की आवश्यकता है। यह उनकी संगठनात्मक संस्कृति का एक प्रमुख तत्व होना चाहिए। इसे सक्रिय रूप से तब विकसित किया जाना चाहिए जब प्रणाली प्रतिक्रियात्मक रूप से स्वस्थ हो, न कि प्रतिक्रियात्मक रूप से जब कार्यनीति बनाने और लागू करने के लिए पर्याप्त गुंजाइश न हो।

सौभाग्य से, भारत में सभी हितधारकों, अर्थात्, रिजर्व बैंक, बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), और सरकार ने इस दिशा में ठोस प्रयास किए हैं। भारत की घरेलू वित्तीय प्रणाली अब बहुत मजबूत स्थिति में है<sup>4</sup>, जिसकी विशेषता मजबूत पूंजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्तियों के निम्न स्तर और बैंकों और एनबीएफसी की स्वस्थ लाभप्रदता है। मैं ऐसे शानदार प्रदर्शन के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं को बधाई देना चाहूंगा। हालांकि, संतोष के लिए कोई जगह नहीं है। हमें निरंतर निगरानी रखनी चाहिए और इस प्रगति को बनाए रखने के लिए सक्रिय उपाय करना जारी रखना चाहिए।

आज के परिवेश में, जो अशांत वैश्विक प्रभाव-विस्तार और अनिश्चितताओं की विशेषता है, वित्तीय क्षेत्र के लिए उभरती चुनौतियों के बीच अपना रास्ता बनाने के लिए एक अनुकूली और दूरदेशी दृष्टिकोण का पालन करना महत्वपूर्ण है। यह

<sup>4</sup> अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCB) के लिए सकल अनर्जक आस्तियों (जीएनपीए) का अनुपात मार्च 2024 (अंतिम) के अंत में 2.74 प्रतिशत था, जो 31 मार्च 2023 को 3.87 प्रतिशत और 31 मार्च 2022 को 5.82 प्रतिशत से कम था। मार्च 2024 के अंत में 16.8 प्रतिशत पर जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी भी न्यूनतम नियामक आवश्यकता से बहुत अधिक है। एनबीएफसी का जीएनपीए अनुपात मार्च 2024 (अंतिम) के अंत में 3.96 प्रतिशत था, जो मार्च 2023 के अंत में 5.03 प्रतिशत और मार्च 2022 के अंत में 6.29 प्रतिशत था। मार्च 2024 के अंत में 26.58 प्रतिशत पर जोखिम-भारित आस्तित्व अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी भी न्यूनतम नियामक आवश्यकता से काफी अधिक है।

अभिशासन और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को मजबूत करने; स्थायी व्यापार मॉडल को रोजगार देने; और तकनीकी प्रगति को अपनाने और उन्हें हमारे लाभ के लिए उपयोग करने में सहायता करेगा। वित्तीय प्रणाली के दीर्घकालिक आघातसहनीयता और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, जैसा भी आवश्यक हो, रिज़र्व बैंक अपनी ओर से विनियामक संरचना और पर्यवेक्षी कठोरता को ठीक करना जारी रखेगा। अब मैं इनमें से प्रत्येक पहलू पर विस्तार से बताता हूँ।

### अभिशासन

मजबूत अभिशासन आघातसहनीयता के मूल में है, खासकर वित्तीय क्षेत्र में। यह वास्तव में सूचित और कार्यनीतिक निर्णयों के लिए आधार है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों और जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों के साथ संरेखित होते हैं। इस संदर्भ में, मैं तीन प्रमुख अनिवार्यताओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले, प्रभावी अभिशासन निदेशक मंडल और कार्यकारी प्रबंधन के लिए स्पष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्थापित करने पर जोर देता है। दोनों के पास सही निर्णय लेने और परिचालन पर प्रभावी ढंग से उचित निगरानी रखने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और स्वतंत्रता होनी चाहिए।

दूसरा, मजबूत अभिशासन में व्यापक आंतरिक नियंत्रण और मजबूत आश्वासन कार्यों को लागू करना भी शामिल है, अर्थात्, जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और अनुपालन। आंतरिक नियंत्रणों को महत्वपूर्ण मुद्दों में बढ़ने से पहले संभावित जोखिमों का पता लगाने और कम करने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। नियमित आंतरिक और बाहरी लेखांकन इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे संगठन के वित्तीय स्वास्थ्य का स्वतंत्र आकलन प्रदान करते हैं। वे विनियामक आवश्यकताओं के वास्तविक अनुपालन की सुविधा भी प्रदान करते हैं। नियमों का लापरवाही से पालन करना वास्तव में आत्म-पराजय होगा। मुझे यह जानकर खुशी हो रही है कि प्रणालीगत स्तर पर, हमारी वित्तीय प्रणाली में अनुपालन संस्कृति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। रिज़र्व बैंक जहां कहीं भी कमियां पाता है, बाहरी संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय रूप से जाँचता है। जोखिम प्रबंधन, आंतरिक लेखा परीक्षा और

अनुपालन कार्यों के प्रमुख एक वित्तीय संस्थान के विवेक के रखवाले हैं। उनके पास संगठन के भीतर आवश्यक वरिष्ठता और स्वतंत्रता होनी चाहिए। बैंक या एनबीएफसी में ऐसे वरिष्ठ अपने संगठनों में अंतराल और कमजोरियों, यदि कोई हों, की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जोखिमों का प्रबंधन करने और संस्थान और इसकी प्रतिष्ठा की सुरक्षा करने में मदद करते हैं।

तीसरा बिंदु जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ वह शासन में नैतिकता का महत्व है जिसमें कानूनों और विनियमों का अक्षरशः और मूल भाव से अनुपालन शामिल है; स्थायी व्यावसायिक प्रथाओं का अनुसरण; और बिना सोचे समझे कोई सीमा निर्धारित करने से बचना।

### व्यापार मॉडल

अब मैं बिजनेस मॉडल की ओर मुड़ता हूँ। विनियमित संस्थाओं और पर्यवेक्षकों दोनों को संगठनों के व्यापार मॉडल में जोखिमों, यदि कोई हो, के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। जबकि व्यवसाय मॉडल को लाभप्रदता और वृद्धि के वाहक के रूप में डिज़ाइन किया जा सकता है, उनमें कभी-कभी कमियाँ होती हैं जो स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। व्यवसाय को वृद्धि की ओर अग्रसर होना महत्वपूर्ण है, लेकिन यह अस्वीकार्य जोखिम लेने की कीमत पर कभी नहीं आना चाहिए। एक विनियमित इकाई के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सफलता और आघात-सहनीयता सुनिश्चित करने के लिए मजबूत जोखिम शमन आवश्यक है।

### जोखिमों का प्रबंधन करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

जैसे-जैसे वित्तीय क्षेत्र तेजी से डिजिटल हो रहा है, उन्नत तकनीकों को अपनाने से बैंकों और एनबीएफसी की विभिन्न जोखिमों का सामना करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता काफी मजबूत हो सकती है। हालांकि, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ये प्रौद्योगिकियां सुरक्षित, विश्वसनीय और संस्थान के समग्र कार्यनीतिक लक्ष्यों के साथ संरेखित हों।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), और बिग डेटा एनालिटिक्स जैसी उन्नत और उभरती प्रौद्योगिकियों

को संगठनात्मक कार्यों में एकीकृत करना वित्तीय संस्थानों के संचालन के तरीके को बदल सकता है। एआई और एमएल प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बढ़ा सकते हैं और बैंकों और एनबीएफसी को संभावित जोखिमों और रुझानों की अधिक सटीक पहचान करने में सक्षम बना सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां वास्तविक समय में असामान्य पैटर्न और लेनदेन को पहचानकर धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार ला सकती हैं।

इस प्रकार, वे संस्थानों और उनके ग्राहकों को वित्तीय अपराधों और धोखाधड़ी से बचा सकते हैं। नियमित कार्यों के स्वचालन के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार किया जा सकता है, जो मानवीय त्रुटि को कम करता है और अधिक कार्यनीतिक गतिविधियों के लिए संसाधनों को मुक्त करता है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए) मनुष्यों की तुलना में अधिक तेज़ी से और सटीक रूप से डेटा प्रविष्टि और लेनदेन प्रसंस्करण जैसे उच्च-मात्रा और दोहराव वाले कार्यों को संभाल सकता है।

चूंकि वित्तीय संस्थान अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए उन्नत तकनीकों पर भरोसा करते हैं, इसलिए तीसरे पक्ष के विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता बढ़ सकती है। मज़बूती से सेवाएं देने में एक विक्रेता की असमर्थता सीधे विनियमित इकाई के परिचालन और ग्राहक सेवा को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं का चयन करने से पहले पूरी तरह से उचित परिश्रम आवश्यक हो जाता है। इसमें उनकी वित्तीय स्थिरता, तकनीकी क्षमताओं, सुरक्षा मानकों और विनियमों का पालन करने की उनकी क्षमता का आकलन करना शामिल है। इसके अलावा, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की निरंतर निगरानी होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सहमत मानकों और प्रथाओं का पालन करते हैं।

### विनियामक ढांचे और पर्यवेक्षी कठोरता को उचित बनाना

जैसे-जैसे जोखिम विकसित होते हैं और नई चुनौतियां सामने आती हैं, रिज़र्व बैंक एक विनियामक और पर्यवेक्षक के रूप में वित्तीय प्रणाली की स्थिरता की रक्षा के लिए विनियामक ढांचे और पर्यवेक्षी प्रणालियों के संबंध में सतर्क, अनुकूल और सक्रिय रहने पर लगातार ध्यान केंद्रित करता है।

पिछले कुछ वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने अपने द्वारा गठित विनियम समीक्षा प्राधिकरण (आरआरए) 2.0 के तत्वावधान में विनियमों की व्यापक समीक्षा की है। कई निरर्थक निर्देशों को वापस लेने के अलावा, आरआरए ने अनुपालन को आसान बनाने और विनियामक बोझ को कम करने; रिपोर्टिंग तंत्र को सुव्यवस्थित करने; और विनियामक निर्देशों में अधिक स्पष्टता लाने के लिए मूल्यवान सिफारिशें भी की हैं।

हाल के वर्षों में, रिज़र्व बैंक ने बैंकों (वाणिज्यिक और शहरी सहकारी बैंक दोनों), एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), आर्स्टि पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), डिजिटल ऋणदाताओं, व्यक्ति-वित्त ऋणदाताओं और मूल-निवेश कंपनियों के लिए विनियामक संरचना का व्यापक पुनर्गठन किया है। इस प्रकार, वित्तीय क्षेत्र के विनियम अब न केवल बदलते समय के अनुरूप हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार और सक्रिय उपाय करने के लिए अपेक्षित तत्परता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के लिए स्व-विनियामक संगठन (एसआरओ) स्थापित करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। यह प्रणाली में हितधारकों के साथ अधिक परामर्श और घनिष्ठ इंटरफेस की सुविधा के लिए एक पूरी तरह से नया दृष्टिकोण है। यह नियमों को और भी गतिशील और सक्रिय बना देगा। साथ ही, मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि बार-बार विनियामक परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए है कि बदलती परिस्थितियों के लिए अधिक विनियामक स्पष्टता और जवाबदेही हो।

रिज़र्व बैंक ने अपनी पर्यवेक्षी प्रणालियों को भी काफी मजबूत किया है, एक इकाई-केंद्रित दृष्टिकोण से अधिक विषयगत और गतिविधि-आधारित दृष्टिकोण में परिवर्तित हो गया है। अब हम बैंकों और एनबीएफसी के व्यापार मॉडल की धारणीयता को देखते हैं। समस्याओं और कमियों के मूल कारण का विश्लेषण किया जाता है। जहां भी हमें संकट दिखाई देता है या संकट महसूस होता है, अग्रिम कार्रवाई शुरू की जाती है।

<sup>5</sup> बैंकिंग पर्यवेक्षण, गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण और सहकारी बैंकिंग पर्यवेक्षण के पूर्ववर्ती विभागों को पर्यवेक्षण के एकल एकीकृत विभाग के रूप में विलय कर दिया गया।

वित्तीय क्षेत्र के समग्र मूल्यांकन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ एक समूह के भीतर कई संस्थाओं की स्थितियों का विश्लेषण करने के लिए पर्यवेक्षण का एकीकृत विभाग<sup>6</sup> बनाकर रिज़र्व बैंक के भीतर संरचनात्मक परिवर्तन लागू किए गए हैं। ऐसा विचार पर्यवेक्षण की चपलता और व्यापकता को बढ़ाने के लिए है। अब अपरंपरागत तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। ऋण सूचना कंपनियों का ऑनसाइट पर्यवेक्षण वार्षिक और गहन बनाया गया है। जब किसी वित्तीय इकाई में समस्याएं बहुत गंभीर दिखाई देती हैं, तो कार्यपालक निदेशक के रैंक का रिज़र्व बैंक का एक वरिष्ठ अधिकारी संगठन के पूर्ण बोर्ड को संबोधित करता है और हमारी चिंताओं को साझा करता है। इसी प्रकार, जब हम लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और हमारे पर्यवेक्षी निष्कर्षों के बीच भौतिक विसंगतियां पाते हैं, या जब हम देखते हैं कि लेखा परीक्षकों द्वारा कुछ भौतिक मुद्दों को ठीक से संबोधित नहीं किया गया है, तो हम लेखा परीक्षकों को प्रत्यक्ष चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं। ये पर्यवेक्षण के हमारे नए तरीकों के कुछ उदाहरण हैं।

कॉलेज ऑफ सुपरवाइज़र (सीओएस) अपने आप में हमारे पर्यवेक्षण की गुणवत्ता और हमारे पर्यवेक्षकों की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमारी सक्रिय पहल का एक लाजवाब उदाहरण है। यह रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी प्रणाली को मजबूत करने के हमारे प्रयासों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। सीओएस के जनादेश के मूल में पर्यवेक्षकों का पेशेवर विकास है, दोनों प्रारंभिक नींव स्तर पर और साथ ही उनके करियर में बाद के चरणों के दौरान भी। हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षक गतिशील वित्तीय परिदृश्य में उभरती प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और पर्यवेक्षी और नियामक विकास से अवगत रहें।

अब जबकि रिज़र्व बैंक अपने शताब्दी वर्ष (आरबीआई @100) की ओर बढ़ रहा है, हमने ऐसी कार्यनीतियाँ तैयार की हैं जो इसे भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए भविष्य की तैयारी के लिए तैयार करेंगी। हम रिज़र्व बैंक को दक्षिणी विश्व<sup>6</sup> के एक मॉडल केंद्रीय बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए

आवश्यक नीतिगत कार्रवाई करने का प्रस्ताव करते हैं। हमारा लक्ष्य निरंतर क्षैतिज स्कैनिंग और समग्र जोखिम आकलन के साथ 'श्रू द साइकिल' जोखिम मूल्यांकन ढांचे का निर्माण करके रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षण को एक वैश्विक मॉडल बनाना है। इसमें अधिक ग्राहक केन्द्रित ढांचे की भी परिकल्पना की गई है जो पर्यवेक्षित संस्थाओं के आचरण में सुधार करके ग्राहकों के हितों की रक्षा और संवर्धन करे। इस लक्ष्य के अनुसरण में, हम सभी वित्तीय क्षेत्र के खिलाड़ियों से सक्रिय सहयोग की उम्मीद करते हैं जो मुझे यकीन है कि वे प्रदान करेंगे।

### निष्कर्ष

अंत में, एक अधिक आघात-सहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी वित्तीय प्रणाली की ओर यात्रा जारी है। यह सभी हितधारकों से सामूहिक प्रयासों, नवाचार और अनुकूलन क्षमता की मांग करता है। मैंने कुछ पहलुओं पर ध्यान दिया है जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अभिशासन और आश्वासन से लेकर टिकाऊ व्यापार मॉडल को अपनाने के साथ-साथ इसके जोखिमों का प्रबंधन करते हुए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना शामिल है। मैंने वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा में विनियामक और पर्यवेक्षी ढांचे की भूमिका पर भी जोर दिया है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सभी हितधारकों के लिए इन सिद्धांतों और प्रथाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध रहना अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि वे भारतीय वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता और आघात-सहनीयता में योगदान देना जारी रखेंगे।

इसी के साथ, मैं इस तीन दिवसीय सम्मेलन के सफल विचार-विमर्श के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और आयोजकों की उनके प्रयासों के लिए सराहना करता हूँ। मेरी कामना है कि अगले तीन दिन सार्थक आदान-प्रदान, नवान्वेषी विचारों और सहयोगात्मक समाधानों से भरे हों, जो हमारी वित्तीय प्रणाली को आघात-सहनीय, भविष्य के लिए तैयार और संकट प्रतिरोधी बनाए रखने की प्रक्रिया में योगदान देंगे।

<sup>6</sup> गवर्नर के मौखिक नीति वक्तव्य दिनांक 7 जून, 2024 का पैराग्राफ 2 देखें ([https://www.rbi.org.in/Scripts/BS\\_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58049](https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=58049))

# भारत की मौद्रिक नीति की भावी तैयारी\*

माइकल देवब्रत पात्र

नमस्कार!

मुझे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) में आमंत्रित किए जाने पर गर्व है, जो स्वतंत्र भारत का एक मंदिर है, जिसका इतिहास स्वतंत्रता से पहले का है। मैं मैडम सौजन्या को उनकी सौम्य दृढ़ता और कुशल प्रबंधन के लिए धन्यवाद देता हूँ, जिनकी वजह से मेरा यहां आना संभव हो पाया। मैं समझता हूँ कि यह अकादमी के मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम के चरण IV का 18वां दौर है। यहां के प्रतिभागी पहले ही राष्ट्र की सेवा में 15 से 18 साल लगा चुके हैं और इसलिए, वे अगले 40-50 वर्षों में हमारे देश को विकसित देश बनने के हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य की खोज में नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्र उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपकी ओर देखता है, क्योंकि आप लोक नीति का संचालन करेंगे और राष्ट्र को उसके आकांक्षानुकूल लक्ष्य की ओर ले जाते हुए शासन की चुनौतियों का सामना करेंगे। ऐसा करते समय, आपको संगठनात्मक और तकनीकी परिवर्तनों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संरचनात्मक परिवर्तनों के रूप में टेक्टोनिक उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करना होगा। मुझे आशा है कि मेरा व्याख्यान आपके सामने आने वाली यात्रा पर थोड़ा प्रकाश डाल सकेगा।

इसी संदर्भ में मैं आपसे मौद्रिक नीति के बारे में बात करूंगा, लेकिन मैं इसे अगले चालीस से पचास वर्षों के परिप्रेक्ष्य में रखूंगा, ताकि उन अवसरों और चुनौतियों के बारे में कुछ परिप्रेक्ष्य सामने आ सकें, जो भारत को उसके भविष्य की ओर ले जाते समय आपके सामने आएंगी।

\* मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए मध्य-करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर, श्री माइकल देवब्रत पात्र द्वारा दिया गया संबोधन। हरेंद्र बेहरा, आशीष थॉमस जॉर्ज से प्राप्त मूल्यवान टिप्पणियों और विनीत कुमार श्रीवास्तव से प्राप्त संपादकीय सहायता के लिए आभार।

## प्रथम सिद्धांत

मौद्रिक नीति के डिजाइन और संचालन को आकार देने वाले मार्गदर्शक सिद्धांतों की चर्चा करना महत्वपूर्ण है।

सबसे पहले, लोक नीति साधनों के शस्त्रागार में, मौद्रिक नीति को इसकी तीव्र तैनाती के लिए जाना जाता है क्योंकि जिन स्थितियों का सामना इसे करना पड़ता है, उनके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे आम तौर पर अपनी उत्पादक क्षमता के आसपास अर्थव्यवस्था को स्थिर करने का कार्य सौंपा जाता है। उदाहरण के लिए, जब कुल मांग या कुल व्यय देश की उत्पादक क्षमता से अधिक हो जाता है, तो असंतुलन विकसित होता है जो आसानी से अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। इन असंतुलनों के पहले संकेत आमतौर पर मूल्य दबाव या मुद्रास्फीति होते हैं। तदनुसार, मौद्रिक नीति कुल मांग को कम करने और इसे उत्पादक क्षमता के साथ संरेखित करने के लिए कार्य करती है। इसी तरह, जब मांग उत्पादक क्षमता से कम हो जाती है, तो अपस्फीति की स्थिति विकसित हो सकती है और इसलिए मौद्रिक नीति को मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बहाल करने के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना पड़ता है।

दूसरा, मौद्रिक नीति को भविष्योन्मुखी होना चाहिए। किसी भी समय, मौद्रिक नीति अधिकारियों के पास लक्ष्य चरों पर उपलब्ध जानकारी पिछड़ी हुई होती है - उदाहरण के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जैसी आर्थिक गतिविधि के माप पर, किसी भी समय उपलब्ध जानकारी आम तौर पर तीन महीने पुरानी होती है, यानी भारत में जनवरी-मार्च से संबंधित; भारत में उपभोक्ता कीमतों पर जानकारी केवल मई के लिए उपलब्ध होती है। इसके अलावा, नीतिगत गति ब्याज दरों की संरचना के माध्यम से परिवर्तनशील और अनिश्चित अंतराल के साथ यात्रा करते हैं - नीतिगत ब्याज दर में परिवर्तन बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए उधार दरों में पूरी तरह से परिलक्षित होने में समय लेते हैं। इसलिए, अक्सर ऐसा होता है कि मौद्रिक नीति को अंधाधुंध तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। इसके अलावा, लक्ष्य चर गतिशील होते हैं और इसलिए, मौद्रिक नीति को आगे बढ़ना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए, यह चलती लक्ष्य चरों के निर्माण को ट्रैक करने और उन्हें सटीक रूप से लक्षित करने के लिए रडार स्क्रीन की तरह सभी उपलब्ध सूचनाओं का उपयोग

करता है। यह कार्य तब और भी जटिल हो जाता है जब उनके अप्रत्याशित भविष्य जैसे कि अगले चालीस से पचास वर्षों में संभावित घटनाक्रम से निपटना पड़ता है। हम अभी वहां पहुंचेंगे।

तीसरा, जैसा कि अर्थशास्त्र के लिए 1969 के नोबेल पुरस्कार विजेता जान टिनबर्गन ने दिखाया, कोई भी नीति अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे अधिक कुशल होती है जब वह असाइनमेंट नियम का पालन करती है - यदि नीति ब्याज दर जैसा एक साधन है, तो एक लक्ष्य भी होना चाहिए। इसके बजाय, यदि मौद्रिक नीति बहुत सारे लक्ष्यों से बोझिल है, लेकिन बहुत कम साधनों से भी बाधित है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि साधन किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा।

चौथा, मौद्रिक नीति को कुछ नियम जैसे व्यवहार के संदर्भ में संचालित किया जाना चाहिए जो इसे समय के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है। इसके बजाय, यदि यह अल्पावधिक ट्रेड-ऑफ का फायदा उठाने के प्रलोभन का शिकार हो जाता है - जैसे अल्पावधि में मुद्रास्फीति नियंत्रण को छोड़ना और संवृद्धि को बढ़ावा देना या जिसे अर्थशास्त्री समय असंगति कहते हैं - तो यह अंततः अपने उद्देश्य से भटक जाएगा क्योंकि अल्पावधिक संवृद्धि की खोज में, मुद्रास्फीति को ऐसे स्तरों तक बढ़ने दिया जा सकता है जो विकास के लिए हानिकारक हो सकते हैं।

पांचवां, आधुनिक मौद्रिक नीति प्राधिकरणों ने पाया है कि मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता तब बढ़ जाती है जब इसे नीतिगत कार्रवाइयों के इरादे और इसके लक्ष्यों के संदर्भ में रुख और उन्हें प्राप्त करने के तरीके और समय सीमा के बारे में स्पष्ट और पारदर्शी संचार द्वारा समर्थित किया जाता है। संचार मौद्रिक नीति को जवाबदेह बनाता है क्योंकि जनता इसके प्रभाव को मापने में सक्षम होती है। यह, बदले में, नीति प्राधिकरण को इसके घोषित इरादे से बांधकर और मध्यम अवधि के लक्ष्यों की कीमत पर अल्पकालिक लाभ प्राप्त करने में असीमित विवेक को बाधित करके इसे विश्वसनीय बनाता है। वास्तव में, उच्च विश्वसनीयता बड़े नीतिगत परिवर्तनों या यहां तक कि किसी भी बदलाव की आवश्यकता को समाप्त कर देती है यदि जनता नीति के कल्याणकारी अभिविन्यास में विश्वास करती है। नतीजतन, संचार मौद्रिक नीति के लक्ष्यों के लिए जनता की अपेक्षाओं को

जोड़ने में मदद करता है ताकि नीति निर्माता और सभी हितधारक अपेक्षाओं के एक समान सेट के साथ काम करें। नीति, उसके आचरण और उसके लक्ष्यों के आसपास की अपेक्षाओं में स्थिरता व्यापक आर्थिक स्थिरता को जन्म देती है जो मध्यम अवधि की विकास संभावनाओं के लिए ठोस आधार प्रदान करती है।

### भविष्य का आकलन

मौद्रिक नीति का एक अंतर्निहित घरेलू अभिविन्यास होता है। इसलिए, जिस अर्थव्यवस्था में यह काम करती है उसकी विशेषताओं और जिस मार्ग पर आर्थिक गतिविधि के विकसित होने की सबसे अधिक संभावना है, उसकी अच्छी समझ अच्छी मौद्रिक नीति को तैयार करने और लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है। मैंने शुरू में जो समय परिप्रेक्ष्य चुना था, उसके संदर्भ में, पूछने का सवाल यह है: आज हम कहाँ हैं? और यहाँ से हमें कहाँ जाना है?

2023-24 तक, यानी, अभी-अभी बीता वर्ष, भारत वर्तमान विनिमय दरों पर ₹295.4 लाख करोड़ या यूएस\$3.6 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। ₹2,07,030 या यूएस\$2,500 की प्रति व्यक्ति आय के साथ, भारत देशों के निम्न मध्यम आय वर्ग में आता है। यहां तक पहुंचना एक घटनापूर्ण और कठिन यात्रा रही है, जिसे सांख्यिकीविदों ने 'संरचनात्मक विराम' कहा है। पहला विराम 1980 में हुआ, जो आजादी के बाद के उस दौर का अंत था जब जीडीपी वृद्धि औसतन 3.6 प्रतिशत या तथाकथित हिंदू विकास दर थी। यह अंतर्मुखी होने का युग था। 1980 से लेकर 2002 के आसपास दूसरे विराम तक, विकास दर औसतन 5.5 प्रतिशत तक पहुंच गई क्योंकि भारत खुल गया, व्यापार और पूंजी प्रवाह की बाधाओं को हटा दिया, तीसरा ब्रेक 2020 में महामारी के कारण हुआ। 2002 और 2020 के बीच, उदारीकरण और संरचनात्मक परिवर्तन के लाभ समेकित हुए और प्रवृत्ति वृद्धि 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई, लेकिन 2020-21 में जीडीपी में 5.8 प्रतिशत की भारी गिरावट के कारण यह बाधित हो गई। हालांकि, राष्ट्रव्यापी टीकाकरण और चतुर मैक्रोइकॉनॉमिक नीति समर्थन के सहारे, महामारी के बाद की अवधि में एक मजबूत वापसी हुई है। हालांकि पर्याप्त डेटा बिंदुओं की कमी के कारण यह कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक और संरचनात्मक बदलाव हो सकता है जो प्रवृत्ति वृद्धि को 8 प्रतिशत से ऊपर ले जा रहा है - जो आज दुनिया की सबसे तेजी

से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। 2024 में, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि भारत वैश्विक संवृद्धि में लगभग छठा हिस्सा योगदान करने जा रहा है।<sup>1</sup>

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि भारत अगले दस वर्षों में प्रति वर्ष 9.6 प्रतिशत की दर से विकास कर सकता है, तो यह निम्न मध्यम आय के जाल से मुक्त हो जाएगा और एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन लाभों को प्रति व्यक्ति आय में परिलक्षित होना चाहिए - मध्यम आय वाले देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए प्रति व्यक्ति आय स्तर 4516-14,005 अमेरिकी डॉलर और आज विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के लिए उस स्तर से आगे बढ़ना। हालाँकि, 2047 तक, विकसित देश की सीमा 34,000 अमेरिकी डॉलर तक बढ़ जाएगी।

बाजार में निर्धारित वर्तमान विनिमय दरें अस्थिरता और अजीबोगरीब व्यवहार के अधीन हैं जो उन्हें वास्तविकता से अलग कर देती हैं। इसलिए, राष्ट्रीय मुद्राओं में मापी गई जीडीपी के डीनॉमिनेटर के रूप में उनका अनुप्रयोग क्रॉस-कंट्री तुलना के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। एक वैकल्पिक उपाय क्रय शक्ति समता (पीपीपी) है। यह प्रत्येक देश में वस्तुओं और सेवाओं की एक औसत बास्केट की कीमत है। पीपीपी के साथ, तुलना नाटकीय रूप से बदल जाती है। पीपीपी के संदर्भ में, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 के लिए 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य पीपीपी के संदर्भ में 16 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में तब्दील होता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) का अनुमान है कि पीपीपी के संदर्भ में, भारत 2048 तक अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

विक्टर ह्यूगो के शब्दों में कहें तो, किसी देश से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता जिसका समय आ गया हो। जापान का युग 1960 के दशक में शुरू हुआ और 1980 के दशक तक चला। चीन का युग 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ, जिसने इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया। 2010 से भारत का समय आ गया है। भारत को आगे बढ़ाने और अगले दो-तीन दशकों में विश्व नेता के रूप में अपना सही स्थान प्राप्त करने के लिए कई ताकतें एक साथ आ रही हैं।

<sup>1</sup> विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक; 15 जनवरी 2024।

## अनुकूलताएं

मौद्रिक नीति के निर्माण में जोखिमों के संतुलन का मूल्यांकन करना एक अच्छा हाउसकीपिंग माना जाता है। कई सकारात्मक ऊर्जाएँ हैं जो अगले कुछ दशकों में भारत के भविष्य की दृष्टि को आकार देने में मदद कर रही हैं। इन शक्तियों की भूमिका भविष्य की मौद्रिक नीति की स्थापना को प्रभावित करेगी।

सबसे पहले, एक पारंपरिक लाभ है जो भारत की विकास संभावनाओं के पक्ष में जारी रहने की संभावना है। विकास प्रक्रिया मुख्य रूप से पूंजी संचय द्वारा संचालित होती रही है, जो निवेश को संवृद्धि का मुख्य साधन बनाती है। 2010-11 में निवेश दर जीडीपी के करीब 40 प्रतिशत पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद 2020-21 तक असमान रूप से कम हो गई। हालाँकि, 2021-23 के दौरान यह 31.2 प्रतिशत के आसपास स्थिर हो गई है और इसमें तेजी के संकेत दिख रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से, भारत के निवेश को घरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जिसमें परिवार अर्थव्यवस्था के बाकी हिस्सों के लिए संसाधनों के प्रमुख प्रदाता रहे हैं। 2021-23 की अवधि में सकल घरेलू बचत दर सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय का औसतन 30.7 प्रतिशत रही है। इस प्रकार, कई देशों के विपरीत, भारत को विदेशी संसाधनों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जो विकास प्रक्रिया में एक छोटी और पूरक भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, इस परिघटना की दर्पण छवि - भुगतान संतुलन में चालू खाता अंतर - 2023-24 में सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत पर मामूली बना हुआ है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहरी झटकों से सुरक्षा प्रदान करता है और बाहरी क्षेत्र को व्यवहार्यता और मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, भारत का सकल विदेशी ऋण, जो समय के साथ चालू खाता घाटे का संचय है, सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम है और लगभग पूरी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर से कवर किया जाता है। ऋण सेवा, यानी ब्याज और मूलधन चुकौती एक साथ चालू प्राप्तियों के 7 प्रतिशत से कम है। जहां तक सुपरसेवर्स - परिवारों का संबंध है - वित्तीय बचत से भौतिक बचत की ओर स्विच करने के प्रमाण हैं, जिसमें बाद में परिवारों की वित्तीय देनदारियों में वृद्धि द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

दूसरा, भारत जिस बढ़ती हुई विकास की राह पर आगे बढ़

रहा है, वह व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता से जुड़ी हुई है। महामारी और भू-राजनीतिक संघर्षों द्वारा उत्पन्न ऊपरी दबावों के साथ एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद, और खाद्य आपूर्ति आघातों के छिटपुट हमलों से और भी बढ़ गई, मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत के लक्ष्य के आसपास स्वीकार्य दायरे में वापस आ गई है। यह दृढ़ मौद्रिक नीति कार्यों और आपूर्ति प्रबंधन के संचयी प्रभाव को दर्शाता है। वास्तव में, मुख्य मुद्रास्फीति जिसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं है और जो मौद्रिक नीति के लिए सबसे अधिक अनुकूल है, अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। आरबीआई ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रतिबद्ध रहकर उम्मीदों को स्थिर किया है और मूल्य दबावों में हाल ही में आई कमी को प्रगति पर काम के रूप में माना है। इसने 2024-25 में मुद्रास्फीति के औसतन 4.5 प्रतिशत और 2025-26 में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। मुद्रास्फीति पर काबू पाना उपभोग की स्थिति, निवेश के दृष्टिकोण और बाहरी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके भविष्य में निरंतर उच्च संवृद्धि की नींव रखता है।

व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता विवेकपूर्ण वित्तीय नीतियों और सक्रिय ऑन-साइट पर्यवेक्षण के साथ-साथ ऑफ-साइट निगरानी से सुदृढ़ हो रही है, जो सुपटेक, बड़े डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा अभ्यासों का उपयोग करती है। भारत का वित्तीय क्षेत्र मुख्य रूप से बैंक आधारित है। बैंकिंग प्रणाली में सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) मार्च 2018 में अपने चरम से लगातार गिरकर मार्च 2024 तक कुल आस्तियों का 2.8 प्रतिशत रह गई हैं। प्रावधानों के लिए समायोजित, शुद्ध एनपीए सिर्फ 0.6 प्रतिशत है। पूंजी और तरलता बफर विनियामक मानदंडों से काफी ऊपर हैं। लाभप्रदता अधिक है और इस चक्र ने ऋण वृद्धि का समर्थन किया है। क्रेडिट जोखिम और ब्याज दर जोखिम के लिए दबाव परीक्षण से पता चलता है कि बैंक गंभीर दबाव परिदृश्यों में भी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं से ऊपर रहेंगे।

समष्टि आर्थिक स्थिरता का एक अन्य पहलू चालू राजकोषीय सुदृढ़ता है। नतीजतन, सामान्य सरकारी ऋण जो मार्च 2024 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 81.6 प्रतिशत होने का अनुमान

है, आईएमएफ द्वारा इस दशक के अंत तक घटकर 78.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। हमारे अनुमानों से पता चलता है कि यदि विनिर्माण के सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्रों में श्रम बल को फिर से कौशल प्रदान करने/अपस्किंग करने, डिजिटलीकरण में निवेश करने और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने पर व्यय बढ़ाया जाता है, तो सामान्य सरकारी ऋण 2030-31 तक सकल घरेलू उत्पाद के 73.4 प्रतिशत तक और भी कम हो जाएगा<sup>2</sup> यह आईएमएफ के अनुमानों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए 2028 में 116.3 प्रतिशत और उभरते और मध्यम आय वाले देशों के लिए 78.1 प्रतिशत तक ऋण अनुपात दिखाते हैं।

भारत की अनुकूल जनसांख्यिकी गतिशीलता से एक शक्तिशाली विकास त्वरक उभरता है। भारत की जनसंख्या, जिसे कभी माल्थसियन अभिशाप माना जाता था, अब अंतर-कालिक परिप्रेक्ष्य में इसकी सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है, खासकर जब बाकी दुनिया तेजी से बूढ़ी हो रही है और आबादी घट रही है। आज, दुनिया में हर छठा कामकाजी उम्र का व्यक्ति भारतीय है। 28 वर्ष की औसत आयु के साथ, कुल जनसंख्या में कामकाजी आयु वर्ग का हिस्सा 2050 के दशक के मध्य तक बढ़ता रहेगा, जिससे आय और बचत में वृद्धि के मामले में समान लाभ होगा। भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश तीन दशकों से अधिक समय तक रहने की उम्मीद है। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

भारत की डिजिटल क्रांति विकास को बढ़ाने वाला एक और कारक है। भारत परिवर्तनकारी बदलाव के लिए डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने में विश्व में अग्रणी बन रहा है। जे ए एम की त्रिमूर्ति - जन धन (बुनियादी नो-फ्रिल्स खाते); आधार (सार्वभौमिक विशिष्ट पहचान); और मोबाइल फोन कनेक्शन - औपचारिक वित्त के दायरे का विस्तार कर रहे हैं, तकनीकी स्टार्ट-अप को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को लक्षित करने में सक्षम बना रहे हैं। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई), एक ओपन-एंडेड सिस्टम है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में सक्षम बनाता है, जो अंतर-बैंक पीयर-टू-पीयर और व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन को सहजता से

<sup>2</sup> पात्र एम.डी., बेहरा, एस., बेहरा, एच., बर्नजी, एस., पाधी, आई. और सूद, एस. (2024)। विकास संगत राजकोषीय समेकन का स्वरूप आरबीआई बुलेटिन, फरवरी।

आगे बढ़ा रहा है। भारत में भुगतान प्रणाली 24x7x365 आधार पर काम करती है। ऑफलाइन भुगतान, फीचर फोन के माध्यम से भुगतान और संवादात्मक भुगतान जैसी कार्यक्षमताएँ शामिल की गई हैं। यूपीआई का अंतरराष्ट्रीयकरण तेजी से आगे बढ़ रहा है।

### प्रतिकूलताएं

भारत की संवृद्धि संबंधी महत्वाकांक्षाओं की दिशा में प्रगति को चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या जिन्हें मौद्रिक नीति विश्लेषण में नकारात्मक जोखिम कहा जाता है। इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटना मौद्रिक नीति के संचालन का परीक्षण होगा क्योंकि भारत अपनी नियति की तलाश में आगे बढ़ रहा है।

जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने की कुंजी सकल मूल्य वर्धन में श्रम बल के योगदान को बढ़ाने में है। नौकरी सृजन और उच्च कौशल के लिए पुरस्कारों में हाल के सुधारों के बावजूद, मात्रा और गुणवत्ता दोनों के हिस्से - जो कौशल निर्माण के प्रतिफल को संदर्भित करता है - भारत के श्रम का अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार कम है। किसी विशिष्ट नौकरी के लिए उपयुक्त कौशल के मामले में, केवल 51 प्रतिशत ही रोजगार योग्य हैं, जिससे नौकरी की आवश्यकताओं और तकनीकी बदलाव के अनुरूप कार्यबल को फिर से कुशल और उन्नत करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता है।<sup>3</sup> 80 प्रतिशत से अधिक कार्यबल अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं और यह रोजगार के औपचारिकरण के विस्तार की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके अलावा, भारत कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में निचले पायदान पर है। महिला श्रम भागीदारी को बढ़ाना एक प्रमुख चुनौती है, जिसके लिए कामकाजी महिलाओं के पक्ष में सामाजिक मानकों की आवश्यकता है, मसलन - शैक्षिक संस्थानों और कार्यस्थलों में विविधता को प्रोत्साहित करना; कार्यस्थलों पर लचीले कार्य घंटे और महिलाओं के लिए अनुकूल नीतियां और सुविधाएं; और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देना।

एक और बड़ी चुनौती उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे का निर्माण है। भारत में बुनियादी ढांचे में प्रति व्यक्ति निवेश 2015 के स्थिर डॉलर में 90 अमेरिकी डॉलर है, जिसे बुनियादी ढांचे में

निवेश को सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 4 प्रतिशत से बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए सक्षम विनियमन, तेज मंजूरी, सुचारू भूमि अधिग्रहण और जलवायु मंजूरी नीतियों और पर्याप्त बुनियादी ढांचा वित्त की आवश्यकता होगी। लगातार केंद्रीय बजटों में निरंतर बुनियादी ढांचा खर्च और लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने से भारत के बुनियादी ढांचे के लक्ष्य को वित्तपोषित करने के लिए माहौल बन रहा है।

उच्च श्रेणी का विनिर्माण आधार विकसित करके नौकरियों के औपचारीकरण को सुगम बनाया जाएगा। भारत ने अपनी विकास यात्रा में विनिर्माण को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया - आज भारत की अर्थव्यवस्था में सेवाओं का हिस्सा दो-तिहाई है जबकि विनिर्माण का योगदान लगभग 17 प्रतिशत है। 1990 के दशक से विनिर्माण की औसत वृद्धि 7 प्रतिशत रही है। 7.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, विनिर्माण का हिस्सा 2030-31 तक जीवीए का 20 प्रतिशत हो सकता है। यदि विनिर्माण की विकास दर को 10 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है, तो सकल मूल्य वर्धन में विनिर्माण का हिस्सा 25 प्रतिशत तक बढ़ सकता है, जिससे भारत अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के लिए आगे और पीछे के संबंधों के साथ एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की कगार पर पहुंच जाएगा। विनिर्माण शक्ति के रूप में सफल होने के लिए कुशल श्रम शक्ति का होना आवश्यक है।

भारत के विनिर्माण को वैश्विक बाजारों में स्थान मिलना चाहिए - दुनिया के लिए भारत में विनिर्माण। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत और विविधतापूर्ण विनिर्माण आधार आवश्यक है। भारत के माल और सेवाओं के निर्यात को 768 बिलियन अमेरिकी डॉलर या दुनिया के कुल 2.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 2030 तक माल और सेवा निर्यात के लिए 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर या वैश्विक कुल का 5 प्रतिशत करने के लिए तीव्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। आईटी और डिजिटल सेवाओं, उच्च मूल्य वाले कृषि उत्पादों, उच्च मूल्य वाले पर्यटन; वित्तीय सेवाओं; खुदरा और ई-कॉमर्स जैसे क्षेत्रों के रूप में क्षमता मौजूद है। भारत उत्पादन-लिंकड प्रोत्साहन योजना, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों, जैसी पहलों के माध्यम से इस निर्यात अभियान के लिए तैयारी कर रहा है; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम

<sup>3</sup> व्हीबॉक्स : भारत कौशल रिपोर्ट 2024. [https://wheebox.com/assets/pdf/ISR\\_Report\\_2024.pdf](https://wheebox.com/assets/pdf/ISR_Report_2024.pdf)

उद्यमों (एमएसएमई) की निर्यात क्षमता का समर्थन कर रहा है। भारत में स्थापित वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) पहले से ही इन अंतर्निहित शक्तियों का दोहन कर रहे हैं। वे पहले से ही भारत के कार्यबल का लाभ उठा रहे हैं, उत्पाद नवाचार का नेतृत्व कर रहे हैं, तकनीकी प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, अगली पीढ़ी की बौद्धिक संपदा (आईपी) बना रहे हैं और डिजिटलीकरण पहलों का नेतृत्व कर रहे हैं।

भारत एक मजबूत विनिर्माण आधार द्वारा समर्थित निर्यात शक्ति के रूप में उभर रहा है, जिसका स्वाभाविक परिणाम भारतीय रुपये का पूर्ण अंतरराष्ट्रीयकरण होगा। कई कारक पहले से ही मौजूद हैं। भारतीय प्रवासी दुनिया में सबसे बड़े हैं और भारत विप्रेषण का शीर्ष प्राप्तकर्ता है। भारतीय रुपया ऑनशोर की तुलना में तीन गुना अधिक ऑफशोर ट्रेड करता है। भारत एशिया और मध्य पूर्व के कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान व्यवस्था का विस्तार कर रहा है और भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़ने का काम चल रहा है। गहरे और तरल वित्तीय बाजार विकसित हो रहे हैं। गुजरात के गिफ्ट शहर में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र एक संपन्न वित्तीय परितंत्र के साथ वैश्विक वित्तीय और प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभर रहा है। समष्टि अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता पर नीतिगत जोर भी आईएनआर के अंतरराष्ट्रीय होने के लिए सकारात्मक है।

आखिरी चुनौती जिस पर मैं बात करूंगा, वह है धारणीय विकास के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाना। इसमें जलवायु परिवर्तन का प्रबंधन करना शामिल है। जलवायु परिवर्तन हम पर हावी हो रहा है, जिससे ग्रह और मानवता खतरे में पड़ रहे हैं। यह वैश्विक स्तर पर खतरनाक पैमाने और गति से प्रकट हो रहा है। यह आजीविका और बुनियादी ढांचे को कमजोर कर रहा है और स्वास्थ्य, भोजन, ऊर्जा और जल सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। जलवायु संबंधी आपदाएँ अधिक बार और दुनिया भर में हो रही हैं। वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष साबित हुआ। 2024 में, भारत अपनी सबसे खराब गर्मी और जंगल की आग का सामना कर रहा है। बेंगलुरु जल संकट का सामना कर रहा है। जलाशय

सूख रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी मौसम एजेंसियां ला नीना के कारण इस मानसून के मौसम में बाढ़ की भविष्यवाणी कर रही हैं। हम अब और प्रतिरक्षित या निष्क्रिय नहीं रह सकते।

2021 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टिज 26 (सीओपी26) में, 2030 तक पर्यावरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता में शामिल हैं: (i) 500 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता; (ii) 50 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा वाला ऊर्जा मिश्रण; (iii) कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में एक बिलियन टन की कमी करना; (iv) अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करना; और (v) 2070 तक निवल शून्य प्राप्त करना। यह अनुमान लगाया गया है कि तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त पहुंच के साथ-साथ 10.1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश की आवश्यकता है।

### निष्कर्ष

मैंने जिन अंतर्निहित शक्तियों का वर्णन किया है तथा अपने आकांक्षात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के संकल्प को देखते हुए, यह कल्पना करना संभव है कि भारत अगले दशक में प्रवेश करेगा तथा 2048 तक नहीं, बल्कि 2031 तक विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तथा 2060 तक विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

इस संदर्भ में मौद्रिक नीति की क्या भूमिका है? मौद्रिक नीति का मुख्य कार्य भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार बनना है। समग्र मांग के अल्पकालिक उतार-चढ़ाव को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जाना चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की उभरती हुई उत्पादक क्षमता के साथ व्यापक संरक्षण सुनिश्चित हो सके। मूल्य स्थिरता वह सर्वोत्तम योगदान है जो मौद्रिक नीति अगले कुछ दशकों में संवृद्धि के आकांक्षी पथ की नींव को मजबूत करने के लिए कर सकती है। भारत में मुद्रास्फीति के गठन को वैश्विक मुद्रास्फीति के साथ अभिसरण की दिशा में ले जाने की आवश्यकता है ताकि रुपये का आंतरिक और बाह्य मूल्य दोनों संरक्षित रहें। यह रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण और कल की दुनिया के आर्थिक महाशक्ति के रूप में भारत के उभरने के लिए जमीन तैयार करेगा।

## उभरते वित्तीय परिदृश्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका\*

एम राजेश्वर राव

मुझे वाणिज्यिक बैंकों और एआईएफआई की सांविधिक लेखापरीक्षा के मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आज यहां उपस्थित होने पर प्रसन्नता हो रही है। कई मायनों में, हम, विनियामकों / पर्यवेक्षकों के रूप में और आप लेखा परीक्षकों के रूप में, एक समान लक्ष्य साझा करते हैं। लेखा परीक्षक वित्तीय प्रणाली सही रहे ये सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे यह सुनिश्चित करके विनियामक निरीक्षण के रखरखाव में सहायता करते हैं कि वित्तीय विवरण विनियमित इकाई (आरई) के मामलों की सही और निष्पक्ष तस्वीर पेश कर रहा है। सांविधिक लेखा परीक्षक लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों में हितधारकों का विश्वास बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह बैंकिंग उद्योग के मामले में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां संपूर्ण साम्राज्य 'विश्वास' पर बनाया गया है और सबसे बड़े बाह्य हितधारक अर्थात् जमाकर्ता खंडित और असंगठित हैं। इसलिए, रिजर्व बैंक की बैंकिंग और वित्तीय उद्योग के लिए ठोस और उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन और प्रकटीकरण मानकों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारदर्शी और तुलनीय वित्तीय विवरण रखने में बहुत रुचि है जो बाज़ार अनुशासन को मजबूत करते हैं।

### लेखा परीक्षक महत्वपूर्ण हितधारक हैं

एक इकाई की वित्तीय रिपोर्ट अपने वित्तीय प्रदर्शन के साथ-साथ जोखिम प्रोफाइल का एक पटल प्रदान करती है और इसलिए, वित्तीय रिपोर्टिंग को अक्सर एक इकाई और उसके बाह्य हितधारकों के बीच "संचार" के लिए "भाषा" के रूप में संदर्भित किया जाता है। "संचार" केवल तभी प्रभावी हो सकता है जब प्रबंधन और हितधारक दोनों एक ही "भाषा" बोलते हों।

\* श्री एम राजेश्वर राव, उप गवर्नर द्वारा 9 जुलाई 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई) के सांविधिक लेखा परीक्षकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों के सम्मेलन में दी गई टिप्पणी। जयकर मिश्रा, संदीप महाजन और प्रदीप कुमार द्वारा प्रदान किए गए इनपुट की सराहना की जाती है।

इसके लिए, हमें नियमों और सिद्धांतों के एक सेट के रूप में एक आम भाषा की आवश्यकता है, जहां लेखांकन मानक खेल में आते हैं। सामान्य संहिताबद्ध सिद्धांतों और मानकों के एक सेट के आधार पर तैयार किए गए वित्तीय विवरण सूचना विषमता को कम करते हैं; संस्थाओं और सभी क्षेत्रों के बीच तुलनात्मकता और पारदर्शिता को बढ़ाते हैं; और वित्तीय रिपोर्टिंग पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से प्रदान की गई जानकारी को प्रासंगिक और विश्वसनीय बनाते हैं। इस तरीके से तैयार किए गए वित्तीय विवरण उपयोगकर्ताओं और हितधारकों को इकाई की संसाधन स्थिति, इनके खिलाफ किए गए दावों, संसाधनों और दावों में परिवर्तन के स्रोतों, और भविष्य के नकदी प्रवाह के समय और अनिश्चितता को समझने और आकलन करने में मदद करते हैं जो उन्हें प्रबंधन को चलाने में सक्षम बनाता है।

विनियामक इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। एक इकाई की वित्तीय स्थिति की जानकारी उसके विनियामक द्वारा किए गए आकलन से प्राप्त होती है। लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण भी रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण विनियमों के महत्वपूर्ण तत्वों का आधार बनते हैं। पूंजी और लीवरेज अनुपात, चलनिधि की स्थिति, हानि और प्रावधानों की गणना आदि विनियमित संस्थाओं द्वारा तैयार किए गए सटीक और पारदर्शी वित्तीय विवरणों पर निर्भर करते हैं। वित्तीय विवरण केवल तभी सटीक हो सकते हैं जब लेखांकन मानकों की सही व्याख्या की जाती है और लगातार लागू किया जाता है। लेखा परीक्षक अभिभावक हैं जिनसे इस प्रक्रिया की सटीकता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है। वे प्रबंधन और हितधारकों के बीच सेतु भी हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि प्रबंधन का निर्णय मजबूत है और इकाई ने लेखांकन मानकों का पालन किया है।

विनियामक का हित उसके द्वारा विनियमित संस्थाओं में मामलों के निष्पक्ष और पारदर्शी प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है। बैंक और वित्तीय संस्थान भी वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता हैं और काफी हद तक उनकी भलाई उन संस्थाओं से जुड़ी हुई है जिन्हें वे उधार देते हैं या निवेश करते हैं। इसलिए, हम सुदृढ़ लेखा परीक्षा प्रथाओं के समान रूप से पक्ष में हैं जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाली कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग होती

है। हम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और लेखा परीक्षा मानक सेटिंग के क्षेत्र में विकास की बारीकी से निगरानी करते हैं।

इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, हम बैंकिंग क्षेत्र में लेखांकन मुद्दों पर भारत में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के साथ मिलकर काम करना जारी रखते हैं। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने लेखा मानकों के अनुपालन में कमियों की पहचान करने के लिए आईसीएआई के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एन डी गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था। समूह की सिफारिशों के आधार पर, लेखांकन मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मार्च 2003 में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए थे। हमने आईएनडी एस को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के रोड मैप पर उद्योग और आईसीएआई के साथ मिलकर काम किया था और बैंकों में इंड एस कार्यान्वयन के मुद्दों से निपटने के लिए एक कार्य समूह की स्थापना की थी।

### सिद्धांत आधारित विनियामक वातावरण में लेखा परीक्षकों की भूमिका

रिज़र्व बैंक, पिछले कुछ समय से, सिद्धांत आधारित विनियमों के साथ नियम-आधारित विनियमों को पूरक कर रहा है ताकि आरई को उनके व्यवसाय निर्णय लेने में लचीलापन मिल सके। यह प्रक्रिया भारतीय वित्तीय क्षेत्र के अधिक परिपक्वता प्राप्त करने के साथ विकसित हुई है। सिद्धांत-आधारित नियम लेखांकन के एक पहलू को भी शामिल करता है जो लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए निर्देशात्मक, नियम आधारित मानदंडों से दूर जाने को प्रतिबिंबित करेगा। मैं हाल के दो उदाहरण देता हूँ।

पहला दिशानिर्देश बैंकों में निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन से संबंधित है। 1 अप्रैल 2024 से प्रभावी संशोधित मानदंड बड़े पैमाने पर बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन पर दिशानिर्देशों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के साथ संरेखित करते हैं। इन मानदंडों में बैंकों को वित्तीय आस्तियां (व्यवसाय मॉडल) रखने के इरादे और उद्देश्य और ऐसी आस्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं के आधार पर निवेश पोर्टफोलियो को वर्गीकृत करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, बैंकिंग बुक और

ट्रेडिंग बुक के बीच एक आस्ति के वर्गीकरण में महत्वपूर्ण पूंजी निहितार्थ हो सकते हैं। इन पहलुओं को प्रबंधन निर्णय के व्यापक उपयोग की आवश्यकता होगी। हम उम्मीद करते हैं कि लेखा परीक्षक विनियमों को ध्यान से समझेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि बैंक न केवल विनियमों का पालन करें बल्कि विनियामक इरादे का भी पालन करें।

दूसरा उदाहरण अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) आधारित प्रावधान मानदंडों का है। यह इस समय एक कार्य-प्रगति है। हमने एक चर्चा पत्र (डीपी) जारी किया है और इसमें शामिल महत्वपूर्ण बदलावों पर स्वतंत्र इनपुट प्राप्त करने के लिए एक बाहरी कार्य समूह भी स्थापित किया गया। प्रस्तावित ईसीएल ढांचे का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आरबीआई द्वारा निर्धारित व्यापक ढांचे के भीतर, बैंक ऋण हानि प्रावधानों का आकलन करने के लिए विभिन्न पद्धतियों और मॉडलों का उपयोग कर सकते हैं। यह विनियामकों और लेखा परीक्षकों दोनों के लिए एक अनूठी चुनौती पेश करेगा। सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में, आपको स्वयं को संतुष्ट करने की आवश्यकता होगी कि बैंक ऐसे प्रावधानों की सही गणना कर रहा है और विनियमित संस्थाओं द्वारा नियोजित मॉडल मजबूत हैं।

विनियमों के सिद्धांत आधारित दृष्टिकोण की स्थापना इस विश्वास पर की गई है कि वित्तीय रिपोर्टिंग लेनदेन की आर्थिक वास्तविकता को दर्शाती है। हालांकि, सिद्धांत-आधारित मानकों के प्रयोग के लिए प्रबंधन निर्णय के महत्वपूर्ण उपयोग की आवश्यकता होती है। कभी-कभी, प्रबंधन लेखांकन अनुमानों का चयन कर सकता है जिसमें तटस्थता या पूर्वाग्रह से स्वतंत्रता की कमी हो सकती है। यह इस संदर्भ में है कि लेखापरीक्षा में अधिक कठोरता और संशयवाद का निर्माण आवश्यक हो जाता है। हालांकि, ऐसा करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता हो सकती है और इन परिवर्तनों और चुनौतियों को संभालने के लिए अतिरिक्त क्षमता के निर्माण पर काम करना शुरू करना समझदारी होगी।

इस संबंध में, मैं आईएनडी एस कार्यान्वयन के संबंध में एनबीएफसी में ऐसे सिद्धांत-आधारित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के साथ अपने अनुभव को भी साझा करना चाहता हूँ। हमारे आकलन से पता चलता है कि सिद्धांतों-आधारित

मानकों द्वारा पेश किया गया लचीलापन, जबकि मूल्यवान है, लेकिन कुछ मामलों में कम हो गया है जहां उनके प्रयोग का संबंध है। मैं उन कतिपय मुद्दों और चुनौतियों का उल्लेख करना चाहूंगा जिनका हमने सामना किया है और जिनका लेखापरीक्षकों द्वारा अधिक सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जा सकता था।

- हालांकि मानक परिशोधन लागत श्रेणी के तहत आस्तियों से बिक्री की अनुमति देते हैं, एक इकाई को यह आकलन करने की आवश्यकता होती है कि इस तरह की बिक्री संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य के अनुरूप कैसे है। व्यवहार में, हमने देखा है कि प्रतिभूतिकरण और प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से परिशोधन लागत श्रेणी से महत्वपूर्ण बिक्री हुई है। यह स्पष्ट नहीं है कि इस तरह की बिक्री व्यवसाय मॉडल के अनुरूप कैसे है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए आस्ति रखना है।
- एक और उदाहरण यह है कि आईएनडी एस 109 के तहत निर्धारित हानि ढांचा कैसे लागू किया जाता है। जबकि ढांचा दूरदर्शी है और चरण 1 से चरण 2 तक आस्तियों के आवागमन के लिए क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में किसी भी महत्वपूर्ण वृद्धि का आकलन केवल पिछले दिनों के देय (डीपीडी) की तुलना में अधिक दूरदेशी मानदंडों में कारक होना आवश्यक है, यह देखा गया है कि कुछ एनबीएफसी मुख्य रूप से 30 डीपीडी मानदंडों पर भरोसा करते हैं। डीपीडी एक लैगिंग संकेतक होने के नाते, हमेशा ईसीएल के दूरदर्शी दृष्टिकोण का उपयोग करने के साथ एक समान नहीं होता है।
- आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) के मामले में, यह देखा गया कि प्रबंधन शुल्क और व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था जो 180 दिनों से अधिक समय तक अप्राप्य रहे। ऐसी टिप्पणियों के कारण रिजर्व बैंक के लिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण से दिशानिर्देश जारी करना आवश्यक हो गया ताकि पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना करते समय ऐसे अप्राप्त प्रबंधन शुल्क विनियामक पूंजी से काट लिए जाएं।

उपर्युक्त हाइलाइट किए गए उदाहरण सिद्धांत आधारित ढांचे में पेश किए गए लचीलेपन का उपयोग करने की आरई की हमारी चिंता को इस तरह से सामने लाते हैं जो पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं है। हमारा विचार है कि ऐसे मुद्दों के लिए लेखा परीक्षकों से संशयवाद के ऊंचे स्तर की आवश्यकता होती है। स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के रूप में, लेखा परीक्षकों को प्रबंधन के निर्णय और मान्यताओं का गंभीर मूल्यांकन करना चाहिए और चुनौती देनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये लेखांकन मानकों और विवेकपूर्ण मानदंडों के अंतर्निहित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) ने हाल ही में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के मामले में आदेश दिया है जिसमें कहा गया है कि लेखापरीक्षा ने ईसीएल प्रावधानों की तर्कसंगतता सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया। यह लेखांकन प्रक्रिया में संभावित कमियों का एक कठोर अनुस्मारक भी है।

### प्रकटीकरण ढांचा

सिद्धांत-आधारित ढांचे के बारे में चर्चा मुझे मेरी टिप्पणी के दूसरे भाग में लाती है जो प्रकटीकरण ढांचे पर केंद्रित है।

ऐसा कहा जाता है कि महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। मैं इसे पुनः कहना चाहूंगा – “लेखांकन और विवेकपूर्ण मानदंडों में अधिक लचीलेपन के साथ प्रकटीकरण में अधिक जिम्मेदारी आती है।” प्रकटीकरण पारदर्शिता की आधारशिला है। स्पष्ट प्रकटीकरण प्रबंधन क्या जानता है और बाहरी उपयोगकर्ता वित्तीय विवरणों से क्या अनुमान लगा सकते हैं, इसके बीच की खाई को पाटते हैं। लेकिन विवादास्पद सवाल यह है कि सूचना अधिभार के साथ उपयोगकर्ताओं पर भार दिए बिना स्पष्ट समझ सुनिश्चित करने के लिए कितना प्रकटीकरण ‘अच्छा’ है। व्यापक प्रकटीकरण और संक्षिप्तता के बीच संतुलन बनाना ही सबसे बड़ा मुद्दा है। जब प्रकटीकरण स्पष्ट और व्यापक होते हैं, तो वे बाजार में विश्वास को बढ़ावा देते हैं।

मैं इस संबंध में अपने अनुभवों को साझा करना चाहूंगा। हमने ईसीएल ढांचे के संदर्भ में एनबीएफसी द्वारा किए जा रहे प्रकटीकरण को देखा। कुछ एनबीएफसी की लेखांकन नीतियों के प्रकटीकरण के अवलोकन पर, हमने देखा कि अधिकांश

प्रकटीकरण काफी हद तक संबंधित लेखांकन मानकों के पाठ की पुनरावृत्ति थी। हम ईसीएल को मापने में लागू मान्यताओं और विधियों की चर्चा, सामूहिक आधार पर अपेक्षित नुकसान का आकलन करने के लिए साझा क्रेडिट जोखिम विशेषताओं, एसआईसीआर के निर्धारण में गुणात्मक मानदंड आदि जैसी कोई विशिष्ट अंतर्दृष्टि नहीं जुटा सके।

इस स्थिति को मापने के लिए, हम आरई को उनके प्रकटीकरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन मैं यहां उपस्थित सभी लोगों के साथ-साथ बड़े लेखा परीक्षक समुदाय से भी आग्रह करूंगा कि वे प्रकटीकरण प्रथाओं का गंभीर मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि लेखांकन मानकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा किया जाए। लेखा परीक्षकों की यह सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी है कि संस्थाएं शासन और नियंत्रण तंत्र से संबंधित उपयुक्त गुणात्मक जानकारी प्रदान करें।

### उभरती चुनौतियां और अपेक्षाएं

आगे बढ़ते हुए, अब मैं आगे आने वाली कुछ चुनौतियों और अपेक्षाओं को रेखांकित करता चाहूंगा।

यह पुनरावृत्ति के योग्य है कि यह लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह चल रही चिंता अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए पर्याप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करे। इस बदलते परिवेश में, लेखा परीक्षक की भूमिका को केवल वित्तीय विवरणों की पुष्टि करने से ऊपर इकाई द्वारा अपनाए व्यवसाय संचालन और व्यवसाय मॉडल द्वारा उत्पन्न भौतिक जोखिमों का समग्र रूप से आकलन करने तक बढ़ाया जाना चाहिए। अतीत में, हमने ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां इकाई का अस्थिर व्यापार मॉडल अंततः इसके पतन का कारण बना। सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में, यह एक उभरती हुई चुनौती है जिस पर आपको विचार करने और अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रिया में आत्मसात करने के तरीके खोजने की आवश्यकता है।

एक दूसरी उभरती चुनौती जलवायु और स्थिरता से संबंधित है। जलवायु जोखिमों के बढ़ने और हितधारकों की जांच तेज होने के साथ, मजबूत स्थिरता रिपोर्टिंग अब एक अच्छी स्थिति में नहीं होगी, लेकिन वित्तीय और गैर-वित्तीय संस्थाओं के लिए एक

आवश्यकता बन जाएगी। रिज़र्व बैंक ने जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रकटीकरण पर मसौदा विनियम भी जारी किए हैं। वित्तीय फर्मों में निहित जटिलता और विविधता जलवायु जोखिम के आकलन को चुनौतीपूर्ण बनाती है और इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो लेखा परीक्षक प्रक्रिया में निभा सकते हैं।

तीसरा मुद्दा जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा वह प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका, विशेषकर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में से संबंधित है। उभरती प्रौद्योगिकियां बैंकिंग और वित्तीय परिदृश्य को काफी हद तक बदल रही हैं। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि इस प्रौद्योगिकीय क्रांति के कारण लेखा-परीक्षा करने का तरीका भी बदल रहा है। वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए डिजिटल चैनलों के उपयोग में घातांकीय वृद्धि ने तीसरे पक्ष के सेवा प्रदाताओं पर आरईएस निर्भरता को बढ़ा दिया है और उन्हें साइबर और आउटसोर्सिंग जोखिमों सहित परिचालन जोखिमों के लिए अनावृत कर दिया है। बदलते परिवेश में, पारंपरिक मूल परीक्षण और प्रक्रियाएं पर्याप्त/उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकती हैं। लेखा परीक्षकों को यह मूल्यांकन करने की आवश्यकता है कि क्या प्रबंधन आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का सही आकलन कर रहा है। फिर, विक्रेता निर्भरता, सघनता के साथ-साथ नियंत्रण तंत्र से संबंधित गुणात्मक पहलुओं को लेखा परीक्षकों के विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखा परीक्षा के प्रभावी होने के लिए, उसे उपयोगकर्ताओं की जरूरतों और अपेक्षाओं पर विचार करना चाहिए। ये उभरते मुद्दे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं और उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए कि नियंत्रणों के डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावशीलता को समझने के लिए विशेष कौशल आवश्यक हैं या नहीं। लेखा परीक्षकों की इन अपेक्षाओं का जवाब देने की क्षमता और कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण है ताकि उचित आश्वासन प्रदान किया जा सके और अंततः उच्च गुणवत्ता वाले लेखा परीक्षा परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें।

### समापन विचार

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि बैंकों द्वारा तेजी से जटिल उभरते परिदृश्य की दिशा निर्धारित करने के बावजूद, विनियामकों

और लेखा परीक्षकों द्वारा एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण जोखिम की पहचान और शमन में कमियों को दूर कर सकता है। इससे वित्तीय स्थिरता के हमारे साझा लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों की मजबूती सुनिश्चित होगी। इसलिए, विनियामकों और लेखा परीक्षकों के बीच गहन जुड़ाव और सहयोग की आवश्यकता है। 'वित्तीय रिपोर्टिंग और बाह्य लेखा परीक्षा' पर प्रभावी बैंकिंग पर्यवेक्षण हेतु बेसल कोर सिद्धांतों में भी इस बात पर जोर दिया गया है जो पर्यवेक्षकों (विनियामकों) को बैंक परिचालनों से संबंधित सामान्य हित के

मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बाह्य लेखा परीक्षकों से आवधिक रूप से मिलने के लिए प्रोत्साहित करता है। मुझे पता है कि ऐसी चर्चाएं हमारी पर्यवेक्षी प्रक्रिया के दौरान होती हैं और हम इन चर्चाओं के दौरान लेखापरीक्षकों द्वारा किए गए योगदान को बहुत महत्व देते हैं।

अंत में, मैं यह स्वीकार करना चाहूंगा कि बाह्य लेखापरीक्षा एक मजबूत विनियामक ढांचे का एक अनिवार्य घटक है। हम अपनी वित्तीय प्रणाली की स्थिति, स्थिरता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग की उम्मीद करते हैं।

धन्यवाद। नमस्कार।



## साझा दृष्टिकोण, साझा जिम्मेदारियाँ: बैंकिंग पर्यवेक्षण में अग्रिम आश्वासन\*

स्वामीनाथन जे.

श्री अजय भूषण प्रसाद पांडे, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण; श्री एम आर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक; भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक; सीए रणजीत अग्रवाल, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्ट्स ऑफ इंडिया; बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के लेखा परीक्षक और मुख्य वित्तीय अधिकारी; भारतीय रिज़र्व बैंक के मेरे सहयोगी; देवियो और सज्जनों। शुभ प्रभाता।

हमारी बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय ईमानदारी और अनुशासन के प्रमुख स्तंभों में से एक - लेखा परीक्षकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों (सीएफओ) की इस विशिष्ट सभा को संबोधित करना वास्तव में एक सम्मान की बात है। आज का सम्मेलन ऐसे लक्षित दर्शकों के संदर्भ में अपनी तरह का एक पहला सम्मेलन है, लेकिन यह रिज़र्व बैंक द्वारा अपनी विनियमित संस्थाओं के साथ किए जा रहे जुड़ावों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जो अनुशासन और आश्वासन कार्यों के विशिष्ट महत्व को रेखांकित करता है।

आज के सम्मेलन का विषय, साझा दृष्टिकोण और साझा जिम्मेदारियाँ, लेखा परीक्षकों और बैंक पर्यवेक्षकों की भूमिकाओं के बीच तालमेल प्रतिबिंबित करता है, जो हमारी वित्तीय प्रणाली के स्वास्थ्य और स्थिरता दोनों के लिए महत्वपूर्ण हैं। साथ मिलकर, हम अग्रिम आश्वासन और बैंकिंग पर्यवेक्षण के लिए एक दृष्टिकोण और जिम्मेदारी साझा करते हैं।

### सीएफओ की भूमिका और अपेक्षाएं

आज हमारे बीच बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के सीएफओ मौजूद हैं। एक बैंक के सीएफओ के रूप में कार्य करने के बाद, मैं इस भूमिका की बहुत बड़ी जिम्मेदारियों को गहराई से

\* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. का 9 जुलाई, 2024 को मुंबई में वाणिज्यिक बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के संवैधानिक लेखा परीक्षकों और मुख्य वित्तीय अधिकारियों के सम्मेलन में भाषण।

समझता हूँ। मैं आपके लिए बस यही कामना कर सकता हूँ कि आपकी लेखा परीक्षा साफ-सुधरी हो, आपके आंकड़े सटीक हों और आपका भविष्य हमेशा उज्वल हो।

सीएफओ के रूप में, आपको बैंक के वित्तीय विवरणों और रिपोर्टों की सटीकता, पूर्णता और सत्यता सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। इसके अलावा, आपको यह सब सख्त संवैधानिक और विनियामक समय-सीमाओं को ध्यान में रखते हुए करना होगा। यद्यपि जोखिम प्रबंधन के लिए समर्पित एक मुख्य जोखिम अधिकारी होता है, फिर भी इस क्षेत्र में, विशेष रूप से पूंजी पर्याप्तता, परिपक्वता अंतर और चलनिधि प्रबंधन में सीएफओ का योगदान महत्वपूर्ण है। सीएफओ रणनीतिक योजना, बजटन और निवेशक संबंधों - संक्षेप में, अपने संस्थानों के वित्तीय भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वास्तव में, आज के गतिशील वित्तीय परिदृश्य में, सीएफओ की भूमिका केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है, बल्कि संस्थान को सतत विकास और समुत्थानशीलता की ओर ले जाने की भी है। व्यक्तिगत अनुभव से, मैं कह सकता हूँ कि यदि यह केवल आंकड़ों के बारे में होता, तो यह काम उतना दिलचस्प नहीं होता।

इन कार्यों की व्यापकता देखते हुए, सीएफओ बैंक के दैनिक कार्यों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं और उन्हें संगठन के किसी भी अन्य प्रमुख व्यवसाय प्रमुखों या उच्च अधिकारियों की तुलना में अपने संस्थान की ताकत और कमजोरियों की गहरी समझ है। इस गहन ज्ञान के कारण सीएफओ की जिम्मेदारी का स्तर ऊँचा रहता है। संभवतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के बाद यह वह पद है जिसे पूरे बैंक और इसकी वित्तीय ताकत के प्रमुख साधनों की सम्पूर्ण जानकारी होती है। इसलिए, यह उनका कर्तव्य है कि वे लेखा परीक्षकों और पर्यवेक्षकों, विशेष रूप से नए लेखा परीक्षकों और पहली बार पधारे पर्यवेक्षी दलों के सदस्यों को बैंक के संचालन की बारीकियों से परिचित कराएं, व्यापक अवलोकन और संदर्भ प्रदान करके सीएफओ इन दलों को बैंक के आंतरिक वातावरण, चुनौतियों और रणनीतिक उद्देश्यों से पूरी तरह से अवगत कराने में मदद कर सकते हैं। यह न केवल अधिक प्रभावी लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है बल्कि बैंक के समग्र कार्यनिष्पादन और विनियामक अनुपालन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सहयोगी संबंध को भी बढ़ावा देता है।

सीएफओ के लिए लेखा परीक्षकों और बैंक पर्यवेक्षकों के साथ खुले और ईमानदार संप्रेषण माध्यम बनाए रखने की आवश्यकता इस सहयोग का अभिन्न अंग है। इन दलों से किसी भी जानकारी को छुपाने, रोक रखने या अधूरी जानकारी प्रदान करने की धारणा से बचना आवश्यक है। पारदर्शिता महत्वपूर्ण है; व्यापक और सटीक डेटा साझा करके, सीएफओ न केवल एक आसान लेखा परीक्षा और पर्यवेक्षण प्रक्रिया सुचारु करते हैं, बल्कि ईमानदारी और अनुपालन के लिए बैंक की प्रतिबद्धता भी मजबूत करते हैं। यह सहयोग विश्वास दृढ़ करता है, विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करता है, और अंततः संस्थान की वित्तीय स्थिरता और प्रतिष्ठा में योगदान देता है।

यह आंतरिक रूप से भी उतना ही सच है। सीएफओ को किसी भी दुस्साहस या विनियमों या लेखांकन मानकों की बुद्धिमान व्याख्या से बचते हुए वित्तीय रिपोर्टिंग की सत्यता की रक्षा करनी चाहिए। मैं, सीएफओ से आग्रह करूंगा कि वे विस्तृत जानकारी पर नजर रखें और एमडी एवं सीईओ तथा बाकी शीर्ष प्रबंधन के साथ स्पष्ट और पारदर्शी चर्चा करें। यदि किसी मामले में उच्च स्तर के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो आपको बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के अध्यक्ष तक संपर्क के माध्यम को भी खुला रखना चाहिए।

सीएफओ को लेखा परीक्षा या पर्यवेक्षी समीक्षा के दौरान पायी गई किसी भी कमी के गहन मूल कारण का विश्लेषण करना चाहिए। अल्पकालिक सुधारों को लागू करने के बजाय, इन मुद्दों के अंतर्निहित कारणों को समझकर उनका समाधान करना, अनुपालन के दीर्घकालिक रूप से बने रहने को सुनिश्चित करता है। यह दृष्टिकोण समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकने में मदद करता है और समग्र अनुशासन को मजबूत तथा बैंक के वातावरण को नियंत्रित करता है।

एक क्षेत्र जो पिछले कुछ वर्षों में अधिक प्रकाश में आया है वह है, आंतरिक खातों का नियंत्रण और प्रबंधन। हमने पाया कि कुछ बैंकों में बिना किसी वैध कारण के लाखों खाते हैं। इनमें से कुछ खातों का उपयोग कतिपय धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ऋण खातों के एवर ग्रीनिंग के रूप में भी किया गया था। आंतरिक खाते दुरुपयोग की संभावना के कारण उच्च जोखिम की प्रकृति के होते

हैं। इसलिए मैं सीएफओ से अनुरोध करता हूँ कि उन्हें पूरी तरह से तर्कसंगत बनाया जाए, उन्हें आवश्यक न्यूनतम स्तर तक लाया जाए और समय-समय पर मिलान व एसीबी को उचित रिपोर्टिंग के माध्यम से उन पर अधिक नियंत्रण रखा जाए।

मैं सीएफओ से प्रौद्योगिकी और डेटा एनालिटिक्स में निवेश करने का भी आग्रह करूंगा जो उन्हें अधिक सटीक और वास्तविक समय की वित्तीय जानकारी प्रदान करने में सशक्त बनाएगा। यह न केवल रणनीतिक निर्णय लेने में सहायता करता है बल्कि लेखा परीक्षा या पर्यवेक्षी समीक्षा के दौरान पहचाने गए किसी भी मुद्दे पर शीघ्र प्रतिक्रिया देने की क्षमता भी बढ़ाता है।

### लेखापरीक्षकों की भूमिका और अपेक्षाएँ

सटीक वित्तीय विवरण तैयार करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंकों के प्रबंधन की है, जिसमें सीएफओ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालाँकि, लेखा परीक्षकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नियामकों, निवेशकों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जमाकर्ताओं सहित सभी हितधारक, लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान किए गए आश्वासन पर भरोसा करते हैं कि वित्तीय विवरण बैंक की स्थिति और कार्यनिष्पादन के बारे में वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण दर्शाते हैं, जो कि गलत बयानी से मुक्त है। बैंकिंग क्षेत्र में यह भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जहां विश्वास सर्वोपरि है।

सुरक्षा मॉडल की तीन पंक्तियों से आप सभी परिचित होंगे। सुरक्षा की पहली पंक्ति लाइन प्रबंधन है, इसके बाद अनुपालन और जोखिम प्रबंधन है और तीसरी पंक्ति आंतरिक लेखा परीक्षा है। ये सभी मिलकर बैंक में एक आंतरिक सुरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। लेकिन एक नियामक के लिए आश्वासन की चौथी और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति बैंक के संवैधानिक लेखा परीक्षक हैं।

लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लेखा परीक्षण प्रक्रिया की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इनमें पर्यवेक्षी दलों और लेखा परीक्षकों के बीच संरचित बैठक तंत्र, अपवाद रिपोर्टिंग की शुरुवात, लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए अन्य उपाय शामिल हैं। बेहतर समझ को बढ़ावा देने के लिए, आरबीआई ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड

अकाउंट्स ऑफ इंडिया के साथ लेखा परीक्षित स्थितियों और आरबीआई की टिप्पणियों के बीच अंतर के विशिष्ट कारणों को साझा करने की एक प्रणाली भी स्थापित की है। इसके अलावा, बैंक विशिष्ट व्यवसाय और वित्तीय जोखिमों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय व्याप्ति निर्धारित करने के लिए लेखा परीक्षकों को अधिक विवेकाधिकार दिया गया है।

इस संदर्भ में, मैं मजबूत वित्तीय निगरानी और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने में सहायता के लिए लेखा परीक्षकों की पांच प्रमुख अपेक्षाओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा।

सबसे पहले, लेखा परीक्षकों को संवैधानिक और विनियामक आवश्यकताओं के साथ किसी भी विचलन, कम-प्रावधानीकरण, या अननुपालन की संभावना को कम करने के लिए अपनी लेखा परीक्षा क्रियाविधियों में उचित कठोरता बरतनी चाहिए। इसके अलावा, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन यह लेखा परीक्षकों की भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेखा परीक्षक सावधानीपूर्वक मानकों को बनाए रखते हुए, नियामक दिशानिर्देशों के साथ-साथ लेखा परीक्षण मानकों का पालन करके, पर्यवेक्षकों के हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम कर सकते हैं।

दूसरे, जैसे-जैसे विनियामक ढाँचे और लेखांकन मानक तेजी से सिद्धांत-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहे हैं, लेखा परीक्षकों की निर्णायन भूमिका भी तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रही है। अपनी जिम्मेदारियों को निष्पादित करने में, लेखा परीक्षकों को विवेकपूर्ण निर्णय लेना चाहिए, स्वरूप से अधिक सार को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि लेखा परीक्षकों को केवल तकनीकी अनुपालन से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें विनियमों के उद्देश्य को समझना चाहिए और व्यवहार में इसके अनुप्रयोग का मूल्यांकन करना चाहिए ताकि लेखा परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता बढ़ाई जा सके।

तीसरा, लेखा परीक्षक बैंक प्रबंधन और आरबीआई दोनों को प्रारंभिक कमजोरियों की पहचान कराने और उसकी तुरंत रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, अपवाद रिपोर्टिंग की एक प्रणाली लागू की गई है जिसमें चिंता का मुद्दा देखते ही आरबीआई को रिपोर्ट करना आवश्यक

है। परिचालन संबंधी अक्षमताओं, चलनिधि समस्याओं या उभरते अनियमित बाजार प्रवृत्तियों जैसे जोखिमों का शीघ्र पता लगाने से सक्रिय प्रबंधन रणनीतियों और शमन उपायों को सक्षम बनाया जा सकता है। यह न केवल बैंक के हितों की रक्षा करता है बल्कि प्रणालीगत लचीलेपन को भी मजबूत करता है और समग्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ाता है।

चौथा, लेखा परीक्षकों को विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आवश्यक प्रशिक्षण, कौशल और अनुभव से लैस सक्षम कर्मचारियों को तैनात करना चाहिए। आज के डिजिटल युग में, जहां साइबर खतरे तेजी से जटिल होते जा रहे हैं, आईटी जोखिमों का प्रभावी ढंग से आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए विशेष विशेषज्ञतावाले लेखा परीक्षक की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करते हुए कि लेखा परीक्षा दल उभरती प्रौद्योगिकियों और सुरक्षा प्रोटोकॉल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, लेखा परीक्षक संवेदनशील वित्तीय डेटा की सुरक्षा और मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए, लेखा परीक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हितों का कोई ऐसा टकराव न हो, जिससे उनके लेखा परीक्षण की निष्पक्षता और स्वतंत्रता से समझौता हो। विनियामकों, निवेशकों और जनता सहित हितधारकों के बीच विश्वाससहता बढ़ाने में पारदर्शिता और निष्पक्षता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेखा परीक्षकों को अपनी विश्वसनीयता और लेखा परीक्षा परिणामों की सत्यता बनाए रखने के लिए पेशेवर नैतिकता और दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए।

## निष्कर्ष

अंत में, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि आज बैंकिंग क्षेत्र उन सभी वित्तीय मापदंडों के मामले में, एक दशक के उच्चतम स्तर पर है, जिनकी हम निगरानी करते हैं और यह क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है लेकिन यह सुनिश्चित करना हमारी साझा जिम्मेदारी है कि यह वर्षों तक बना रहे। इसलिए, आज का सम्मेलन हमारे वित्तीय संस्थानों की ईमानदारी और स्थिरता की सुरक्षा में

लेखा परीक्षकों, सीएफओ और वित्तीय क्षेत्र के नियामकों के बीच अपरिहार्य साझेदारी को रेखांकित करता है। साथ मिलकर, हमें हितधारकों के बीच विश्वास को बढ़ावा देने और हमारी बैंकिंग प्रणाली की निरंतर समुत्थानशीलता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता, परिश्रम और व्यावसायिकता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना चाहिए।

आज के सम्मेलन के विषय को ध्यान में रखते हुए, हम सभी - लेखा परीक्षकों, सीएफओ और पर्यवेक्षकों को सहयोग

और संप्रेषण को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए ताकि हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ सकें जहां हमारा बैंकिंग क्षेत्र न केवल अपेक्षाओं को पूरा करता है बल्कि अपेक्षाओं से बढ़कर अनुशासन और ईमानदारी में उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करता है।

इसके साथ ही, मैं आज के सम्मेलन में आपकी सहभागिता के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। हम आगे पूरे दिन के लिए निर्धारित परस्पर संवादात्मक सत्रों में आपके विचार सुनने के लिए उत्सुक हैं।

# भविष्य के निर्माण हेतु कमियों को दूर करना: समावेशी विकास में एसएलबीसी की खास भूमिका\*

स्वामीनाथन जे.

श्री वी.जी. शेखर, प्राचार्य, सीएबी, एसएलबीसी के संयोजक, आरबीआई के मेरे सहयोगी, देवियो और सज्जनों! आप सभी को नमस्कार।

मुझे आज आप सभी को और हमारे सभी एसएलबीसी के संयोजकों को संबोधित करते हुए बहुत खुशी हो रही है। मैं समझता हूँ कि इन दो दिनों में आप सभी ने बहुत ही उद्देश्यपरक चर्चा की है, जिसमें आपने विभिन्न कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों पर विमर्श किया है, जिन्हें हम समावेशी और सतत संवृद्धि के लिए ऋण वितरण को मजबूत करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपनाने की योजना बना रहे हैं। एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में अपनी पिछली भूमिका में तेलंगाना में एसएलबीसी के संयोजक होने के नाते, मैं एसएलबीसी मंच के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव लाने से मिलने वाली अपार व्यक्तिगत संतुष्टि का प्रत्यक्ष प्रमाण दे सकता हूँ। वास्तव में, पिछले कुछ वर्षों में एसएलबीसी हितधारकों के बीच तालमेल परिवर्तन के महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। देश भर में एसएलबीसी के तत्वावधान में किए गए प्रयासों के माध्यम से, दूरदराज, बिना बैंक वाले और कम बैंक वाले क्षेत्रों को कवर करने और हाशिए पर रहने वाले वर्गों तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को बढ़ाने में सराहनीय प्रगति हुई है। हाल ही में, एसएलबीसी ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, जिससे आबादी के सभी वर्गों के लिए आसानी और दक्षता के साथ वित्तीय लेनदेन की सुविधा देकर औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इन प्रयासों ने निस्संदेह विभिन्न आयामों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम किया है।

इस सम्मेलन का विषय 'समावेशी और सतत संवृद्धि के लिए ऋण वितरण को मजबूत करना' बहुत प्रासंगिक है। समावेशी संवृद्धि कई कारणों से महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्रों और जनसंख्या समूहों

\* भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, श्री स्वामीनाथन जे. का भाषण - 19 जून 2024 - कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), पुणे में आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के संयोजकों के सम्मेलन में।

में आर्थिक अवसरों, रोजगार और आय के स्तर में असमानताओं को कम करने में मदद करता है। जब संवृद्धि से सभी को लाभ होता है, तो यह व्यापक कल्याण की ओर ले जाता है। अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देती है और साझा प्रगति की भावना पैदा करती है। यदि हम 2047 तक एक विकसित देश बनने की अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो समावेशी संवृद्धि वास्तव में एक अनिवार्य शर्त है।

इस संदर्भ में, मैं समाधान प्रदान करने में एसएलबीसी की अग्रणी भूमिका को स्वीकार करना और उसकी सराहना करना चाहूँगा। अब मैं कुछ प्राथमिकताओं का उल्लेख करना चाहूँगा जिन्हें हम समावेशी संवृद्धि के संबंध में अपना सकते हैं।

**विस्तार में प्रगति हुई, लेकिन उपयोग और गुणवत्ता पर काम किया जाना बाकी है।**

आरबीआई द्वारा विकसित वित्तीय समावेशन सूचकांक वित्तीय सेवाओं की पहुंच, उपयोग और गुणवत्ता के तीन आयामों में वित्तीय समावेशन में हासिल की गई प्रगति को मापता है। अंतर्निहित मापदंडों की समीक्षा से पता चलता है कि पहुंच बनाने में कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन उपयोग और गुणवत्ता में सुधार के लिए अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है।

मैं इसे एक उदाहरण से समझाता हूँ। एसएलबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, पाँच किलोमीटर के दायरे में हर गाँव (या पहाड़ी इलाकों में 500 घरों की बस्ती) को बैंकिंग की सुविधा प्रदान की गई है, कुछ को छोड़कर। उदा यह भी दर्शाता है कि यह बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट (बीसी) मॉडल है जिसका उपयोग इस तरह की पहुँच बढ़ाने में किया गया है। हालाँकि, रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि बीसी बड़े पैमाने पर केवल सीमित सेवाएँ प्रदान करते हैं जैसे कि कैश-इन/कैश-आउट सेवाएँ और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को अभी भी बैंकिंग सेवाओं के पूरे समूह तक पहुँच नहीं हो सकती है, जो आमतौर पर बैंक शाखाओं में उपलब्ध होती है।

**ऋण अनुपलब्धता**

भारत में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि के बावजूद, ऋण अनुपलब्धता को कम करने की अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है जो आर्थिक समावेश और संवृद्धि को बढ़ावा दे सकती है। जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण वितरण में वास्तव में सुधार हुआ है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की ऋण

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है<sup>1</sup>। इसी तरह, लगभग आधे स्वयं सहायता समूह (SHG) अभी भी ऋण से जुड़े नहीं हैं, जबकि छोटे और सीमांत किसानों का एक बड़ा हिस्सा अभी भी बैंक ऋण के तहत कवर नहीं हुआ है<sup>2</sup>। इन ऋण अनुपलब्धताओं को दूर करने के लिए एक बहुआयामी प्रयास की आवश्यकता है जिसमें एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है।

### एस.एल.बी.सी. से अपेक्षाएं

मैं चार प्रमुख क्षेत्रों को शामिल करना चाहूंगा जहां मेरा मानना है कि एसएलबीसी अत्यधिक सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।

#### (i) सरकारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) के साथ प्रभावी समन्वय

सबसे पहले, सरकारी एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय अनिवार्य है। एक सामूहिक मंच होने के नाते, एसएलबीसी को बैंकिंग पहलों को विकास कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए विभिन्न सरकारी निकायों के साथ मजबूत भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करना शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंकिंग सेवाएँ वंचित क्षेत्रों तक पहुँचें, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाया जा सके और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों का समाधान किया जा सके।

अग्रणी बैंक योजना के दायरे और इसके अंतर्गत बैंकों की भूमिका के बारे में जिला प्रशासन को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अग्रणी बैंक योजना के कार्यान्वयन से जुड़े बैंकों और सरकारी एजेंसियों के परिचालन स्तर पर कर्मचारियों को नवीनतम घटनाक्रम और उभरते अवसरों के बारे में पता होना चाहिए। बेहतर समन्वय वित्तीय समावेशन पहलों के प्रभाव को बढ़ा सकता है और यह सुनिश्चित कर सकता है कि लाभ जमीनी स्तर तक पहुँचें और जिससे समावेशी संवृद्धि के व्यापक लक्ष्य को समर्थन मिले।

<sup>1</sup> सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर विशेषज्ञ समिति (अध्यक्ष: श्री यू.के. सिन्हा) द्वारा एमएसएमई क्षेत्र में कुल ऋण अंतर ₹20-25 ट्रिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

<sup>2</sup> कृषि ऋण की समीक्षा के लिए आंतरिक कार्य समूह की रिपोर्ट, 2019 के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों को अभी भी बैंक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाना है।

#### (ii) समुचित नियोजन

मेरा दूसरा बिंदु वार्षिक ऋण योजनाओं की तैयारी के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के बारे में है। यह महत्वपूर्ण है। एसएलबीसी को कुछ क्षेत्रों में देखी गई ऋण वृद्धि की कमी के मूल कारणों की पहचान करने के लिए विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधियों, स्थानीय ऋण आवश्यकताओं और ऋण पहुँच में बाधाओं को समझने के लिए डेटा एनालिटिक्स और फील्ड सर्वेक्षण का उपयोग करना शामिल है। विशिष्ट मुद्दों को इंगित करके, चाहे वे बुनियादी ढाँचे, उधारकर्ता जागरूकता या बैंकिंग प्रक्रियाओं से संबंधित हों, एसएलबीसी अधिक लक्षित और प्रभावी ऋण योजनाएँ विकसित कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल ऋण प्रवाह को बढ़ाएगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि यह उन क्षेत्रों तक पहुँचे जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे सतत आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।

नियमित निगरानी और मूल्यांकन इस नियोजन प्रक्रिया का अभिन्न अंग होना चाहिए। स्पष्ट मानक और प्रदर्शन संकेतक निर्धारित करके, एसएलबीसी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और अपनी रणनीतियों में आवश्यक समायोजन कर सकते हैं। यह पुनरावृत्त दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि ऋण योजनाएँ गतिशील रहें और बदलती आर्थिक स्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी रहें।

#### (iii) प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना

तीसरा, वित्तीय समावेशन और ऋण वितरण को बढ़ाने में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना एक बड़ा बदलाव हो सकता है। एसएलबीसी को बैंकिंग संचालन को सुव्यवस्थित करने और ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए फिनटेक समाधानों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। मोबाइल बैंकिंग, तकनीक से प्रेरित ग्राहक सहायता और डिजिटल ऋण प्रोसेसिंग जैसी तकनीकों ने कार्य-निपटान समय को काफी कम कर दिया है और पहुँच को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, उन्नत डेटा एनालिटिक्स को लागू करने से बेहतर जोखिम मूल्यांकन और क्रेडिट स्कोरिंग में मदद मिल सकती है, जिससे संसूचित ऋण निर्णय लेने में सुविधा होगी। तकनीकी नवोन्मेषों को अपनाने से बैंकिंग सेवाओं की दक्षता में सुधार होगा, दूरदराज और कम सेवा वाले क्षेत्रों तक उनकी पहुँच बढ़ेगी और वे सस्ती होंगी।

डिजिटल ऋण निपटान (प्रोसेसिंग) प्लेटफॉर्म ने ऋण वितरित करने के तरीके में क्रांति ला दी है। इन प्लेटफॉर्म ने ऋण आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया को स्वचालित कर दिया है, जिससे यह तेज़ और अधिक कुशल हो गया है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके, यह प्लेटफॉर्म आवेदकों की ऋण पात्रता का अधिक सटीक और निष्पक्ष मूल्यांकन कर सकते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ऋण उन लोगों तक पहुँचाया जाए जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है। यह कृषि-ऋण के साथ-साथ एमएसएमई दोनों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकता है, जिन्हें अक्सर समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

आरबीआई नवोन्मेष केंद्र द्वारा निर्बाध ऋण के लिए सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच इस दिशा में की गई पहलों में से एक है। इसमें एक ओपन आर्किटेक्चर, ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) और मानक हैं और यह प्लग एंड प्ले मॉडल में काम करता है जिससे सभी वित्तीय क्षेत्र के प्लेयर जुड़ सकते हैं। हाल ही में, नाबार्ड ने आरबीआई नवोन्मेष केंद्र के साथ मिलकर अपने ई-केसीसी ऋण उत्पत्ति प्रणाली को सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच (प्लेटफॉर्म) के साथ एकीकृत किया है, जिससे कृषि ऋणों के लिए कार्य-समाप्ति समय को हफ्तों से घटाकर मिनटों में किया जा सकता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे तकनीक इस क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। मैं एसएलबीसी को ऋण वितरण में सुधार के लिए अभिनव दृष्टिकोणों की तलाश करने के लिए और अधिक रास्ते तलाशने के लिए प्रोत्साहित करूंगा।

डिजिटल भुगतान परितंत्र के विस्तार और गहनता का कार्यक्रम एसएलबीसी के तत्वावधान में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। 31 मार्च 2024 तक 179 जिले 100 प्रतिशत डिजिटल रूप से सक्षम हैं। इस कार्यक्रम के तहत, पांच राज्यों, अर्थात् केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और तमिलनाडु ने अपने सभी जिलों को पूरी तरह से डिजिटल रूप से सक्षम बना दिया है। मुझे उम्मीद है कि अन्य राज्यों के एसएलबीसी भी जल्द ही अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी जिलों का 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण हासिल करने के लिए कमर कस लेंगे। जिन राज्यों में 100 प्रतिशत कवरेज हासिल हो गया है, वहां डिजिटल भुगतान मोड के उपयोग की निगरानी के साथ-साथ डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासों पर जोर देने की जरूरत है।

#### (iv) वित्तीय साक्षरता

यह मुझे मेरे चौथे और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ले आता है जो वित्तीय साक्षरता, विशेष रूप से डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर है। डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता के बावजूद, आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन सेवाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके के बारे में अनभिज्ञ रहता है। बुनियादी वित्तीय सेवाओं के अलावा, एसएलबीसी को वित्तीय शिक्षा कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देना चाहिए जो डिजिटल बैंकिंग के लाभों और उपयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। डिजिटल वित्तीय साक्षरता को बढ़ाकर, एसएलबीसी व्यक्तियों को अपने वित्त को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने, औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने और उनके लिए उपलब्ध बैंकिंग सेवाओं की पूरी शृंखला से लाभ उठाने के लिए सशक्त बना सकते हैं।

जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज हमारे पास वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) हैं जो देश के लगभग सभी ब्लॉकों को कवर करते हैं। यह जरूरी है कि ये केंद्र स्थानीय समुदायों और लक्षित क्षेत्रों तक अपनी पहुंच के माध्यम से ठोस बदलाव का माध्यम बनें, और जागरूकता और कार्रवाई के बीच की खाई को प्रभावी ढंग से पाटें। इसलिए, एसएलबीसी स्तर पर निगरानी केवल आयोजित किए गए शिविरों की संख्या पर ही नहीं बल्कि ठोस परिणामों पर भी केंद्रित होनी चाहिए, जैसे कि- इन वित्तीय जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप औपचारिक वित्तीय प्रणालियों से जुड़े लाभार्थियों की संख्या।

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी प्रसार के लिए स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप लक्षित जागरूकता अभियानों पर जोर दिया जाना चाहिए। इसमें विभिन्न समुदायों के अनूठे वित्तीय व्यवहारों, जरूरतों और चुनौतियों को समझना और उनके साथ तालमेल बिठाने वाली शैक्षिक सामग्री तैयार करना शामिल है। उदाहरण के लिए, कृषि क्षेत्रों में, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम कृषि वित्तपोषण, फसल बीमा और कुशल बाजार संपर्कों के लिए डिजिटल उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्थानीय संदर्भ में फिट होने के लिए दृष्टिकोण को अनुकूलित करके, एसएलबीसी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वित्तीय साक्षरता पहल न केवल जानकारीपूर्ण हो बल्कि आकर्षक और कार्रवाई योग्य भी हो।

## आरबीआई@100 के लक्ष्य

इस वर्ष हम भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, साथ ही हमने आरबीआई की शताब्दी के लिए अपने आकांक्षात्मक लक्ष्यों की रूपरेखा भी तैयार की है, जिसे आरबीआई @100 कहा जाता है। इन लक्ष्यों में वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना और ऋण उपलब्धता का विस्तार करना शामिल है।

वित्तीय समावेशन को व्यापक बनाना केवल बैंक खातों की संख्या बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला तक पहुँच प्राप्त हो। इसमें बचत, ऋण, बीमा और निवेश उत्पाद शामिल हैं जो उनकी आर्थिक लाभ को बढ़ा सकते हैं। ऋण उपलब्धता का विस्तार करना, विशेष रूप से एमएसएमई, कृषि और हाशिए पर पड़े समुदायों जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में, समावेशी विकास और सतत संवृद्धि को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि ये आरबीआई@100 उद्देश्यों के हिस्से के रूप में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में ये राष्ट्रीय हित से जुड़े वित्तीय परितंत्र में प्रत्येक हितधारक के लक्ष्य हैं। इन आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग समुदाय को शामिल करते हुए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस यात्रा में एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे विभिन्न हितधारकों को जोड़ने और यह सुनिश्चित करने की मुख्य कड़ी हैं कि वित्तीय प्रणाली जमीनी स्तर पर निर्बाध रूप से कार्य करें। इसलिए मैं इस मिशन में आपके सक्रिय सहयोग और सहभागिता का अनुरोध करता हूँ।

## निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में, समावेशी और सतत संवृद्धि को बढ़ावा देने में एसएलबीसी की भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी दोनों है। वित्तीय साक्षरता बढ़ाने से लेकर प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने तक, एसएलबीसी वित्तीय सेवाओं और वंचित आबादी के बीच की खाई को पाटने में महत्वपूर्ण प्रगति कर सकते हैं। सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय पर ध्यान केंद्रित करके, ऋण नियोजन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाकर और डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर जोर देकर, एसएलबीसी एक अधिक समावेशी वित्तीय परितंत्र बना सकते हैं।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रयासों के ठोस परिणामों की निगरानी और मापन आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय समावेशन का लाभ हमारे देश के हर कोने तक पहुंचे। स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पहल करके और वित्तीय साक्षरता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, हम व्यक्तियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सशक्त बना सकते हैं, जिससे समावेशी और सतत आर्थिक संवृद्धि के व्यापक लक्ष्य में योगदान दिया जा सके जो कि विकसित भारत 2047 के लिए आवश्यक है।

मैं सभी हितधारकों से आग्रह करता हूँ कि वे सहयोगात्मक रूप से काम करना जारी रखें, प्रत्येक क्षेत्र की ताकत का लाभ उठाएँ और वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने के लिए प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करें। साथ मिलकर, यह सुनिश्चित करते हुए कि आर्थिक संवृद्धि और विकास की हमारी यात्रा में कोई भी पीछे न छूटे, हम सभी के लिए एक सुदृढ़ और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

धन्यवाद।

## आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

महामारी के बाद के साक्ष्य के साथ भारत के लिए ब्याज की आधार दर के अनुमान को अद्यतन करना

भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाना

भारत में सकल मूल्य संवर्धन में श्रम संरचना के योगदान का आकलन – मानव पूंजी दृष्टिकोण

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन



## अर्थव्यवस्था की स्थिति\*

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में वैश्विक आर्थिक गतिविधि मजबूत होती दिख रही है और वस्तुओं और सेवाओं में वैश्विक व्यापार गति पकड़ रहा है। मौद्रिक नीति में वैविध्य वैश्विक आर्थिक विकास के लिए दिशा तय कर रहा है। भारत में, 2024-25 की दूसरी तिमाही अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ शुरू हुई है। कृषि के प्रति दृष्टिकोण में सुधार और ग्रामीण खर्च में सुधार, मांग स्थितियों के उद्भव में उज्ज्वल बिंदु साबित हुए हैं। जून 2024 में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में लगातार तीन महीनों की नरमी के बाद बढ़ोतरी हुई, क्योंकि सब्जियों की कीमतों में व्यापक उछाल ने चल रही समग्र अवरस्फीति को रोक दिया।

### परिचय

'अर्थव्यवस्था की स्थिति' के जून 2024 संस्करण के बाद से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में मजबूत होती दिख रही है। विश्व बैंक के अनुसार, आर्थिक विचलन सूचकांक (ईएसआई) बताते हैं कि गतिविधि, ईई के लिए वृद्धिशील और ईएमई में अधिक मार्जिन के कारण, प्रत्याशा से अधिक है। भावना संकेतक यह भी संकेत देते हैं कि आर्थिक स्थितियाँ और अपेक्षाएँ स्थिर बनी हुई हैं। क्रय प्रबंधकों के सूचकांकों के संदर्भ में, ईएमई ने लगातार दूसरे वर्ष ईई से बेहतर प्रदर्शन करना जारी रखा, जिसमें मजबूत संवृद्धि अपेक्षाओं के कारण भारत बाकी देशों से आगे रहा। श्रम बाजार ऐतिहासिक रूप से तंग स्थितियों से मुक्त हो रहे हैं और वेतन वृद्धि धीमी हो रही है। दूसरी ओर, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) ने अपनी नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ ऋण स्तर निवेशकों में अत्यधिक विकर्षण और वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रति जोखिम पैदा करता है। अपने हालिया बजट पूर्वानुमान

\* यह आलेख डॉ. माइकल देवव्रत पात्र, जी. वी. नथनएल, शाहबाज खान, अर्पिता अग्रवाल, कुणाल प्रियदर्शी, हर्षिता केशन, यामिनी जांब, हरेंद्र बेहरा, के. एम. नीलिमा, अरिजीत शिवहरे, मधुरेश कुमार, ऋषभ कुमार, सत्येन्द्र कुमार, खुशी सिन्हा, आयुषी खंडेलवाल, देबप्रिया साहा, शिवम, शैलजा भाटिया, युवराज कश्यप, अरात्रिका कुंडू, शाओनी नंदी, कमल गुप्ता, अवनीश कुमार, सुप्रियो मंडल, अमित पवार, हिमानी शेखर, आशीष थॉमस जॉर्ज, समीर रंजन बेहरा, विनीत कुमार श्रीवास्तव और रेखा मिश्र द्वारा तैयार किया गया है।

में, यूएस कांग्रेसनल बजट ऑफिस (सीबीओ) को उम्मीद है कि 2024 में अमेरिकी राजकोषीय घाटा जीडीपी के 7 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा, जो कुछ मंदियों की अवधि के स्तर से अधिक है। सीबीओ का कहना है कि घाटा कई वर्षों तक ऊंचा बना रहेगा और 2034 में जनता द्वारा रखा गया अमेरिकी ऋण जीडीपी के 122 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संघीय ऋण के एक अज्ञात समुद्र में जा रही है। इस संदर्भ में, जहाँ बीआईएस ने केंद्रीय बैंकों को उपयुक्त समय से पहले नीतिगत दरों को कम न करने की सलाह दी है, वहीं स्थिति के गंभीर होने से पहले राजकोषीय रूप से कार्य करने के महत्व को रेखांकित किया है।

अमेरिका में सकारात्मक व्यापार गतिशीलता और एशिया में मजबूत निर्यात प्रदर्शन से प्रेरित होकर वैश्विक व्यापार वस्तुओं और सेवाओं में गति पकड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) के तात्कालिक अनुमान ने पहली तिमाही के सापेक्ष दूसरी तिमाही में अधिक सकारात्मक गति पकड़ी, जिससे 2024 की पहली छमाही में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया। यदि ये रुझान शेष वर्ष में भी बने रहते हैं, तो वैश्विक व्यापार 2024 में लगभग 32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है, हालाँकि यह 2022 के रिकॉर्ड स्तर (32.2 अमेरिकी डॉलर) को पार करने की संभावना नहीं है। जहाँ वैश्विक माल व्यापार में गति फिर से आ रही है, वहीं सेवा व्यापार में जोरदार उछाल खत्म होता दिख रहा है। व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ रही हैं, मात्रा की तुलना में मूल्यों में अधिक वृद्धि हो रही है। इस उछाल के बावजूद, व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमत में वार्षिक परिवर्तन नकारात्मक रहने की उम्मीद है। लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती शिपिंग लागत और सख्त औद्योगिक नीतियाँ - नकारात्मक जोखिम बनी हुई हैं।

विशेष रूप से, औद्योगिक नीतियाँ पारंपरिक और उच्च वृद्धि दोनों क्षेत्रों को लक्षित कर रही हैं, जिससे व्यापार पुनर्वितरण और आपूर्ति संकेन्द्रण में वृद्धि हो रही है। व्यापारिक प्रकाशनों में 'औद्योगिक नीति' के उल्लेख की बारंबारता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, दुनिया भर में औद्योगिक नीति हस्तक्षेपों में भी भारी वृद्धि हुई है। ये नीतिगत

हस्तक्षेप, भू-राजनीतिक पुनर्व्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण की आवश्यकता और कंप्यूटिंग शक्ति और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित हैं। आई और ईएमई में, रणनीतिक उद्योगों को बढ़ाने, घरेलू फर्मों को कम कार्बन उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं के रूप में स्थान देने और आपूर्ति शृंखलाओं और महत्वपूर्ण उत्पादों के लचीलेपन को मजबूत करने के उद्देश्य से समर्थन उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। व्यापार के दृष्टिकोण से, ये नीतिगत हस्तक्षेप व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए और ऊर्ध्वाधर समेकन की सुविधा देते हुए आयात प्रतिस्थापन की तलाश करते हैं। परिणामस्वरूप, व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव तब पड़ा है, जबकि कई लक्षित क्षेत्रों में वैश्विक मांग बढ़ रही है, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहना। इस दृष्टिकोण के बुरे प्रभाव - आपूर्ति संकेन्द्रण में वृद्धि, प्रमुख खंडों में वैश्विक व्यापार विखंडन और संरक्षणवाद, व्यापार लागत और अनिश्चितता में वृद्धि - हैं।

ये घटनाक्रम विलय और अधिग्रहण (एम एंड ए) में गिरावट के कारण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह के लिए एक निराशावादी माहौल की ओर ले जा रहे हैं, हालांकि विकासशील देशों में ग्रीनफील्ड निवेश की संभावना उज्ज्वल है, जैसा कि खंड IV में अधिक विस्तार से चर्चा की गई है। 2024 में एफडीआई के लिए वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, जिसमें बहुराष्ट्रीय उद्यम विदेशी विस्तार के लिए सतर्क दृष्टिकोण अपना रहे हैं। फिर भी, इन निगमों का लाभ स्तर उच्च बना हुआ है, जिसे पुनर्निवेशित आय द्वारा बढ़ावा मिला है। इसके अलावा, वित्तीय स्थितियाँ आसान हो रही हैं, विशेष रूप से आई में, जिससे परियोजना वित्त की संभावनाएँ उज्ज्वल हो रही हैं। हालांकि, 'अंकटाड' के अनुसार, ग्रीनफील्ड परियोजना घोषणाओं के शुरुआती संकेतक अभी भी कमजोर हैं।

मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब पहुंच रही है, लेकिन मुद्रास्फीति में कमी की गति कुछ धीमी हुई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, 2 प्रतिशत के स्तर पर कुछ दूरी से ही सही, नज़र आ रहे हैं। अधिकांश उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में, मुद्रास्फीति लक्ष्य पर या उससे थोड़ा ऊपर स्थिर है। मौद्रिक नीतियां वैश्विक आर्थिक संवृद्धि के लिए दिशा तय कर रहा है। यूएस फेड से संबंधित विचारों का एकीकरण अब 'अगर' नहीं बल्कि 'कब' है। फेड फंड फ्यूचर्स

चालू कैलेंडर वर्ष में 60 आधार अंकों की दर कटौती की उम्मीद कर रहे हैं, जिसमें पहली कार्रवाई एफओएमसी की सितंबर 2024 की बैठक के लिए पूरी तरह से मूल्यांकित है। यह मई 2024 में कोर व्यक्तिगत उपभोग व्यय मुद्रास्फीति के 2021 के बाद से सबसे कम वृद्धि पर पहुंचने और श्रम बाजार में सुस्ती के संकेतों के मद्देनजर हुआ है। आगे की पुष्टि में, जून 2024 के लिए उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति हेडलाइन और कोर दोनों के लिए अपेक्षाओं से कम रही, जैसा कि खंड II में विस्तार से बताया गया है। आखिरी मील स्पष्ट रूप से आखिरी चरण तक छोटा होता जा रहा है।<sup>1</sup> यू.एस. प्रतिफल और व्यापक डॉलर सूचकांक में तेज गिरावट आई, जिससे दुनिया के बाकी हिस्सों को काफी राहत मिली। पाठ्यपुस्तकों के पूर्वानुमान के अनुसार, ढीली राजकोषीय और सख्त मौद्रिक नीतियों के मिश्रण ने अब तक यू.एस. डॉलर को मजबूत बनाया है। मुद्रास्फीति में कमी के साथ-साथ नीतिगत दरों में कमी की जा रही है, इसलिए नीतिगत मिश्रण संभवतः डॉलर के लिए कम सकारात्मक होगा। यू.के. में, मुद्रास्फीति अंततः मई में 2 प्रतिशत के लक्ष्य पर पहुंच गई, लेकिन इसके परिणामस्वरूप दरों में कटौती नहीं हुई। बैंक ऑफ कनाडा, जिसने दरों में कटौती की शुरुआत की, अपनी जुलाई की बैठक में विराम ले सकता है। ईएमई में, पहले कदम उठाने वाले देश सहजता-गति को कम कर रहे हैं, जबकि इंडोनेशिया जैसे अन्य देश और दक्षिण कोरिया और सिंगापुर भी दरों को स्थिर रख रहे हैं, और कुछ ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया है, जैसे कि रूस। वर्ष की शुरुआत के सापेक्ष, बाजार सहभागियों को अब देशों के बीच अधिक नीतिगत-दर वैविध्य की उम्मीद है।

वित्तीय स्थितियाँ मोटे तौर पर अपरिवर्तित बनी हुई हैं। उल्लेखनीय अस्थिरता के बीच ईएमई मुद्राएँ आम तौर पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर रहीं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नीति दर अंतर में कमी, प्रतिफल संवाहक व्यापारों (कैरी ट्रेडों) के समापन के साथ मिलकर ईएमई में समूह के रूप में पोर्टफोलियो प्रवाह में कुछ मंदी आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, दुनिया के 30 प्रतिशत केंद्रीय बैंक 2023 में जोड़े गए 1037 टन के अलावा 2024 में अपने स्वर्ण भंडार में वृद्धि करेंगे, जो अमेरिकी डॉलर में विश्वास में कमी और रणनीतिक स्तर

<sup>1</sup> रॉयटर्स, 11 जुलाई 2024।

पर स्वर्ण होल्डिंग्स के अधिक पसंदीदा पुनर्संतुलन की कोशिश को दर्शाता है। ब्लॉकबस्टर पहली छमाही के बाद जब ईएमई सरकारों और कॉरपोरेट्स ने हार्ड करेंसी<sup>2</sup> में मूल्यवर्गित रिकॉर्ड 321 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बॉन्ड बेचे, परंतु 2024 की दूसरी छमाही में वित्तीय राजधानियों में बढ़ते राजनीतिक जोखिम के मद्देनजर जारीकर्ताओं में घबराहट के संकेत मिल रहे हैं। वर्ष के लिए फंडिंग जरूरतों के संदर्भ में, यह अनुमान लगाया गया है कि 80 प्रतिशत पहले ही कवर किया जा चुका है। ईएमई द्वारा जारी किए गए अमेरिकी डॉलर मूल्यवर्ग के बॉन्ड ने धारकों को अब तक 2.2 प्रतिशत का लाभ दिया है, क्योंकि अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण प्रतिफल में वृद्धि हुई है। यह प्रदर्शन मोटे तौर पर अमेरिकी उच्च-प्रतिफल वाले कॉरपोरेट बॉन्ड के अनुरूप है।

28 जून को जारी संयुक्त राष्ट्र की सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2024 ने बताया है कि 2030 तक एसडीजी हासिल करने के लिए सिर्फ छह वर्ष शेष हैं, प्रगति असमान, धीमी और ज्यादातर अबूझ बनी हुई है। केवल 17 प्रतिशत एसडीजी पटरी पर हैं, जबकि लगभग आधे न्यूनतम या मध्यम प्रगति दिखाते हैं और एक तिहाई से अधिक रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में “शांति को सुरक्षित करने, जलवायु परिवर्तन का सामना करने और अंतरराष्ट्रीय वित्त को बढ़ावा देने में हमारी विफलता विकास को कमजोर कर रही है।”<sup>3</sup> अगले छह वर्षों में लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की आवश्यकता होगी, विशेष रूप से विकासशील देशों में जहां निवेश अंतर लगभग 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष होने का अनुमान है। 2024 का रिपोर्ट कार्ड कुछ आशाहीन नहीं है। उदाहरण के लिए, मोबाइल ब्रॉडबैंड दुनिया के 95 प्रतिशत लोगों तक पहुंच चुका है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग में प्रगति हुई है, जो वर्तमान में दुनिया की बिजली आपूर्ति का 30 प्रतिशत है।

21 जून, 2024 को, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति का अनुभव हुआ जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचा। यह एक मौन क्रांति की शुरुआत थी। यह कोई सांसारिक संसाधन

उपयोग नहीं करती, लगभग कुछ भी खर्च नहीं करती लेकिन वह प्रदान करती है जो दुनिया को चलाती है - बिजली। सौर क्रांति, सिलिकॉन से बने छोटे फोटोवोल्टिक सेल द्वारा संचालित होती है जिसमें 60-72 सेल एक विद्युत परिपथ के साथ होते हैं, जो दुनिया भर में 10,000 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र को कवर करते हैं, 2023 में दुनिया की लगभग 6 प्रतिशत बिजली का उत्पादन करते हैं। 2024 में, लगभग 70 बिलियन सेल का उत्पादन किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप 520-655 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की स्थापित क्षमता होगी जो हर तीन वर्ष में दोगुनी हो रही है और हर दशक में दस गुना बढ़ रही है। सौर पैनल वर्तमान में बिजली उत्पादन में निवेश की सबसे बड़ी श्रेणी है, जिसका अनुमान अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) द्वारा 2024 में US \$ 500 बिलियन लगाया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा सोसाइटी के अनुसार, सौर ऊर्जा 2026 में दुनिया के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, 2027 तक सभी पवन टर्बाइनों, 2028 तक सभी बांधों, 2030 तक सभी गैस-चालित बिजली संयंत्रों और 2032 तक सभी कोयला- चालित संयंत्रों से अधिक बिजली पैदा करेगी। न केवल बिजली, सौर ऊर्जा 2040 के दशक तक मानव जाति के प्राथमिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत बनने के लिए तैयार है।<sup>4</sup> आगे का रास्ता नवोन्मेषों से होकर गुजरेगा जिसमें लंबी दूरी के कनेक्शन, भंडारण (विशेष रूप से बैटरी) और सौर ऊर्जा की समग्र मांग को बढ़ाने के नए रास्ते शामिल होंगे। इसके अलावा, सौर ऊर्जा के विकास में चीन, अमेरिका और उत्तरी यूरोप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब उत्पादन के लिए वैश्विक दक्षिण की ओर रुख करने का समय आ गया है, जहाँ बहुत सारी खाली जमीन है, धूप तक बेहतर पहुँच है और बहुत अधिक अपूरित मांग है। निकट भविष्य में, सौर ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा, जिसका उपयोग बैटरी की तुलना में अधिक समय तक ऊर्जा संगृहीत करने के तरीके के रूप में किया जा सकता है, लेकिन जिस बाधा को दूर करना होगा, वह है इलेक्ट्रोलिसिस की निषेधात्मक लागत, जिसके तहत हाइड्रोजन को पानी से अलग किया जाता है।

इस संदर्भ में भारत का महत्व बढ़ जाता है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सौर डेवलपर्स का घर, जिसकी क्षमता पिछले 25 वर्षों में जर्मनी द्वारा स्थापित की गई क्षमता से दो-तिहाई से अधिक है,

<sup>2</sup> ब्लूमबर्ग, 1 जुलाई 2024।

<sup>3</sup> 28 जून 2024 को न्यूयॉर्क में धारणीय विकास लक्ष्य (एसडीजी) रिपोर्ट 2024 के शुभारंभ पर प्रेस को संयुक्त राष्ट्र महासचिव की टिप्पणी।

<sup>4</sup> इकोनॉमिस्ट, 22 जून 2024।

भारत 84 गीगा वाट (जीडब्ल्यू) में वैश्विक सौर क्षमता का 5.2 प्रतिशत हिस्सा रखता है, जो पांचवां सबसे अधिक है। 2017-18 से 2023-24 के दौरान कोयला बिजली में 1.6 प्रतिशत की तुलना में सौर स्थापित क्षमता 24.1 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़ी है। सौर ऊर्जा उत्पादन कुल बिजली का क्रमशः 6.7 प्रतिशत और नवीकरणीय बिजली का 28.4 प्रतिशत है। सौर मॉड्यूल की लागत में गिरावट सौर क्षमता वृद्धि में निरंतर वृद्धि में योगदान दे रही है - 2.54 रुपये प्रति यूनिट का सौर शुल्क नए कोयला बिजली संयंत्रों (5-6 रुपये प्रति यूनिट) की तुलना में कम है। आगे बढ़ते हुए, ग्रिड स्थिरता और चौबीसों घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा भंडारण में निवेश की आवश्यकता है, जिससे सौर ऊर्जा की कुल लागत बढ़ जाती है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, भारत में बैटरी स्टोरेज के साथ संयुक्त सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल के लिए बिजली की स्तरीय लागत (एलसीओई) पहले से ही नए कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है और इसमें और कमी आने की उम्मीद है। भारत का लक्ष्य राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, जिसमें लगभग 125 जीडब्ल्यू की संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वृद्धि शामिल है। घरों में छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। निर्माण के विभिन्न चरणों में अतिरिक्त 85 जीडब्ल्यू क्षमता अगले कुछ वर्षों में भारत की सौर क्षमता को बढ़ाएगी। हाल के वर्षों में, विशेष रूप से अमेरिका को सौर सेल और मॉड्यूल का निर्यात बढ़ा है। वर्तमान में, भारत सौर सेल और मॉड्यूल का शुद्ध आयातक है क्योंकि इसे अभी भी सौर सेल के उत्पादन में पर्याप्त क्षमता हासिल करनी है। एक बार जब उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) और अन्य विनिर्माण परियोजनाओं से उत्पादन क्षमता चालू हो जाएगी, तो भारत सौर मॉड्यूल का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन जाएगा, जो पूरे मूल्य शृंखला में पर्याप्त विनिर्माण क्षमताओं का दावा करेगा।

2024-25 की दूसरी तिमाही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेतों के साथ शुरू हुई है। जून में रुकी हुई और कम बारिश देने के बाद, दक्षिण-पश्चिम मानसून ने जुलाई में गति पकड़ी है,

पिछले 12 वर्षों में सातवीं बार पूरे देश को समय से पहले कवर किया है, जिसका विवरण भाग III में विस्तार से दिया गया है। जुलाई के पहले पखवाड़े में, अतिरिक्त वर्षा ने जून की कमी को मिटा दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) को उम्मीद है कि मानसून और भी जोरदार होगा और पूरे महीने में लंबी अवधि के औसत से अधिक होगा। 04 जुलाई, 2024 तक प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण 39 सप्ताह में पहली बार बढ़ा है। खरीफ की बुवाई ने गति पकड़ी है, जो एक वर्ष पहले के रकबे से अधिक है (विवरण के लिए भाग III देखें)। इस दर से, इस वर्ष सामान्य बोंग क्षेत्र को पार कर जाने की संभावना है। खेतों पर तीव्र गतिविधि ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम की मांग को कम कर दिया है। अल नीनो वर्तमान में तटस्थ है और समुद्र की सतह का तापमान ठंडा हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो ने संकेत दिया है कि ला नीना, जिसके कारण भारत और पूरे एशिया में भारी वर्षा होती है, संभवतः अगस्त के बाद उभरेगी, जिससे मानसून के विस्तार और लंबे समय तक वर्षा होने का संकेत मिलता है।

कृषि के लिए परिदृश्य में सुधार 2024-25 में मांग की स्थितियों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बनने जा रहा है - ग्रामीण क्षेत्रों में व्यय में सुधार जो शहरी क्षेत्रों से आगे निकल रहा है। परिणामस्वरूप, ग्रामीण-शहरी विभाजन कम हो रहा है, जैसा कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के हालिया मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) सर्वेक्षण में बताया गया है। यह बढ़ते राजकोषीय हस्तांतरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा दर्शाई गई मजदूरी दर में वृद्धि और शहरी प्रवास के कारण ग्रामीण परिवारों को भेजे जाने वाले धन की बढ़ती मात्रा के कारण है। ये कुछ ऐसे तात्कालिक कारक हैं जो ग्रामीण परिवारों की प्रभावी व्यय शक्ति को बढ़ा रहे हैं। सर्वेक्षण में सामने आए उपभोग पैटर्न से पता चलता है कि ग्रामीण भारत में 46.4 प्रतिशत व्यय भोजन पर होता है, जबकि शहरी परिवारों के लिए यह 39.2 प्रतिशत था। ग्रामीण खाद्य बास्केट में, अनाज की हिस्सेदारी कम हो गई है और पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, दूध, मांस और अंडे की हिस्सेदारी बढ़ गई है। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीण एम.पी.सी.ई. में परिवहन, चिकित्सा व्यय और

उपभोक्ता सेवाओं का हिस्सा अनाज से अधिक है। इन विकासों ने आशा जगाई है कि ग्रामीण भारत अपने शहरी समकक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है और अभिसरण की परिकल्पना की जा सकती है। एक चिंताजनक विशेषता ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए वर्तमान और स्थिर कीमतों पर एम.पी.सी.ई. में वृद्धि के बीच का अंतर है, जो पिछले कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति के बोझ को दर्शाता है।

फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स (एफएमसीजी) सेगमेंट की कंपनियों को बेहतर नतीजे मिल रहे हैं और आय में सुधार से स्टॉक वैल्यूएशन में बढ़ोतरी हो रही है। यह मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे कमी आने के साथ बिक्री की मात्रा में सुधार को दर्शाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में कमी आने के कारण उम्मीदें कम हैं, हालांकि न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को कृषि आय में वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। अधिकांश एफएमसीजी कंपनियों को लागत बचत पहलों और विज्ञापन और प्रचार खर्चों के समर्थन से उच्च एकल अंकों में राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। पर्सनल केयर और होम केयर सेगमेंट में, उत्प्रेरक प्रीमियम पेशकश है जो परिचालन मार्जिन का विस्तार कर रही है। इस वर्ष भीषण गर्मी की स्थिति ने बोटलबंद शीतल पेय जैसे गर्मियों के लिए विशेष एफएमसीजी की बिक्री को भी एक नए उच्च स्तर पर पहुंचा दिया है। फैब्रिक सॉफ़नर और वॉशिंग लिक्विड ने पैठ के उच्च स्तर हासिल कर लिए हैं। घरेलू खपत पर नज़र रखने वाली निजी शोध फ़र्म 2024-25 की दूसरी छमाही में व्यापक ग्रामीण नेतृत्व वाली रिकवरी की उम्मीद कर रही हैं।<sup>5</sup>

विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आ रही है, नए ऑर्डर के कारण जून में क्रय प्रबंधकों का सूचकांक (पीएमआई) अपने दीर्घकालिक औसत से अधिक हो गया है। विनिर्माण विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए इसके हिस्से को सकल घरेलू उत्पाद के 20-25 प्रतिशत तक पहुंचने की आवश्यकता है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स और ऑटोमोबाइल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बढ़त मिलेगी। विनिर्माण के लिए संघीय रूप से समावेशी नीतियां, बुनियादी ढांचे और रसद पर ध्यान केंद्रित करना, व्यापार करने

में आसानी और लागत, नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले अनुसंधान और विकास और एक आक्रामक निर्यात अभिविन्यास भारतीय विनिर्माण को उस आकांक्षात्मक लक्ष्य की ओर ले जाएगा। एक उद्योग में, भारत के विनिर्माण पावरहाउस में बदलने के प्रयास पहले से ही फल दे रहे हैं - इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण। 2015-16 और 2023-24 के बीच उत्पादित इलेक्ट्रॉनिक्स का मूल्य \$37 बिलियन से बढ़कर \$115 बिलियन (जीडीपी का 3 प्रतिशत) हो गया। निकट-अवधि का उद्देश्य 2025-26 तक उत्पादन को तिगुना करना है। वर्तमान में, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वैश्विक कुल का 3 प्रतिशत है, और यह हिस्सा किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। 2023-24 में, भारत ने 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक सामान और 2024-25 के पहले दो महीनों में 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। फोन का उत्पादन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग का लगभग आधा हिस्सा बनाता है, जो इसे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनाता है। 2015-16 में, भारत ने अपने फोन का लगभग 4/5वां हिस्सा आयात किया था। अब यह बमुश्किल कोई आयात करता है। 2023-24 में, इसने 15.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मोबाइल फोन और अप्रैल 2024 में 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। Apple अपने सात में से लगभग एक iPhone भारत से खरीदता है, जो एक वर्ष पहले की तुलना में दोगुना है। सैमसंग - जो दक्षिण कोरियाई प्रतिद्वंद्वी है - के पास भारत में सबसे बड़ी फोन निर्माण सुविधा है।<sup>6</sup>

विनिर्माण क्षेत्र का विस्तार करना भारत के निर्यात में हिस्सेदारी को विश्व निर्यात के मौजूदा 2.4 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 5 प्रतिशत करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों को मिलाकर।<sup>7</sup> वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, 2023-24 में करीब 780 अरब अमेरिकी डॉलर के निर्यात और पहली तिमाही में 10.2 प्रतिशत की संचयी विस्तार दर के दम पर भारत 2024-25 में 800 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्यात हासिल करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। इसके लिए श्रम-गहन निर्यात को फिर से शुरू करना होगा जो

<sup>6</sup> द इकोनॉमिस्ट, 21 जून 2024।

<sup>7</sup> भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर, डॉ. माइकल देवब्रत पात्र द्वारा, 9 जुलाई 2024 को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बीच 'मिड-करियर ट्रेनिंग प्रोग्राम' में प्रस्तुत संबोधन।

<sup>5</sup> कांतार, एफएमसीजी पल्स, ति2 2024।

बीते वर्ष धीमा रहा था; एमएसएमई से निर्यात को बढ़ावा देना जो भारत के कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन में 38 प्रतिशत का योगदान देता है और 110 मिलियन लोगों को रोजगार देकर कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है; और सॉफ्टवेयर, आईटी और व्यापार से हटकर अन्य श्रेणियों में सेवा निर्यात में विविधता लाना, जो विश्व निर्यात का 64 प्रतिशत है लेकिन जिसमें भारत की वैश्विक बाजार में केवल 1.9 प्रतिशत हिस्सेदारी है। ई-कॉमर्स निर्यात को प्राथमिकता देकर उन्हें वर्तमान स्तर 4-5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2030 तक लगभग 250-300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने से पारंपरिक निर्यात को रोकने वाली बाधाओं और भू-राजनीतिक चुनौतियों को दूर किया जा सकेगा। भारत के माल व्यापार के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में बंदरगाह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। महाराष्ट्र के तट पर वधावन बंदरगाह सभी मौसम गहरे पानी के मेगा बंदरगाहों की स्थापना की दिशा में एक कदम है। इसमें नौ कंटेनर टर्मिनल, एक तटीय बर्थ सहित चार बहुउद्देशीय बर्थ, चार लिक्विड कार्गो बर्थ, रोल ऑन रोल ऑफ जहाजों के लिए एक बर्थ और एक तट रक्षक बर्थ होगा। कंटेनर जहाज वर्तमान में दुनिया के समुद्री व्यापार का 16 प्रतिशत संभालते हैं। इसके लिए कंटेनर हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 20 मिलियन टीईयू से बढ़ाना ज़रूरी है।

भारत की विकास संभावनाओं के बारे में बढ़ती आशा, मजबूत लाभ वृद्धि और भागीदारी नोटों के जारी होने सहित विभिन्न क्षेत्रों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों से खरीद समर्थन की वापसी ने जून और जुलाई में इक्विटी बाजारों को नए शिखर पर पहुंचा दिया। जुलाई में तेजी का नेतृत्व बैंकिंग और प्रौद्योगिकी शेयरों ने किया है। एमएससीआई सूचकांक के पुनर्संतुलन ने भारत की हिस्सेदारी 2020 में 8 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गई है, और सहकर्मी ईएमई के सापेक्ष मूल्यांकन अंतर बढ़ रहा है। छोटे और मध्यम-कैप शेयर आय से आगे चल रहे हैं और बड़े कैप साधियों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रबंधन के तहत समग्र संस्थागत इक्विटी परिसंपत्तियों में म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी जून 2024 के अंत में रिकॉर्ड पर पहुंच गई, यह दर्शाता है कि इक्विटी कीमतों में मौजूदा गति शायद बरकरार रह सकती है।

द्वितीयक बाजार के साथ-साथ प्राथमिक बाजार भी ऊर्जा से गुलजार है। 2024 की पहली छमाही 17 वर्षों में आईपीओ के लिए सबसे अच्छी पहली छमाही साबित हुई है, और सौदों का आकार बढ़ा होता जा रहा है (बॉक्स 1, खंड IV)। इससे पता चलता है कि कंपनियाँ अपनी बैलेंस शीट को मजबूत बनाने के लिए नई पूंजी जुटा रही हैं, ताकि नई क्षमता जोड़ने की तैयारी की जा सके। इसी तरह, स्टार्ट-अप फंडिंग का ज्वार बदल रहा है, इस वर्ष अब तक 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए गए हैं, जबकि स्टार्ट-अप आईपीओ की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। अक्षय ऊर्जा आईपीओ में तेजी आ रही है, क्योंकि निवेशक सौर ऊर्जा क्षेत्र में बढ़ते रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं। वेंचर कैपिटल सौदे रुकने के बाद बढ़ रहे हैं, आखिरकार वे बिना अनाबंटित पूंजी के रूप में आरक्षित नकद धन (ड्राई पाउडर) का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भारत के लिए 8-10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अब तक, द्वितीयक हिस्सेदारी बिक्री और बायआउट ने इस क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और देर से होने वाली गतिविधियाँ गति पकड़ रही हैं। रिकॉर्ड ऋण वितरण और ऋण आकार में वृद्धि के बावजूद फिनटेक फंडिंग में भारी गिरावट देखी गई है। बड़ी लागत वाले टेक-आउट सौदों में वृद्धि से आईटी सेवा कंपनियों के लिए माहौल बेहतर हो सकता है। बहुराष्ट्रीय निगम (एमएनसी) मूल्य अनलॉक करने और अपनी मूल कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद करने के लिए आईपीओ के माध्यम से भारत में सूचीबद्ध होने के विकल्प तलाश रहे हैं। यह घरेलू समकक्षों के सापेक्ष एमएनसी शेयरों के अपेक्षाकृत आकर्षक मूल्यांकन के अनुरूप है। कुछ एमएनसी शेयर बाजार के प्रदर्शन का लाभ उठाकर हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार में, व्यापार घाटे में वृद्धि और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती के बावजूद, मजबूत पूंजी प्रवाह के कारण जुलाई में रुपया मजबूत होने लगा है। मौद्रिक नीति के भावी पथ और अमेरिकी डॉलर (डीएक्सवाई) में उतार-चढ़ाव से संबंधित बाजार की अपेक्षाओं पर असर पड़ने के बावजूद, रुपया एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। तदनुसार, मुद्रा हेजिंग लागत पहले की तुलना में कम हो गई है। कथित तौर पर यूरो को लंबे समय तक रुपया कैरी ट्रेड के लिए मुद्रा के रूप में पसंद किया जा रहा है।

जेपी मॉर्गन इंडेक्स में भारतीय सॉवरेन बॉन्ड को शामिल किए जाने से पहले, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इन बॉन्ड में अपना स्वामित्व 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक बढ़ा दिया है। विदेशी बैंक सबसे बड़े निवेशक के रूप में उभरे हैं, जिनका निवेश इंडेक्स-योग्य बॉन्ड में निवल प्रवाह के मूल्य से अधिक है। दुनिया के कुछ सबसे बड़े सॉवरेन वेल्थ फंड ने भारत में अपने निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि की है। समावेशन के बाद, प्रवाह धीमा रहा है और प्रतिफल लगभग स्थिर रहा है, जो आने वाले महीनों में अस्थिर उछाल के बजाय स्थिर प्रवाह का संकेत है।

ऋण बाजार में, कम लागत वाली चालू और बचत जमाराशियों की हिस्सेदारी 2021-22 में लगभग 44 प्रतिशत से लगातार गिरावट के साथ 39-40 प्रतिशत की सीमा में काफी हद तक नीचे आ गई है। इससे आगे चलकर बैंकों के शुद्ध मार्जिन में कमी आने और जमा बही के पुनर्मूल्यन को बढ़ावा मिलने की संभावना है। वास्तव में, बैंकों को तिमाही समाप्ति से पहले जून में जमा प्रमाणपत्रों (सीडी) के माध्यम से धन जुटाने के लिए प्रेरित किया गया है, जैसा कि खंड IV में दर्शाया गया है। सीडी में निवेश के लिए फंड जुटाने में म्यूचुअल फंड मुख्य भूमिका निभाते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ने आकलन किया कि बैंकों और वित्तीय संस्थानों की बेहतर बैलेंस शीट और निरंतर ऋण विस्तार के साथ वित्तीय प्रणाली मजबूत और लचीली बनी हुई है। मार्च 2024 के अंत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का पूंजी से जोखिम-भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) और सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) अनुपात क्रमशः 16.8 प्रतिशत और 13.9 प्रतिशत रहा। एससीबी की सकल अनर्जक आस्ति (जीएनपीए) अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर 2.8 प्रतिशत और निवल अनर्जक आस्ति (एनएनपीए) अनुपात मार्च 2024 के अंत में 0.6 प्रतिशत पर आ गया। आस्ति पर प्रतिलाभ (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) क्रमशः 1.3 प्रतिशत और 13.8 प्रतिशत के दशक के उच्चतम स्तर के करीब हैं। क्रेडिट जोखिम के लिए समष्टि दबाव परीक्षणों से पता चलता है कि एससीबी न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में

सक्षम होंगे, मार्च 2025 में सिस्टम-स्तरीय सीआरएआर क्रमशः 16.1 प्रतिशत, 14.4 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत अनुमानित है, जो कि आधारभूत, मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत विनियामक न्यूनतम से काफी ऊपर है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) स्वस्थ बनी हुई हैं, जिनका सीआरएआर 26.6 प्रतिशत, जीएनपीए अनुपात 4.0 प्रतिशत और आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) क्रमशः मार्च 2024 के अंत में 3.3 प्रतिशत है। सिस्टम स्तर पर, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) का सीआरएआर मार्च 2024 में 17.5 प्रतिशत तक बढ़ गया। म्यूचुअल फंड और क्लियरिंग कॉरपोरेशन पर दबाव परीक्षण वित्तीय क्षेत्र के इन खंडों की सुदृढ़ता को प्रमाणित करते हैं। नेटवर्क विश्लेषण से पता चलता है कि वित्तीय संस्थानों के बीच कुल बकाया द्विपक्षीय जोखिम बढ़ रहे हैं, जिसमें एससीबी का सबसे बड़ा हिस्सा है।

हर उम्मीद की किरण के पीछे एक बादल भी होता है। जून 2024 के आंकड़ों से पता चलता है कि उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति लगातार तीन महीनों की नरमी के बाद बढ़ गई है क्योंकि सब्जियों की कीमतों में व्यापक तेजी ने समग्र अवस्फीति को रोक दिया है जो चल रही थी। इस विकास ने मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के कुछ सदस्यों द्वारा जून की बैठक से संबंधित अपने मिनटों में व्यक्त की गई दूरदर्शी चेतावनियों को पुष्ट किया: “लगातार उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के साथ, ... जल्दबाजी में की गई कोई भी कार्रवाई ... अच्छे से अधिक नुकसान पहुंचाएगी<sup>8</sup>; यह सुनिश्चित करने के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण उपयुक्त है कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति का उपभोग बास्केट में अन्य वस्तुओं की कीमतों पर कोई प्रभाव न पड़े<sup>9</sup>; खाद्य मूल्य झटकों की बार-बार घटना मुद्रास्फीति के लक्ष्य तक अंतिम रूप से उतरने में देरी कर रही है<sup>10</sup>; (खाद्य मूल्य झटकों की पुनरावृत्ति) मौद्रिक नीति सतर्कता को तीव्र करने की मांग करती है<sup>11</sup>” मुद्रास्फीति के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, जैसा कि अंतिम भाग में विस्तार से बताया गया है।

<sup>8</sup> श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर

<sup>9</sup> डॉ. शशांक भिड़े

<sup>10</sup> डॉ. राजीव रंजन

<sup>11</sup> डॉ. माइकल देवब्रत पात्र

इस पृष्ठभूमि में, इस आलेख का शेष भाग चार खंडों में संरचित है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। खंड III में घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों का सार प्रस्तुत किया गया है, जबकि अंतिम खंड में समापन टिप्पणियाँ दी गई हैं।

## II. वैश्विक परिदृश्य

श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार और मुद्रास्फीति में नरमी के संकेतों के बीच 2024 की दूसरी तिमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधि मध्यम गति से बढ़ी। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने 16 जुलाई 2024 को जारी अपने नवीनतम विश्व आर्थिक परिदृश्य (डब्ल्यूईओ) अपडेट में 2024 के लिए वैश्विक संवृद्धि पूर्वानुमान को 3.2 प्रतिशत (अप्रैल 2024 के अनुमान के समान) पर बनाए रखा और 2025 के लिए संवृद्धि पूर्वानुमान को 10 बीपीएस बढ़ाकर 3.3 प्रतिशत कर दिया (सारणी II.1)। हमारे मॉडल-आधारित नाउकास्ट, नवीनतम उच्च आवृत्ति संकेतकों के साथ संवर्धित, दूसरी तिमाही और 2024 की तीसरी तिमाही के दौरान गति बनाए रखने की ओर इशारा करते हैं (चार्ट II.1)।

### सारणी II.1: सकल घरेलू उत्पाद संवृद्धि पूर्वानुमान – चुनिंदा आई और ईएमई

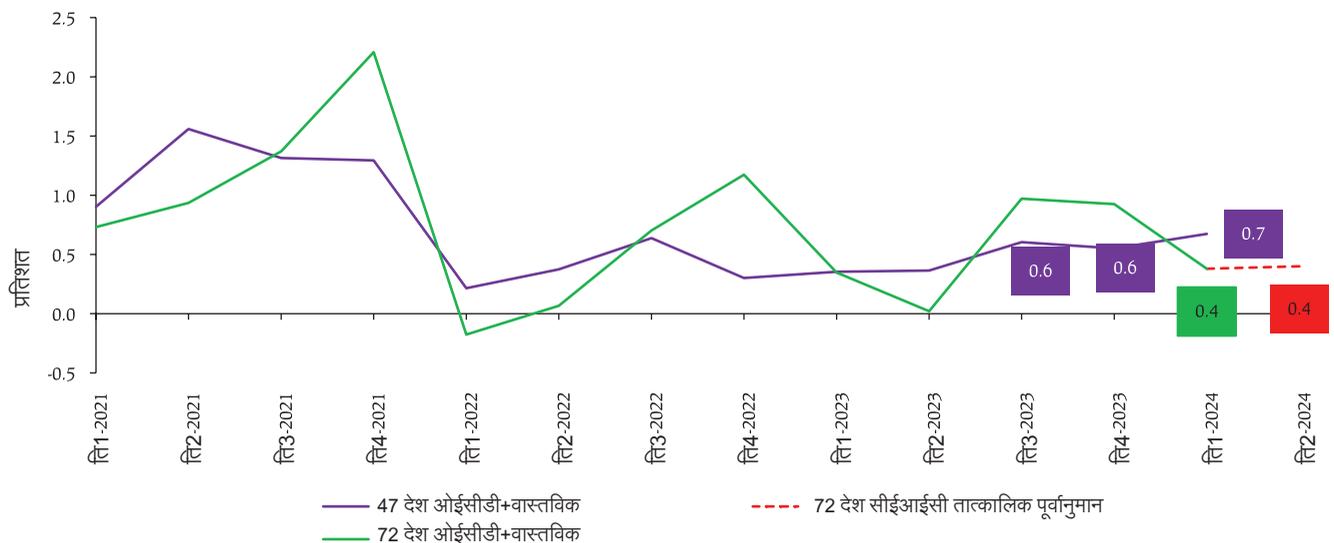
(प्रतिशत)

पूर्वानुमान माह क्षेत्र / देश	2024		2025	
	जुलाई 2024	अप्रैल 2024	जुलाई 2024	अप्रैल 2024
 विश्व	3.2	3.2	3.3	3.2
<b>उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (आई)</b>				
 यूएस	2.6	2.7	1.9	1.9
 यूके	0.7	0.5	1.5	1.5
 यूरो क्षेत्र	0.9	0.8	1.5	1.5
 जापान	0.7	0.9	1.0	1.0
<b>उदयमान बाजार अर्थव्यवस्थाएं (ईएमई)</b>				
 ब्राजील	2.1	2.2	2.4	2.1
 रूस	3.2	3.2	1.5	1.8
 भारत#	7.0	6.8	6.5	6.5
 चीन	5.0	4.6	4.5	4.1
 दक्षिण अफ्रीका	0.9	0.9	1.2	1.2

टिप्पणी: \* #: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष के आधार पर है।

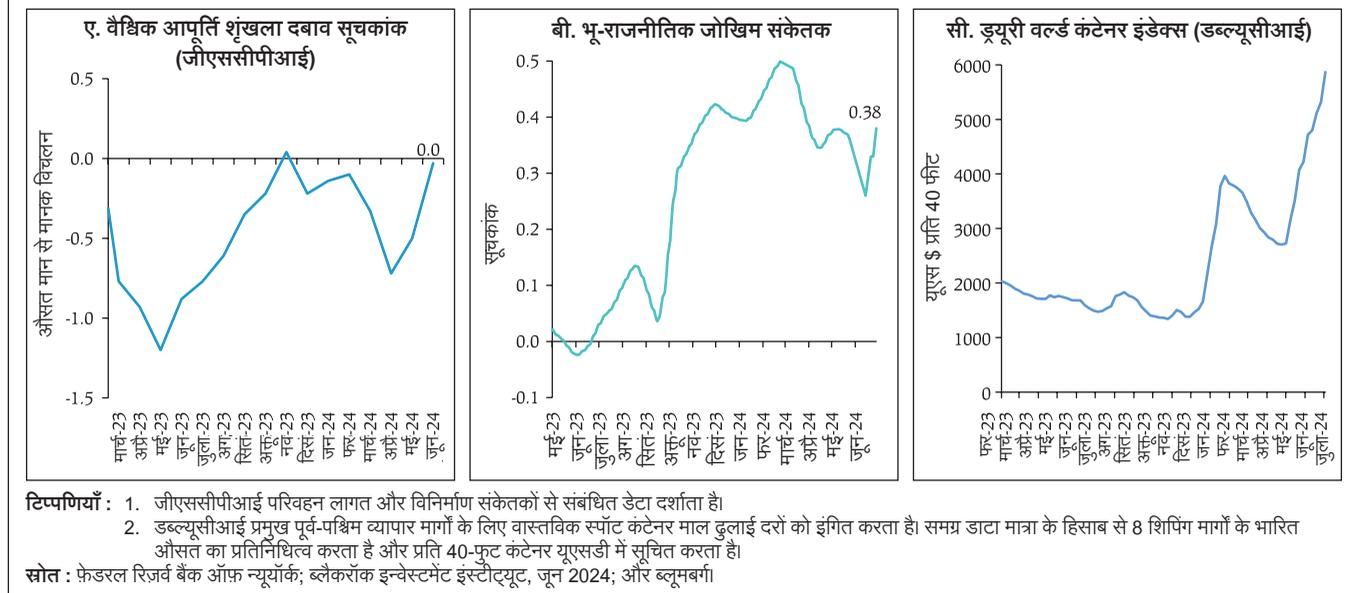
स्रोत: आईएमएफ।

### चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान (ति-द-ति)



स्रोत: सीईआईसी; ओईसीडी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

**चार्ट II.2: आपूर्ति शृंखला दबाव और भू-राजनीतिक जोखिमों में प्रवृत्तियां**

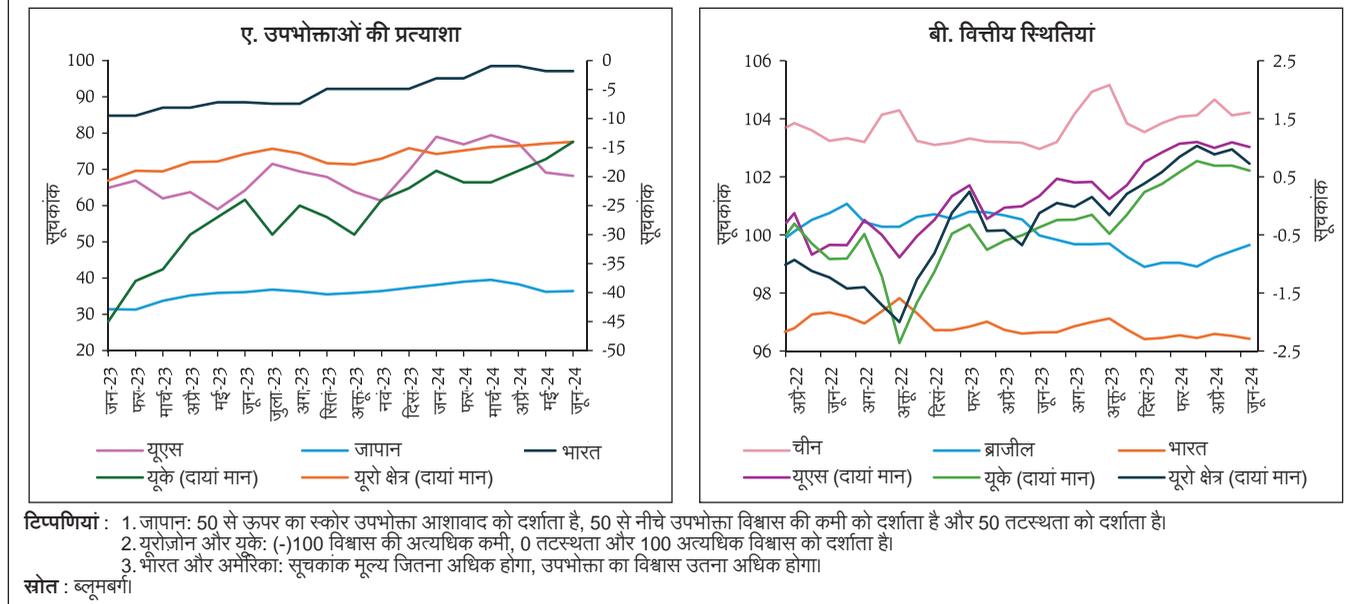


वैश्विक आपूर्ति शृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) ने जून 2024 में वृद्धि दर्ज की, जो इसे अपने ऐतिहासिक औसत (चार्ट II.2ए) के करीब ले गया। भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक, जिसमें जून 2024 की पहली छमाही में मामूली गिरावट आई थी, उसके बाद मध्य पूर्व में शत्रुता के बढ़ने से प्रेरित होकर वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट II.2बी)। लाल सागर (चार्ट II.2सी) में

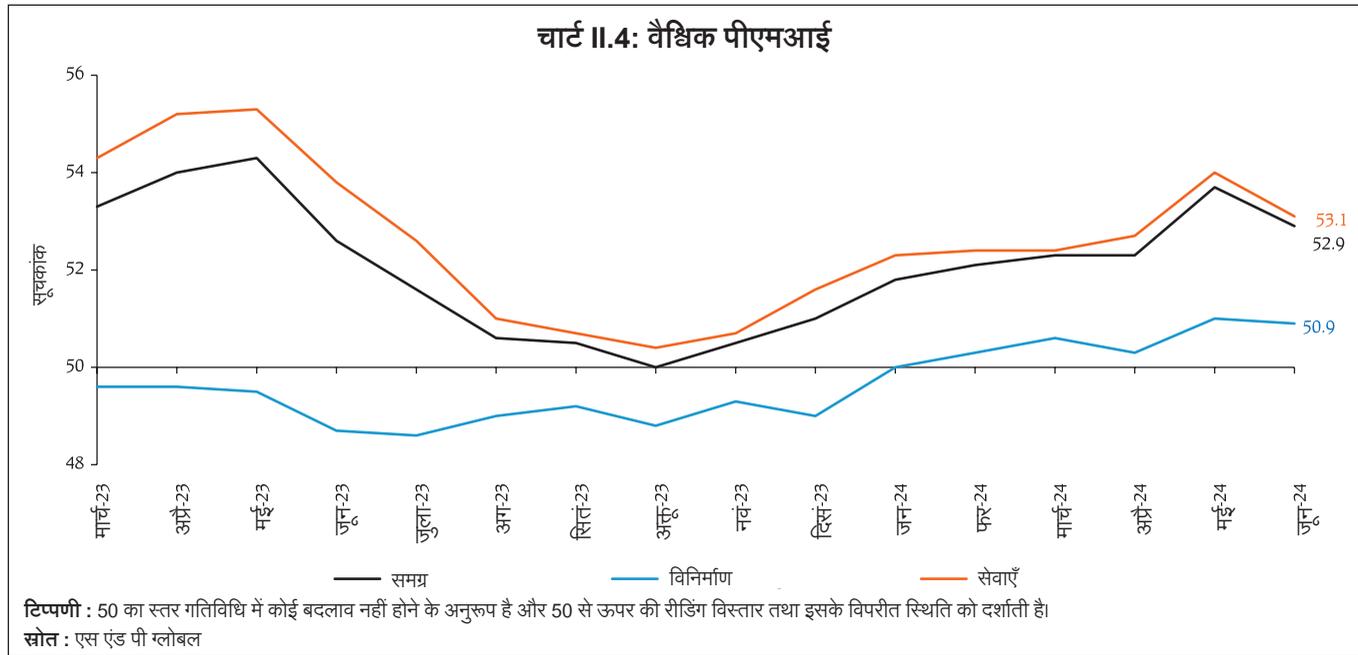
व्यवधानों के कारण यात्रा पारगमन समय बढ़ा रहने के कारण शिपिंग लागत में वृद्धि जारी रही।<sup>12</sup>

जून 2024 में अमेरिका में उपभोक्ता भावनाएँ लगातार तीसरे महीने गिरकर नवंबर 2023 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई (चार्ट II.3ए)। यूरो क्षेत्र में भी भावनाएँ इस उम्मीद पर सतर्क रहीं कि रोजगार में और गिरावट आने

**चार्ट II.3: उपभोक्ता प्रत्याशा और वित्तीय स्थितियां**



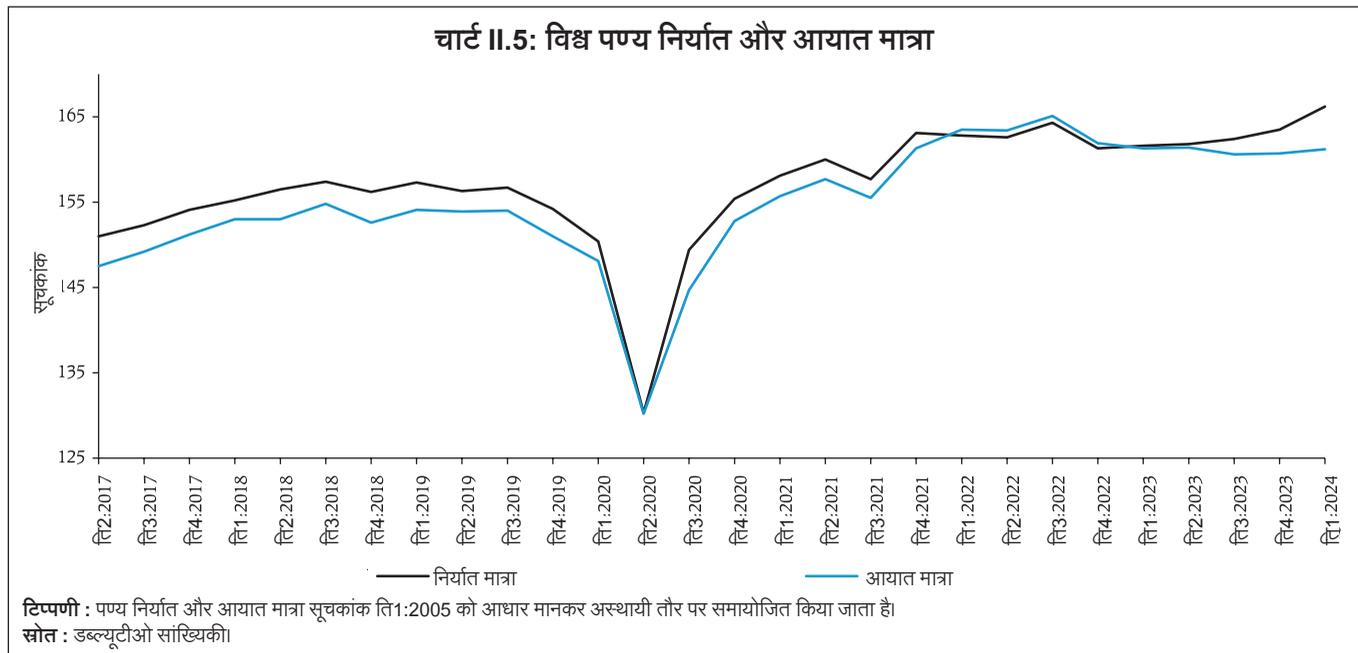
<sup>12</sup> कंटेनर उपकरण पूर्वानुमान रिपोर्ट | <https://www.drewry.co.uk/maritime-research-opinion-browser/maritime-research-opinions/global-container-equipment-fleet-growth-picks-up-pace>.

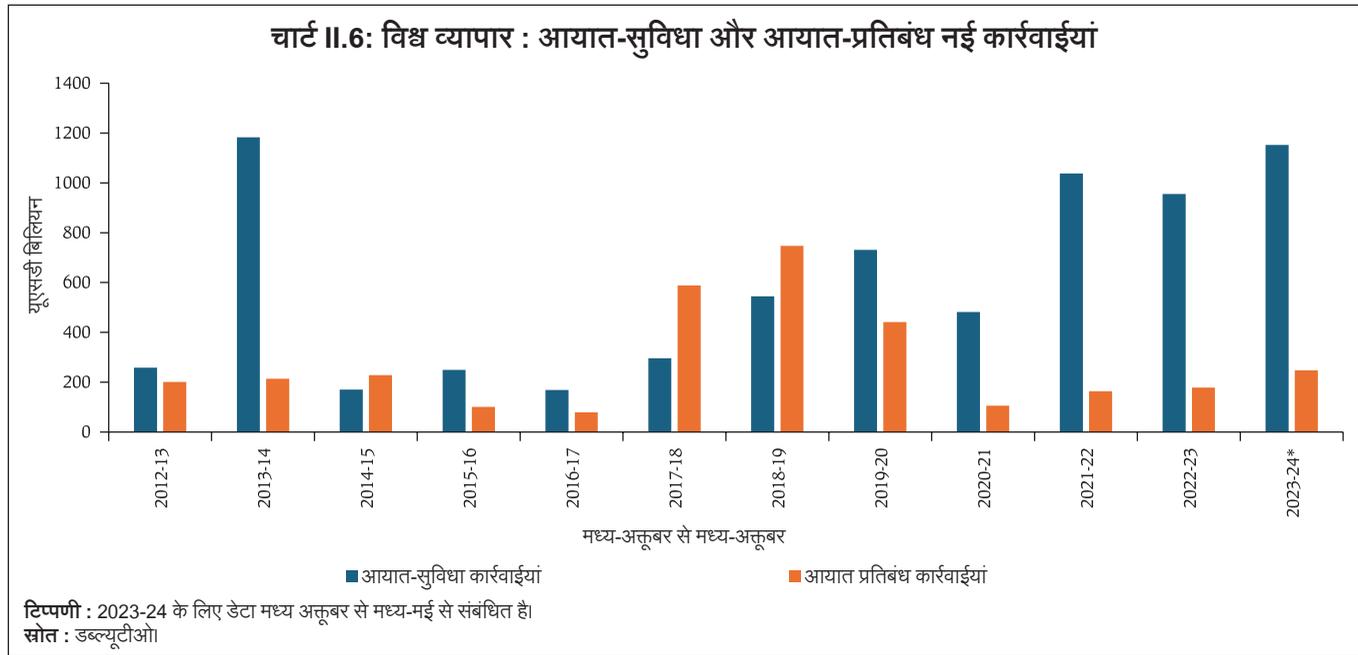


की संभावना है। एई में वित्तीय स्थितियाँ थोड़ी कम हुईं, जबकि ब्राज़ील और चीन जैसी उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं में जोखिम की आशंका के कारण कुछ सख्ती हुई (चार्ट II.3बी)।

वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने लगातार आठवें महीने विस्तार दर्ज किया, हालांकि मई में 53.7 से जून में क्रमिक मॉडरेशन के साथ 52.9 रहा। विनिर्माण

उत्पादन और सेवा क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधि (चार्ट II.4) दोनों के लिए विस्तार की दरें महीने-दर-महीने कम हुई हैं। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई मई के ढाई वर्ष के उच्च स्तर से जून में नरम होकर 50.9 पर आ गया, जबकि सेवा पीएमआई मई में 54.0 से जून में धीमी होकर 53.1 पर आ गया। क्रमिक मॉडरेशन के बावजूद, विकास व्यापक हो रहा है, पीएमआई



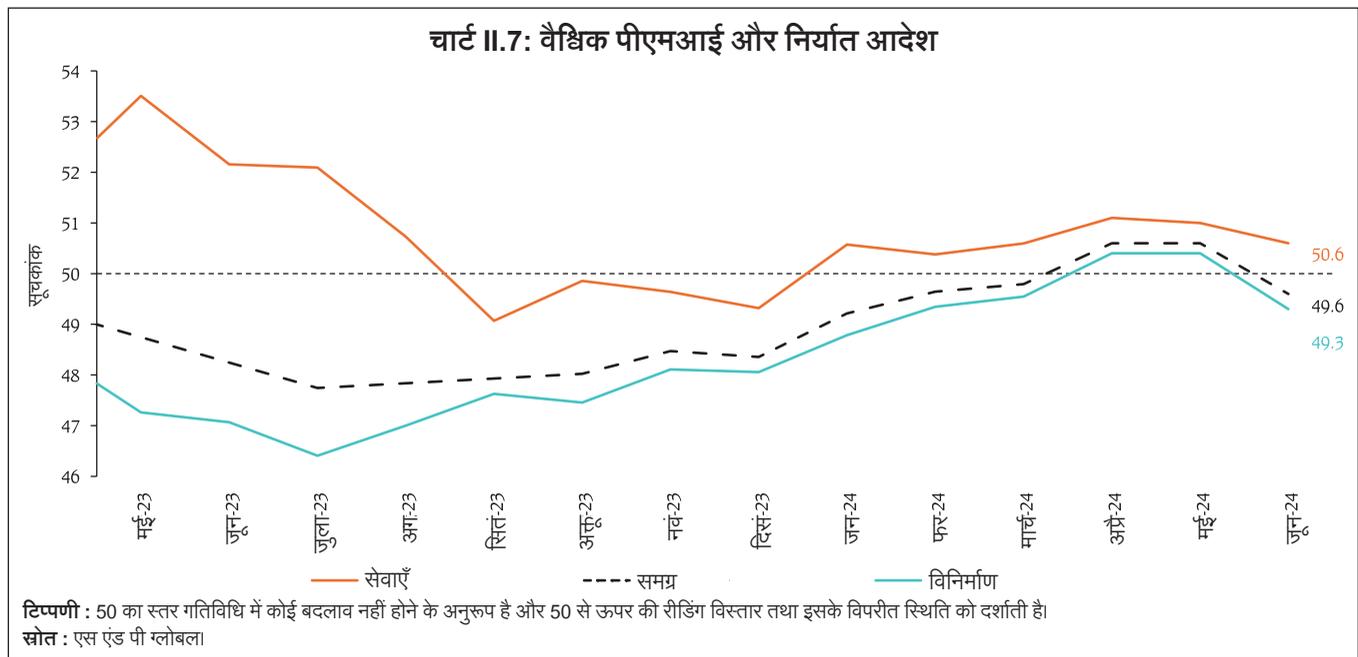


द्वारा कवर किए गए सभी 25 उप-क्षेत्रों में जुलाई 2021 के बाद पहली बार जून 2024 में विस्तार (जैसा कि 50 से ऊपर के सूचकांक मूल्य में स्पष्ट है) दर्ज किया गया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नवीनतम व्यापार निगरानी अपडेट<sup>13</sup> के अनुसार, 2023 में अपेक्षा से अधिक

गिरावट के बाद 2024-25 के दौरान विश्व व्यापार में धीरे-धीरे वृद्धि होने की उम्मीद है। ति1:2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विश्व माल निर्यात मात्रा में 2.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट II.5)।

यद्यपि विश्व माल आयात मात्रा में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर मामूली संकुचन दर्ज किया गया, लेकिन यह क्रमिक रूप से बढ़ा।



<sup>13</sup> ट्रेड मॉनिटरिंग अपडेट, विश्व व्यापार संगठन, 08 जुलाई 2024।

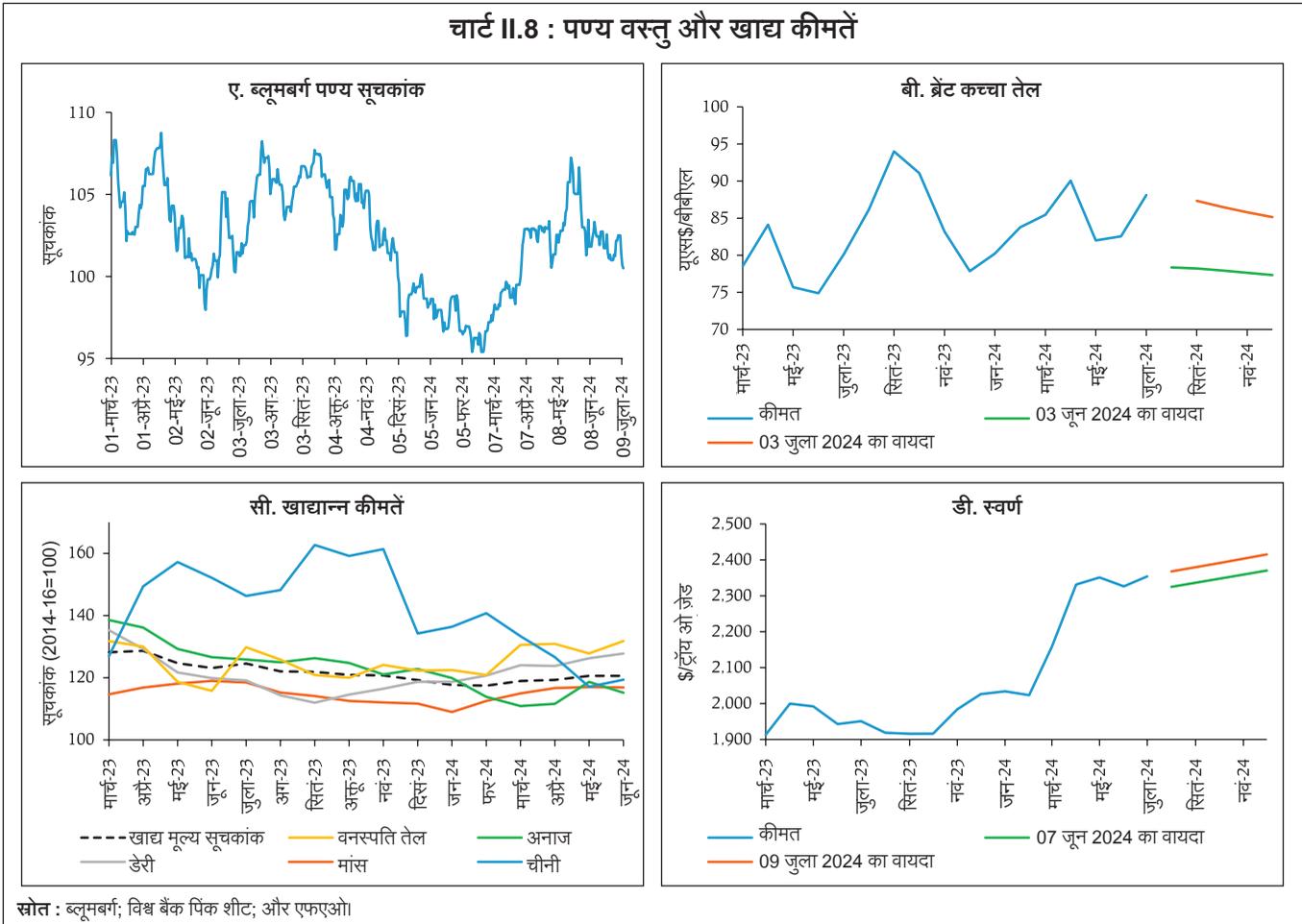
पिछले वर्ष आयात को सुविधाजनक बनाने वाले व्यापार उपायों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो आयात प्रतिबंधक उपायों में वृद्धि से अधिक है। 2024 के दौरान अब तक इस बदलाव के बने रहने से, यह वैश्विक व्यापार सुधार को और अधिक सहायता प्रदान कर सकता है (चार्ट 11.6)।

हालांकि, निर्यात ऑर्डर के लिए समग्र पीएमआई जून में कम हुआ, जबकि पिछले दो महीनों में यह विस्तार क्षेत्र में रहा। विनिर्माण और सेवा निर्यात ऑर्डर दोनों में नरमी देखी गई (चार्ट 11.7)।

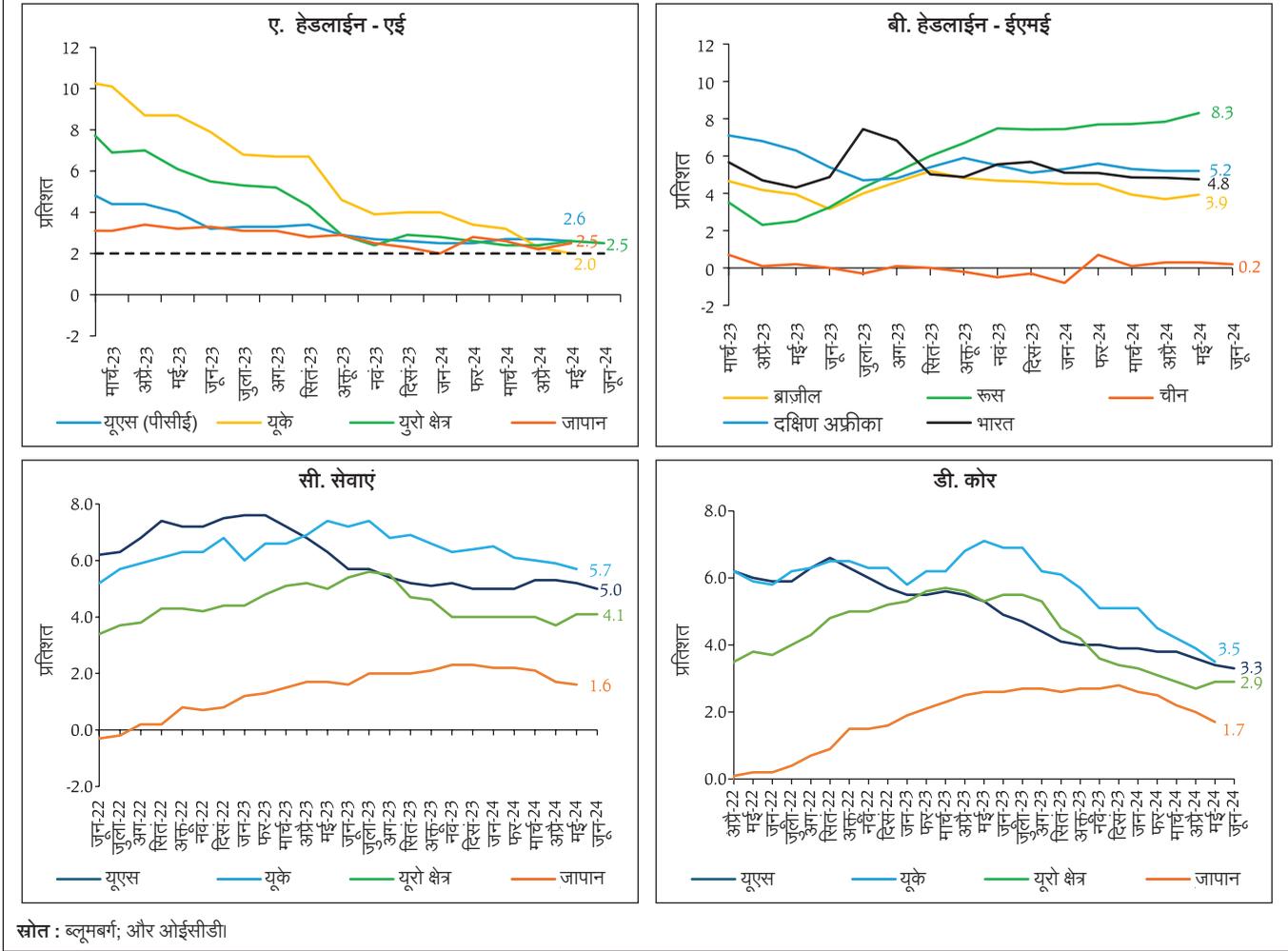
वैश्विक कमोडिटी की कीमतें अस्थिर बनी हुई हैं। कम कृषि कमोडिटी की कीमतें और औद्योगिक धातु की कीमतें आंशिक रूप से उच्च ऊर्जा कीमतों से ऑफसेट हुईं, जिसके परिणामस्वरूप ब्लूमबर्ग कमोडिटी इंडेक्स जून में 1.9 प्रतिशत

(माह-दर-माह) गिर गया (चार्ट 11.8ए)। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो जून के अंत में 85 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल को पार कर गई, इसका कारण भू-राजनीतिक जोखिम बढ़ना और साथ ही अमेरिकी कच्चे तेल के भंडार में उम्मीद से अधिक गिरावट थी (चार्ट 11.8बी)। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) का खाद्य मूल्य सूचकांक जून 2024 में स्थिर (माह-दर-माह) रहा क्योंकि वनस्पति तेलों (3.1 प्रतिशत) और चीनी (1.9 प्रतिशत) की कीमतों में वृद्धि अनाज की कीमत में कमी (-3.0 प्रतिशत) से ऑफसेट हुई। जून (माह-दर-माह) में स्वर्ण कीमतों में 1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मजबूत अमेरिकी डॉलर और कमजोर मौसमी मांग को दर्शाता है (चार्ट 11.8डी)।

चार्ट 11.8 : पण्य वस्तु और खाद्य कीमतें



चार्ट II.9 : मुद्रास्फीति - आई और ईएमई

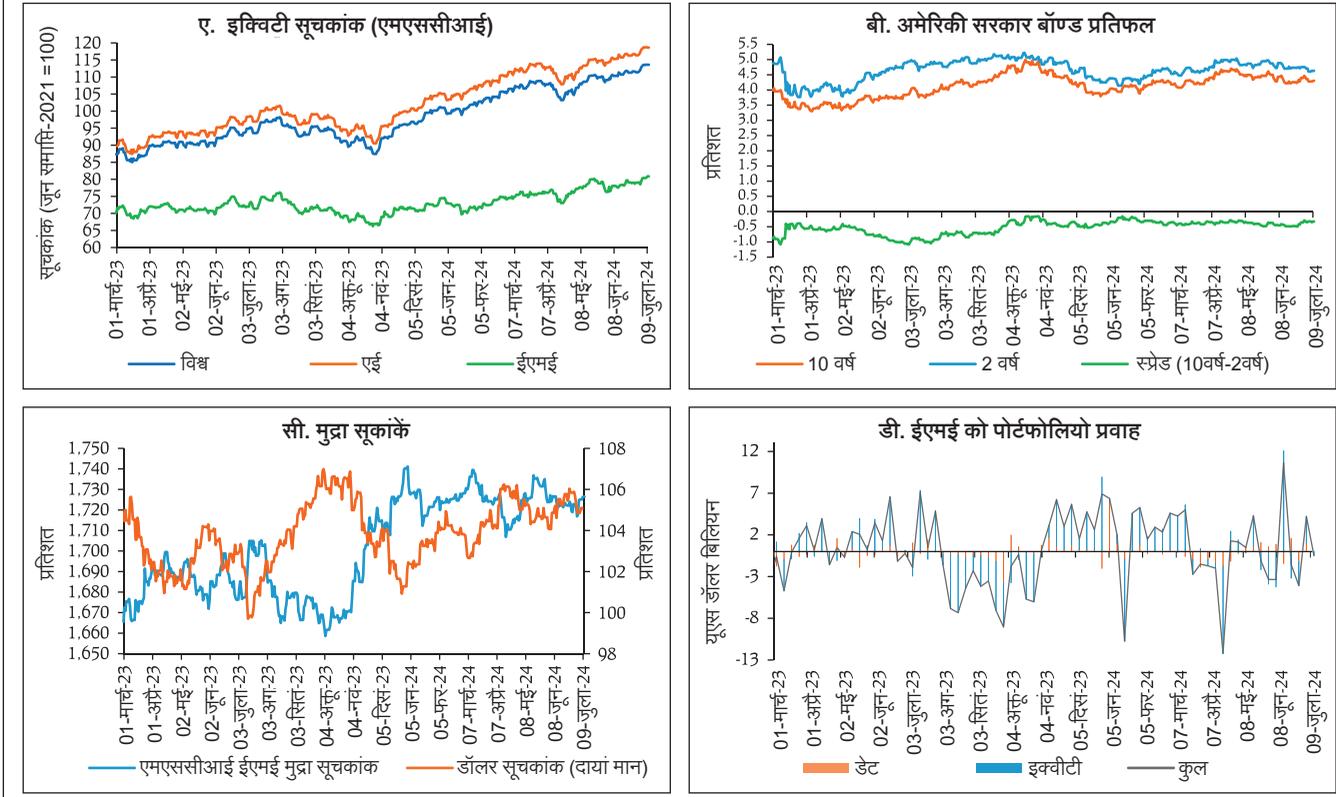


अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति में धीरे-धीरे गिरावट जारी रही। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति मई में 3.3 प्रतिशत से जून में 3.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) तक कम हो गई, और सूचकांक ने गैस और ऑटोमोबाइल की कीमतों में गिरावट के कारण मई 2020 के बाद पहली बार माह-दर-माह गिरावट दर्ज की। हेडलाइन व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मुद्रास्फीति भी अप्रैल में 2.7 प्रतिशत से मई में 2.6 प्रतिशत तक कम हो गई। फ्लैश अनुमानों के अनुसार, यूरो क्षेत्र की मुद्रास्फीति जून में 2.5 प्रतिशत तक कम हो गई, जो एक महीने पहले 2.6 प्रतिशत थी, बावजूद इसके कि कोर और सेवाओं की मुद्रास्फीति जड़ बनी रही। जापान में मुद्रास्फीति (ताजा भोजन को छोड़कर सीपीआई) मई में

2.5 प्रतिशत तक बढ़ गई, जबकि यूके में यह 2.0 प्रतिशत तक कम हो गई (चार्ट II.9ए)। ईएमई में, ब्राजील और रूस में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि जून में चीन में यह कम हुई (चार्ट II.9बी)। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में कोर और सेवा मुद्रास्फीति में गिरावट का रुख रहा है, हालांकि अधिकांश में यह कोर मुद्रास्फीति से अधिक बनी हुई है।

जून में वैश्विक इक्विटी बाजारों में तेजी आई, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व सूचकांक में 2.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई क्योंकि अनुमान से पहले अमेरिकी फेड दर में कटौती की बढ़ती उम्मीदों ने शेयर बाजारों में जोखिम-जनित-भावना को बढ़ावा दिया (चार्ट II.10ए)।

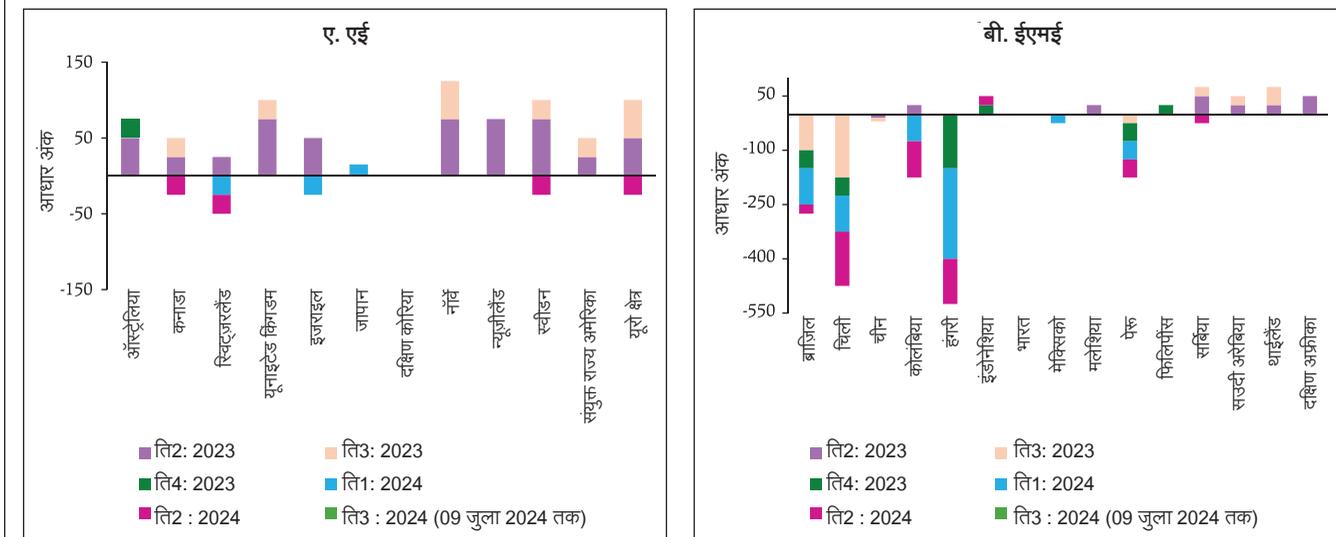
चार्ट II.10 वैश्विक वित्तीय बाजार



स्रोत : ब्लूमबर्ग; और आईआईएफा

अमेरिकी सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) का प्रतिफल – 12 बीपीएस तक कम हो गया, क्योंकि वित्तीय बाजारों ने 10-वर्ष और 2-वर्ष दोनों – जून में क्रमशः 10 बीपीएस और उम्मीद से कमजोर श्रम बाजार और व्यावसायिक गतिविधि

चार्ट II.11: नीति दरों में परिवर्तन



स्रोत : ब्लूमबर्ग

डेटा को महत्व दिया (चार्ट II.10बी)<sup>14</sup> मुद्रा बाजारों में, सुरक्षित पनाहगाह अपील की वजह से जून में अमेरिकी डॉलर में लगभग 1 प्रतिशत की मजबूती आई। दूसरी ओर, ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक जून में अस्थिर पूंजी प्रवाह के साथ सीमाबद्ध रहा, मुख्य रूप से इक्विटी खंड में (चार्ट II.10सी और II.10डी)।

ईई केंद्रीय बैंकों में, स्विस नेशनल बैंक ने लगातार दूसरी बैठक में जून में अपनी बेंचमार्क दर को 25 बीपीएस घटाकर 1.25 प्रतिशत कर दिया (चार्ट II.11ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, कोलंबिया ने जून की बैठक में अपनी प्रमुख दर में 50 बीपीएस की कटौती करते हुए अपने सहजता चक्र को जारी रखा (चार्ट II.11बी)। अधिकांश अन्य केंद्रीय बैंकों ने अपनी नवीनतम बैठकों में अपनी नीतिगत दरों को बरकरार रखा है,

हालांकि उनमें से कुछ ने मुद्रास्फीति पर अनुकूल आंकड़ों की शर्त पर आगामी दर कटौती पर भावी संकेत दिए हैं।

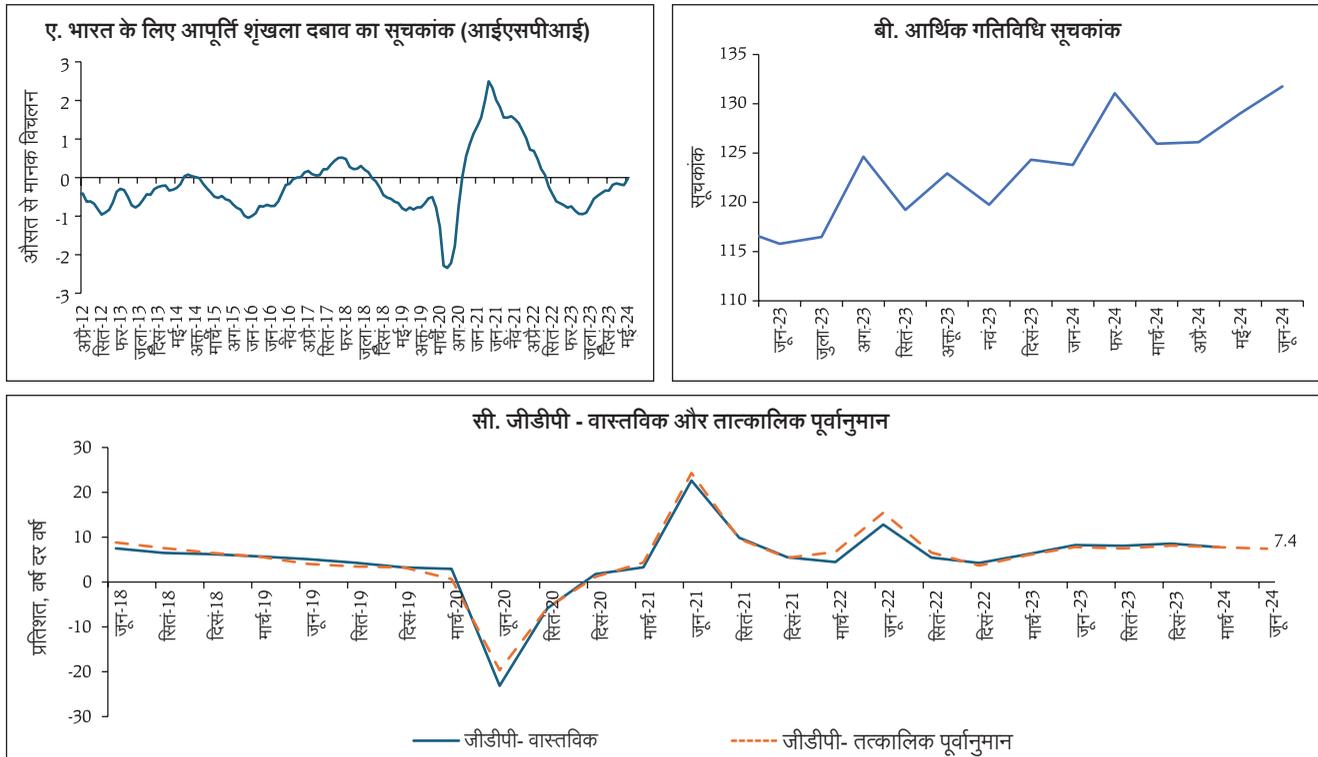
### III. घरेलू घटनाक्रम

भू-राजनीतिक प्रतिकूलताओं और आपूर्ति शृंखला दबावों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने मजबूत संवृद्धि गति बनाए रखी (चार्ट III.1ए)। कई उच्च आवृत्ति संकेतकों से उपलब्ध जानकारी का उपयोग करते हुए, हमारा आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) अनुमान लगाता है कि ति1:2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.4 प्रतिशत होने की संभावना है (चार्ट III.1बी और चार्ट III.1सी)।

### समग्र मांग

उच्च आवृत्ति संकेतकों में उतार-चढ़ाव से पता चलता है कि 2024-25 की पहली तिमाही के दौरान घरेलू मांग की

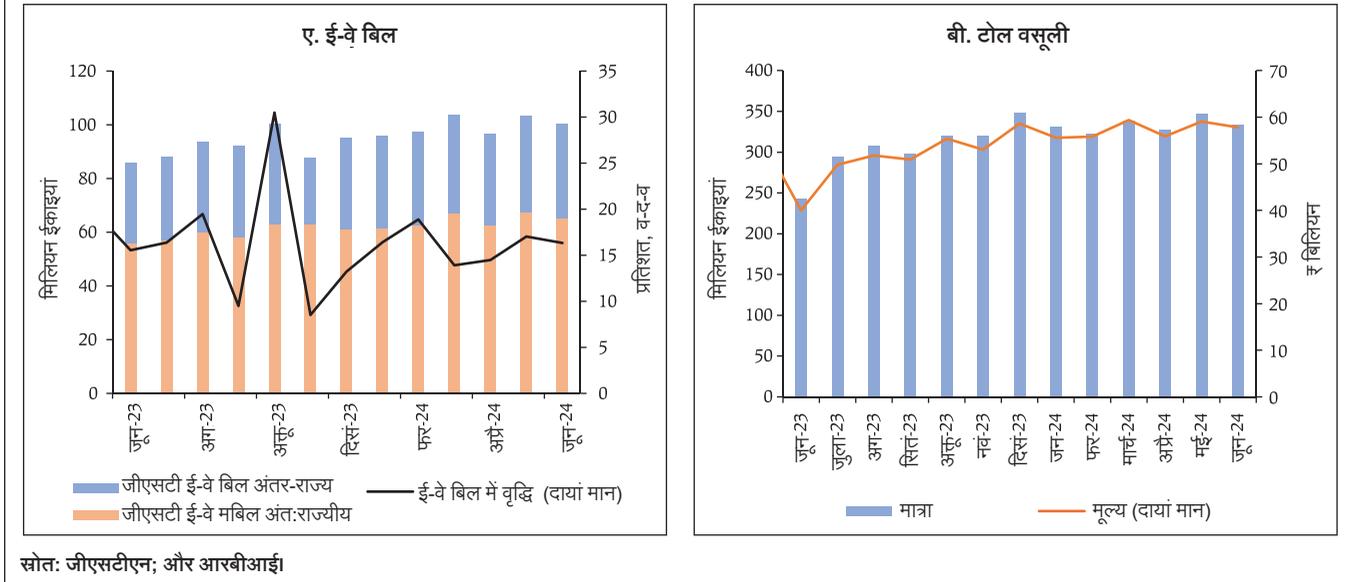
चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि और जीडीपी संवृद्धि तात्कालिक पूर्वानुमान



**टिप्पणी :** आर्थिक गतिविधि सूचकांक (ईएआई) का निर्माण गतिशील कारक मॉडल का उपयोग करते हुए आर्थिक गतिविधि के सत्ताईस उच्च आवृत्ति संकेतकों में अंतर्निहित सामान्य प्रवृत्तियों को लेते हुए किया गया। ईएआई फरवरी 2020 में 100 तक बढ़ गया और अप्रैल 2020 में 0 था जो गतिशीलता प्रतिबंधों के कारण सबसे अधिक प्रभावित महीना था।  
**स्रोत :** आरबीआई; राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

<sup>14</sup> आपूर्ति प्रबंधन संस्थान (आईएसएम) डेटा।

**चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल वसूली**

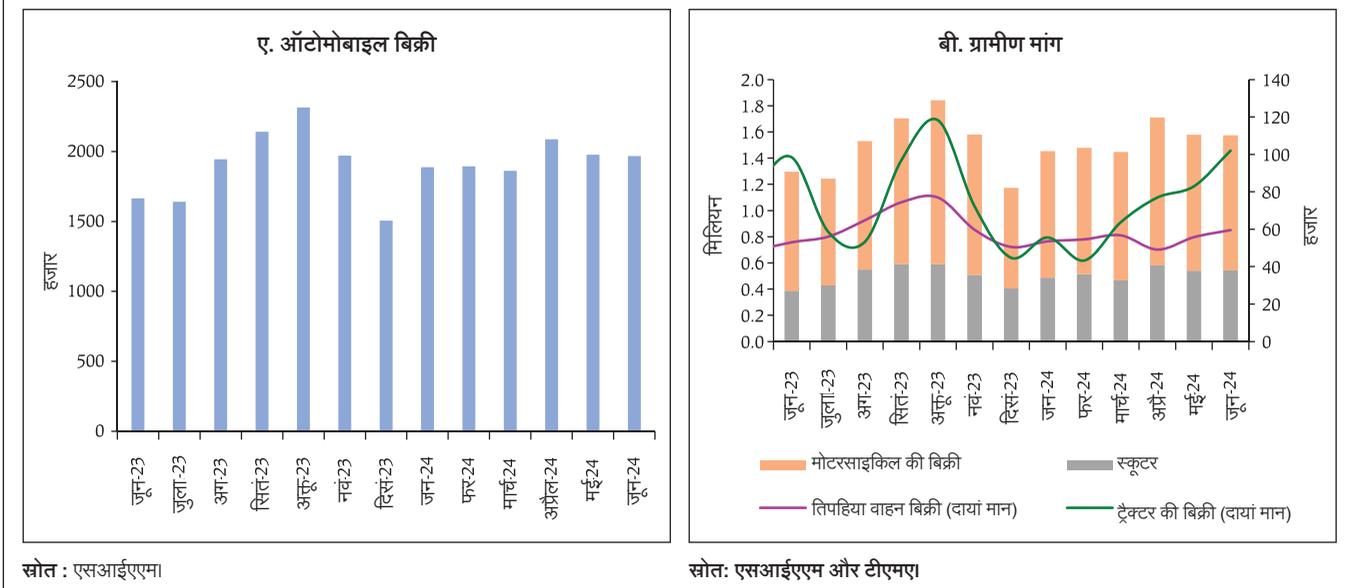


स्थिति मजबूत बनी हुई है। जून 2024 में ई-वे बिल में 16.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसमें अंत:राज्यीय और अंतर-राज्यीय दोनों तरह से क्रमिक वृद्धि हुई (चार्ट III.2ए)। जून 2024 में टोल संग्रह में 37.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मजबूत वृद्धि हुई (चार्ट III.2बी)।

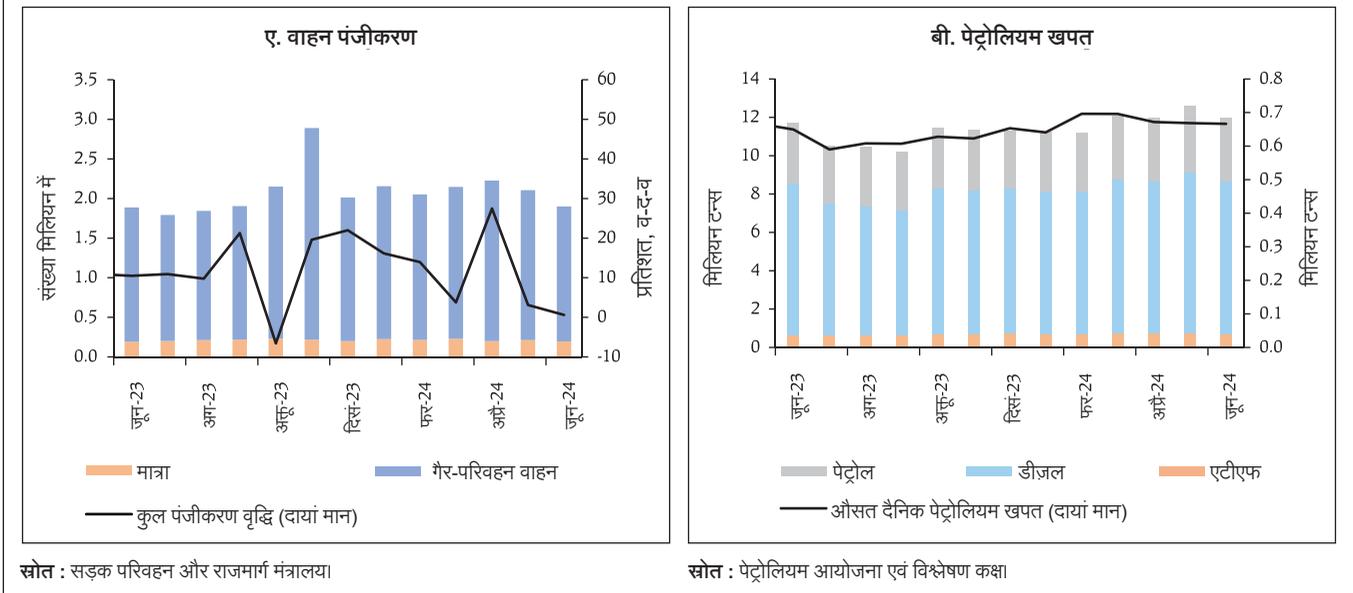
जून 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 18.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई, जिसकी अगुवाई दोपहिया

और तिपहिया वाहनों ने की और उसके बाद यात्री वाहनों का स्थान रहा, जबकि प्रवेश स्तर के वाहनों की वृद्धि कमजोर बनी रही (चार्ट III.3ए)। कृषि भावनाओं में सुधार के साथ, घरेलू ट्रैक्टर की बिक्री जून 2024 में आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई, कुल मात्रा एक लाख के आंकड़े को पार कर गई (चार्ट III.3बी) जून 2024 में गैर-परिवहन वाहनों और परिवहन वाहनों दोनों क्षेत्रों में वाहन पंजीकरण में कमी आई

**चार्ट III.3 ऑटोमोबाइल क्षेत्र के संकेतक**



**चार्ट III.4 वाहन पंजीकरण और पेट्रोलियम खपत**



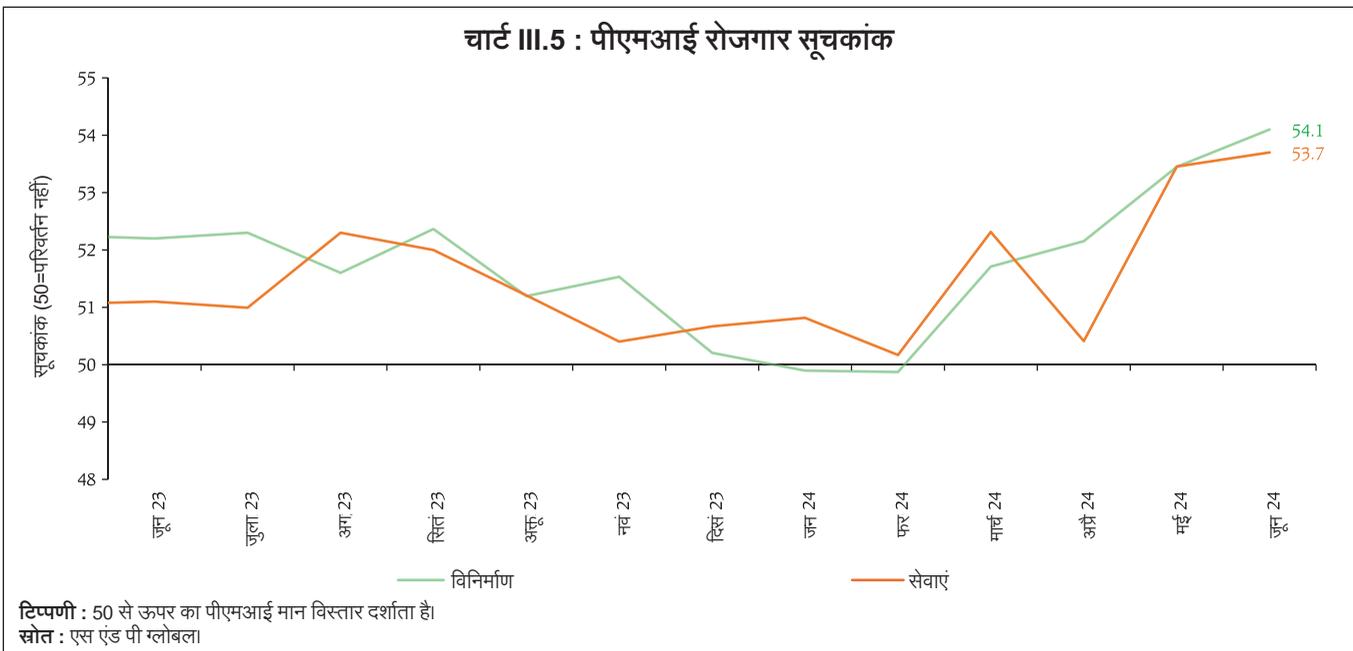
(चार्ट III.4ए)। मोटर स्पिरिट्स (पेट्रोल) और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) [चार्ट III.4बी] के कारण जून 2024 में औसत दैनिक पेट्रोलियम खपत में 2.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई।

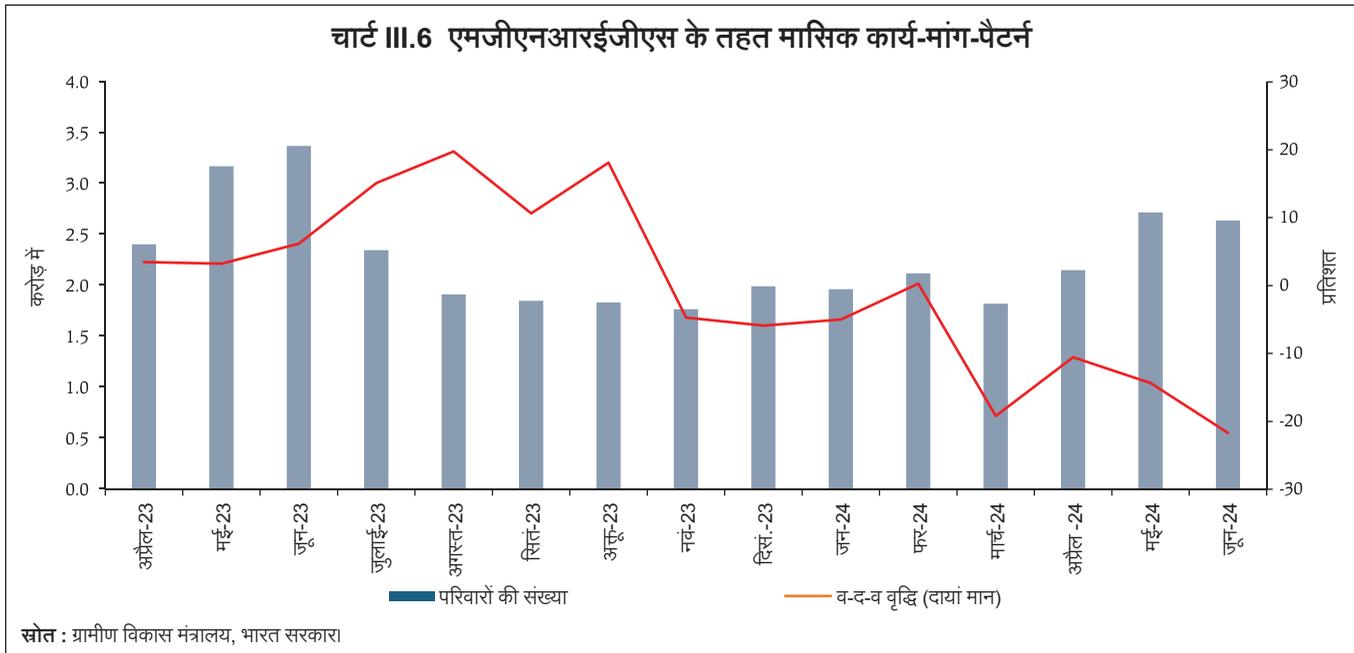
उसी महीने, संगठित विनिर्माण रोजगार, जैसा कि पीएमआई रोजगार परिदृश्य द्वारा दर्शाया गया है, ने बढ़ते उत्पादन के कारण

19 वर्षों में सबसे तेज़ विस्तार दर दर्ज की। नए व्यवसाय में उछाल के कारण सेवा क्षेत्र में रोजगार सृजन अगस्त 2022 के बाद से अपने सबसे मजबूत स्तर पर पहुँच गया (चार्ट III.5)।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अंतर्गत घरेलू कार्य मांग में जून माह में 2.9 प्रतिशत (मासिक) की मामूली गिरावट देखी गई (चार्ट III.6)।

**चार्ट III.5 : पीएमआई रोजगार सूचकांक**

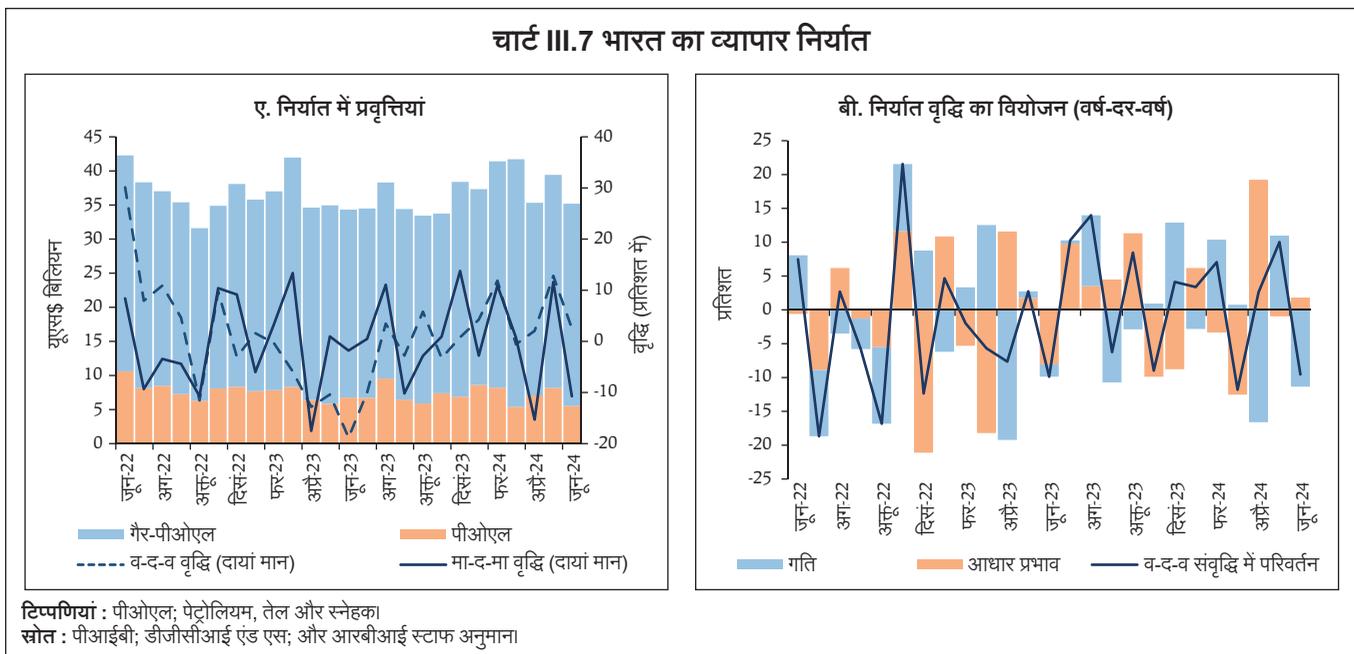


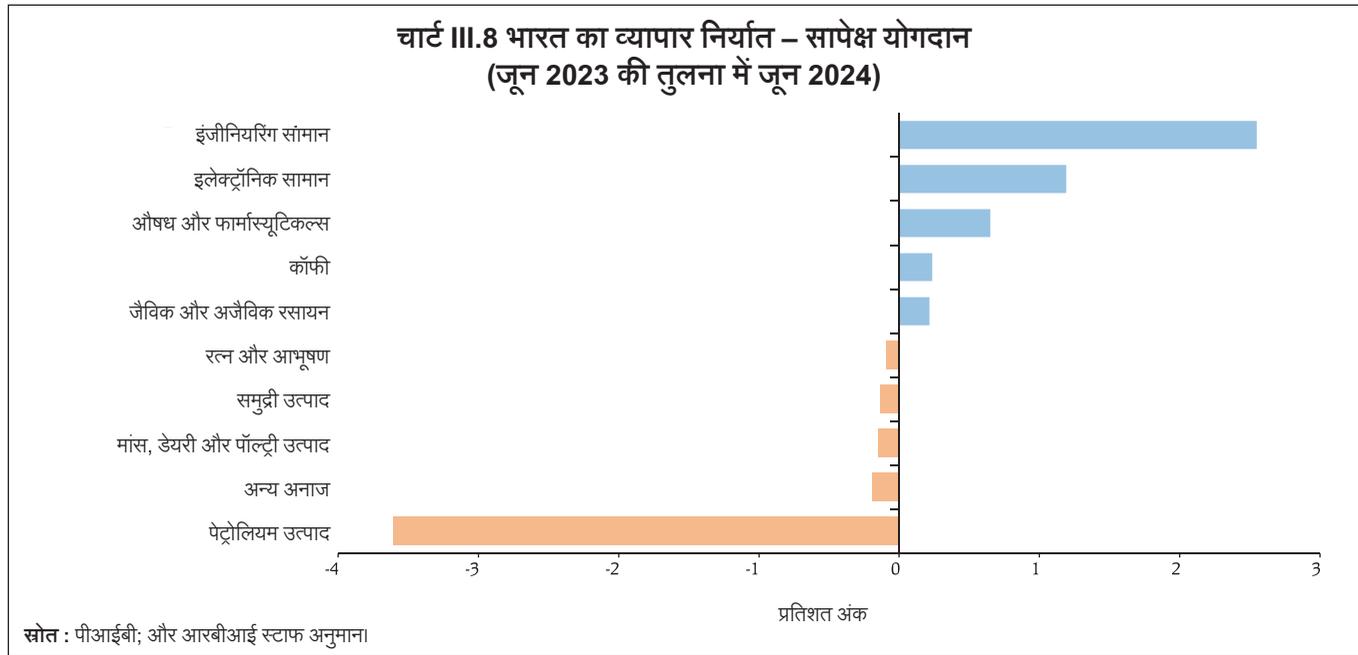


अनुक्रमिक (माह-दर-माह) गिरावट के बावजूद, अनुकूल आधार प्रभाव के कारण जून 2024 में भारत का व्यापारिक निर्यात 2.5 प्रतिशत (वर्ष दर वर्ष) बढ़कर 35.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.7)।

निर्यात विस्तार व्यापक आधार पर था, क्योंकि 30 प्रमुख वस्तुओं में से 19 (निर्यात बास्केट का 62.6 प्रतिशत हिस्सा) में

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी, और कार्बनिक और अकार्बनिक रसायनों ने जून में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य अनाज, मांस, डेयरी और पोल्ट्री उत्पाद, समुद्री उत्पाद, और रत्न और आभूषण ने वृद्धि को कम कर दिया (चार्ट III.8)।



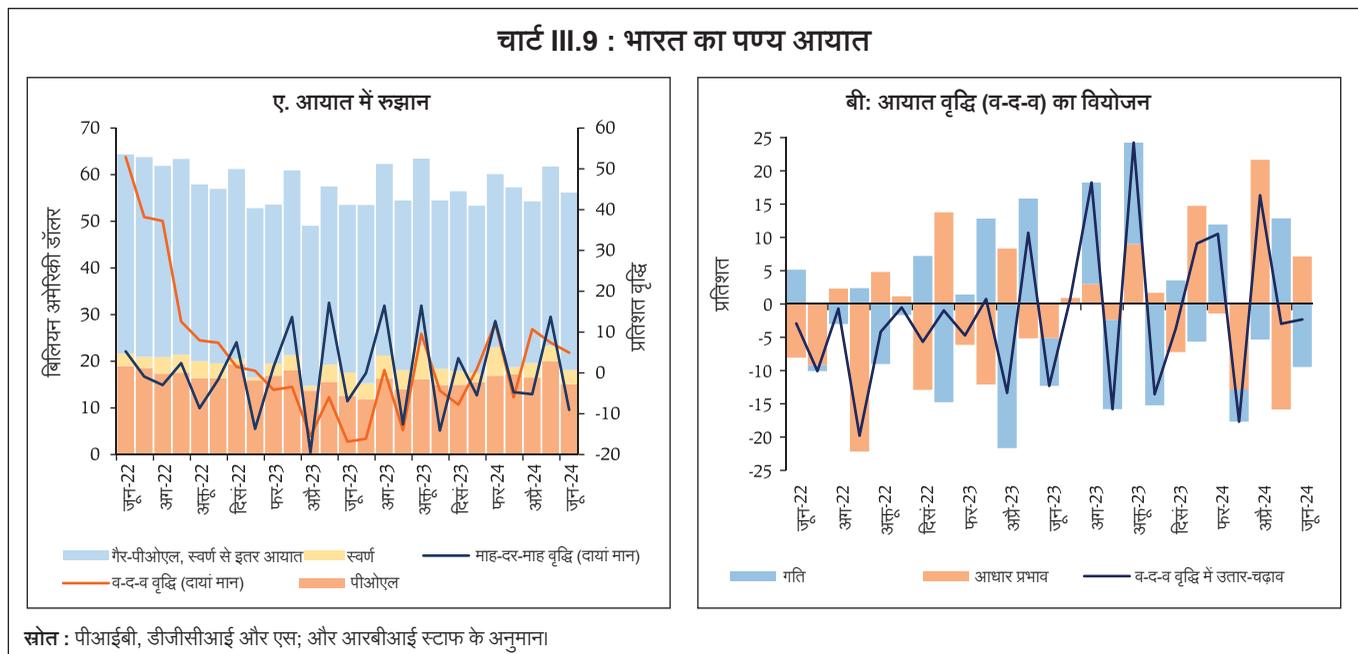


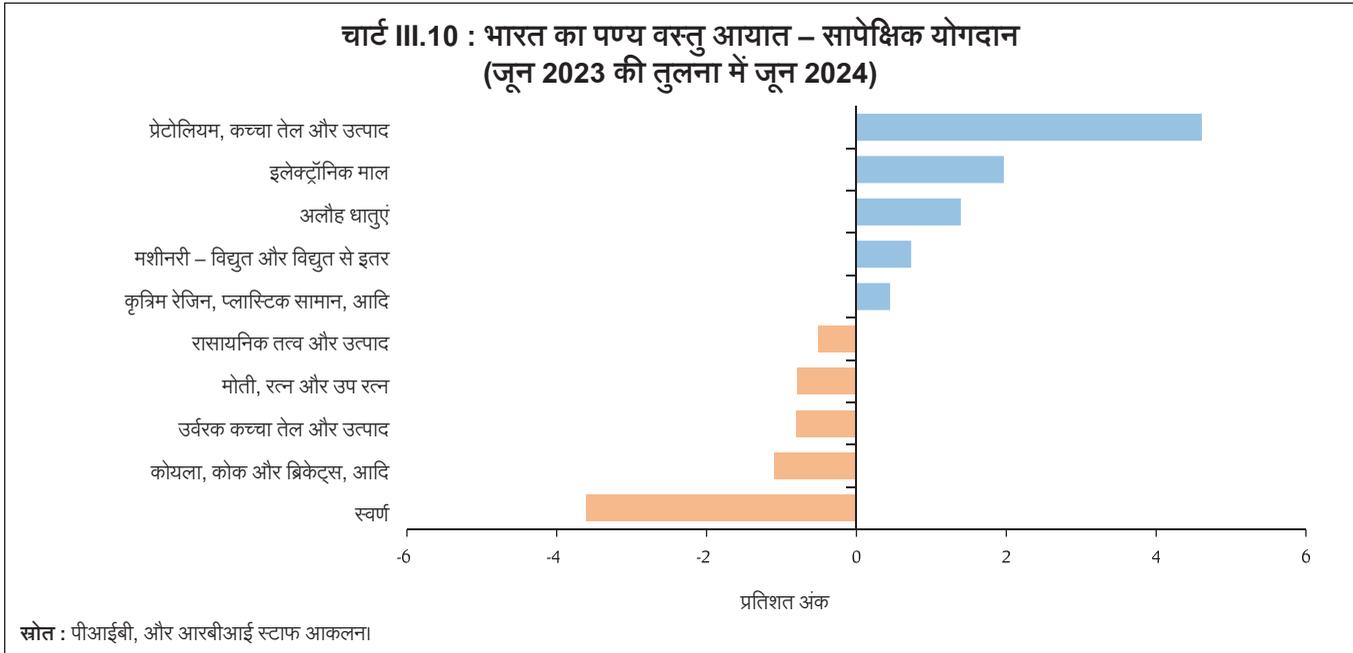
2024-25 की पहली तिमाही में, भारत का वस्तु निर्यात 5.8 प्रतिशत बढ़कर 110.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण जून 2024 के परिणाम थे।

जून में वस्तु आयात 5.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 56.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जिसे सकारात्मक आधार प्रभाव से सहायता मिली (चार्ट III.9)। 30 प्रमुख वस्तुओं में से 21

वस्तुओं (आयात बास्केट का 71.8 प्रतिशत हिस्सा) ने जून में वर्ष दर वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की।

पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातुएं, मशीनरी और कृत्रिम रेजिन की कीमतों में वृद्धि रही, जबकि सोना, कोयला, उर्वरक, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर और रासायनिक सामग्री और उत्पाद सुस्त थे (चार्ट III.10)।



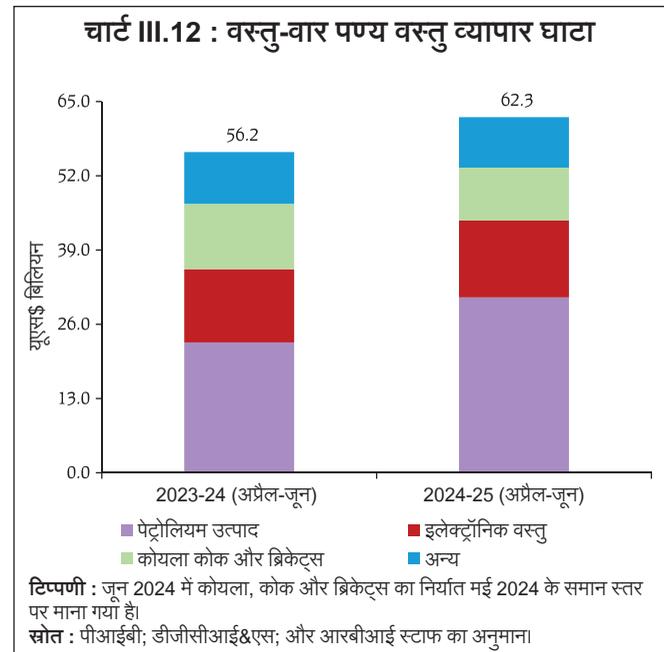
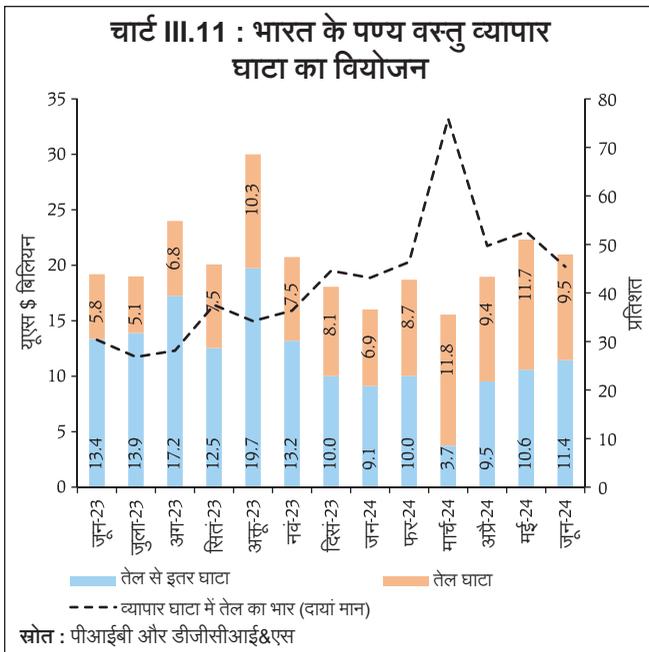


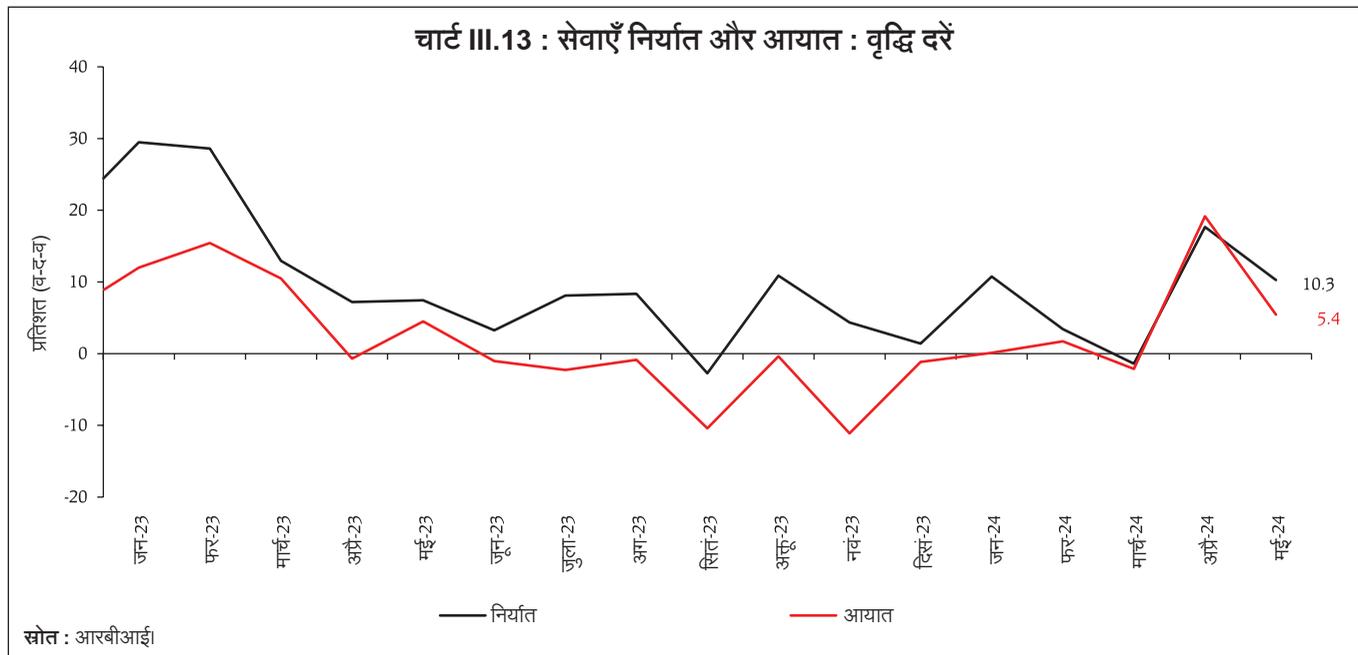
वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का व्यापारिक आयात 7.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 172.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण पेट्रोलियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, अलौह धातुएं, वनस्पति तेल और दालें रहीं।

जून 2024 में वस्तु व्यापार घाटा बढ़कर 21.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो जून 2023 में 19.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कुल वस्तु व्यापार घाटे में पीओएल की

हिस्सेदारी मई 2024 में 52.6 प्रतिशत से घटकर 45.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.11)।

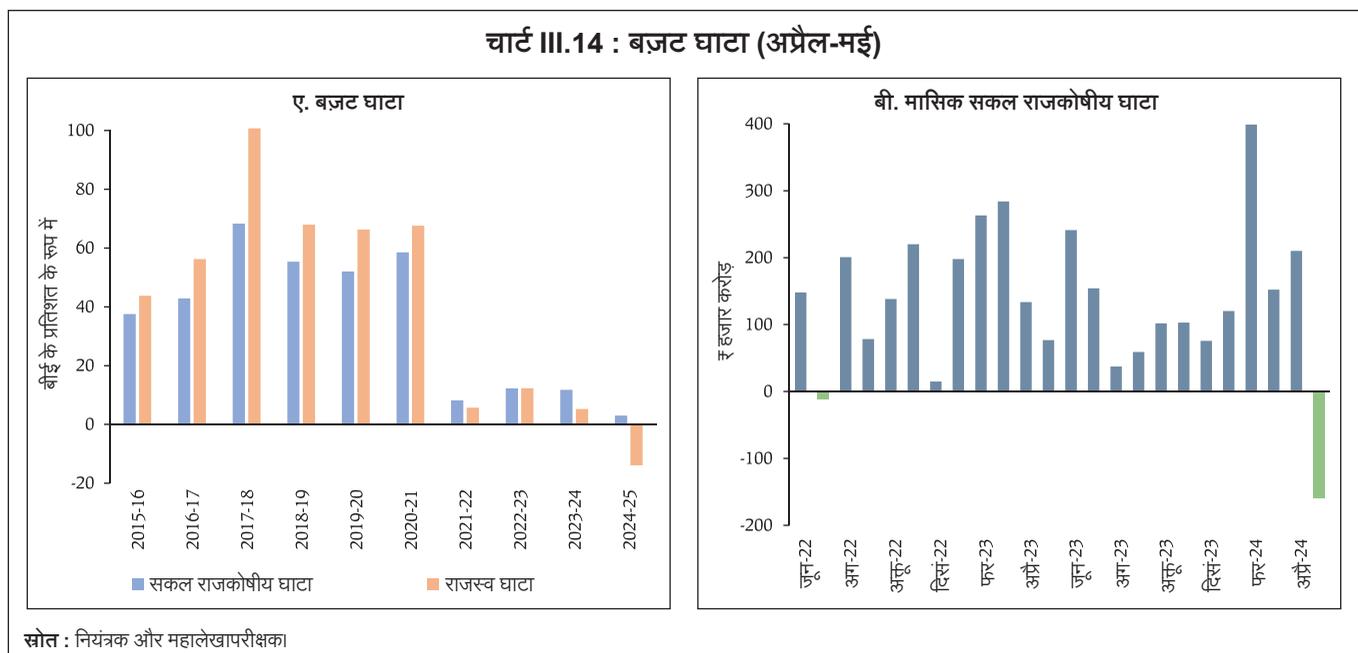
वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में भारत का व्यापारिक घाटा एक वर्ष पहले के 56.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 62.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पेट्रोलियम उत्पाद घाटे का सबसे बड़ा स्रोत थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान (चार्ट III.12) थे।





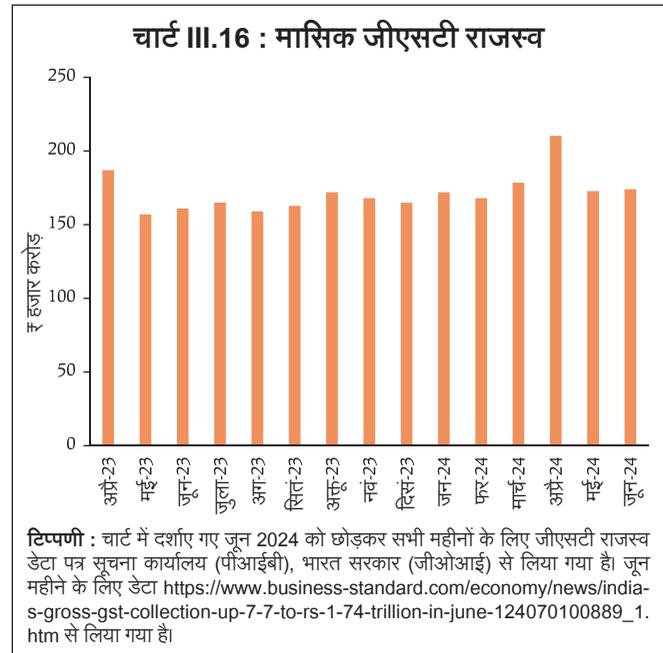
मई 2024 में, सेवाओं का निर्यात 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवाओं का आयात 5.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.13)। नतीजतन, मई 2024 में शुद्ध सेवा निर्यात आय 17.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 13.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई।

केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतक, अर्थात् सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी), राजस्व घाटा (आरडी) और प्राथमिक घाटा (पीडी) में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-मई 2024 के दौरान सुधार देखा गया। जीएफडी एक वर्ष पहले के बजट अनुमानों (बीई) के 11.8 प्रतिशत के मुकाबले घटकर 3 प्रतिशत रह गया (चार्ट III.14ए)। इसके अलावा,

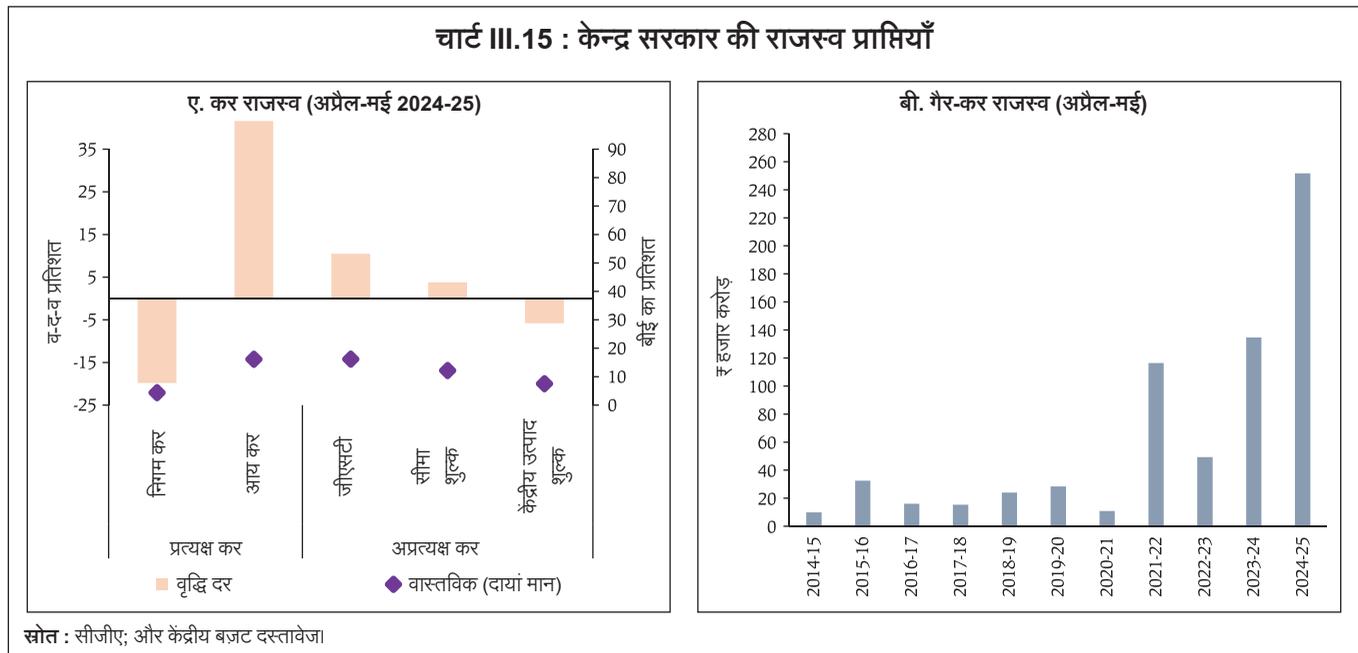


22 महीने के अंतराल के बाद मई 2024 में राजकोषीय अधिशेष दर्ज किया गया (चार्ट III.14बी)। अप्रैल-मई 2024 के दौरान केंद्र सरकार की वित्तीय स्थिति में यह सुधार राजस्व प्राप्तियों में मजबूत और व्यापक-आधारित वृद्धि के दम पर हुआ। दूसरी ओर, केंद्र सरकार का कुल व्यय अप्रैल-मई 2024 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 6.2 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर रहा, जिसका मुख्य कारण 2024 के आम चुनावों के लिए 7 मार्च 2024 से 4 जून 2024 तक लागू आदर्श आचार संहिता है।

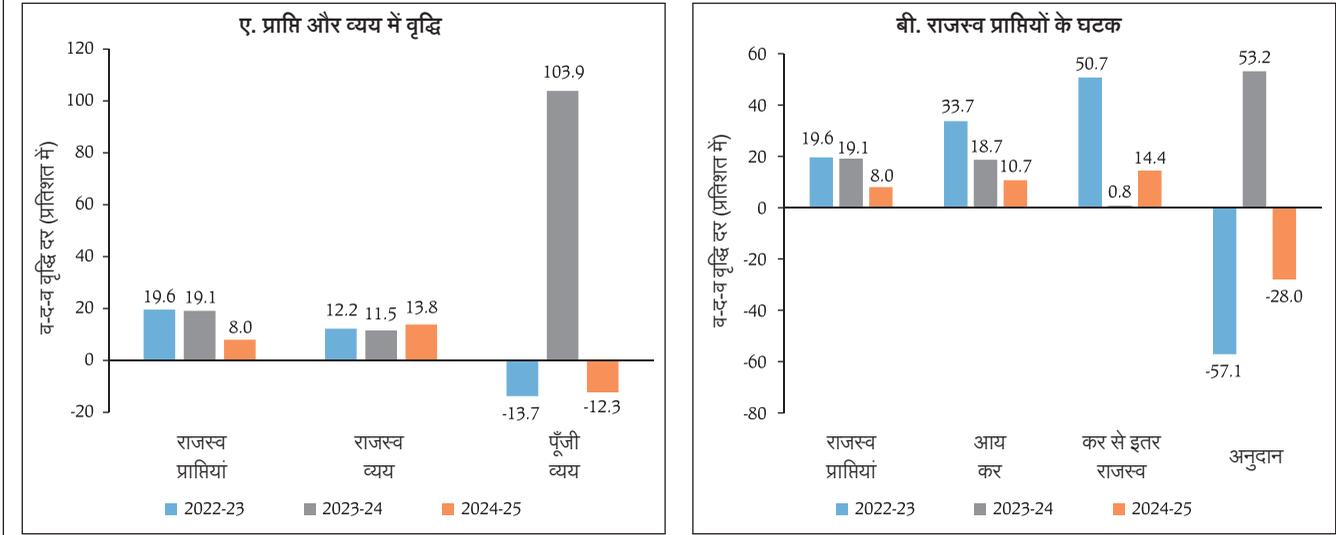
प्राप्तियों के मामले में, सकल कर राजस्व में अप्रैल-मई 2024 के दौरान 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में क्रमशः 24.6 प्रतिशत और 8.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। प्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, निगम कर में 19.8 प्रतिशत की संकुचन दर्ज की गई, लेकिन आयकर में 41.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष करों के अंतर्गत, जीएसटी संग्रह और सीमा शुल्क में क्रमशः 10.5 प्रतिशत और 3.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.15ए)। रिज़र्व बैंक से बजट से



अधिक अधिशेष हस्तांतरण के कारण अप्रैल-मई 2024 के दौरान गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में 86.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.15बी)। दूसरी ओर, अप्रैल-मई 2024 के दौरान गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में 30.2 प्रतिशत की संकुचन हुई।



**चार्ट III.17: प्रमुख राजकोषीय प्रदर्शन संकेतक (अप्रैल-मई)**

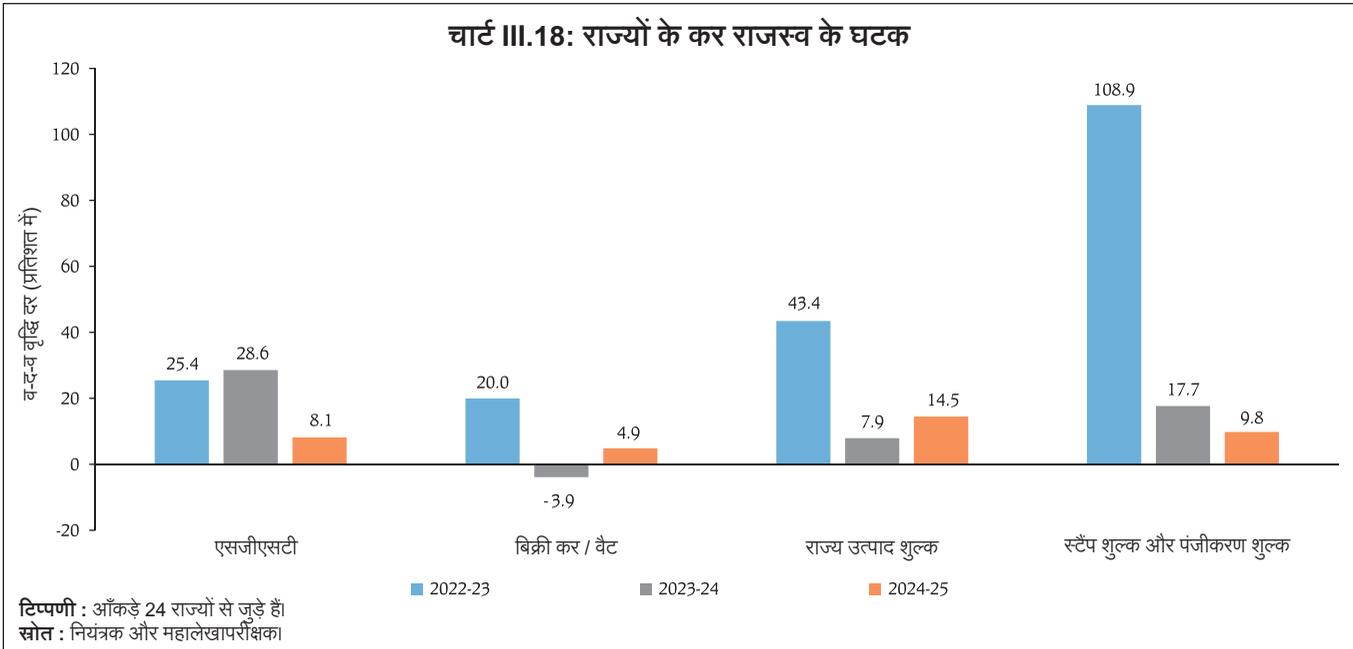


टिप्पणी : आँकड़े 24 राज्यों से संबंधित हैं।  
 स्रोत : नियंत्रक और महालेखापरीक्षक।

जून 2024 के महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹ 1.74 लाख करोड़<sup>15</sup> रहा, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 7.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (चार्ट III.16)। अप्रैल-जून 2024 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह

10.3 प्रतिशत बढ़कर ₹ 5.57 लाख करोड़ हो गया, जो कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कर अनुपालन में सुधार और कर अधिकारियों द्वारा प्रभावी प्रवर्तन को दर्शाता है।

**चार्ट III.18: राज्यों के कर राजस्व के घटक**



<sup>15</sup> [https://www.business-standard.com/economy/news/india-s-gross-gst-collection-up-7-7-to-rs-1-74-trillion-in-june-124070100889\\_1.html](https://www.business-standard.com/economy/news/india-s-gross-gst-collection-up-7-7-to-rs-1-74-trillion-in-june-124070100889_1.html) [पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की ओर से जून 2024 के महीने के लिए जीएसटी संग्रह के लिए कोई प्रेस विज्ञापित जारी नहीं की गई है।]

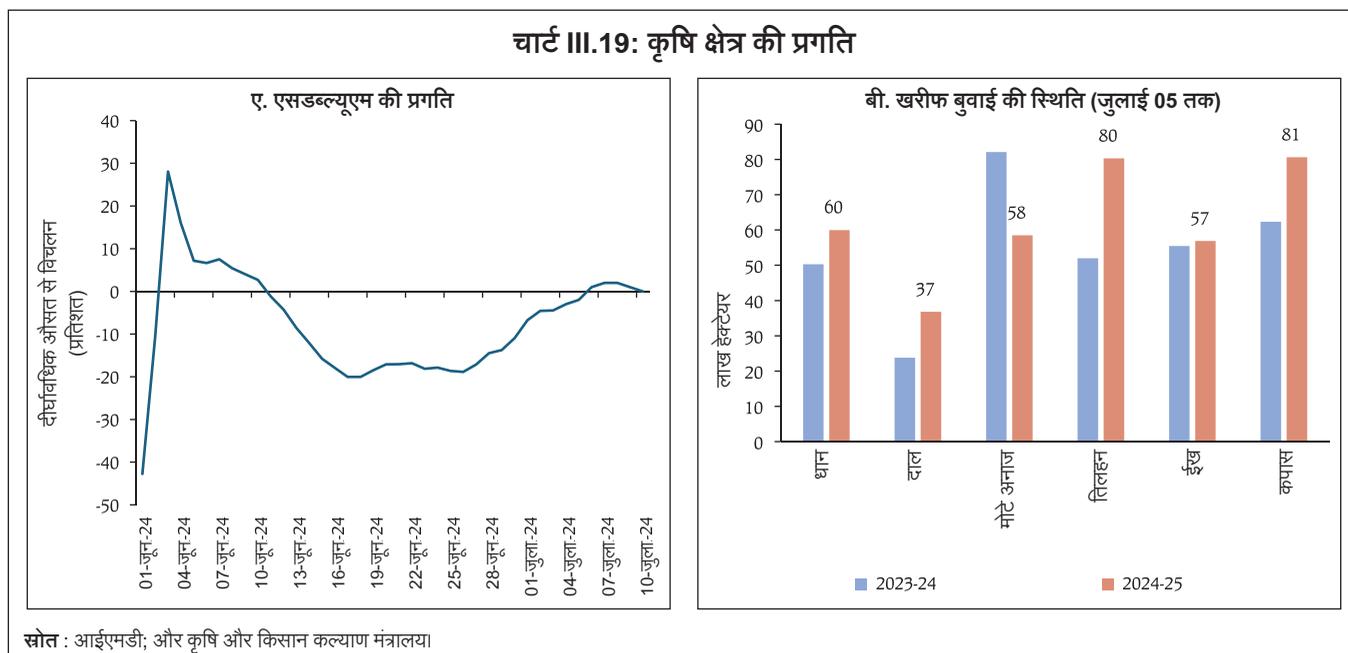
अप्रैल-मई 2024 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि धीमी हुई है, जिसका मुख्य कारण कर राजस्व में मंदी और केंद्र सरकार से अनुदान में कमी है। इसके विपरीत, गैर-कर राजस्व में तेजी से वृद्धि हुई है। व्यय पक्ष पर, राजस्व व्यय में मामूली वृद्धि हुई, लेकिन अप्रैल-मई 2024 के दौरान पूंजीगत व्यय में कमी आई (चार्ट III.17)। राज्यों के अपने कर राजस्व के भीतर, राज्यों के माल और सेवा कर (एसजीएसटी) में वृद्धि उच्च आधार से धीमी हुई, जबकि बिक्री कर/वैट और राज्य उत्पाद शुल्क में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि हुई (चार्ट III.18)।

पिछले वर्ष की तरह, केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए जून में राज्यों को कर हस्तांतरण की एक अतिरिक्त किस्त जारी की है। अप्रैल-जून 2024 के दौरान, राज्यों को हस्तांतरित कुल राशि ₹2.80 लाख करोड़ रही है, जबकि एक वर्ष पहले यह राशि ₹2.37 लाख करोड़ थी।<sup>16,17</sup>

## समग्र आपूर्ति

दक्षिण-पश्चिम मानसून (एसडब्ल्यूएम) ने 08 जुलाई की अपनी सामान्य तिथि से छह दिन पहले पूरे भारत को कवर कर लिया। 01 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर संचयी एसडब्ल्यूएम वर्षा पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के एलपीए से 2 प्रतिशत अधिक की तुलना में अपने दीर्घकालिक औसत (एलपीए) पर रही। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन (एमजेओ)<sup>18</sup> की क्रमिक मजबूती और उसके बाद जून के अंत में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बारिश के अनुकूल कम दबाव प्रणाली के निर्माण ने जून के मध्य में रुकी हुई मानसून की प्रगति में मदद की (चार्ट III.19ए)। परिणामस्वरूप, संचयी खरीफ बुआई 378.7 लाख हेक्टेयर (5 जुलाई, 2024 तक) रही, जो पूरे सीजन की सामान्य एकड़ का 34.6 प्रतिशत और पिछले वर्ष की इसी तारीख की तुलना में 14.1 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.19 बी)। साथ ही, देश के अधिकांश हिस्सों

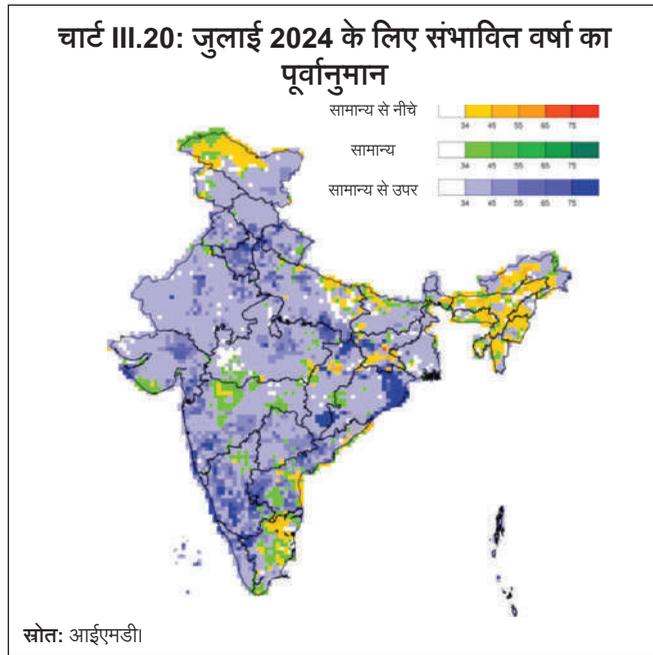
चार्ट III.19: कृषि क्षेत्र की प्रगति



<sup>16</sup> <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2023869#:~:text=The%20Interim%20Budget%202024%2D25.2%2C79%2C500%20crore>

<sup>17</sup> <https://cga.nic.in/MonthlyReport/Published/6/2023-2024.aspx>

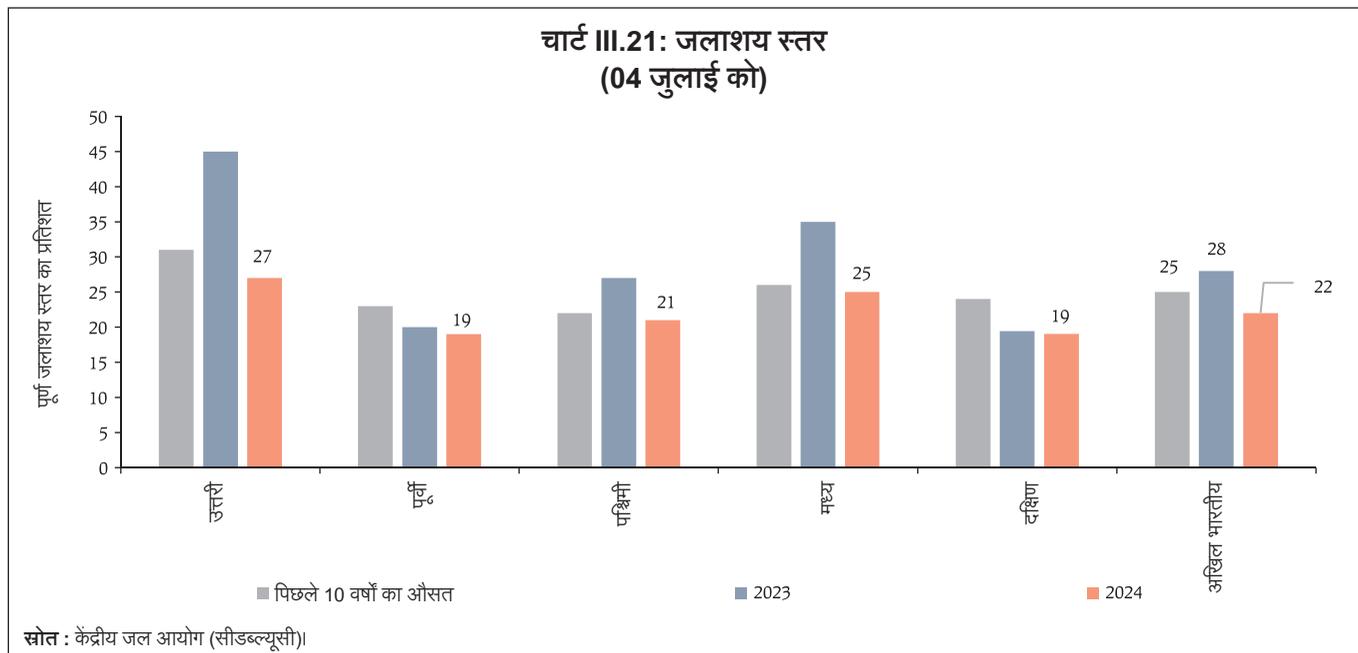
<sup>18</sup> आईएमडी के अनुसार, एमजेओ उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वायुमंडल-महासागर युग्मित घटनाओं में से एक है और इसका भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसकी विशेषता यह है कि यह मुख्य रूप से हिंद और प्रशांत महासागर में देखी जाने वाली बड़ी हुई और दबी हुई उष्णकटिबंधीय वर्षा के बड़े क्षेत्रों के पूर्व की ओर फैलता है। संवहनीयता गतिविधि के आधार पर, एमजेओ की अवधि को 1-8 चरणों में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक चरण लगभग 7 से 8 दिनों तक चलता है।



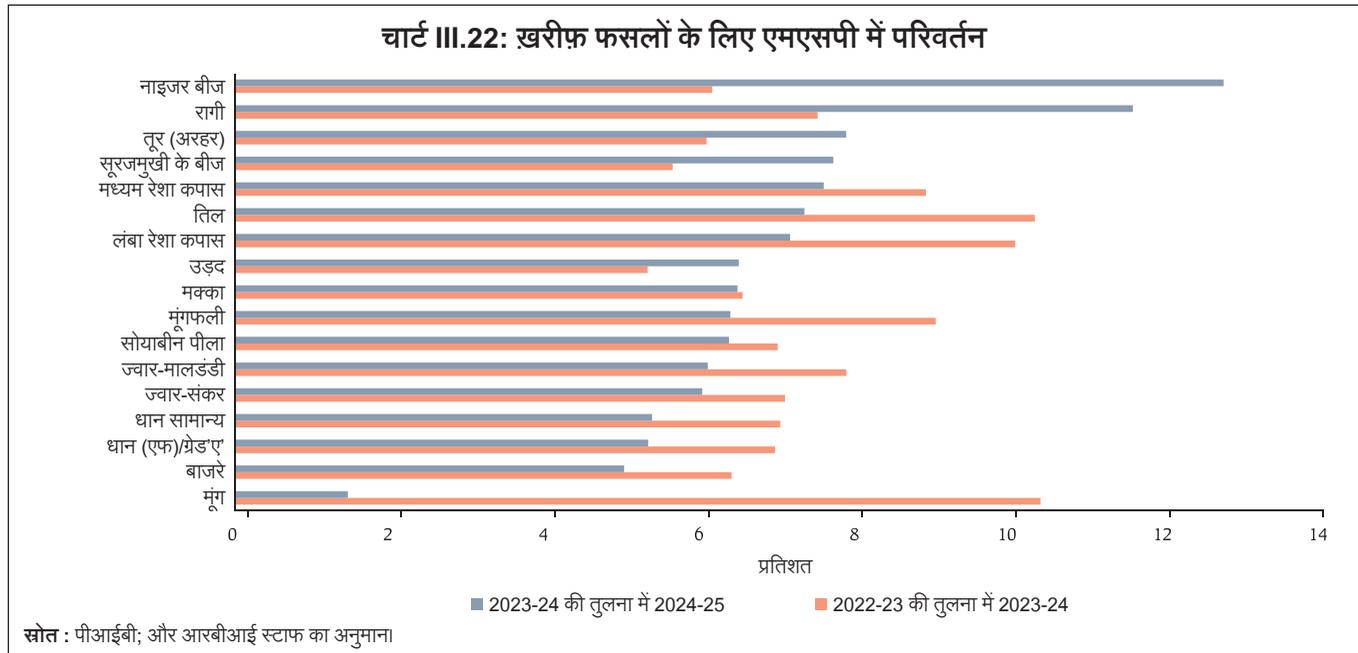
गर्मी के चलते जुलाई के दौरान अधिक बादल छाए रहने से तापमान में भी कमी आने की संभावना है।

01 जुलाई, 2024 तक चावल (बिना पिसे धान के बराबर) और गेहूं का बफर स्टॉक क्रमशः 485.0 लाख टन (मानक का 3.6 गुना) और 282.6 लाख टन (मानक के बराबर) था। 10 जुलाई, 2024 तक धान की सार्वजनिक खरीद (521.9 लाख टन) पिछले वर्ष की इसी तारीख के स्तर से 8.2 प्रतिशत कम रही। गेहूं की 266.0 लाख टन की खरीद एक साल पहले की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक थी, लेकिन इस मौसम के खरीद लक्ष्य 300-320 लाख टन से कम थी। तदनुसार, केंद्र ने 24 जून, 2024 को तत्काल प्रभाव से व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसरों के लिए 31 मार्च, 2025 तक गेहूं पर अखिल भारतीय स्टॉक सीमा लगा दी है।<sup>19</sup> इसके अलावा, 01 अगस्त, 2024 से गेहूं की खुले बाजार में बिक्री की योजना है। इसी तरह, *काबुली चना* सहित तुअर और चना पर भी 21 जून से 30 सितंबर, 2024 तक स्टॉक सीमा लागू की गई है।

में जुलाई के दौरान सामान्य से अधिक वर्षा का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का पूर्वानुमान जलाशय के स्तर की पुनःपूर्ति और खरीफ बुआई की आगे की प्रगति के लिए अच्छा संकेत है (चार्ट III.20 और III.21)। मार्च के बाद से तेज हुई

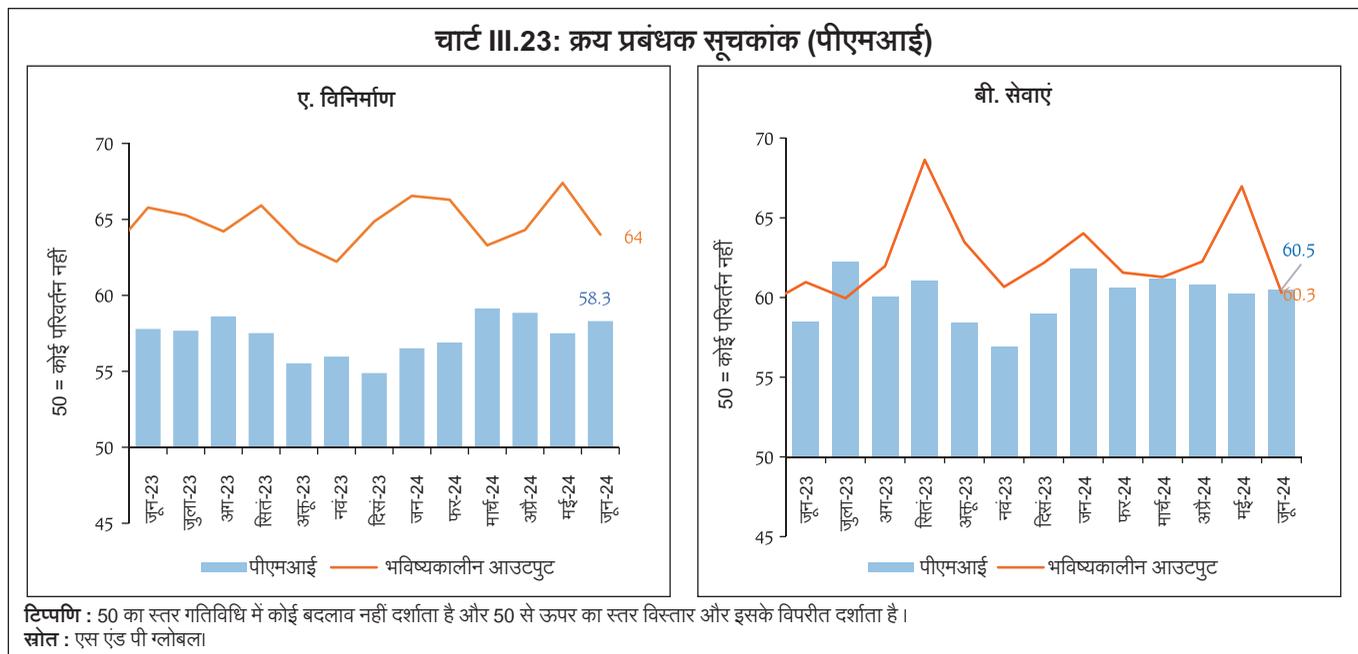


<sup>19</sup> <https://www.financialexpress.com/policy/economy-govt-to-begin-open-market-sale-of-wheat-amp-rice-from-aug-1-3549883/>

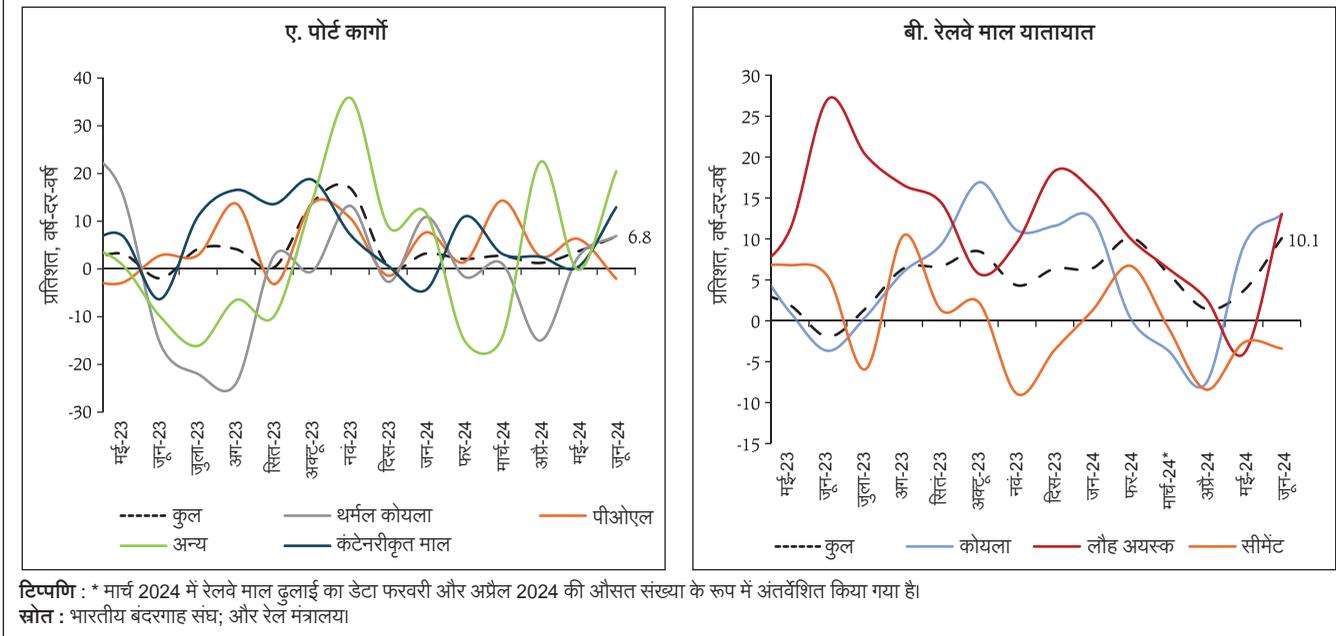


विपणन सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए 19 जून, 2024 को 14 प्रमुख खरीफ़ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की गई थी। एमएसपी को 1.4 प्रतिशत से 12.7 प्रतिशत की सीमा में संशोधित किया गया है (चार्ट III.22)। अधिकांश फसलों के लिए, यह वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप है।

नए कार्यदेश और उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण, जून 2024 में भारत की विनिर्माण पीएमआई रीडिंग बढ़कर 58.3 हो गई (चार्ट III.23ए)। सेवाओं के लिए पीएमआई मई के 60.2 से बढ़कर जून 2024 में 60.5 हो गया। हालाँकि, बाजार की अनिश्चितता और मूल्य प्रतिस्पर्धा के कारण भविष्य की गतिविधि (कारोबारी प्रत्याशाएं) 11 महीने के निचले स्तर पर गिर गई (चार्ट III.23बी)।



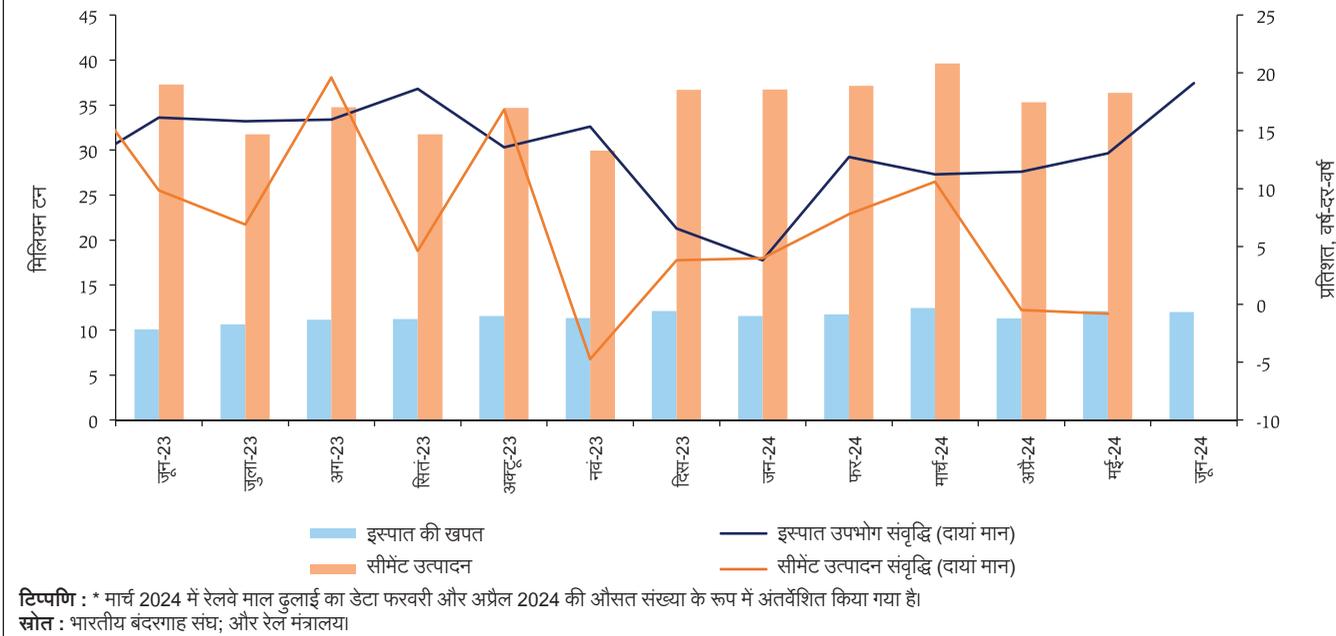
**चार्ट III.24: पोर्ट कार्गो और रेलवे माल यातायात**



जून 2024 में माल परिवहन के संकेतक अच्छे रहे। कंटेनरीकृत और अन्य विविध कार्गो के कारण प्रमुख बंदरगाहों पर यातायात में 6.8 प्रतिशत का विस्तार दर्ज किया गया (चार्ट III.24e)। कोयला और लौह अयस्क यातायात में वृद्धि के कारण, जून में रेलवे माल यातायात में भी तेजी आई (चार्ट III.24बी)।

निर्माण क्षेत्र ने मिश्रित संकेत दिखाए क्योंकि जून 2024 में स्टील की खपत में सालाना 19.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि सीमेंट उत्पादन पिछले दो महीनों से गिरावट के दौर में है (चार्ट III.25)।

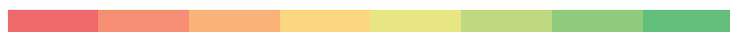
**चार्ट III.25: इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन**



## सारणी III.1: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएं

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	सितं-23	अक्टू-23	नवं-23	दिसं-23	जन-24	फर-24	मार्च-24	अप्रैल-24	मई-24	जून-24
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	3.1	17.3	4.3	3.2	13.9	5.7	8.9	1.2	4.3	4.9
ग्रामीण मांग	दोपहिया वाहनों की बिक्री	0.8	20.1	31.3	16.0	26.2	30.0	15.3	30.8	10.1	21.3
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	47.0	42.1	30.8	30.6	9.5	4.6	4.3	14.5	14.4	12.3
	ट्रैक्टर बिक्री	-14.7	-4.3	6.4	-19.8	-15.3	-30.6	-23.1	-3.0	0.0	3.6
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	6.9		3.2						3.5	
	रेलवे माल यातायात	6.7	8.5	4.3	6.4	6.4	10.1	8.6	1.4	3.7	10.1
	बंदरगाह कार्गो यातायात	0.3	13.8	16.9	0.6	3.2	2.1	2.7	1.3	3.8	6.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात*	-4.5	10.6	9.0	8.7	10.0	7.6	8.7	0.3	10.3	6.7
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात*	2.7	15.0	4.9	12.2	19.3	25.7	22.5	16.2	19.2	12.3
	घरेलू हवाई यात्री यातायात*	19.3	10.7	8.7	8.1	5.0	2.2	4.7	3.8	5.9	6.6
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात*	19.6	17.5	19.8	18.1	17.0	15.2	15.0	16.8	19.6	13.2
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	9.5	30.5	8.5	13.2	16.4	18.9	13.9	14.5	17.0	16.3
	जीएसटी ई-वे बिल (राज्यांतरिक)	12.4	30.0	22.7	14.2	17.9	21.1	15.8	17.3	18.9	16.4
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतरराज्यीय)	4.9	31.2	-16.2	11.4	13.8	15.0	10.7	9.6	13.6	16.3
	होटल अधिभोग दर@	61.0	62.5	63.0	70.0	66.6	72.5	64.4	62.3	60.3	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	18.3	14.8	15.9	12.8	11.0	4.1	6.7	4.8	1.8	
	पर्यटकों का आगमन	17.5	19.8	16.8	7.8	10.4	15.8	8.0	7.7	0.3	
निर्माण	स्टील की खपत	18.6	13.6	15.4	6.5	3.8	12.7	11.2	11.5	13.1	19.1
	सीमेंट उत्पादन	4.7	17.0	-4.8	3.8	4.0	7.8	10.6	-0.5	-0.8	
पीएमआई सूचकांक#	सेवाएं	61.0	58.4	56.9	59.0	61.8	60.6	61.2	60.8	60.2	60.5



&lt;&lt; संकुचन ----- विस्तार &gt;&gt;

नोट: #: डेटा स्तरों में है। \*: जून 2024 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत पर आधारित है। @: डेटा दर में है, साल-दर-साल वृद्धि दर में नहीं। जुलाई-2021 से अब तक की अवधि के लिए प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप का निर्माण किया गया है।

स्रोत: एसआईएम; रेल मंत्रालय: ट्रैक्टर और मशीनीकरण एसोसिएशन; भारतीय बंदरगाह संघ: आर्थिक सलाहकार कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण: एचवीएस एनारॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएचएस मार्किट।

जून 2024 में सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक आर्थिक गतिविधि के लचीलेपन को दर्शाते हैं (सारणी III.1)।

## मुद्रास्फीति

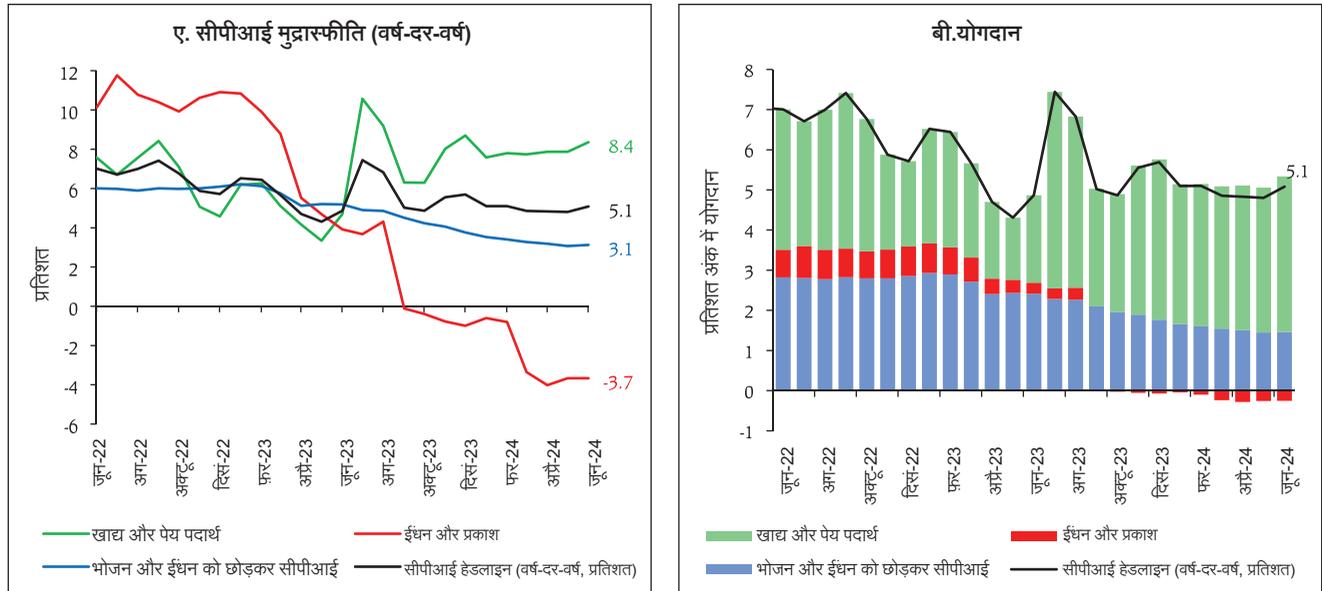
अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)<sup>20</sup> में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों द्वारा मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, मई में 4.8 प्रतिशत से बढ़कर जून 2024 में 5.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट III.26)। मुद्रास्फीति में 28 बीपीएस की वृद्धि 133

बीपीएस की सकारात्मक गति से हुई, जो 106 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभाव से कहीं अधिक है। खाद्य में 269 बीपीएस, ईंधन में 6 बीपीएस और कोर गुप में 12 बीपीएस (यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर) की सकारात्मक गति के कारण समग्र सीपीआई में माह-दर-माह वृद्धि हुई थी।

खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) मई के 7.9 प्रतिशत से बढ़कर जून में 8.4 प्रतिशत हो गई, क्योंकि सकारात्मक मूल्य गति अनुकूल आधार प्रभाव से कहीं अधिक है। उप-

<sup>20</sup> 12 जुलाई, 2024 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट III.26: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और चालक

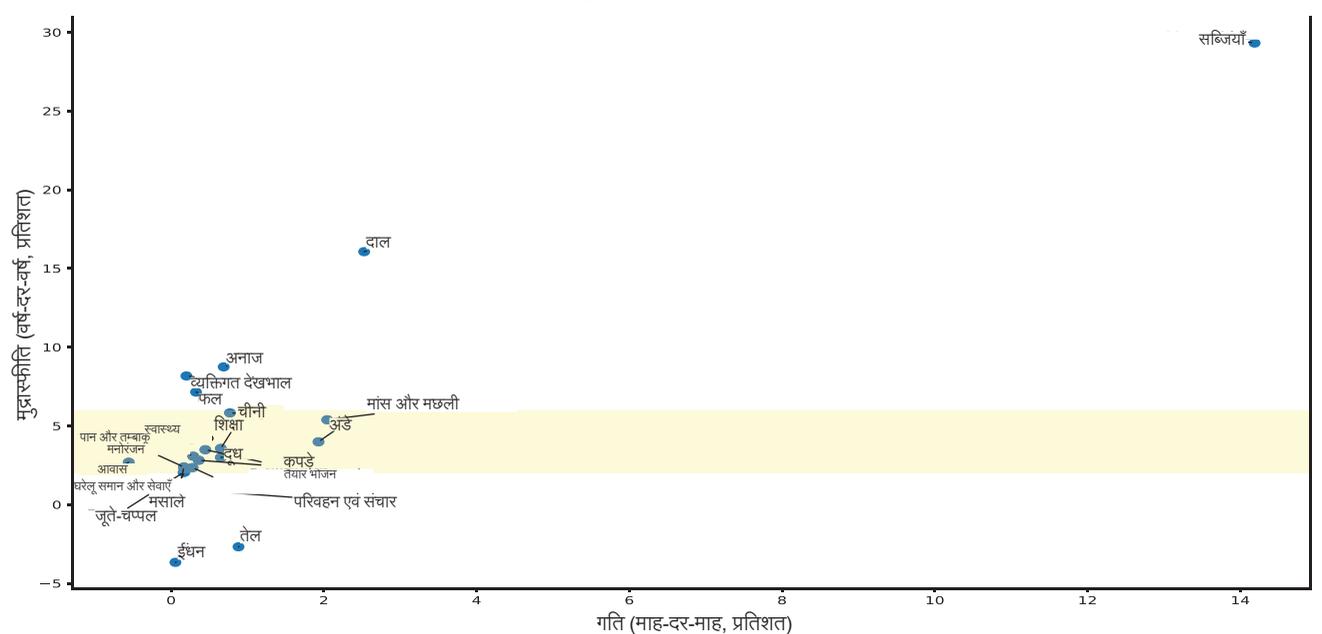


स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

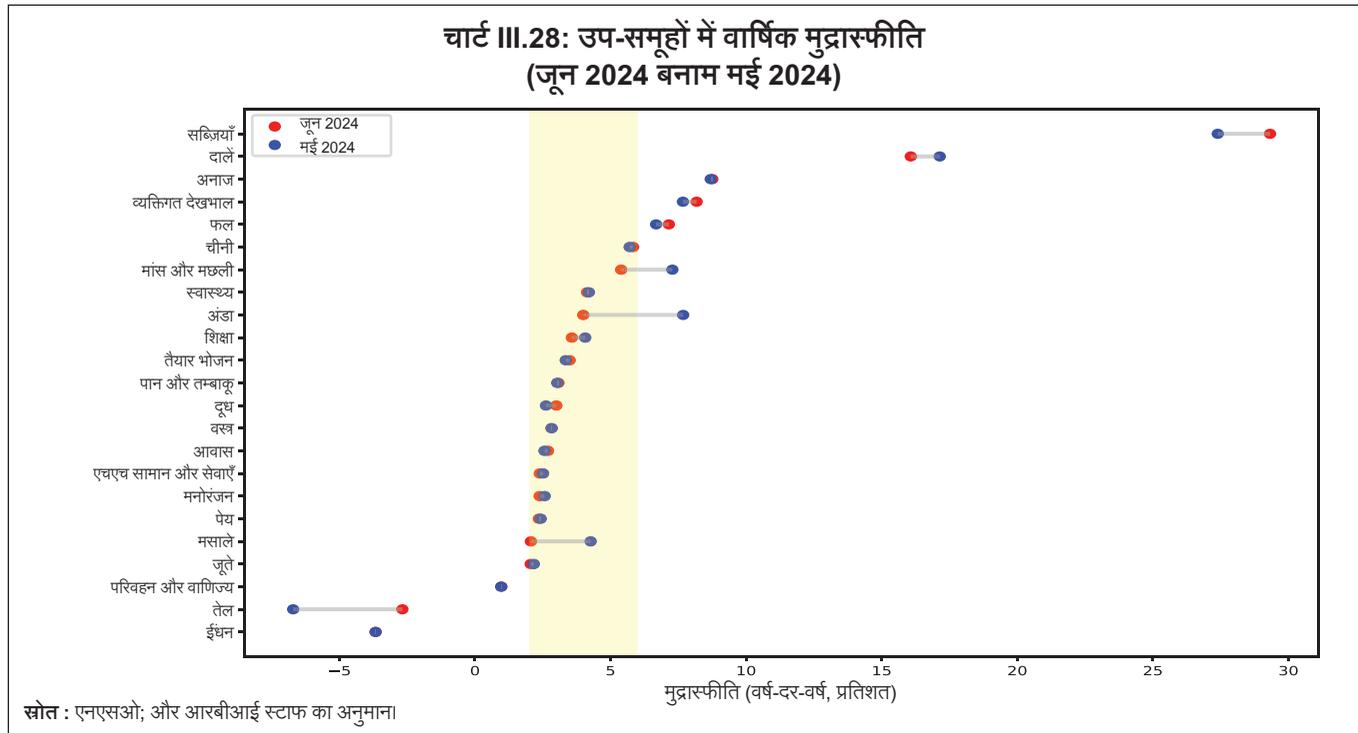
समूहों के संदर्भ में, अनाज, दूध और उत्पाद, फल, चीनी और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि मांस और मछली, अंडे, दालें और मसालों में नरमी दर्ज की गई। सब्जियों की

कीमतों में वर्ष-दर-वर्ष दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। खाद्य तेलों और वसा में अपस्फीति की कम दर दर्ज की गई (चार्ट III.27)।

चार्ट III.27: उप-समूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (माह-दर-माह)

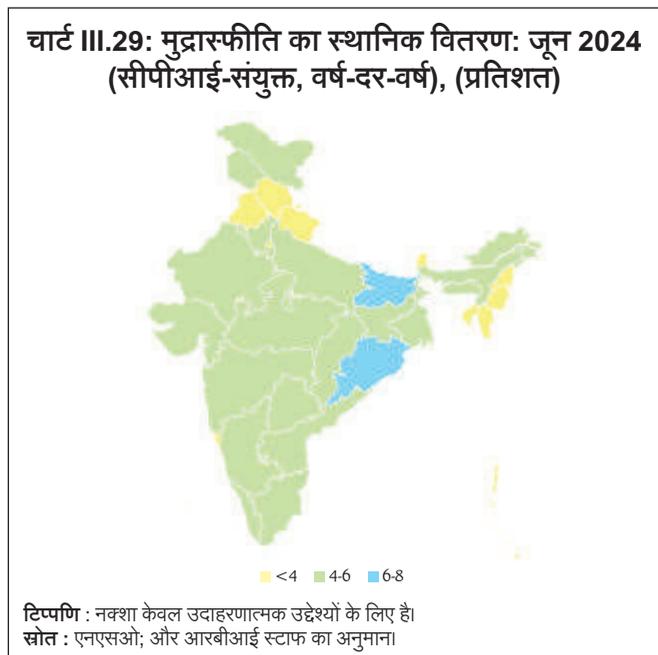


स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



जून में ईंधन और प्रकाश अपस्फीति (-)3.7 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। जबकि केरोसीन और बिजली की कीमतों में कम वृद्धि हुई, एलपीजी की कीमतों में अपस्फीति जारी रही।

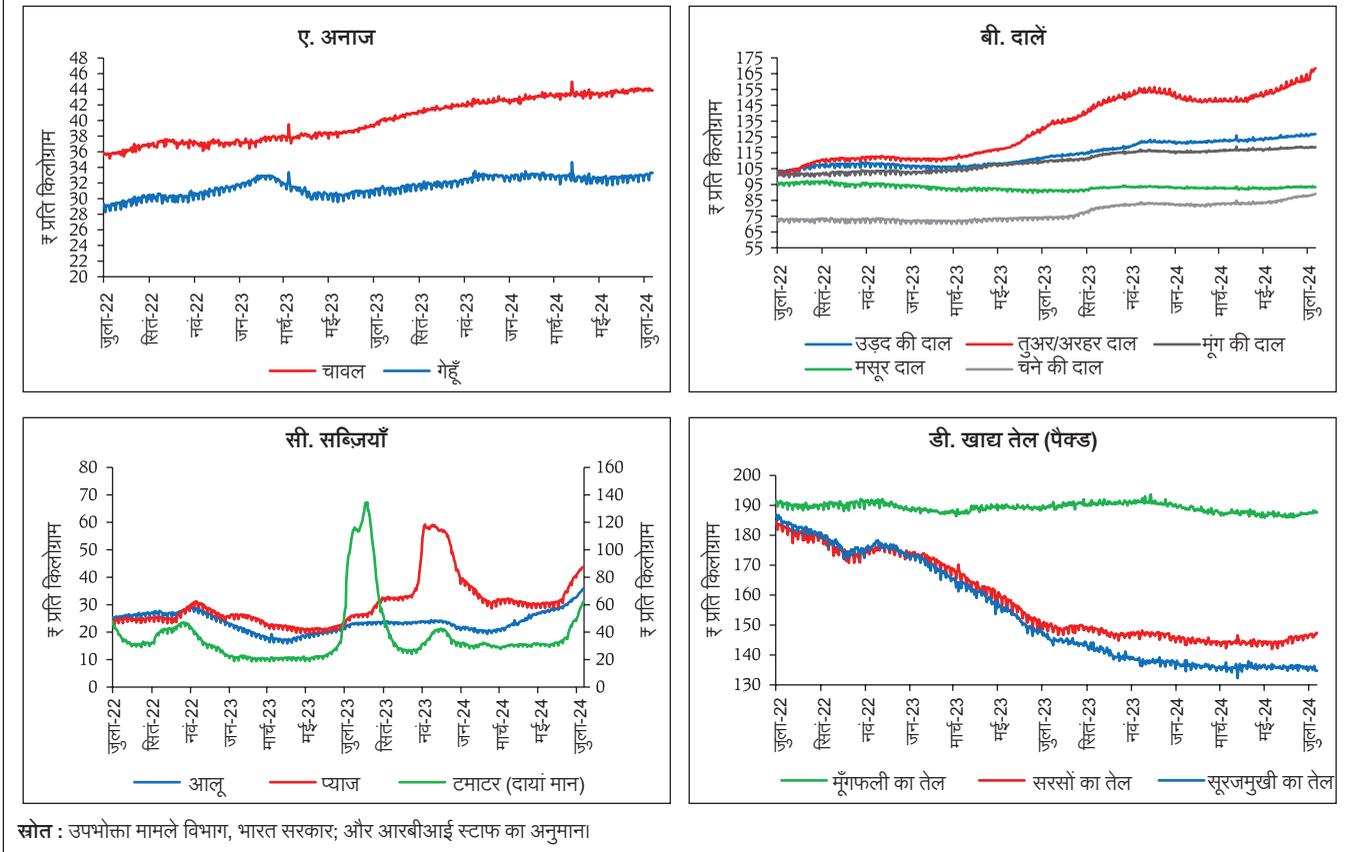
जून में मुख्य मुद्रास्फीति 3.1 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। उप-समूहों के संदर्भ में, पान, तम्बाकू और नशीले पदार्थों, आवास और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभावों में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि घरेलू वस्तुओं और सेवाओं, स्वास्थ्य, मनोरंजन और आमोद और शिक्षा के संबंध में इसमें नरमी दर्ज की गई और कपड़े व जूते, तथा परिवहन और संचार में यह स्थिर रही। (चार्ट III.28)।



क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण मुद्रास्फीति जून 2024 में 5.7 प्रतिशत थी, जो 4.4 प्रतिशत की शहरी मुद्रास्फीति से अधिक थी। अधिकांश राज्यों में मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत से कम दर्ज की गई (चार्ट III.29)।

जुलाई (12 तारीख तक) के अब तक के उच्च आवृत्ति खाद्य मूल्य डेटा से पता चलता है कि अनाज की कीमतों में हुई वृद्धि, मुख्य रूप से गेहूं के कारण हुई है। दालों की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण चना और अरहर/तूरार है। खाद्य तेल विशेषकर, सरसों और मूंगफली तेल की कीमतों में भी वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट III.30)।

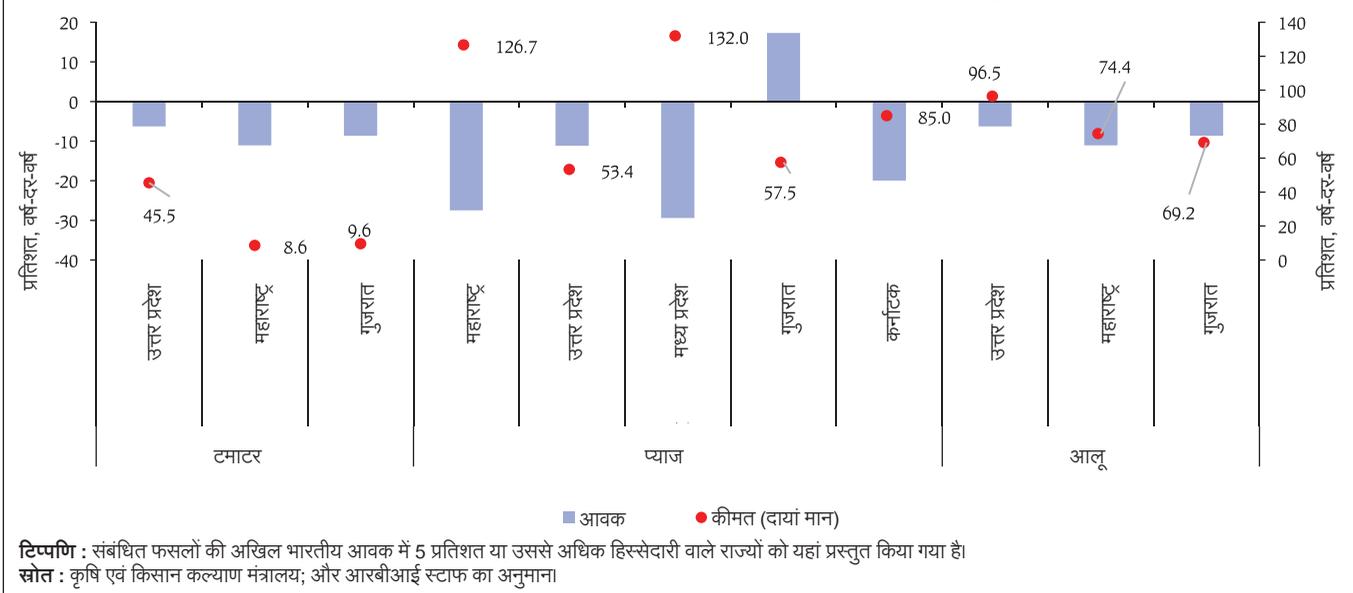
चार्ट III.30: डीसीए आवश्यक वस्तु कीमतें



प्रमुख सब्जियों में से, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में जुलाई में अब तक क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई है (चार्ट III.30सी)।

यह मुख्य रूप से आवक में उल्लेखनीय गिरावट के कारण हुआ है, जो संभवतः प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों में लू और बेमौसम

चार्ट III.31: शीर्ष सब्जियों की मंडी कीमतों में उछाल (01 अप्रैल - 03 जुलाई, 2024)



## सारणी III.2 पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

मदें	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		जुलाई-23	जून-24	जुलाई-24 <sup>^</sup>	जून-24	जुलाई-24 <sup>^</sup>
पेट्रोल	₹/लीटर	102.92	100.89	100.97	0.0	0.1
डीजल	₹/लीटर	92.72	90.68	90.42	0.0	-0.3
केरोसीन (सब्सिडीकृत)	₹/लीटर	44.23	46.61	46.65	-6.8	0.1
एलपीजी (गैर-सब्सिडीकृत)	₹/सिलेंडर	1113.25	813.25	813.25	0.0	0.0

<sup>^</sup>: 1-12 जुलाई, 2024 की अवधि के लिए।

नोट: केरोसीन के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की औसत कीमतों को दर्शाती हैं। केरोसीन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाले मूल्यों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण कक्ष (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बारिश<sup>21</sup> जैसी मौसम संबंधी विसंगतियों के प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट III.31)।

मुंबई और कोलकाता में कीमतों में बदलाव के कारण, जुलाई में अब तक (12 तारीख तक) पेट्रोल की खुदरा बिक्री कीमतों में वृद्धि हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में मामूली गिरावट आई है।<sup>22</sup> केरोसीन की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि एलपीजी की कीमतों को अपरिवर्तित रखा गया है (सारणी III.2)।

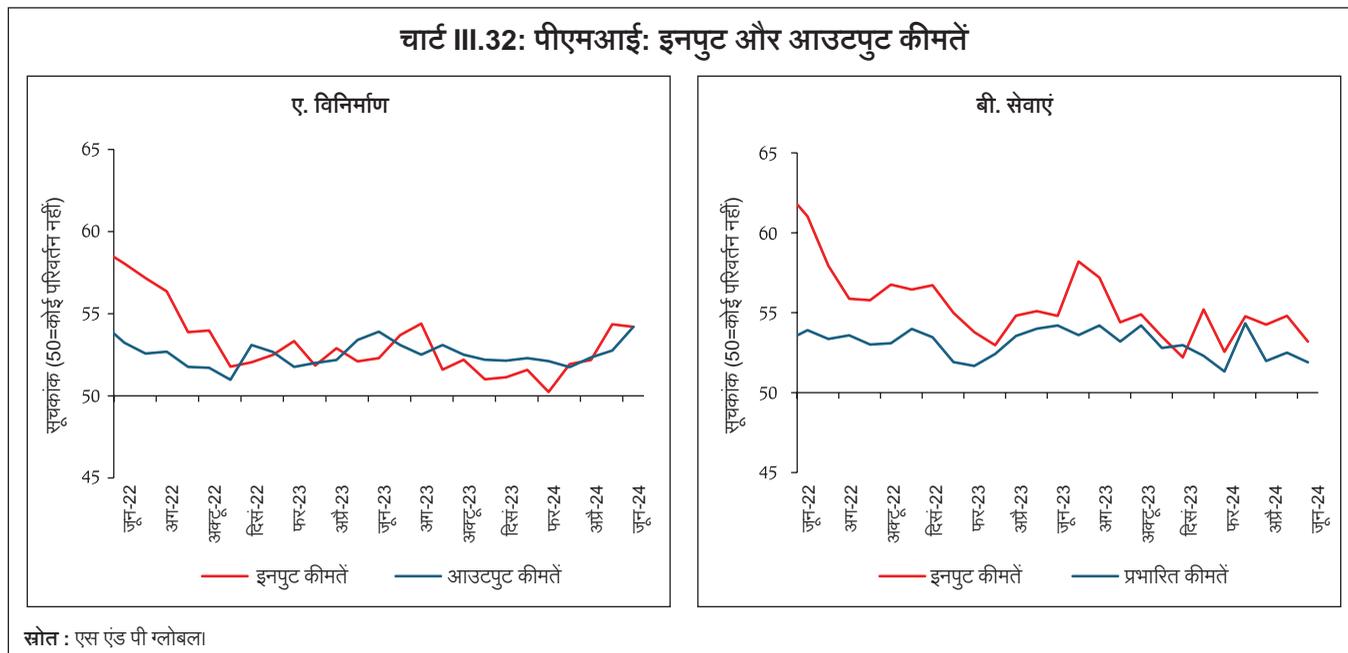
जून 2024 के पीएमआई ने विनिर्माण और सेवा फर्मों में इनपुट लागत में मध्यम वृद्धि का संकेत दिया। दूसरी ओर,

विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री कीमतें बढ़ीं, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए बिक्री कीमतें कम हो गईं (चार्ट III.32)।

## IV. वित्तीय स्थितियाँ

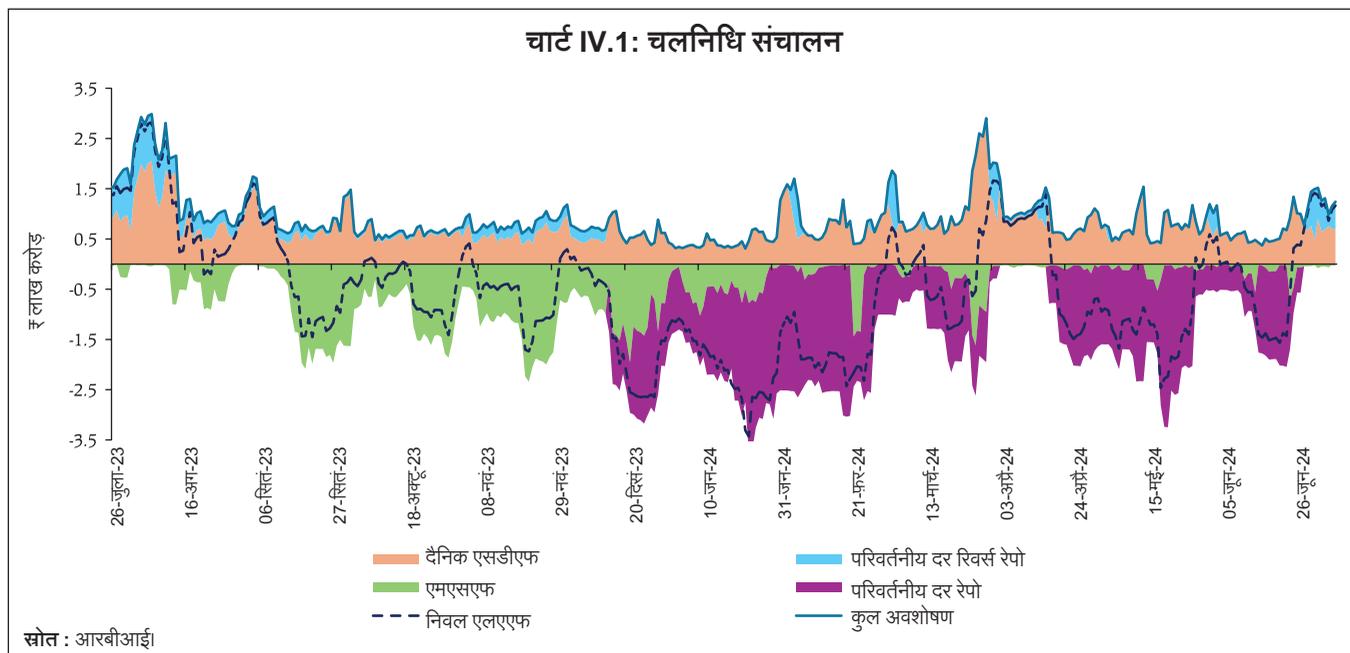
जून 2024 की शुरुआत में अधिशेष में रहने के बाद, सुस्त सरकारी खर्च के बीच अग्रिम कर भुगतान और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित बहिर्वाह के कारण इस महीने की दूसरी छमाही में प्रणालीगत चलनिधि घाटे में बदल गई। महीने के अंत में, सरकारी नकदी शेष में सामान्य गिरावट के साथ यह 28 जून, 2024 से फिर से अधिशेष में बदल गया। इन परिवर्तनों को दर्शाते हुए, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत

चार्ट III.32: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



<sup>21</sup> <https://www.thehindu.com/incoming/unseasonal-rain-in-maharashtra-leads-to-spike-in-agrarian-distress/article68190468.ece>

<sup>22</sup> राज्य सरकारों द्वारा करों में परिवर्तन के कारण।



दैनिक नवल अंतर्वेशन 16 जून - 10 जुलाई, 2024 के दौरान औसतन ₹0.12 लाख करोड़ था, जबकि 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान यह ₹0.73 लाख करोड़ था (चार्ट IV.1)। रिजर्व बैंक ने 16-28 जून, 2024 के दौरान 3 से 6 दिनों की परिपक्वता के चार फाइन-ट्युनिंग परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) संचालन के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि डाली, जिससे प्रणाली की चलनिधि बढ़ाने के लिए संचयी रूप से ₹2.75 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई। जैसा कि इन परिचालनों के लिए उच्च बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है, निधि की मांग अत्यधिक थी। रिजर्व बैंक ने अपने मुख्य परिचालनों के बजाय, 28 जून को 3-दिवसीय वीआरआर नीलामी आयोजित की क्योंकि उसे तरलता की स्थिति में बदलाव और उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद थी। जून के अंत और जुलाई (10 जुलाई तक) में चलनिधि की स्थिति अधिशेष में बदल गई। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने जुलाई में रातोंरात 4 दिनों की परिपक्वता की आठ परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआर) नीलामी आयोजित की, जिससे प्रणाली से संचयी रूप से ₹2.17 लाख करोड़ अवशोषित हुए।

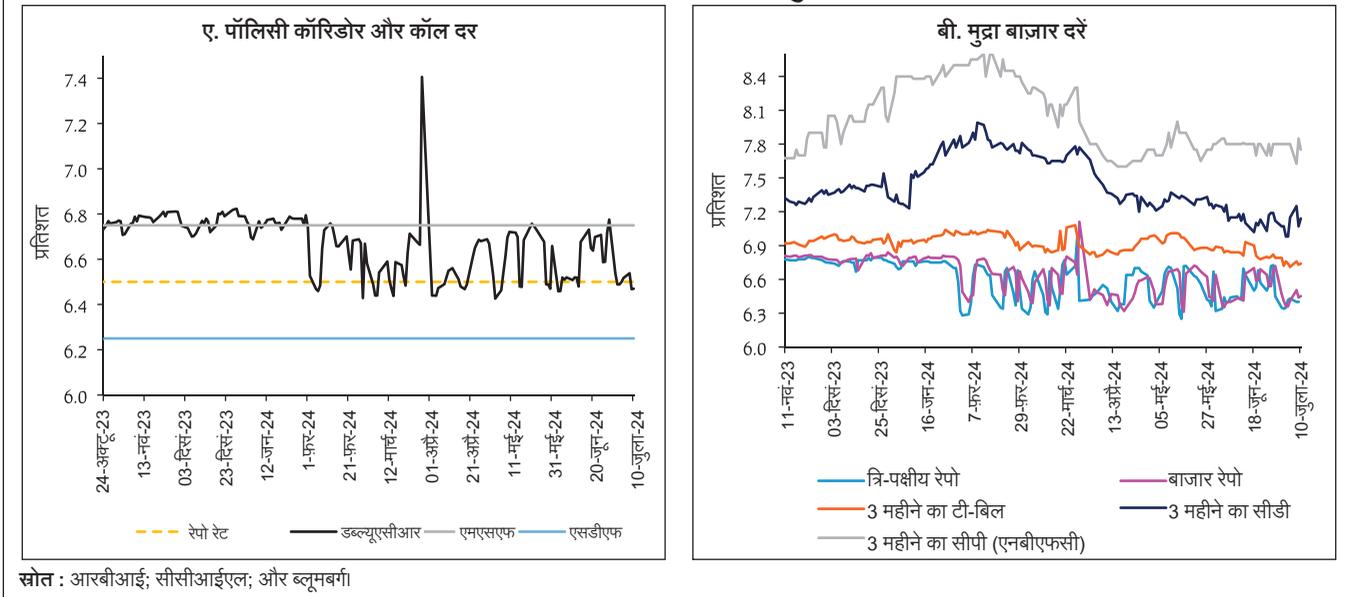
16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत उधारी बढ़कर ₹12,440 करोड़ दैनिक औसत हो गई, जो 16 मई से 15 जून, 2024 के दौरान ₹10,910 करोड़ थी। 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान

औसत कुल अवशोषण ₹0.88 लाख करोड़ था। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत निधि का विनियोजन 16 मई से 15 जून, 2024 के दौरान 94 प्रतिशत की तुलना में 76 प्रतिशत था। शेष राशि फाइन ट्युनिंग - वीआरआर संचालन के माध्यम से जुटाई गई थी।

मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) मोटे तौर पर एलएएफ कॉरिडोर के बीच 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान औसतन 6.59 प्रतिशत रहा, जबकि 16 मई - 15 जून 2024 के दौरान यह 6.57 प्रतिशत था (चार्ट IV.2ए)। संपार्श्विक खंड में त्रिपक्षीय और बाजार रेपो दरें डब्ल्यूएसीआर के साथ मिलकर आगे बढ़ीं। औसत आधार पर, त्रिपक्षीय रेपो दर पॉलिसी रेपो दर के समान थी और बाजार रेपो दर 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान पॉलिसी रेपो दर से 4 बीपीएस ऊपर कारोबार कर रही थी (चार्ट IV.2बी)।

सावधि मुद्रा बाजार खंड में, 3 महीने के खजाना बिल (टी-बिल) पर यील्ड और जमा प्रमाणपत्र (सीडी) पर दरें कम हुईं, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए वाणिज्यिक पत्र (सीपी) पर 16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान यह स्थिर रही। जून 2024 में आपूर्ति में कमी के कारण, 3 महीने के टी-बिल पर यील्ड कम हो गई। मुद्रा बाजार में औसत जोखिम प्रीमियम (3 महीने का सीपी से 91 दिन का टी-बिल

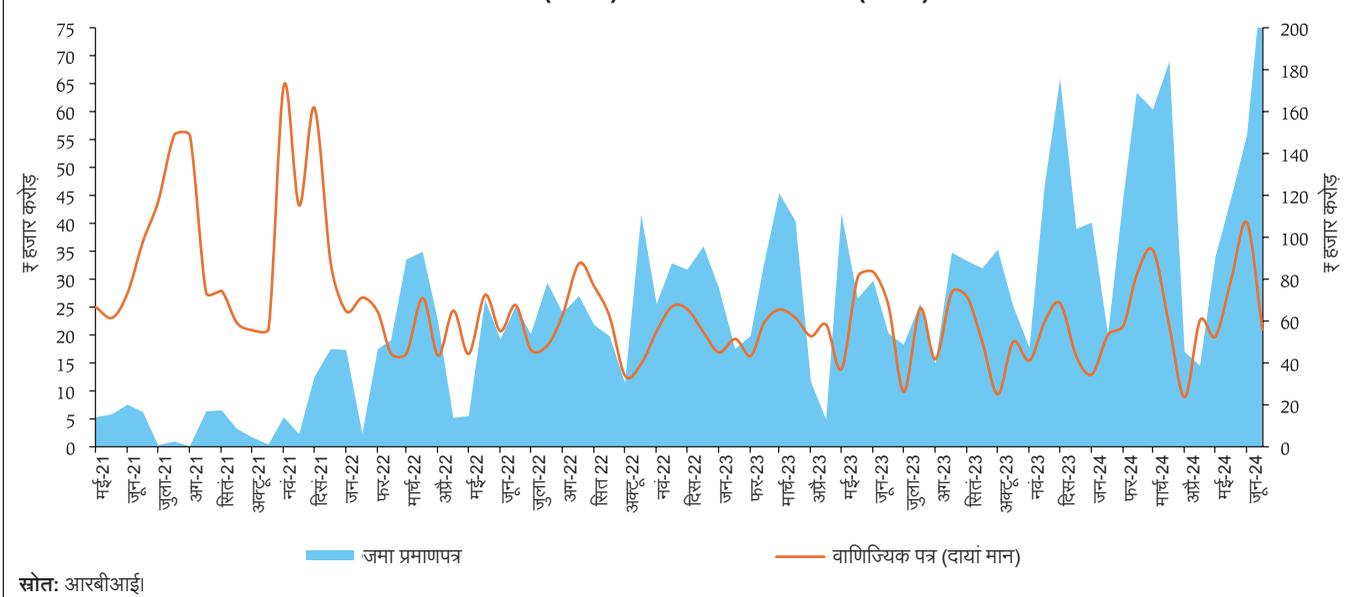
**चार्ट IV.2: पॉलिसी कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें**

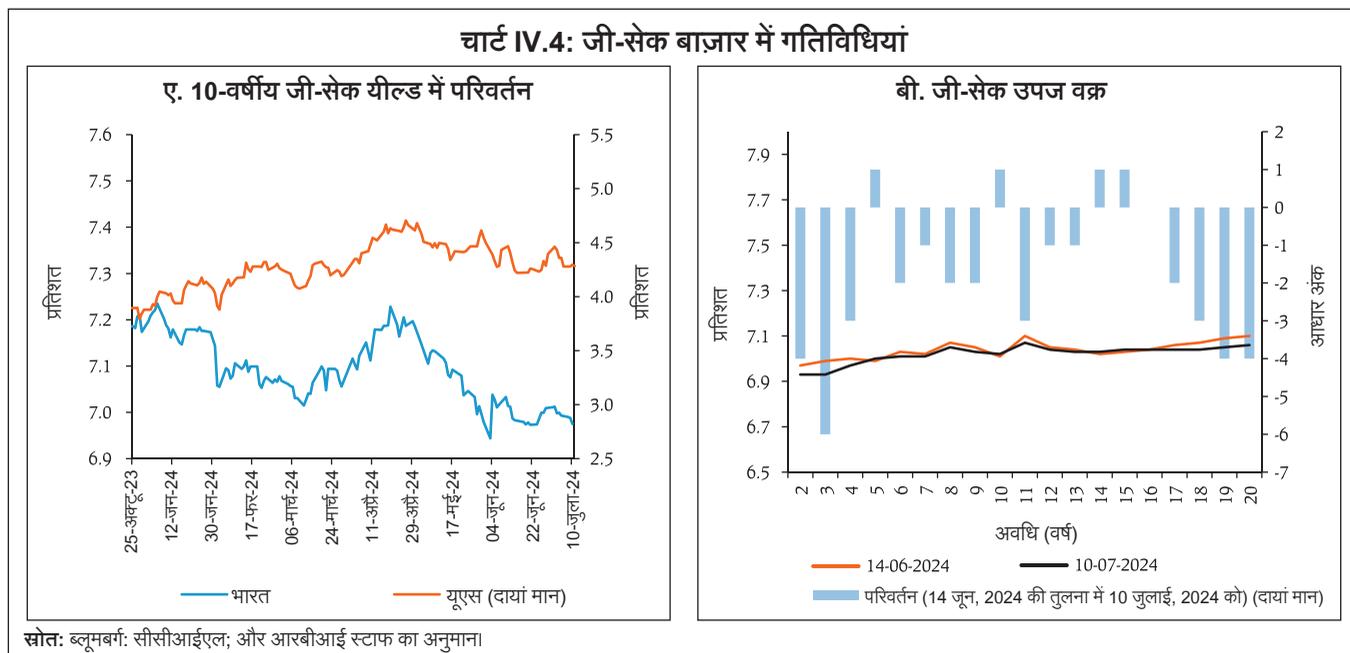


घटाकर) 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान के 92 बीपीएस से बढ़कर, 16 जून - 10 जुलाई, 2024 के दौरान 99 बीपीएस हो गया। इसके अलावा, सावधि स्प्रेड (10 साल की जी-सेक यील्ड से 91 दिन की टी-बिल दर घटाकर) 16 मई - 15 जून, 2024 के दौरान के 14 बीपीएस से 16 जून -10 जुलाई, 2024 के दौरान 20 बीपीएस तक बढ़ गई।

अप्रैल में सुस्ती के बाद, मई-जून में प्राथमिक बाज़ार में, सीडी जारीकरण से धन जुटाने में गति आई। बैंकों ने 2024-25 (28 जून तक) के दौरान ₹2.65 लाख करोड़ की सीडी जारी की, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में जारी ₹1.45 लाख करोड़ से अधिक है (चार्ट IV.3)। जून में अल्पकालिक दरों में गिरावट ने बैंकों को निधीयन अंतराल को पूरा करने हेतु सीडी जारी

**चार्ट IV.3: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम**





करने के लिए प्रेरित किया। 2024-25 (30 जून तक) के दौरान ₹3.8 लाख करोड़ के सीपी का निर्गम पिछले वर्ष की इसी अवधि में संबंधित खंड की गतिविधि के समान था।

16 जून से 10 जुलाई, 2024 के दौरान 10-वर्षीय भारतीय बेंचमार्क (7.10 जीएस 2034) सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) पर यील्ड 6.97-7.01 प्रतिशत के दायरे में रहा (चार्ट IV.4ए)। संपूर्ण अवधि संरचना में जी-सेक यील्ड मोटे तौर पर स्थिर रही (चार्ट IV.4बी)। 28 जून, 2024 को जेपी मॉर्गन के सरकारी बॉन्ड इंडेक्स-इमर्जिंग मार्केट्स (जीबीआई-ईएम) में भारत का समावेश हुआ है। 10 महीने की अवधि में, भारतीय बॉन्ड का भार हर महीने 1 प्रतिशत बढ़ जाएगा, जो अंततः मार्च 2025 तक 10 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।

16 जून से 9 जुलाई, 2024 के दौरान परिपक्वता प्रोफाइल और रेटिंग स्पेक्ट्रम में कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड और जोखिम प्रीमियम मजबूत हो गया (सारणी IV.1)। 16 जून से 10 जुलाई के दौरान 3 साल के एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर यील्ड 7.65-7.75 फीसदी के दायरे में रही और 5 साल के एए रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड पर यील्ड 7.62-7.74 फीसदी के दायरे में रही<sup>23</sup>

<sup>23</sup> स्रोत: ब्लूमबर्ग।

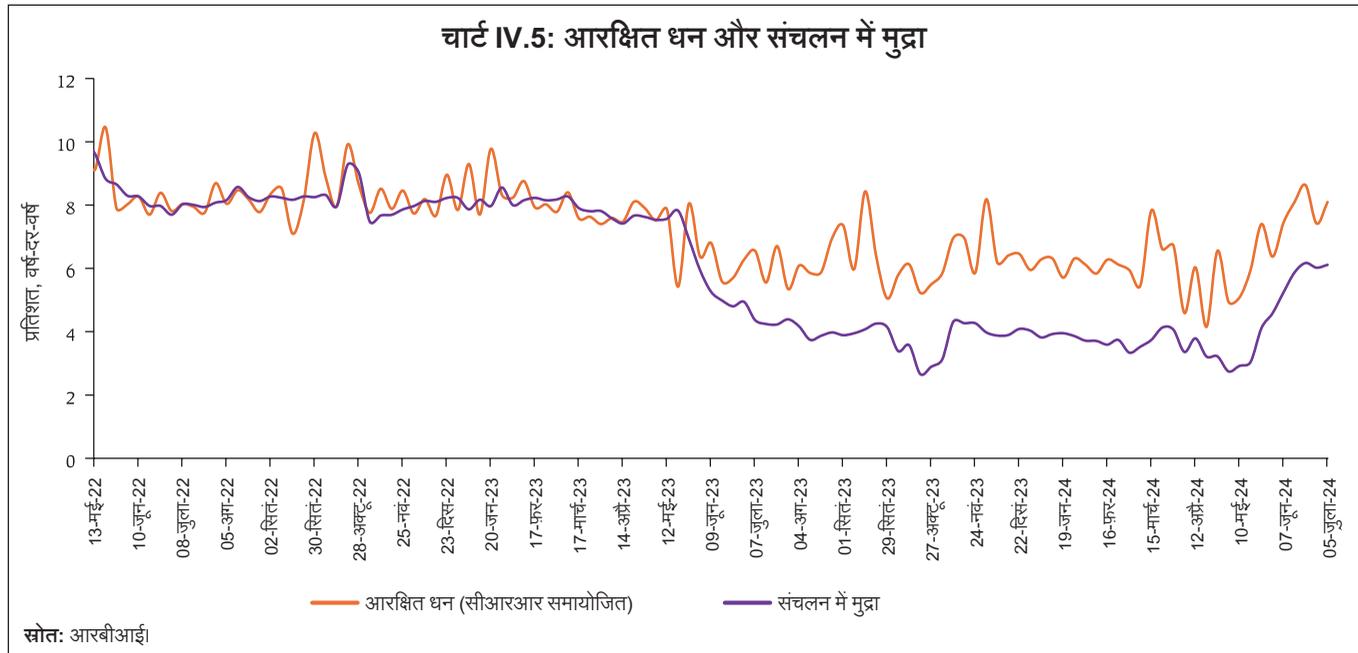
नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर, आरक्षित मुद्रा (आरएम) ने 5 जुलाई, 2024 को 8.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि (एक साल पहले 6.6 प्रतिशत) दर्ज की [चार्ट IV .5]। आरएम का सबसे बड़ा घटक, संचलन में मुद्रा (सीआईसी) 17 मई 2024 के 3.0 प्रतिशत से 5 जुलाई 2024 को 6.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़ गई, यह ₹2000 के बैंकनोटों<sup>24</sup> को संचलन से वापिस

**सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड**

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार अंक)		
	16 मई, 2024-14 जून, 2024	16 जून, 2024-9 जुलाई, 2024	अंतर	16 मई, 2024-14 जून, 2024	16 जून, 2024-9 जुलाई, 2024	अंतर
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
<b>कॉर्पोरेट बॉन्ड</b>						
(i) एए (1 वर्ष)	7.84	7.85	1	71	79	8
(ii) एए (3-वर्ष)	7.90	8.08	18	74	100	26
(iii) एए (5-वर्ष)	7.83	7.85	2	66	71	5
(iv) एए (3-वर्षीय)	8.55	8.79	24	139	170	31
(v) बीबीबी- (3-वर्ष)	12.15	12.42	27	499	533	34

नोट: यील्ड और स्प्रेड की गणना संबंधित अवधि के औसत के रूप में की जाती है।  
स्रोत: फिमडा।

<sup>24</sup> 19 मई, 2023 को घोषित।

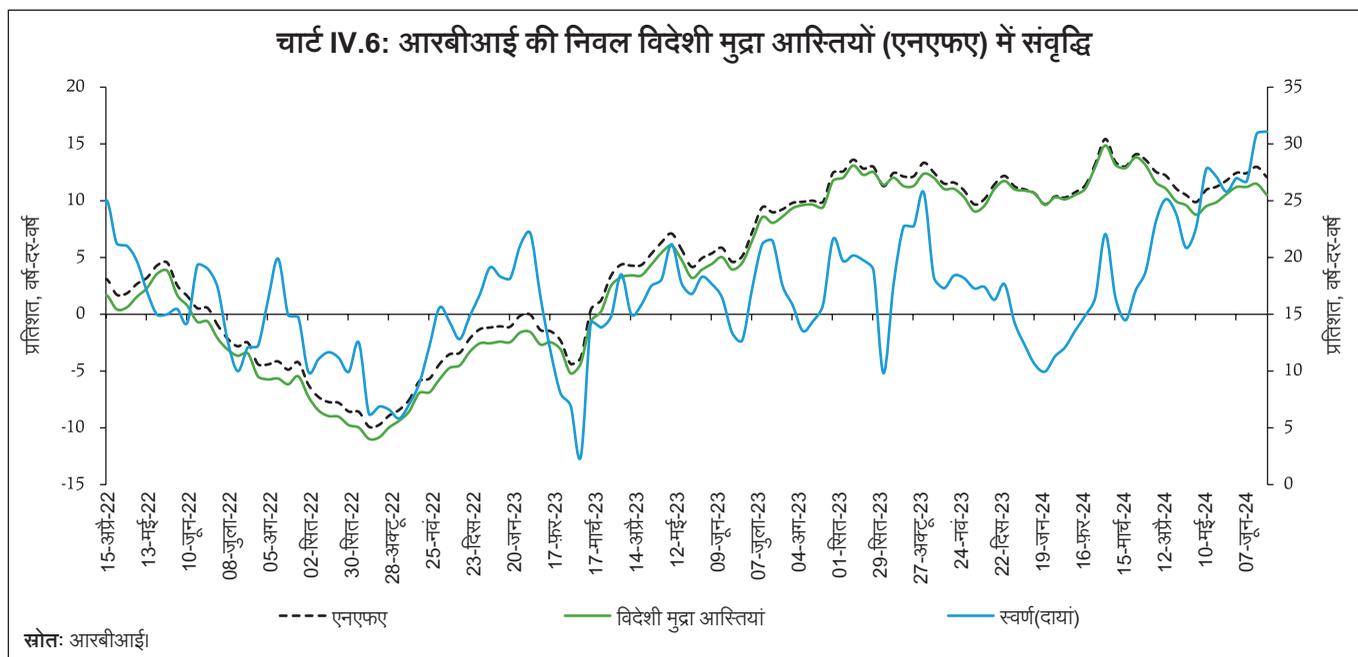


लेने के आधार प्रभाव के कारण हुआ जिससे 97.87 प्रतिशत बैंकनोट ज्यादातर जमा के रूप में बैंकिंग प्रणाली में वापस (28 जून, 2024 तक) आ गए हैं।

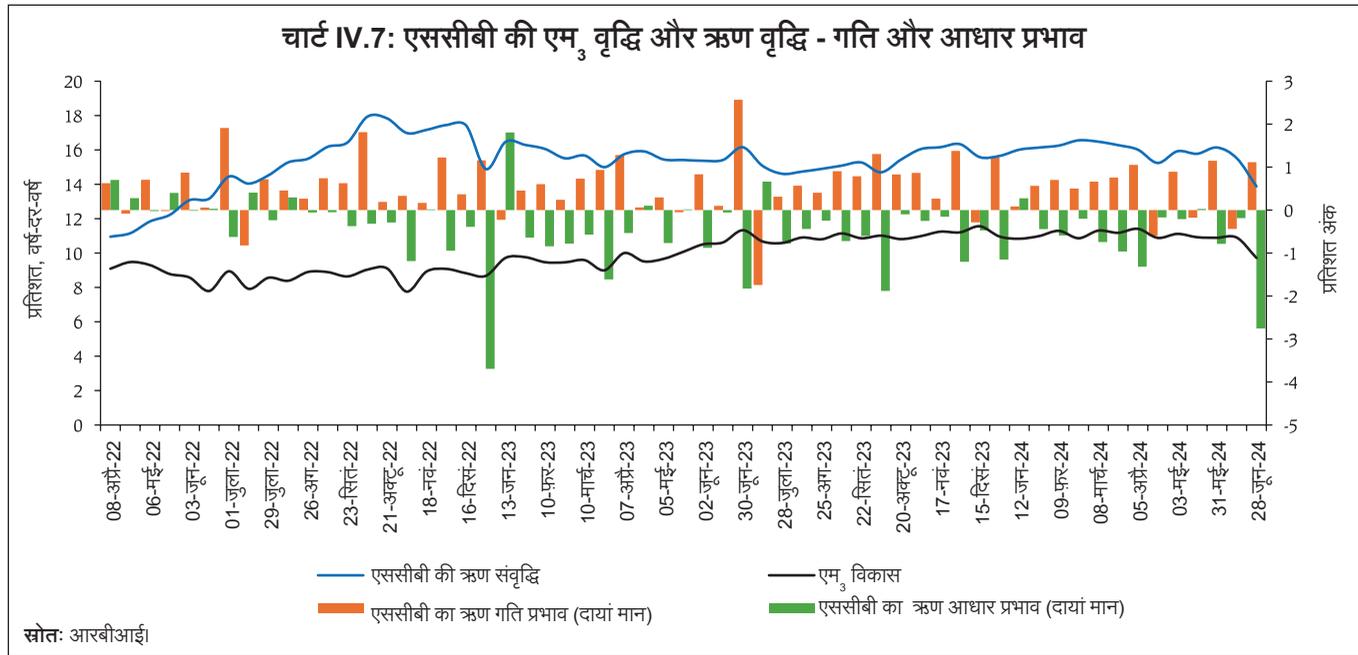
स्रोत पक्ष (आस्ति) को देखे तो, आरएम में रिज़र्व बैंक की निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) और निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) शामिल हैं। 5 जुलाई, 2024 को विदेशी मुद्रा आस्तियों

(एनएफए के 90 प्रतिशत से अधिक के लिए लेखांकन) में 10.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की गई। एनएफए के एक घटक स्वर्ण में 31.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मार्च 2022 से दर्ज की गई सबसे अधिक वृद्धि है (चार्ट IV.6)।

28 जून, 2024 को मुद्रा आपूर्ति (एम<sub>3</sub>) में 9.7 प्रतिशत की (वर्ष-दर-वर्ष) वृद्धि (एक वर्ष पहले 11.3 प्रतिशत) हुई<sup>25</sup> एम3



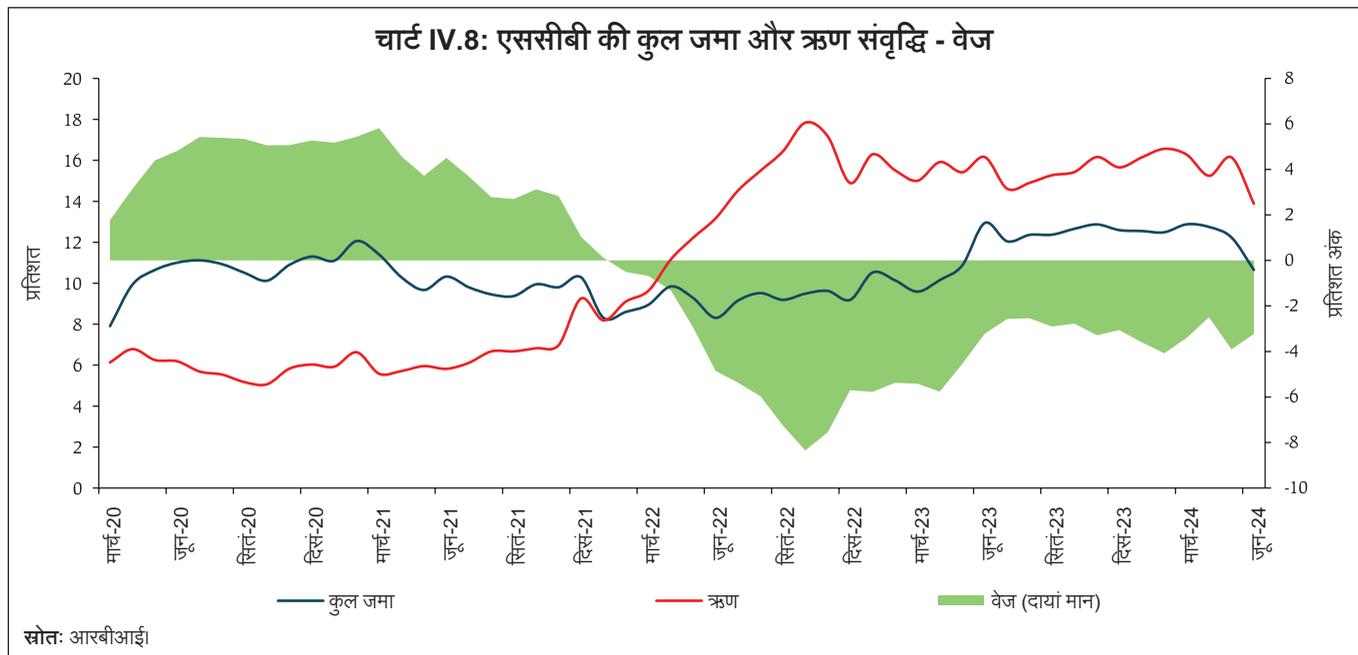
<sup>25</sup> किसी गैर-बैंक के बैंक में विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।



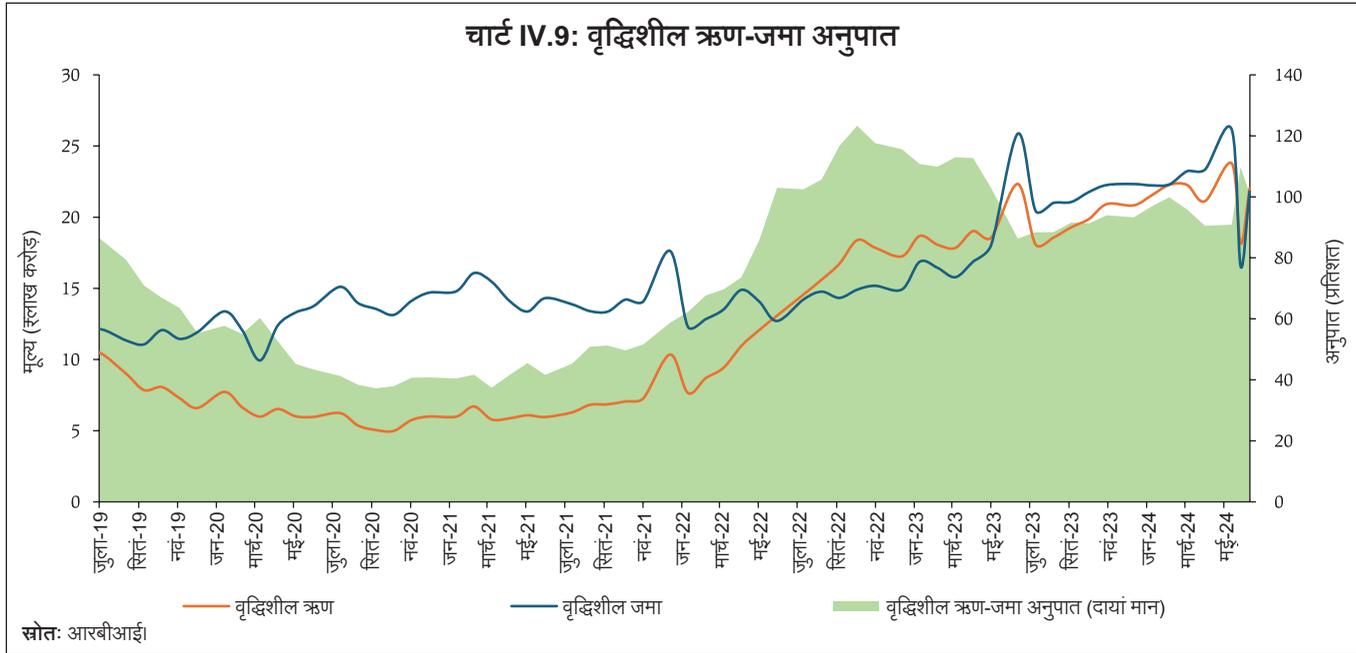
का सबसे बड़ा घटक - बैंकों के पास की कुल जमाराशि में 10.2 प्रतिशत से वृद्धि (एक साल पहले 12.4 प्रतिशत) हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि पिछले पखवाड़े में 15.5 प्रतिशत से घटकर 28 जून, 2024 को 13.9 प्रतिशत (एक साल पहले 16.2 प्रतिशत) हो गई [चार्ट IV.7]।

एससीबी की जमा वृद्धि (विलयन के प्रभाव को छोड़कर<sup>26</sup>) जिसमें ₹2000 बैंक नोटों की वापसी के मद्देनजर वृद्धि दर्ज की गई, वह अप्रैल 2023 से दोहरे अंकों में बनी हुई है (चार्ट IV.8)।

28 जून, 2024 को प्रणालीगत स्तरीय वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 101 प्रतिशत था (चार्ट IV.9)। सीआरआर और



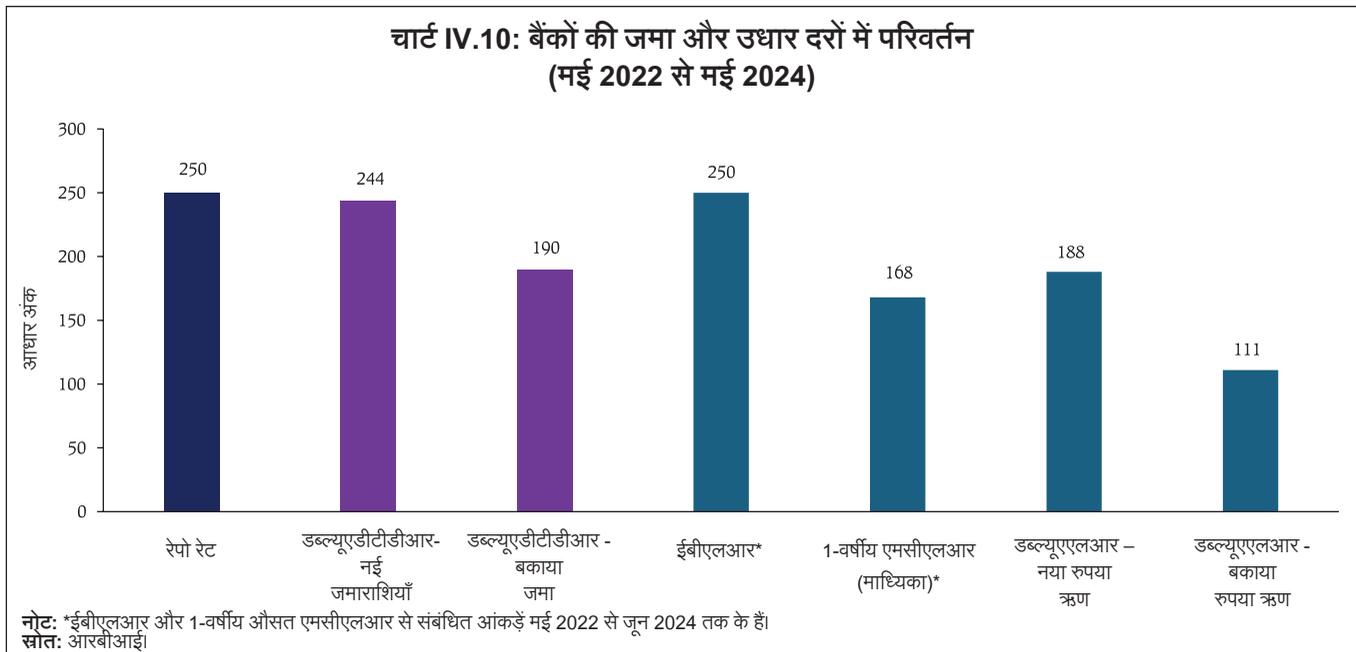
<sup>26</sup> 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी एचडीएफसी लिमिटेड का एचडीएफसी बैंक के साथ विलय।



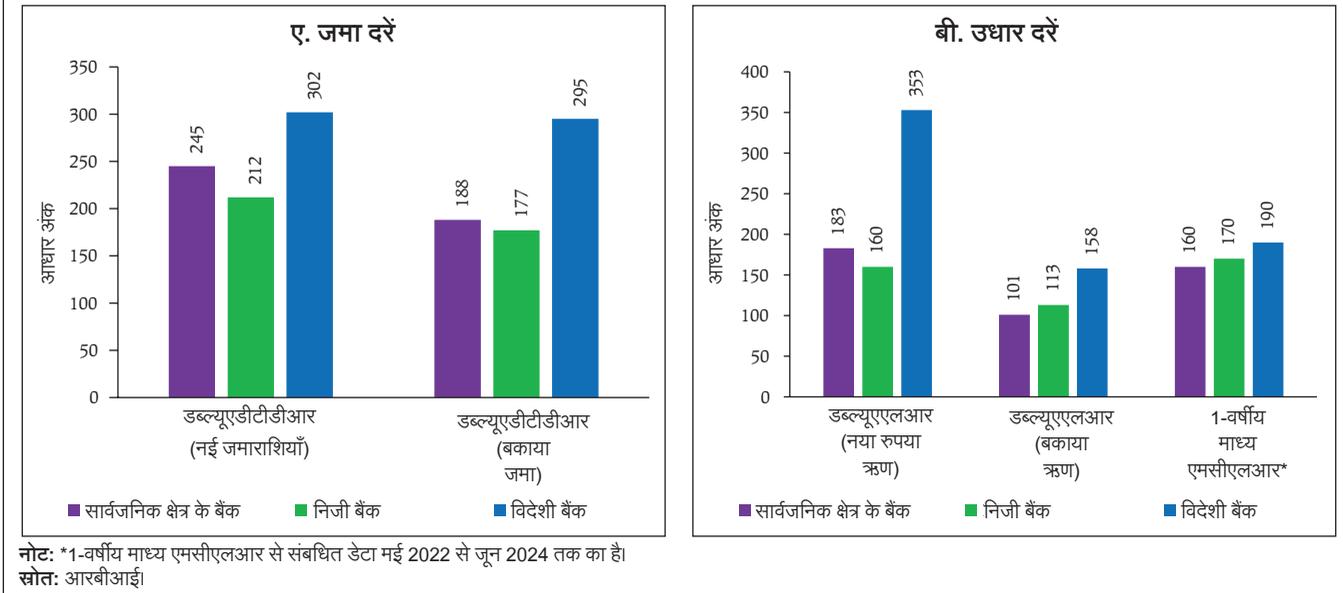
संवैधानिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के लिए क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की संवैधानिक आवश्यकताओं के साथ, 28 जून, 2024 तक लगभग 77 प्रतिशत जमा राशि ऋण विस्तार के लिए बैंकिंग प्रणाली में उपलब्ध थी। जमाराशि आधार को सीडी निर्गम से पूरक बनाया गया।

मई 2022 से नीति दर में 250 बीपीएस की बढ़ोतरी के जवाब में, एससीबी ने अपनी रेपो-लिंकड बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार

दरें (ईबीएलआर) बढ़ाते हुए संशोधित की हैं। मई 2022-जून 2024 के दौरान एससीबी की निधि-आधारित दर (एमसीएलआर) की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत बढ़कर 168 बीपीएस हो गई। नतीजतन, मई 2022 से मई 2024 के दौरान नये और बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत उधार दरें (डब्ल्यूएलआर) क्रमशः 188 बीपीएस और 111 बीपीएस बढ़ गईं। जमाराशि के मामले में, उसी अवधि के दौरान नया और बकाया जमा पर भारित औसत



**चार्ट IV.11: बैंक-समूहों में संचरण (मई 2022 से मई 2024)**



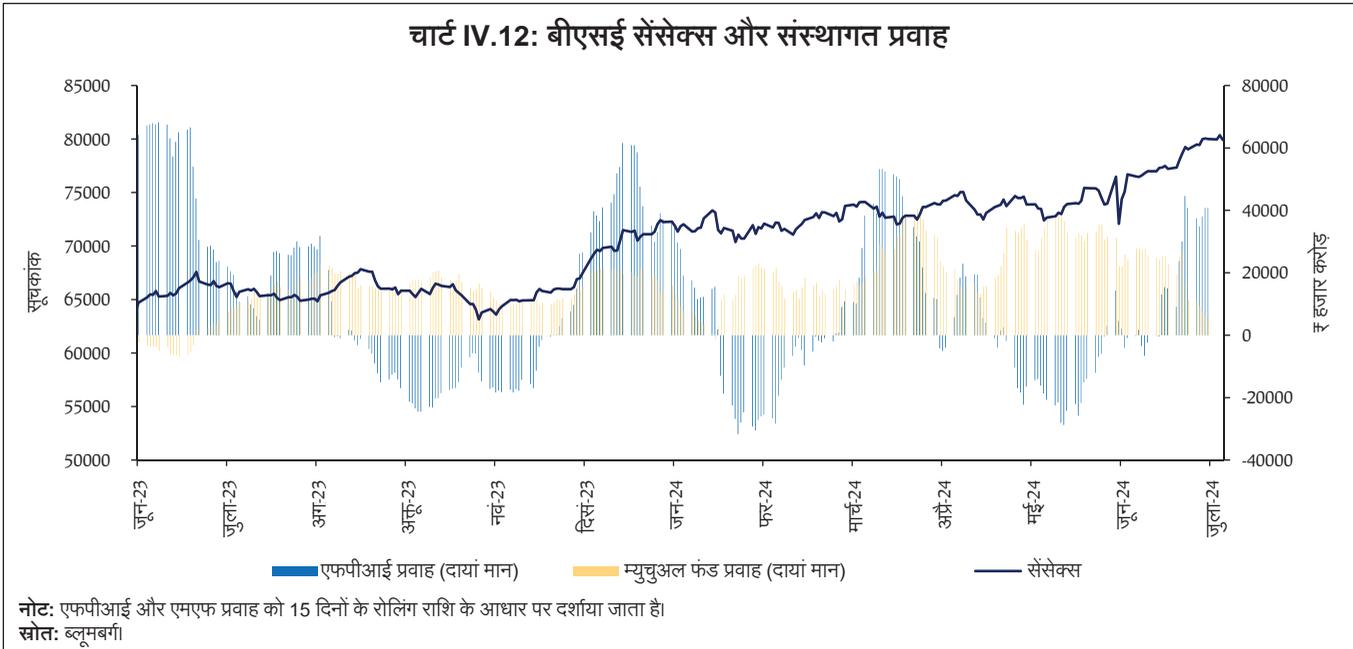
घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 244 बीपीएस और 190 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट IV.10)।

घरेलू बैंकों में, मई 2022 से मई 2024 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों को छोड़कर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में जमा और उधार दरों में वृद्धि अधिक थी (चार्ट IV.11)। पीएसबी की उधार दरें निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) की तुलना में

कम रहीं जबकि उनकी जमा दरें अधिक थीं।

भारत सरकार ने 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर दरें अपरिवर्तित रखीं। सार्वजनिक भविष्य निधि और पांच-वर्षीय आवर्ती जमा को छोड़कर विभिन्न योजनाओं से संबन्धित दरें अब फॉर्मूला-आधारित दरों के अनुरूप हैं।

**चार्ट IV.12: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह**



अब तक, जून-जुलाई 2024 के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार ने नई ऊंचाई हासिल की और बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेंसेक्स 9.1 प्रतिशत बढ़कर 16 जुलाई, 2024 को 80,717 पर बंद हुआ (चार्ट IV.12)। जून की शुरुआत में बढ़ी अस्थिरता के बाद, सूचकांकों में तेजी आई क्योंकि मई 2024 के लिए घरेलू और साथ ही अमेरिकी मुद्रास्फीति प्रिंट में उम्मीद से अधिक नरमी रहने से बाजार को राहत मिली। जून की दूसरी छमाही के दौरान, यूरोप में राजनीतिक अनिश्चितता के बीच कमजोर वैश्विक संकेतों के बावजूद, सूचकांकों में बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के शेयरों में मजबूत गति और उच्च आवृत्ति वाले घरेलू पीएमआई डेटा को प्रोत्साहित करने के बीच ऊपर की ओर रुझान में तेजी जारी रही। इसे भारत के चालू खाते के 2023-24 की चौथी तिमाही में अधिशेष में बदलने से और भी समर्थन मिला। जुलाई में, बीएसई सेंसेक्स ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के शेयरों में बढ़त और

यूएस फेड चेयरमैन की नरम टिप्पणी के समर्थन से 80,000 का नया मील का पत्थर पार कर लिया। जून की शुरुआत में तेजी से बढ़ने के बाद, भारत VIX में दूसरी छमाही के दौरान गिरावट आई और जुलाई की पहली छमाही में यह स्थिर होकर 16 जुलाई, 2024 को 14.2 पर आ गया। जून 2024 के बाद से, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के साथ-साथ म्यूचुअल फंड दोनों ने भी भारतीय इक्विटी बाजार में क्रमशः ₹48,342 और ₹34,598 करोड़ की निवल खरीदारी (12 जुलाई, 2024 तक) की।

मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों और एक उत्साही इक्विटी बाजार की पृष्ठभूमि के सामने कई लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) पर्याप्त लिस्टिंग दिवस रिटर्न के साथ खुले हैं, जिससे निवेशकों की रुचि बढ़ गई है, जैसा कि महत्वपूर्ण अत्यभिदान (बॉक्स I) में

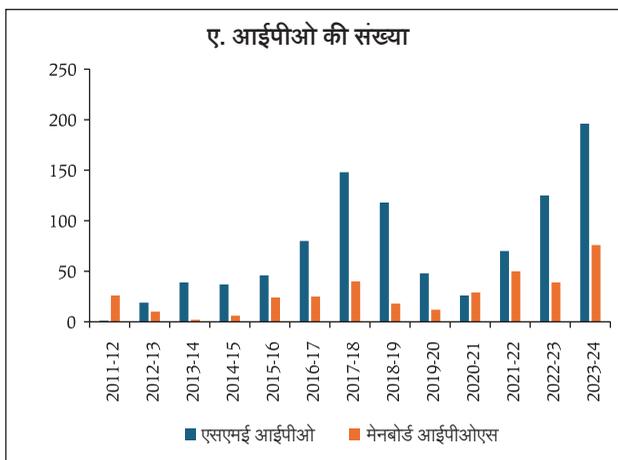
### बॉक्स I: अवमूल्यन : मेनबोर्ड आईपीओ बनाम एसएमई आईपीओ

हाल के वर्षों में एसएमई द्वारा सार्वजनिक इक्विटी जारी करने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है (चार्ट बी1.ए और बी1.बी)। परंपरागत रूप से, एसएमई अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों, एनबीएफसी और ऋण लिखतों पर निर्भर रहे हैं। बीएसई और एनएसई दोनों द्वारा एसएमई एक्सचेंजों<sup>27</sup>

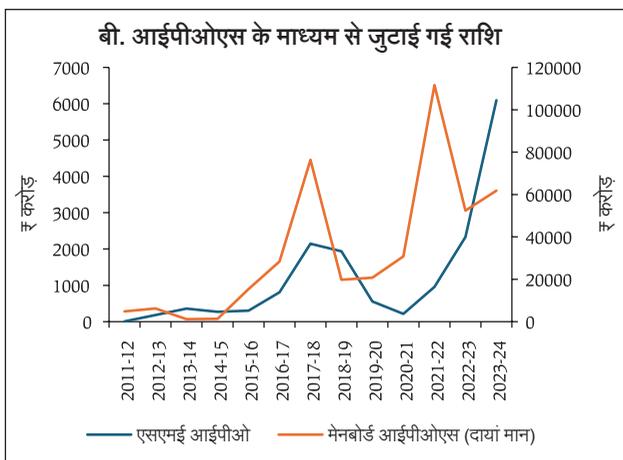
के विकास में एसएमई को धन जुटाने के लिए एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया है।

यहाँ पर निवेशकों की रुचि बढ़ी है। औसत अत्यभिदान दर में तेज वृद्धि हुई है जो लिस्टिंग के दिन उच्च रिटर्न को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है और जिसके परिणामस्वरूप

चार्ट बी1: प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ)



स्रोत: सेबी।



(जारी)

<sup>27</sup> बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म मार्च 2012 में स्थापित किया गया था, जबकि एनएसई एसएमई प्लेटफॉर्म, जिसे इमर्ज के नाम से जाना जाता है, सितंबर 2012 में स्थापित किया गया था।

**सारणी बी1: आईपीओ की औसत अत्यभिदान दरें**

वर्ष	मेनबोर्ड आईपीओ	एसएमई आईपीओ
2018-19	2.69	1.33
2019-20	20.31	1.18
2020-21	30.12	1.42
2021-22	13.44	2.83
2022-23	3.44	11.49
2023-24	22.60	62.28

नोट: (1) डेटा यह दर्शाता है कि आईपीओ को इश्यू के आकार के सापेक्ष कितनी बार ओवरसब्सक्राइब किया गया।

(2) आईपीओ जारी होने की तारीख के आधार पर डेटा संकलित किया गया।

स्रोत: प्राइम डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अधिक अवमूल्यन<sup>28</sup> (सारणी बी1) होता है। अनुभवजन्य विश्लेषण से पता चलता है कि अत्यभिदान दर का मेनबोर्ड आईपीओ के अवमूल्यन<sup>29</sup> पर सकारात्मक और अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

जनवरी 2012 से मार्च 2024 तक के डेटा का उपयोग करके बीएसई एसएमई एक्सचेंज और एनएसई इमर्ज पर सूचीबद्ध एसएमई आईपीओ के अवमूल्यन की तुलना मेनबोर्ड आईपीओ से की जाती है (चार्ट बी2)। अवमूल्यन माप  $\delta$  (डेल्टा) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

$$\delta = r_i - r^*$$

जहां  $r_i$  लिस्टिंग दिवस रिटर्न है जिसकी गणना प्रस्ताव मूल्य के ऊपर लिस्टिंग दिवस के समापन मूल्य के रूप में की जाती है।

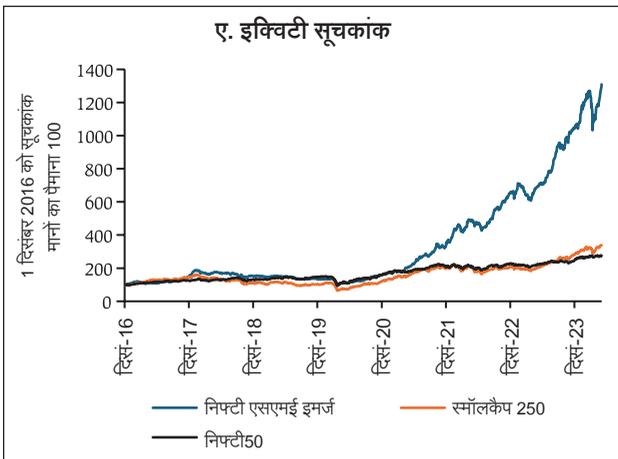
$r^*$  लिस्टिंग के दिन का बेंचमार्क रिटर्न<sup>30</sup> है।

अधिकांश वर्षों में, मेनबोर्ड आईपीओ का औसत अवमूल्यन एसएमई आईपीओ की तुलना में अधिक रहा (गांगुली, 2022)। हालाँकि, हाल में एसएमई आईपीओ का औसत अवमूल्यन मेनबोर्ड आईपीओ की तुलना में काफी अधिक रहा है।

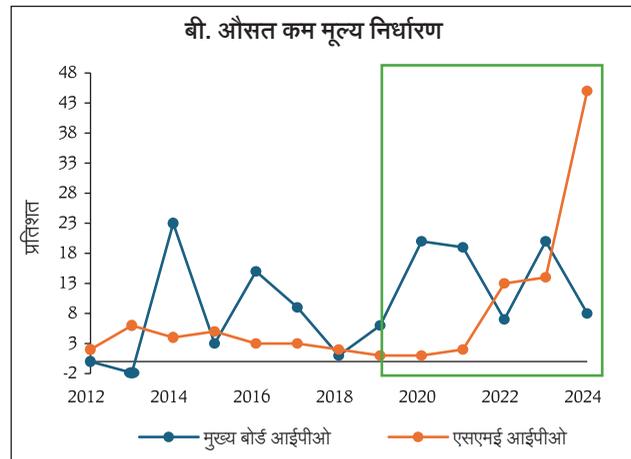
वैश्विक आईपीओ बाजारों में आईपीओ अवमूल्यन आम बात है (महमूद एट अल., 2021)। इसके लिए असममित जानकारी, स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित कारकों से लेकर कई तरह के कारकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है (लुंगक्विस्ट, 2007)। इसके अलावा, वैश्विक स्तर पर आईपीओ अवमूल्यन आईपीओ विशिष्ट चर (जैसे आईपीओ आकार और प्रीमियम); बाजार चर (जैसे पिछड़ा हुआ बाजार रिटर्न और अस्थिरता); और स्थायी विशेषताओं (जैसे आयु, आकार, उद्योग, चलनिधि और लाभप्रदता संकेतक) पर निर्भर करता है (घोष, 2005; भट्टाचार्य, 2017)।

बेंचमार्क से अधिक सूचीबद्ध एसएमई आईपीओ के अपेक्षित अतिरिक्त रिटर्न से संकेत मिलता है कि औसतन, एसएमई

**चार्ट बी2: औसत कम मूल्य निर्धारण : मेनबोर्ड आईपीओ बनाम एसएमई आईपीओ**



स्रोत: एनएसई, प्राइम डेटाबेस और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।



(जारी)

<sup>28</sup> बाजार मूल्य (पहले दिन समापन मूल्य) और प्रस्ताव मूल्य के बीच अंतर के रूप में अवमूल्यन मापा जाता है।

<sup>29</sup> 'भारत में लिस्टिंग रिटर्न की घटना: कुछ अन्वेषण' (बॉक्स-आइटम, आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट, 2020-21)।

<sup>30</sup> बीएसई सेंसेक्स को मेनबोर्ड आईपीओ के लिए बेंचमार्क के रूप में लिया जाता है और बीएसई स्मॉल कैप को एसएमई आईपीओ के लिए बेंचमार्क के रूप में लिया जाता है।

## सारणी बी 2: एसएमई-आईपीओ स्टॉक का बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन

	अपेक्षित अतिरिक्त प्रतिफल (प्रतिशत में)	
	स्मॉलकैप इंडेक्स	सेसेक्स
6-महीने	32.0	42.5
12-महीने	65.2	81.9

**नोट :** (1) 6 महीने और 12 महीने की अवधि के लिए अपेक्षित रिटर्न की गणना सकारात्मक/नकारात्मक रिटर्न वाले शेयरों के अनुपात को उनके औसत सकारात्मक/नकारात्मक रिटर्न से गुणा करके की जाती है।  
अपेक्षित रिटर्न =  $P_{\text{लाभ}} * \text{औसत लाभ} + (1 - P_{\text{लाभ}}) * \text{औसत हानि}$   
जहाँ  $P$  की गणना (सकारात्मक अतिरिक्त रिटर्न वाले स्टॉक) / (विश्लेषण के तहत कुल स्टॉक) के रूप में की जाती है।  
(2) विश्लेषण में मई 2021 और नवंबर 2023 के बीच सूचीबद्ध 311 एसएमई आईपीओ शामिल हैं।  
(3) उल्लेखनीय बात यह है कि 42 और 36 प्रतिशत एसएमई आईपीओ ने सूचीबद्ध होने के क्रमशः छह महीने और एक वर्ष बाद नकारात्मक पूर्ण रिटर्न दिया है।

**स्रोत:** बीएसई, प्राइम डेटाबेस; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शेयरों ने व्यापक बेंचमार्क से बेहतर प्रदर्शन किया है (सारणी बी 2)। एसएमई आईपीओ खंड में उत्साह से मूल्य में हेरफेर<sup>31</sup> और मजबूत प्राथमिक बाजार के दुरुपयोग के रास्ते खुलते हैं जैसे आईपीओ की आय को उसके इच्छित अंतिम उपयोग से दूर ले जाना<sup>32</sup>। सेबी की हालिया कार्रवाइयों से इन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

परिलक्षित होता है। एसएमई आईपीओ प्लेटफॉर्म के लिए विशेष प्री-ओपन सत्र के दौरान एक्सचेंजों में शुरुआती मूल्य खोज/संतुलन मूल्य को मानकीकृत करने की दृष्टि से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने निर्गम मूल्य पर एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग के लिए (4 जुलाई, 2024 से प्रभावी) 90 प्रतिशत तक की समग्र सीमा लगाने का निर्णय लिया।<sup>33</sup>

अप्रैल-मई 2024 के दौरान सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले दर्ज किए गए 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था (चार्ट IV.13ए)। सकल एफडीआई प्रवाह का 80 प्रतिशत से अधिक हिस्सा विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, कंप्यूटर सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं और बिजली और अन्य ऊर्जा

## संदर्भ:

Mayank Gupta, Aayushi Bhattacharya, Satyam Kumar, Dilpreet Sharma and Amit Pawar (2024). Exploring Under-Pricing: A Comparative Study of Indian SME IPOs and Mainboard IPOs, Mimeo.

Bhattacharya, A. (2017). Innovations in New Venture Financing: Evidence from Indian SME IPOs. *Global Finance Journal*, 34, 72-88.

Ganguly, S. (2022). *SME Exchanges in India: Empirical Analysis of Firm Attributes and IPO Characteristics* (Working Paper No. 11). Reserve Bank of India.

Ghosh, S. (2005). Underpricing of Initial Public Offerings: The Indian Experience. *Emerging Markets Finance and Trade*, 41(6), 45-57.

Ljungqvist, A. (2007). IPO Underpricing. In B. Espen Eckbo (Eds.). *Handbooks in Finance: Handbook of Empirical Corporate Finance* (pp. 375-422). Elsevier.

Mehmood, W., Rashid, R. M., & Tajuddin, A. H. (2021). A Review of IPO Underpricing: Evidences from Developed, Developing and Emerging Markets. *Journal of Contemporary Issues and Thought*, 11, 1-19.

RBI (2021). *Annual Report 2020-21*. Reserve Bank of India.

जैसे क्षेत्रों में केंद्रित था। प्रमुख स्रोत देशों में मॉरीशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, अमेरिका और साइप्रस शामिल हैं, जो 80 प्रतिशत से अधिक प्रवाह के लिए जिम्मेदार हैं। सकल प्रवाह में वृद्धि और प्रत्यावर्तन में नरमी के कारण, अप्रैल-मई 2024 में निवल एफडीआई 7.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक साल पहले के 3.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से दोगुना से भी अधिक है।

अस्थिर वित्तीय स्थितियों, बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और गहराते भू-आर्थिक विखंडन के बीच, 2023 में 1.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक एफडीआई प्रवाह में 2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट IV.13बी)<sup>34</sup> कुछ यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को छोड़कर सभी भौगोलिक क्षेत्रों में नरमी आई। उन्हें छोड़कर, वैश्विक प्रवाह में संकुचन 10 प्रतिशत से भी अधिक तीव्र था।

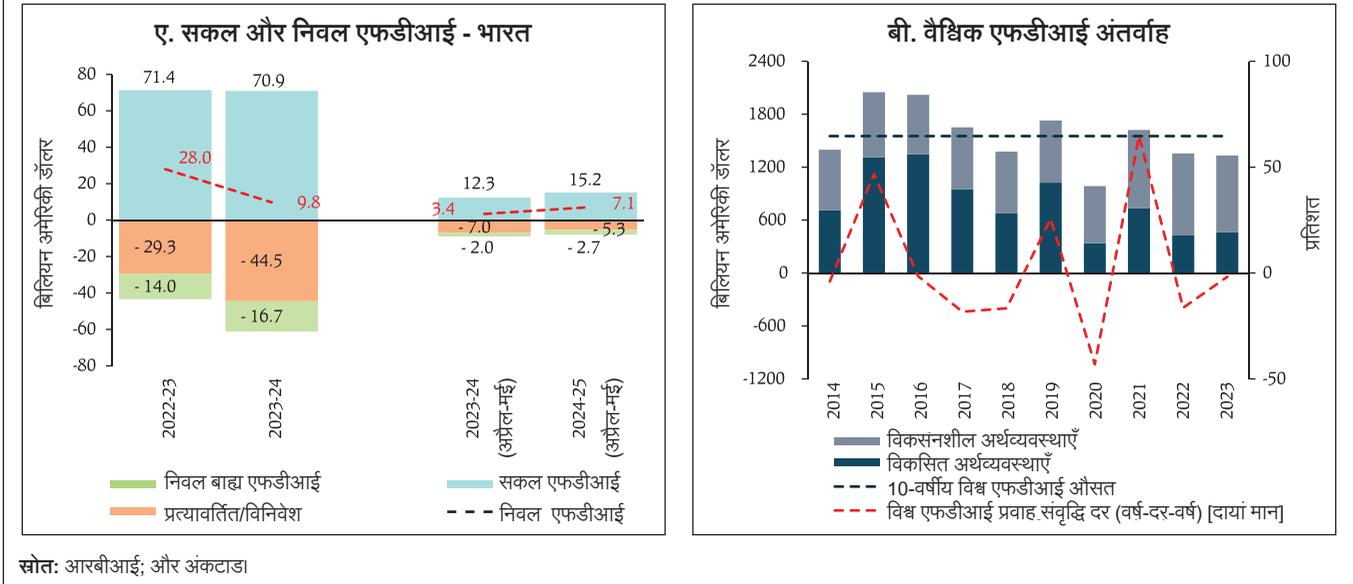
<sup>31</sup> [https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/feb-2024/interim-order-in-the-matter-of-v-marc-india-limited\\_81831.html](https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/feb-2024/interim-order-in-the-matter-of-v-marc-india-limited_81831.html)

<sup>32</sup> [https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/may-2024/interim-order-in-the-matter-of-varanium-cloud-limited\\_83309.html](https://www.sebi.gov.in/enforcement/orders/may-2024/interim-order-in-the-matter-of-varanium-cloud-limited_83309.html)

<sup>33</sup> <https://nsearchives.nseindia.com/content/circulars/SME62757.zip>

<sup>34</sup> विश्व निवेश रिपोर्ट 2024, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (अंकटाड)।

**चार्ट IV.13: प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह**

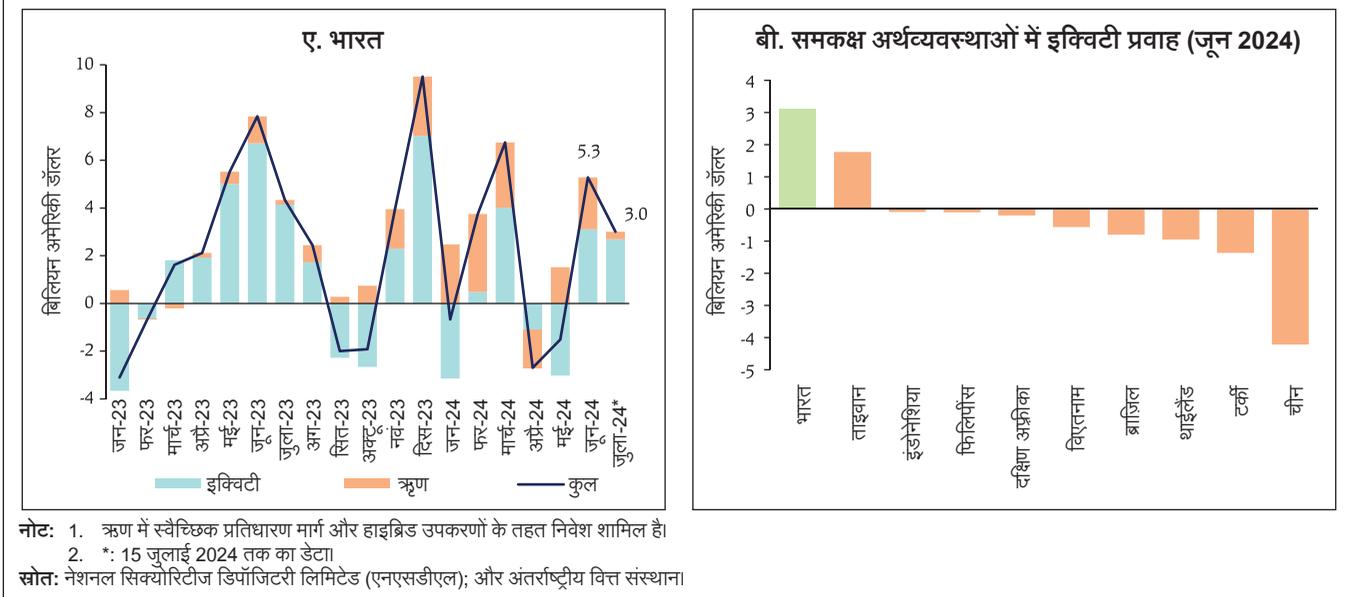


स्रोत: आरबीआई, और अंकटाडा

विनिर्माण परियोजना घोषणाओं में वृद्धि के कारण वैश्विक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिससे मंदी की एक दशक पुरानी प्रवृत्ति टूट गई। 2023 के दौरान एफडीआई अंतर्वाह में नरमी के बावजूद, ग्रीनफील्ड परियोजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों दोनों में भारत शीर्ष 5 गंतव्य देशों में बना रहा।

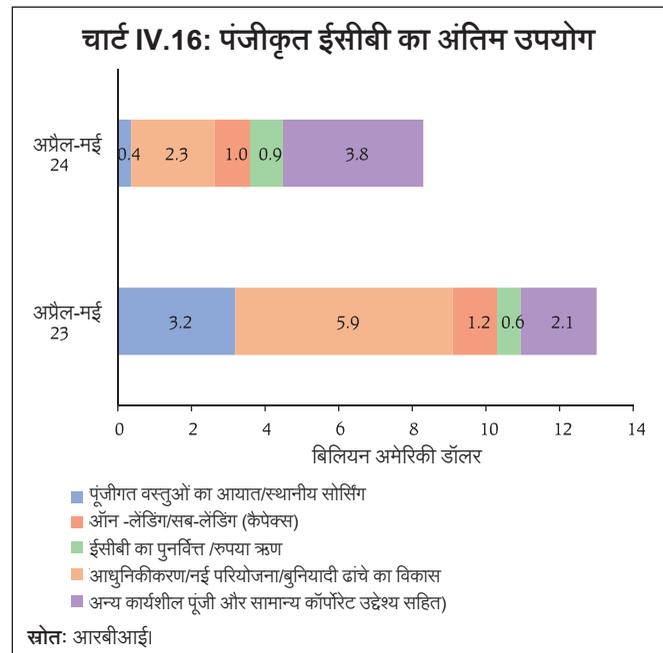
लगातार दो महीनों के निवल बहिर्वाह के बाद, जून 2024 में एफपीआई 5.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह के साथ भारतीय वित्तीय बाजारों में निवल खरीदार बन गए (चार्ट IV.14ए)। बाजार में अस्थिरता कम होने से इक्विटी ने दो महीने की बिक्री प्रक्षेपवक्र को उलट दिया, जिसमें 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल एफपीआई अंतर्वाह हुआ। इसके विपरीत,

**चार्ट IV.14: निवल पोर्टफोलियो निवेश**

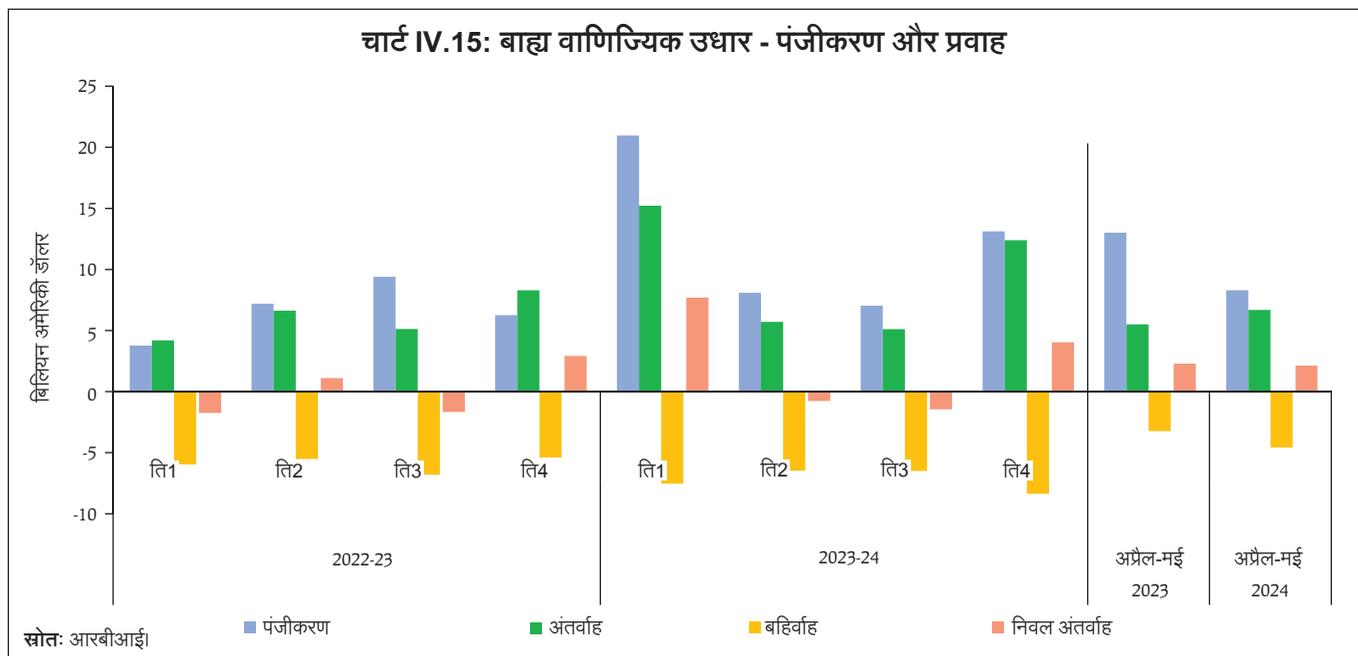


अधिकांश समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं ने जून में इक्विटी खंड में निवल बहिर्वाह दर्ज किया (चार्ट IV.14बी)। वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार और उपभोक्ता सेवा क्षेत्रों ने इस महीने के दौरान सबसे अधिक एफपीआई इक्विटी अंतर्वाह को आकर्षित किया। ऋण खंड में एफपीआई अंतर्वाह जारी है और 28 जून, 2024 से जेपी मॉर्गन के जीबीआई-ईएम में भारतीय सरकारी बांडों को शामिल करने की घोषणा के बाद से 18-21 महीनों के भीतर लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर<sup>35</sup> तक अंतर्वाह में आने का अनुमान है। एफपीआई ऋण अंतर्वाह की संभावनाएं आशावादी प्रतीत होती हैं क्योंकि भारत अन्य वैश्विक सूचकांकों में शामिल होने जा रहा है<sup>36</sup> जुलाई 2024 में (15 जुलाई तक) निवल एफपीआई अंतर्वाह 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

अप्रैल-मई 2024 में अनिवासी जमा में 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले यह 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह सभी तीन खातों अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता [एनआर(ई)आरए], अनिवासी साधारण (एनआरओ) और विदेशी मुद्रा अनिवासी [एफसीएनआर(बी)] खातों में उच्चतर अंतर्वाह के कारण हुआ।

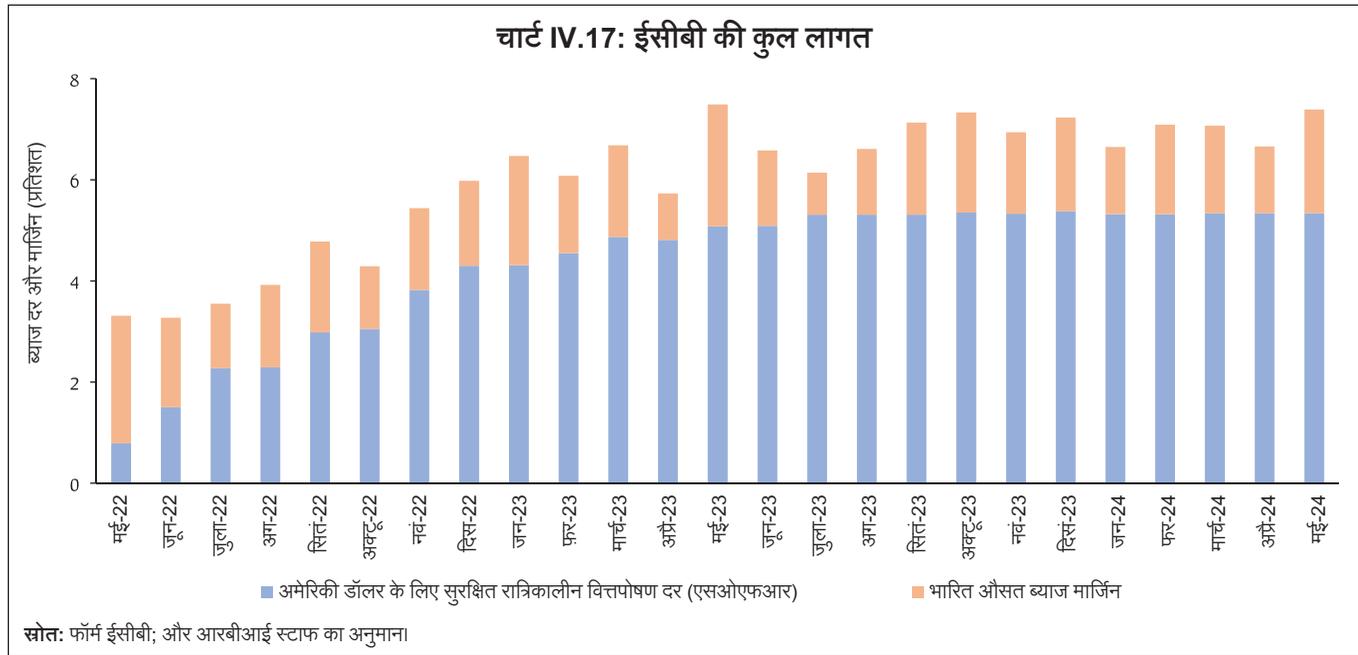


2023-24 की चौथी तिमाही में दर्ज की गई बढ़ोतरी को जारी रखते हुए, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) का सकल संवितरण 2024-25 की पहली तिमाही के पहले दो महीनों के दौरान नए पंजीकरण और संवितरण में क्रमिक मॉडरेशन के बावजूद 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (अप्रैल-मई 2023 में 5.5 बिलियन



<sup>35</sup> <https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-06-27/what-india-s-inclusion-in-jpmorgan-bond-index-means-for-its-economy-markets?sref=QF6yuiF0>

<sup>36</sup> जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 10 प्रतिशत के शुरुआती भार के साथ ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट (ईएम) स्थानीय मुद्रा सरकारी सूचकांक में भारतीय पूरी तरह से सुलभ रूट (एफएआर) बांड शामिल किए जाएंगे। यह भी घोषणा की गई है कि भारत को यूएस रिटायरमेंट फंड के नये फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड (एफआरटीआईबी) इंडेक्स में शामिल किया जाना है।

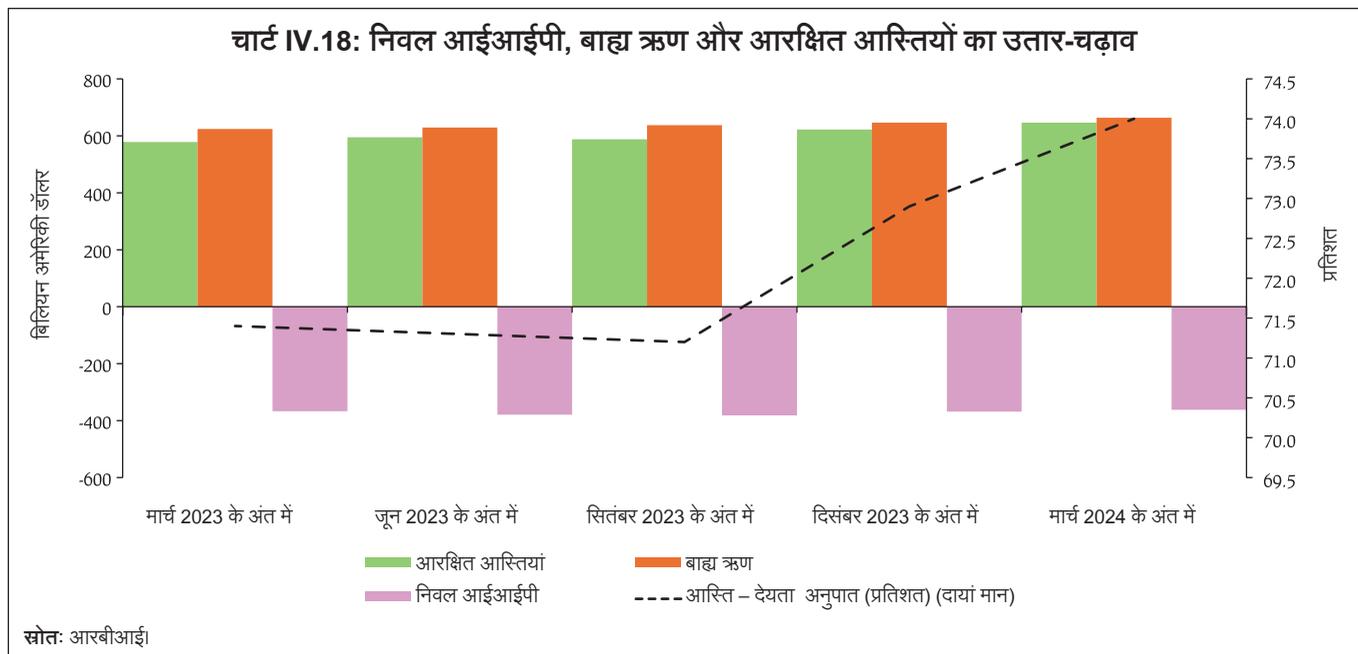


अमेरिकी डॉलर) के उच्च स्तर पर रहा। अंतर्वाह बहिर्प्रवाह से अधिक होने के कारण, निवल प्रवाह सकारात्मक बना हुआ है (चार्ट IV.15)।

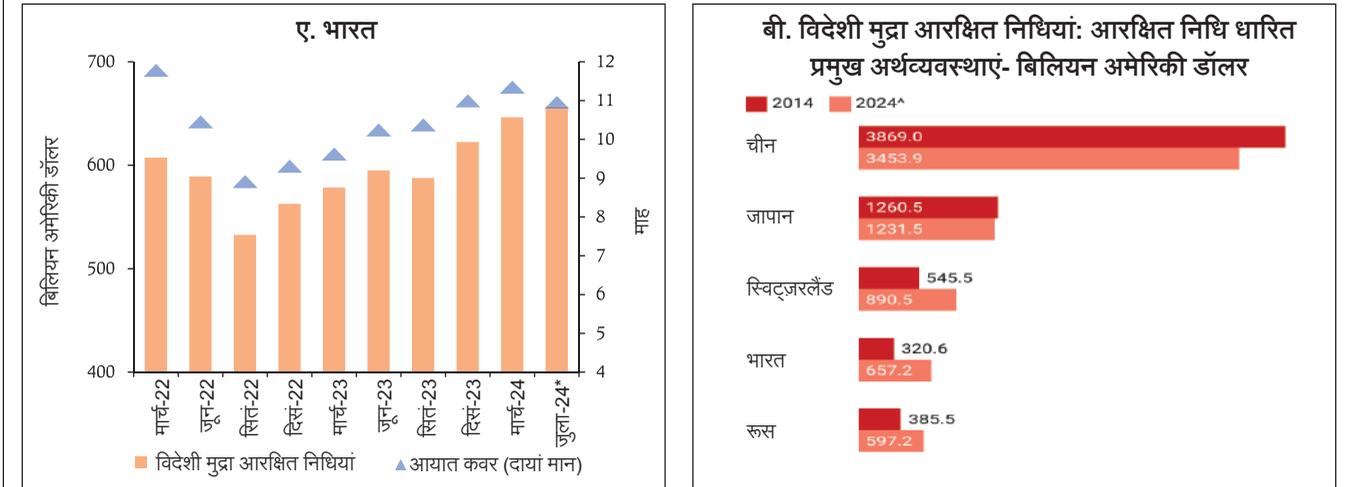
अप्रैल-मई 2024 के दौरान जुटाए गए इसीबी का एक बड़ा हिस्सा नई परियोजनाओं, आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए था (चार्ट IV.16)।

स्थिर बेंचमार्क दर पर भारित औसत मार्जिन 73 बीपीएस बढ़ गया, जिससे मई 2024 में इसीबी ऋण की कुल लागत बढ़ गई (चार्ट IV.17)।

आरक्षित निधि, मुद्रा और जमा और बाह्य एफडीआई में विस्तार के कारण, 2023-24 की चौथी तिमाही के दौरान भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) बढ़कर



**चार्ट IV.19: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां**

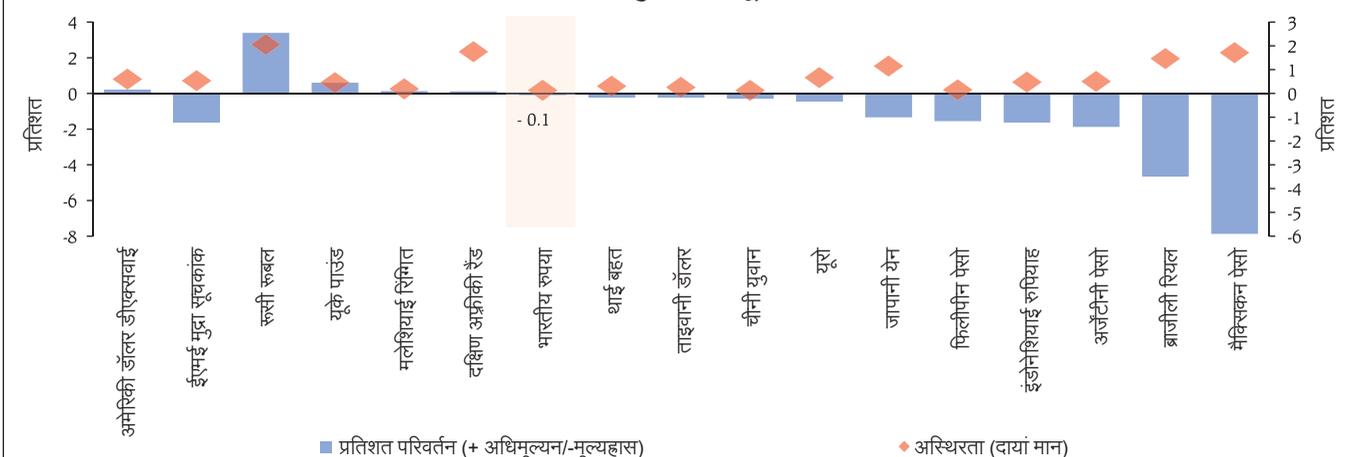


**नोट:** 1. \*: 5 जुलाई का डेटा  
 2. \*: भारत और रूस के लिए आंकड़े 5 जुलाई, चीन और जापान के लिए जून के अंत और स्विट्जरलैंड के लिए मई के अंत के हैं।  
 3. भारत के लिए आयात कवर जुलाई 2024 को छोड़कर, वास्तविक आयात पर आधारित है जो 2024-25 के लिए अनुमानित आयात पर आधारित है।  
**स्रोत:** आरबीआई; आईएमएफ; और संबंधित केंद्रीय बैंक वेबसाइटें।

(-) 361.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जो कि आवक एफडीआई में वृद्धि और बाह्य ऋण देयताओं से मामूली रूप से संतुलित थी (IV.18)। परिणामस्वरूप, मार्च 2024 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय आस्तियों और अंतर्राष्ट्रीय देयताओं का अनुपात सुधरकर 74.0 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का निवल आईआईपी (मौजूदा बाजार मूल्यों पर) अनुपात भी एक साल पहले के (-) 11.3 फीसदी के मुकाबले सुधरकर मार्च 2024 में (-) 10.3 प्रतिशत हो गया।

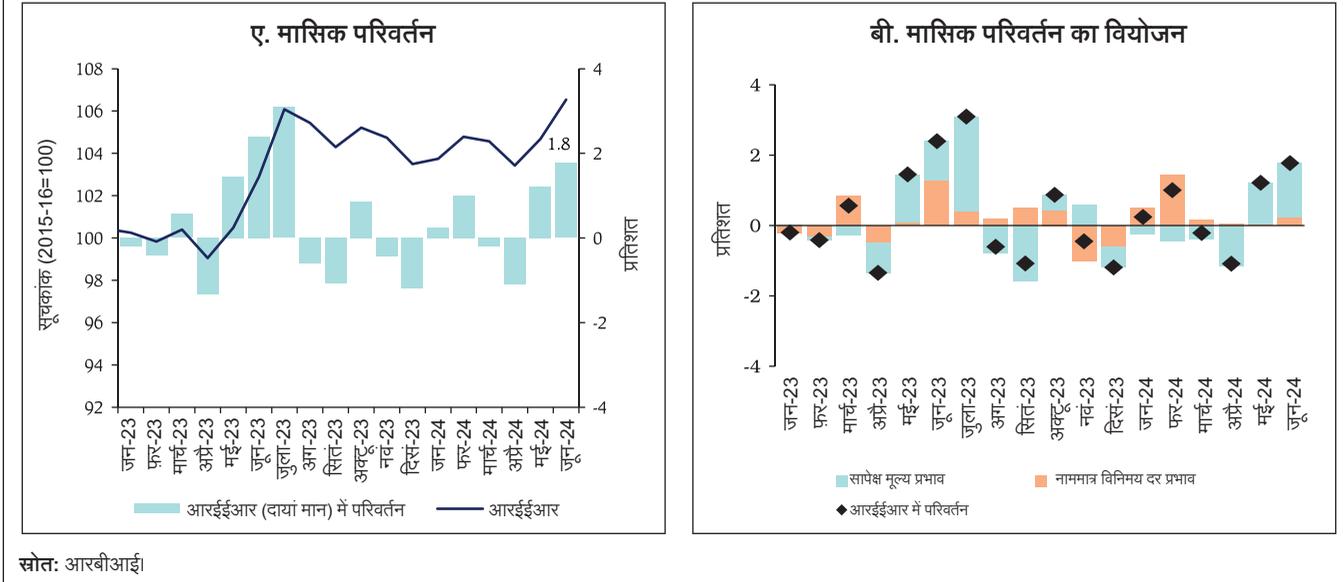
2024 में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 34.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 5 जुलाई, 2024 को 657.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, जो 2024-25 के लिए अनुमानित लगभग 11 महीनों के आयात के बराबर है और मार्च 2024 के अंत में कुल बाह्य ऋण बकाया का लगभग 99 प्रतिशत है। (चार्ट IV.19ए)। वर्तमान में, भारत दुनिया में चौथा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि धारक बना हुआ है (चार्ट IV.19बी)।

**चार्ट IV.20: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये और प्रमुख मुद्राओं का उतार-चढ़ाव (मई 2024 की तुलना में जून 2024 को)**



**नोट:** अमेरिकी डॉलर (डीएसवीआई) प्रमुख मुद्राओं (यूरो, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, कनाडाई डॉलर, स्वीडिश क्रोना, स्विस् फ्रैंक) के एक समूह के मुकाबले अमेरिकी डॉलर के उतार-चढ़ाव को मापता है।  
**स्रोत:** एफबीआईएल; थॉमसन रॉयटर्स; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

**चार्ट IV.21: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव**

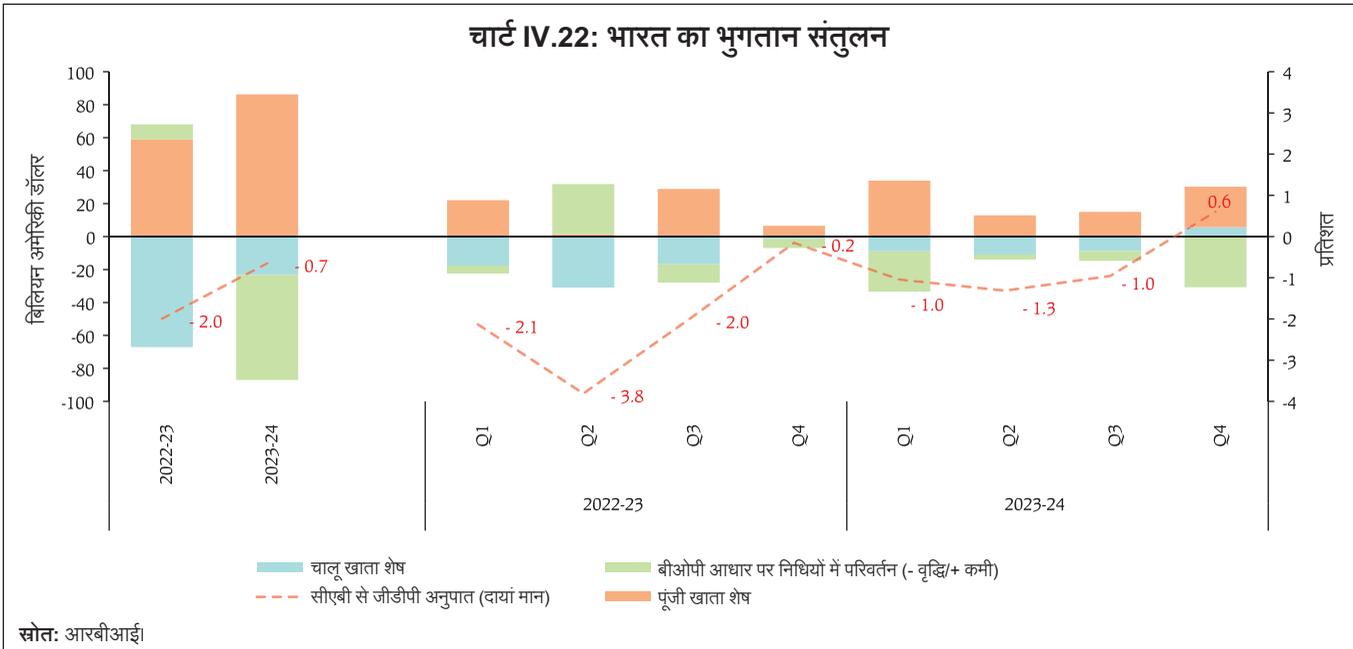


जून 2024 में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये (आईएनआर) में 0.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) की गिरावट आई, क्योंकि उभरते बाजार की मुद्राओं को मजबूत अमेरिकी डॉलर और वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ा। हालाँकि, भारतीय रुपया, इस महीने के दौरान सबसे कम अस्थिर प्रमुख मुद्राओं में से एक रहा (चार्ट IV.20)।

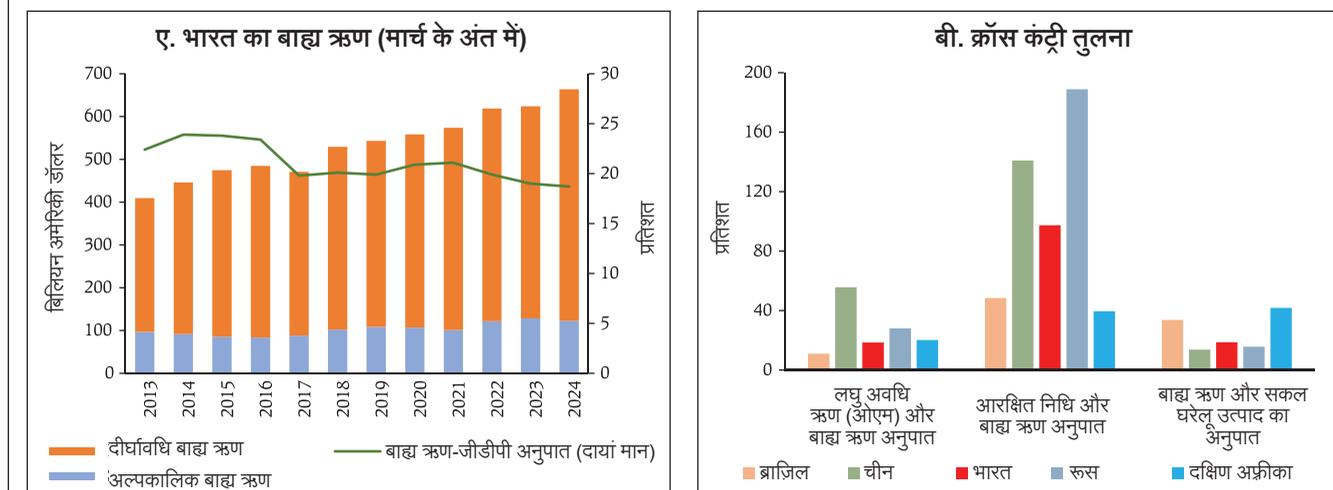
40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में, जून 2024 में भारतीय रुपये में 1.8 प्रतिशत (माह-दर-माह) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सकारात्मक सापेक्ष मूल्य अंतर (चार्ट IV.21) था।

भारत के चालू खाता शेष (सीएबी) में 2023-24 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद का 0.6 प्रतिशत अधिशेष दर्ज

**चार्ट IV.22: भारत का भुगतान संतुलन**



**चार्ट IV.23: बाहरी भेद्यता संकेतक**



**नोट:** 1. ओएम: मूल परिपक्वता।  
 2. भारत के लिए बाह्य भेद्यता अनुपात पर डेटा मार्च 2024 के अंत के लिए है, जबकि अन्य देशों के लिए दिसंबर 2023 के अंत के लिए है।  
**स्रोत:** आरबीआई; भारत सरकार: आईएमएफ; विश्व बैंक; और सीईआईसी।

किया गया, जबकि 2023-24 की तीसरी तिमाही में 1.0 प्रतिशत और 2022-23 की चौथी तिमाही में 0.2 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। मजबूत सेवा निर्यात और प्रेषण प्राप्तियों के साथ-साथ माल व्यापार घाटा कम होने से चालू खाते में अधिशेष दर्ज हुआ (चार्ट IV.22)।

समग्र रूप से 2023-24 के दौरान, माल व्यापार घाटे में गिरावट के कारण चालू खाता घाटा (सीएडी) एक साल पहले के 2.0 प्रतिशत से घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत हो गया। 2023-24 के दौरान विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों (मूल्यांकन प्रभाव को छोड़कर) में 63.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर

की वृद्धि हुई, क्योंकि निवल पूंजी अंतर्वाह - मजबूत एफपीआई प्रवाह और बैंकिंग पूंजी पर हावी अर्थात् सीएडी से अधिक था।

मार्च 2023 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 39.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2024 के अंत में 663.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में विदेशी ऋण एक साल पहले के 19.0 प्रतिशत से कम होकर 18.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.23ए)। भारत के प्रमुख बाह्य भेद्यता संकेतक टिकाऊ स्तर पर बने रहे और अपने समकक्षों की तुलना में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया (चार्ट IV.23बी)।

**सारणी IV.2: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि**

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेन-देन की मात्रा				लेन-देन मूल्य			
	मई-23	मई-24	जून-23	जून-24	मई-23	मई-24	जून-23	जून-24
आरटीजीएस	12.6	13.3	9.2	9.2	15.2	17.9	16.0	11.9
एनईएफटी	28.4	52.5	26.7	43.4	18.8	14.3	11.9	9.6
यूपीआई	58.3	49.1	59.2	48.7	43.2	37.3	45.5	36.0
आईएमपीएस	3.5	11.2	2.7	10.4	16.6	14.9	12.8	15.4
एनएसीएच	-14.3	12.7	18.8	29.5	19.5	20.7	18.7	24.1
एनईटीसी	17.4	3.7	13.7	5.8	24.3	8.7	20.8	11.2
बीबीपीएस	28.4	47.8	24.8	53.6	44.8	114.8	41.6	108.9

**नोट:** आरटीजीएस: रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यूपीआई: यूनिकाइड पेमेंट्स इंटरफेस, आईएमपीएस: तत्काल भुगतान सेवा, एनएसीएच: नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, एनईटीसी: नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।

**स्रोत:** आरबीआई।

## भुगतान प्रणाली

सभी प्रमुख श्रेणियों में डिजिटल भुगतान प्रणाली संकेतकों ने जून 2024 में निरंतर वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) प्रदर्शित की जिसमें मुख्य रूप से भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) और एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) [सारणी IV.2] अग्रणी है। बीबीपीएस ने जून 2024 के दौरान स्थिर वृद्धि बनाए रखी, जो ग्राहकों और बिलर्स दोनों की जरूरतों को पूरा करने वाले एक सहज, सुरक्षित और कुशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरलीकृत बिल भुगतान के कारण बढ़ी हुई पैठ को दर्शाता है।<sup>37</sup> जून 2024 में, यूपीआई ने यद्यपि क्रमिक रूप से मामूली गिरावट के साथ मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) दर्ज की। अन्य भुगतान प्रणाली संकेतकों के संबंध में, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) की वृद्धि दर मई के सापेक्ष जून 2024 में धीमी हो गई। भुगतान प्रणाली के बुनियादी ढांचे - क्रेडिट कार्ड की संख्या में वृद्धि (17.7 प्रतिशत), पॉइंट-ऑफ-सेल (पीओएस) टर्मिनलों की तैनाती (10.6 प्रतिशत), भारत त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड (10.4 प्रतिशत) और यूपीआई क्यूआर कोड (23.7 प्रतिशत) में मजबूत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) के कारण मई 2024 में डिजिटलीकरण लगातार मजबूत हुआ है।

भारतीय भुगतान प्रणालियों की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच के विस्तार को और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, रिजर्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया, जो एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जो चार दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र (एएसईएन) देशों (मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड); और भारत के संगठन की घरेलू तेज भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को आपस में जोड़कर त्वरित सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाती है।<sup>38</sup> उम्मीद है कि यह प्लेटफॉर्म खुदरा सीमा-पार भुगतान को कुशल, तेज और अधिक लागत प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 3 जुलाई, 2024 को पीएसबी और पीवीबी के प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) के साथ आरबीआई गवर्नर की एक बैठक हुई, जिसमें मजबूत साइबर सुरक्षा नियंत्रण, तीसरे पक्ष के जोखिमों के प्रबंधन, ग्राहक जागरूकता और शिक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल थे। डिजिटल धोखाधड़ी पर

अंकुश लगाने की पहल, उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।<sup>39</sup> नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने नेटवर्क इंटरनेशनल (नेटवर्क) के साथ साझेदारी में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में नेटवर्क के पीओएस टर्मिनलों के माध्यम से क्यूआर-कोड आधारित यूपीआई भुगतान की स्वीकृति को सक्षम<sup>40</sup> किया। इससे संयुक्त अरब अमीरात में नेटवर्क के विशाल व्यापारी नेटवर्क में भारतीय पर्यटकों और अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए निर्बाध और सुरक्षित सीमा पार लेनदेन की सुविधा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्मों पर यूपीआई की पहुंच को एनआईपीएल की लायरा के साथ साझेदारी<sup>41</sup> के साथ आगे बढ़ाया गया, जिसने पेरिस में गैलरीज लाफायेट के प्रमुख स्टोर पर सुरक्षित और सुविधाजनक यूपीआई लेनदेन को सक्षम किया।

## निष्कर्ष

इस पृष्ठभूमि में, अपने लक्ष्यों के संदर्भ में, मौद्रिक नीति के संचालन का जायजा लेना उपयोगी है। नीति दर में संचयी वृद्धि ने फरवरी 2023 तक नीति दर के स्तर को 6.5 प्रतिशत तक पहुंचा दिया, जिसके बाद लंबे समय तक विराम लगा रहा। इस नीतिगत दृष्टिकोण से सितंबर 2023 के बाद से सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के सहिष्णुता बैंड में गिरावट के रूप में कुछ लाभ प्राप्त हुए हैं। फिर भी, अवस्फीति निराशाजनक और असमान रही है और मुख्य मुद्रास्फीति पर ऐतिहासिक रूप से कम रीडिंग और ईंधन की कीमतों में निरंतर अपस्फीति के बावजूद हेडलाइन मुद्रास्फीति अपनी नवीनतम रीडिंग में 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 5 प्रतिशत के करीब बनी हुई है।

यह खाद्य मुद्रास्फीति, इसकी प्रकृति और गतिशीलता पर सार्वजनिक चर्चा का ध्यान केंद्रित करता है। यह तर्क कि खाद्य कीमतों के झटके क्षणिक होते हैं, पिछले एक साल के वास्तविक अनुभव से प्रमाणित नहीं होता है - किसी झटके को क्षणभंगुर कहने के लिए यह बहुत लंबी अवधि है! इस 'निरंतर' घटक पर सब्जियों की एक श्रृंखला की कीमतों में छिटपुट बढ़ोतरी होती

<sup>37</sup> 9 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

<sup>38</sup> 1 जुलाई 2024, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति

<sup>39</sup> 3 जुलाई 2024, आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति

<sup>40</sup> 3 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

<sup>41</sup> 5 जुलाई 2024, एनपीसीआई प्रेस विज्ञप्ति

हैं जो सब्जियों की व्यापक श्रेणी की मुद्रास्फीति को एक स्थायी चरित्र देने के लिए घटकों में ओवरलैप होती है। खाद्य कीमतें स्पष्ट रूप से हेडलाइन मुद्रास्फीति और परिवारों की मुद्रास्फीति अपेक्षाओं पर हावी हो रही हैं, जो मौद्रिक नीति और आपूर्ति प्रबंधन के संयोजन के माध्यम से मुख्य और ईंधन मुद्रास्फीति को कम करने के लाभ को कम कर रही हैं। हालाँकि मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की मौजूदा धारणा कम हो रही है, लेकिन यह उनकी तीन महीने आगे और एक साल आगे की प्रत्याशाओं पर प्रतिबिंबित नहीं हो रही है जो ऊंची बनी हुई हैं। खाद्य कीमतों का दबाव बढ़ने से मजदूरी, किराए और प्रत्याशाओं पर असर के रूप में मुद्रास्फीति की संभावना को खतरा है।

इस पृष्ठभूमि में, आरबीआई की एमपीसी ने मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप टिकाऊ रूप से संरेखित करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। जब तक यह हासिल नहीं हो जाता, मुद्रास्फीति रीडिंग में हाल ही में रुकी गिरावट को अभी भी प्रगति पर माना जाना चाहिए।

लगभग आधी सदी पहले, मौलिक कार्य ने समय की असंगति की घटना की ओर इशारा किया था<sup>42</sup> जब मूल्य स्थिरता के लिए

प्रतिबद्ध मौद्रिक नीति अधिकारी बढ़ती वृद्धि के अल्पकालिक लाभ की खोज में उस प्रतिबद्धता से मुकर जाते हैं, तो वे अंततः विश्वसनीयता खो सकते हैं, मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को कमजोर कर सकते हैं और मुद्रास्फीति में वृद्धि को उत्प्रेरित सकते हैं। यह विकास की स्थिरता को भी कमजोर कर सकता है। मुद्रास्फीति के परिदृश्य में छाई उच्च अनिश्चितता को देखते हुए, समय की असंगतता के प्रलोभन से बचना और मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित करने के सीधे और संकीर्ण रास्ते पर बने रहना समझदारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत तक पहुंच जानी चाहिए और मौद्रिक नीति रुख में बदलाव पर विचार करने से पहले वहां बनी रहनी चाहिए; इसके बजाय, जोखिमों के संतुलन के सावधानीपूर्वक मूल्यांकन के आधार पर, लक्ष्य की ओर एक स्थायी गति के साथ दूरदेशी मौद्रिक नीति को प्रतिक्रिया देने के लिए संकेत प्रदान करना चाहिए। गवर्नर श्री शक्तिकांत दास के शब्दों में, “मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने और समयावधि में निरंतर विकास के लिए आवश्यक आधार प्रदान करने के लिए मूल्य स्थिरता पर केंद्रित रहती है”।

<sup>42</sup> किडलैंड, फिन ई., और एडवर्ड सी प्रेस्कॉट, “विवेक के बजाय नियम: इष्टतम योजनाओं की असंगति”, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 85(3):473-492, 1977, जून।

## महामारी के बाद के साक्ष्य के साथ भारत के लिए ब्याज की आधार दर के अनुमान को अद्यतन करना

हरेन्द्र कुमार बेहेरा द्वारा<sup>^</sup>

विभिन्न क्षेत्रों में मौद्रिक नीति विचलन ने ब्याज की प्राकृतिक दर के स्तर के बारे में बहस को फिर से शुरू कर दिया है। महामारी के बाद के आंकड़ों के साथ भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर के अनुमानों को अपडेट करते हुए, हम संभावित उत्पादन की वृद्धि से प्रेरित एक ऊपर की ओर बदलाव पाते हैं। ति4: 2023-24 के लिए प्राकृतिक दर का अनुमान ति3: 2021-22 के लिए हमारे पहले के अनुमान 0.8-1.0 प्रतिशत की तुलना में 1.4-1.9 प्रतिशत है। ये अनुमान अनिश्चितता के व्यापक दायरे में केंद्रित हैं, मौद्रिक नीति के रुख के आकलन में सावधानीपूर्वक व्याख्या की आवश्यकता है।

### भूमिका

भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण महामारी के बाद की अवधि में मुद्रास्फीति में वृद्धि ने सभी क्षेत्रों में साथ-साथ मौद्रिक नीति प्रतिक्रिया पैदा की। चूंकि केंद्रीय बैंकों ने नीतिगत दरों को दशक भर के ऐतिहासिक निम्न स्तर से उठाया और आक्रामक प्रतिबंधात्मक रुख अपनाया, वित्तीय स्थिति कठोर हो गई, और वास्तविक ब्याज दरों में काफी वृद्धि हुई। इसके बाद, मुद्रास्फीति अलग-अलग गति और परिमाण से अपने चरम से कम हो गई, लेकिन अवस्फीति का अंतिम चरण कठिन और लंबा लग रहा है। केंद्रीय बैंकों द्वारा अवस्फीतिकारी रुख बनाए रखने का चयन करने के साथ, बाजार की अपेक्षाओं से बढ़ते विचलन ने ब्याज

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), मुंबई से हैं। लेखक इस आलेख के लिए प्रेरणा प्रदान करने और उनकी संपादकीय टिप्पणियों, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए डॉ. माइकल देवब्रत पात्र के आभारी हैं। लेखक डॉ. अभिषेक रंजन और डॉ. समीर रंजन बेहेरा से प्राप्त इनपुट और बहुमूल्य समर्थन की सराहना करते हैं। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखक के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

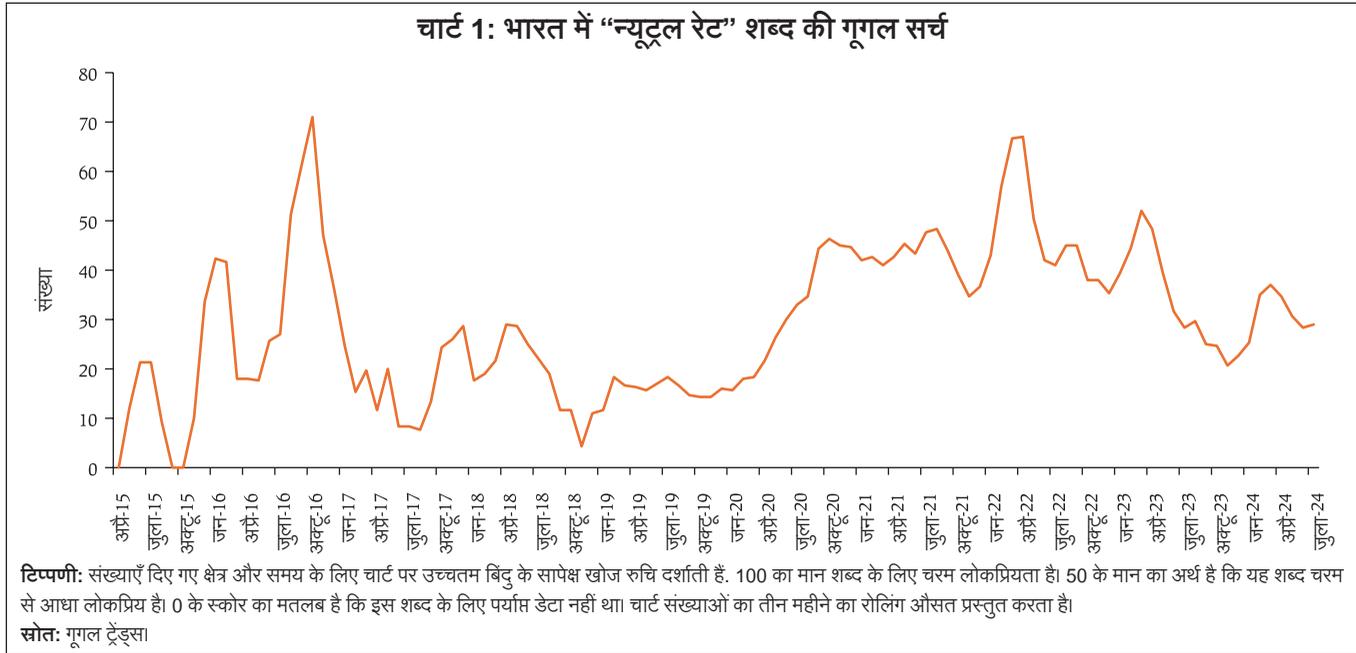
की प्राकृतिक दर या आर-स्टार<sup>1</sup> के स्तर के बारे में बहस को फिर से शुरू कर दिया है। भारत में, यह बहस "तटस्थ दर" शब्द की वेब खोजों के प्रसार में परिलक्षित होती है (चार्ट 1)। बहस के एक पक्ष पर, यह तर्क दिया जाता है कि आर-स्टार के कुछ संरचनात्मक निर्धारकों में परिवर्तन इसे ऊपर की ओर ले जा रहे हैं (ब्रांड एवं अन्य बेनिग्नो एवं अन्य., 2024; श्राबेल, 2024)। स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ, यह माना जाता है कि अल्पकालिक आघात समाप्त होने के बाद वास्तविक ब्याज दर अपने पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ जानी चाहिए (आईएमएफ, 2023ए)। भारत के लिए, महत्वपूर्ण संरचनात्मक परिवर्तनों और जनसांख्यिकीय बदलावों के मद्देनजर प्राकृतिक दर का अनुमान लगाना विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण हो जाता है। विशेष रूप से, महामारी से प्रेरित जटिलताओं ने संभावित उत्पादन के अनुमानों को बदल दिया है और मुद्रास्फीति की गतिशीलता को गहराई से प्रभावित किया है। इसने ब्याज की प्राकृतिक दर को मापने के लिए पारंपरिक मॉडल और दृष्टिकोण के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। चुनौती इन अभूतपूर्व आघातों के प्रभाव को अनुमानों में शामिल करना है।

इसके विकसेलियन मूल में, ब्याज की प्राकृतिक दर मुद्रास्फीति का दबाव पैदा किए बिना पूरी क्षमता से काम करने वाली अर्थव्यवस्था से जुड़ी है: "ऋण पर ब्याज की एक निश्चित दर है जो कमोडिटी की कीमतों के संबंध में तटस्थ है जो न तो इसे बढ़ाती है न घटाती है।"<sup>2</sup> साहित्य की एक धारा ने इस परिभाषा को परिभाषित करके संचालित किया है कि यह ब्याज दर का स्तर है जिस पर बचत निवेश के बराबर होती है, स्थिर कीमतों के अनुरूप होती है। परिचालन के संदर्भ में, प्राकृतिक दर मौद्रिक नीति के रुख को मापने के लिए एक संदर्भ के रूप में कार्य करती है (आईएमएफ, 2023ए)। इसलिए, वास्तविक नीतिगत ब्याज दर और प्राकृतिक दर के बीच का अंतर मौद्रिक नीति के रुख को मापता है। जब नीतिगत दर प्राकृतिक दर से नीचे निर्धारित की जाती है, तो रुख को उदार माना जाता है, और इसके विपरीत प्रतिबंधात्मक रुख का संकेत देता है। जब वास्तविक नीतिगत दर प्राकृतिक दर के स्तर पर होती है तो नीतिगत रुख तटस्थ होता है।

<sup>1</sup> इस आलेख में, प्राकृतिक दर, तटस्थ दर, ब्याज की प्राकृतिक दर और आर-स्टार का पर्यायवाची रूप में उपयोग किया गया है।

<sup>2</sup> विकसेल (1898)

चार्ट 1: भारत में “न्यूट्रल रेट” शब्द की गूगल सर्च



चूंकि प्राकृतिक दर अवलोकनीय नहीं है, इसलिए इसका अनुमान लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह उचित मौद्रिक नीतियों को स्थापित करने और उनका आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक दर अनुमान मॉडल चयन, माप मुद्दों और सांख्यिकीय अनिश्चितता दोनों के प्रति संवेदनशील हैं। आगे विस्तार में, विभिन्न मॉडल ऐसे अनुमान लगा सकते हैं जो काफी भिन्न हो सकते हैं। अनिश्चितता डेटा, उनके माप के साथ-साथ अनुमान दृष्टिकोण से भी उपजी है। इसलिए, प्राकृतिक दर का अनुमान प्रत्येक मॉडल के परिणामों के आसपास विश्वसनीयता बैंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मॉडलों के बाहर उपलब्ध सभी सूचनाओं को शामिल करते हुए व्यापक संभावित मॉडल अनुमानों को छंटने में सूचित निर्णय की आवश्यकता होती है, अर्थात्, उच्च अनिश्चितता की स्थिति में एक जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण (जॉर्डन, 2024)। मौद्रिक नीति को बहुत कम सख्त करने के जोखिम के खिलाफ बहुत अधिक सख्त करने के जोखिम को संतुलित करना नीतिगत दर तय करने में आवश्यक है, बजाय इसके कि केवल प्राकृतिक दर के आधार पर निर्णय लिया जाए जो मूल्यों में अभेद्य है (पॉवेल, 2023)।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में ब्याज की प्राकृतिक दर के निर्धारकों पर चर्चा के बाद, खंड III विभिन्न पद्धतियों को प्रस्तुत करता है जिनका

उपयोग इसका अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। भारत के लिए प्राकृतिक दर के अद्यतन अनुमान में खंड IV में दिए गए हैं। निष्कर्ष खंड V में है।

## II. ब्याज की प्राकृतिक दर के वाहक

प्राकृतिक दर उन कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है जो लंबे समय तक बचत-निवेश व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से, बचत को कम करने या निवेश बढ़ाने वाले कारक प्राकृतिक दर को बढ़ाते हैं। नए निवेश के अवसरों से जुड़ी उच्च उत्पादकता वृद्धि पूंजी की मांग को बढ़ाती है, जो बदले में, वास्तविक ब्याज दरों को बढ़ाती है और इसलिए, ब्याज की प्राकृतिक दर भी बढ़ती है (बूकर एवं अन्य., 2023)। लंबी जीवन प्रत्याशा लंबी सेवानिवृत्ति का समर्थन करने के लिए बचत को बढ़ावा देती है। कम निर्भरता अनुपात - आबादी में कार्यशील आयु के लोगों के उच्च हिस्से को दर्शाता है - बचत को बढ़ाता है क्योंकि कार्यबल में वे आमतौर पर बुजुर्गों और युवा आश्रितों की तुलना में अधिक बचत करते हैं। उच्च असमानता बचत को बढ़ाती है क्योंकि अमीर परिवार कम संपन्न परिवारों के सापेक्ष अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं। उच्च जोखिम से बचने से उच्च बचत होती है - विशेष रूप से, सुरक्षित आस्तियों में - भविष्य की आर्थिक मंदी के खिलाफ एक बफर के रूप में और साथ ही, निवेश को कम करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों में

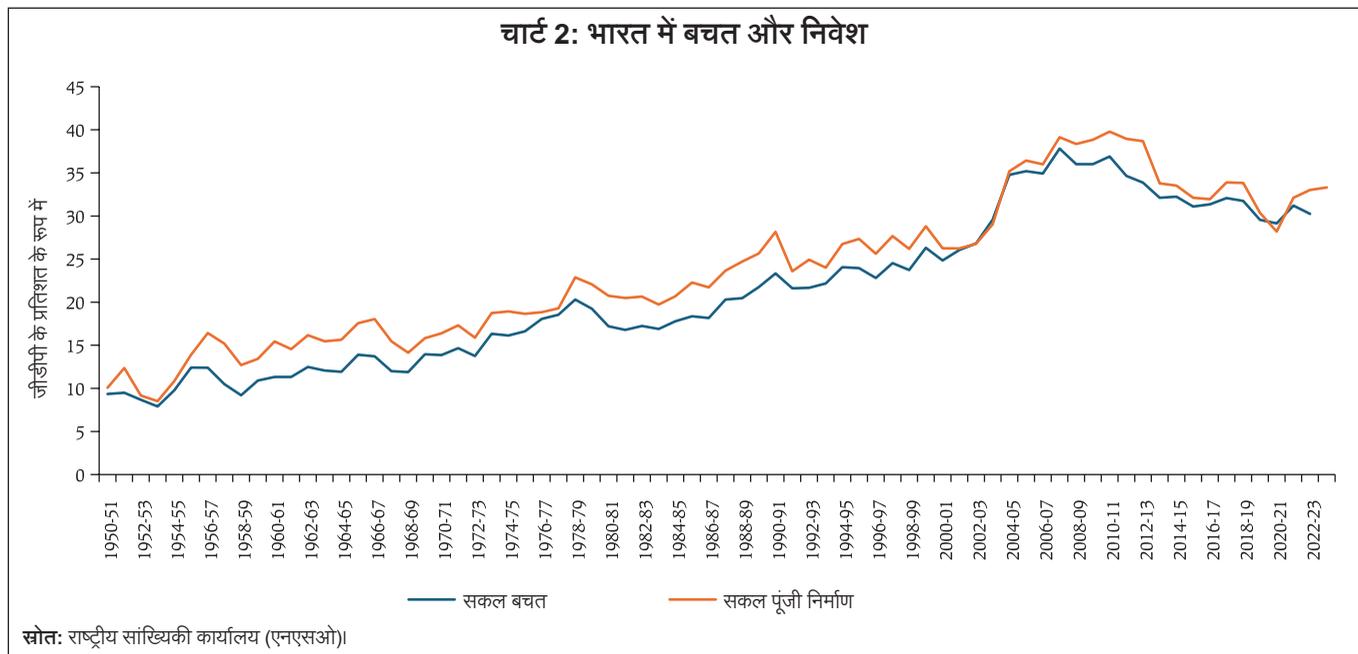
प्रगति के साथ जोखिम भरी आस्तियों में निवेश में वृद्धि पाई गई है। लगातार राजकोषीय घाटे से सकल बचत कम होती है और निजी निवेश कम हो जाता है। धर्मनिरपेक्ष ठहराव परिकल्पना के तहत, एक अर्थव्यवस्था नए निवेश की मांग की कमी के कारण बचत और निवेश में गिरावट का अनुभव कर सकती है और इससे ब्याज दरें लंबे समय तक कम रह सकती हैं (समर्स, 2016)।

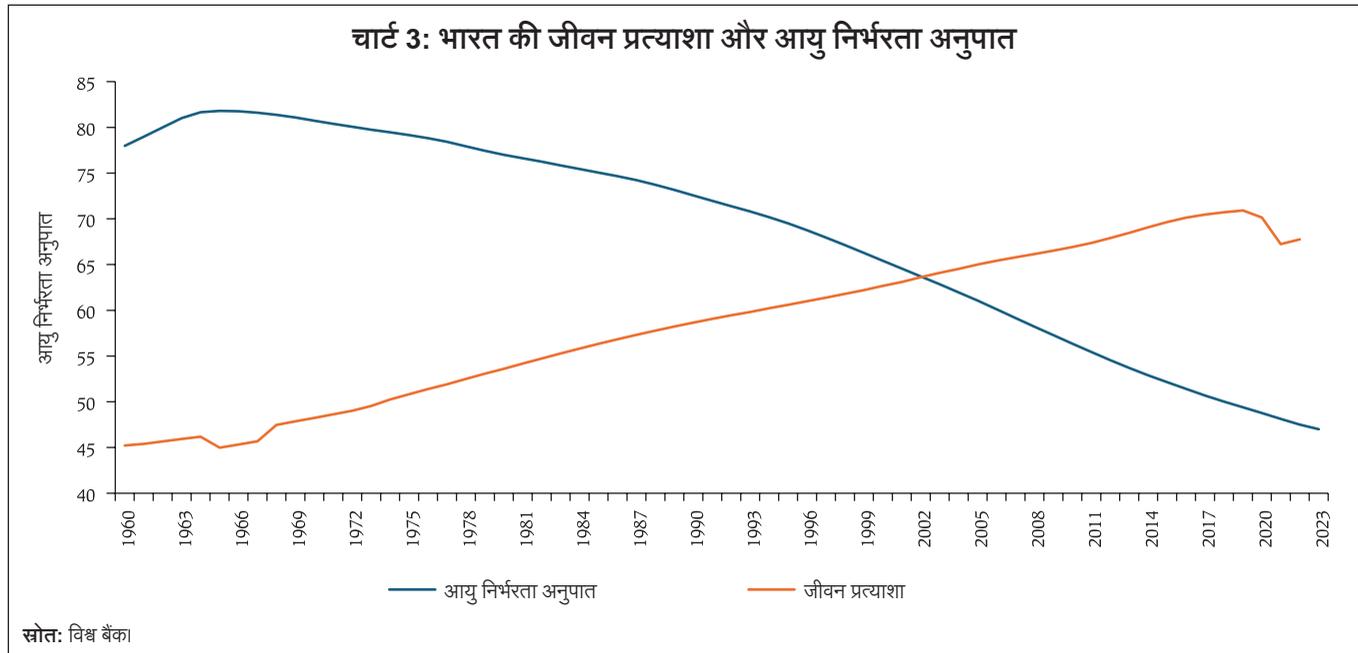
मुक्त पूंजी आवागमन के साथ एक एकीकृत दुनिया में, बचत-निवेश अंतराल को चालू खाता घाटे या अधिशेष के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है। हालांकि, प्राकृतिक दरों को अभी भी वैश्विक स्तर पर वास्तविक और संभावित उत्पादन और बचत और निवेश के बराबर समायोजित करने की आवश्यकता होगी।

लंबे समय में मौद्रिक नीति के प्रभाव के कारण प्राकृतिक दर भी भिन्न हो सकती है - हालांकि मानक समष्टिआर्थिक सिद्धांत यह मानता है कि मौद्रिक नीति लंबे समय में तटस्थ है और केवल क्षणभंगुर तरीके से वास्तविक चर को प्रभावित कर सकती है, हाल के कार्यों से पता चलता है कि मौद्रिक नीति का वास्तविक चर पर लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव हो सकता है (जोर्डॉ एवं अन्य., 2020; बेनिग्नो एवं अन्य., 2024; बोरियो एवं अन्य., 2019)।

इसके अलावा, लंबे समय तक मौद्रिक विस्तार ऋण और आस्ति मूल्य गतिकी को प्रभावित करके ऋण संचयन और वित्तीय असंतुलन को बढ़ावा दे सकता है और इस तरह लंबे क्षितिज पर प्राकृतिक दर को कम कर सकता है (बोरियो एवं अन्य., 2019; बोरियो एवं अन्य., 2022)। इस हद तक कि केंद्रीय बैंकों से अनुमानित संकेतों का निजी खपत और निवेश निर्णयों पर प्रभाव पड़ता है, इसके परिणामस्वरूप सूचनात्मक प्रतिक्रिया लूप भी हो सकते हैं जो प्राकृतिक दर में बदलाव को प्रेरित करते हैं।

भारत की जनसांख्यिकीय संरचना, जिसकी विशेषता एक महत्वपूर्ण युवा आबादी और बढ़ती कार्यशील आयु का समूह है, शिक्षा, आवास, विवाह और सेवानिवृत्ति के लिए उच्च बचत और निवेश के साथ-साथ वित्तीय देयताओं को प्रेरित करके ब्याज की प्राकृतिक दर को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। पूंजी की बढ़ती मांग निवेश में हालिया वृद्धि में परिलक्षित होती है (चार्ट 2)। यह जनसांख्यिकीय लाभ सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और नवाचार को भी बढ़ावा देता है। जैसे-जैसे जनसांख्यिकीय लाभांश परिपक्व होता है, बचत व्यवहार में बदलाव हो सकता है क्योंकि अधिक व्यक्ति सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचते हैं, संभावित रूप से समग्र बचत दर को कम करते हैं।

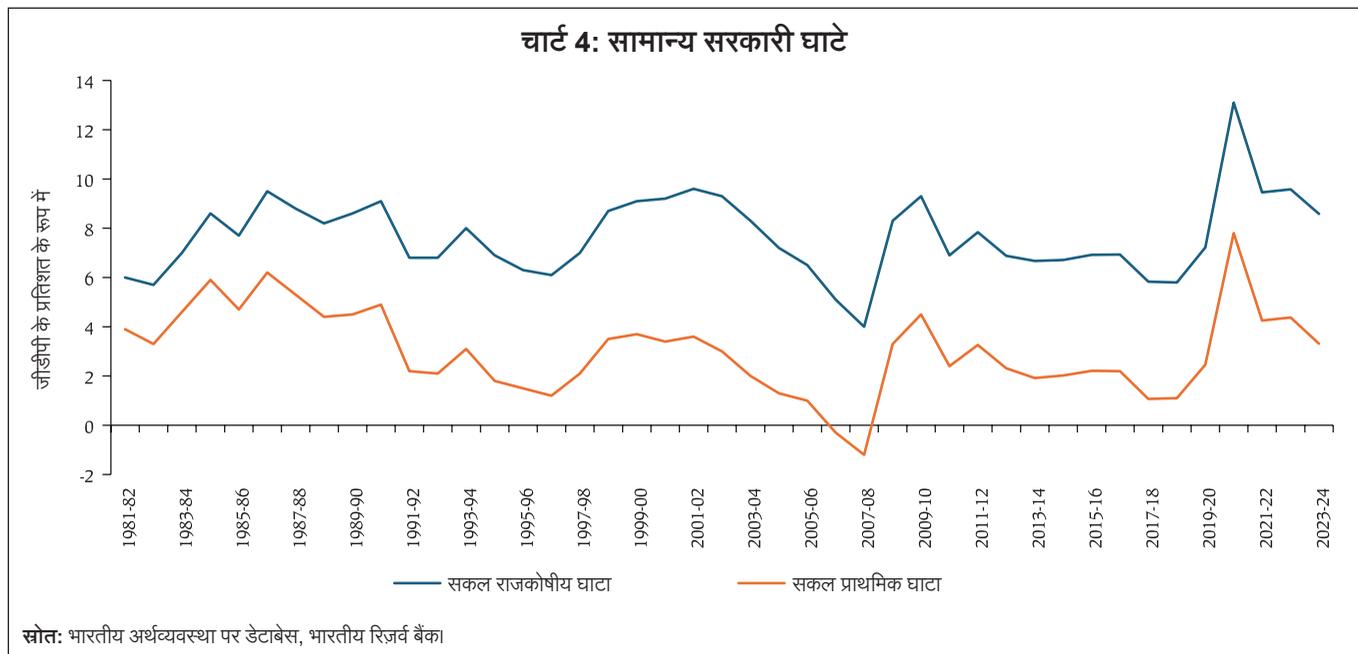


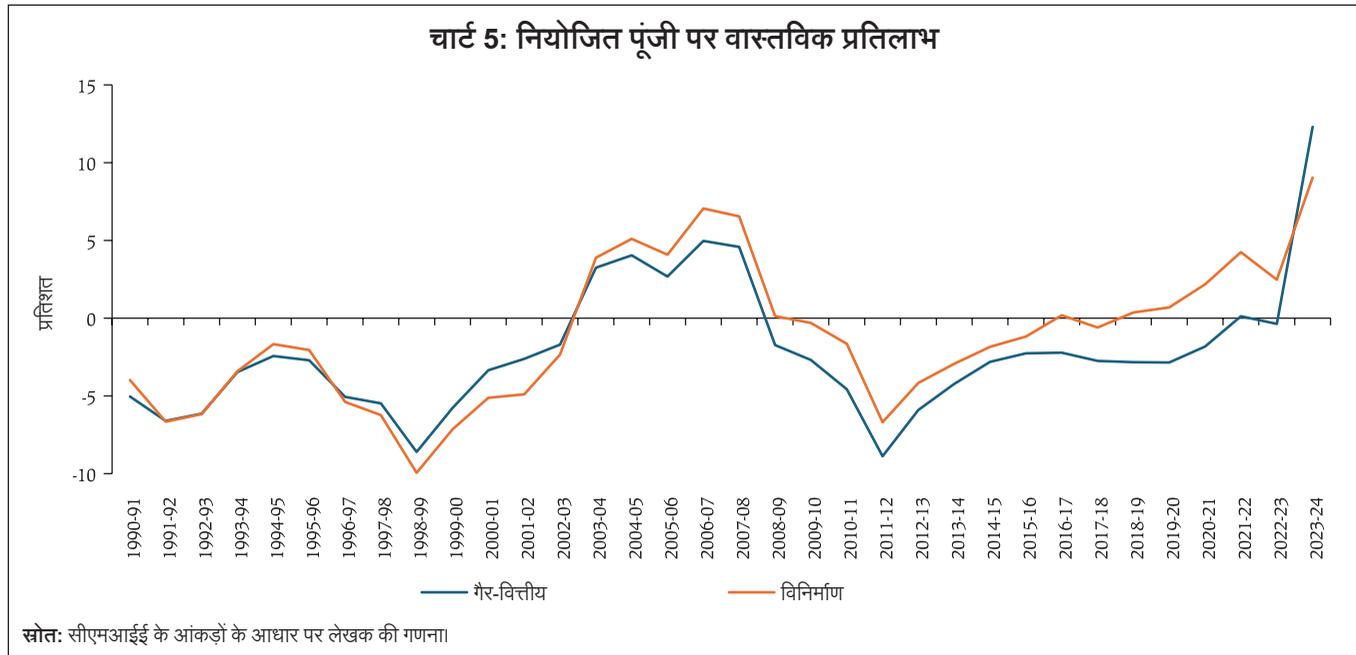


इसके अलावा, भारत कई जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का सामना करता है जैसे कि गिरता निर्भरता अनुपात जो बचत और निवेश क्षमता को बढ़ाता है (चार्ट 3)। हाल ही में, हालांकि, महामारी ने जीवन प्रत्याशा लाभ और आर्थिक स्थिरता में एक अस्थायी आघात लगाया है।

इसके अलावा, राजकोषीय समेकन वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए निवेश की मांग को संतुलित कर रहा है (चार्ट 4)।

ये सभी कारक भारत की दीर्घकालिक संवृद्धि क्षमता में वृद्धि में योगदान दे सकते हैं और भारतीय संदर्भ में साहित्य में पाई जाने वाली ब्याज की प्राकृतिक दर में गिरावट की प्रवृत्ति को उलट सकते हैं (जैसे, बेहरा एवं अन्य, 2016; पटनायक एवं अन्य.,





2022)। यह पहले से ही वास्तविक (मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के लिए समायोजन) दीर्घकालिक ब्याज दरों और हाल के वर्षों में पूंजी पर प्रतिलाभ में वृद्धि में परिलक्षित हो रहा है (चार्ट 5)।

जलवायु परिवर्तन और हरित संक्रमण और डिजिटलीकरण के लिए असाधारण रूप से उच्च निवेश की आवश्यकता होगी। चरम मौसम की घटनाओं की उच्च आवृत्ति पुनर्निर्माण और अनुकूलन दोनों के लिए व्यापक सार्वजनिक और निजी निवेश की आवश्यकता है। इसके अलावा, बढ़ते भू-राजनीतिक जोखिमों को देखते हुए, जो कंपनियां अपनी स्रोतीकरण कार्यनीतियों में विविधता लाकर अपनी आपूर्ति शृंखलाओं को अधिक लचीला बनाना चाहती हैं, वे उच्च निवेश की मांग उत्पन्न करेंगी। अपनी उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों जैसी पहलों के माध्यम से भारत के निर्यात पर जोर; और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की निर्यात क्षमता का समर्थन निवेश की मांग को और बढ़ा सकता है (पात्र, 2024)। इसके अलावा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटलीकरण में तेजी से प्रगति के लिए नई प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने और कार्यान्वित करने और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को नया आकार देने के लिए भौतिक और मानव पूंजी में बड़े सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि इन बड़े पैमाने पर समग्र निवेश आवश्यकताओं का हिस्सा सरकार द्वारा वित्तपोषित होगा, और यह कि, नई भू-राजनीतिक स्थिति

में, रक्षा व्यय में काफी वृद्धि करनी पड़ सकती है, सार्वजनिक ऋण बोझ बढ़ने की संभावना है। संक्षेप में, बढ़ती निवेश मांग को बढ़ावा देने वाली कई ताकतों से आगे चलकर ब्याज की प्राकृतिक दर में वृद्धि होने की उम्मीद है।

### III. ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए दृष्टिकोण

साहित्य में ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए कई दृष्टिकोण अपनाए जाते हैं। चुनौती सबसे मजबूत और कुशल को अपनाना है जो देश-विशिष्ट परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है।

#### III.1 सांख्यिकीय फ़िल्टरिंग के तरीके

प्राकृतिक दर को वास्तविक ब्याज दर में रुझानों द्वारा प्रॉक्सी किया जा सकता है। तदनुसार, सांख्यिकीय फ़िल्टर, जैसे, होड्रिक-प्रेसकॉट और कलमैन फ़िल्टर का उपयोग चक्रीय घटक को अवलोकित वास्तविक ब्याज दरों से अलग करके वास्तविक ब्याज दरों में अंतर्निहित प्रवृत्ति का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

#### III.2 संरचनात्मक आर्थिक मॉडल

डायनेमिक स्टोकेस्टिक जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल व्यक्तिआर्थिक आधारों को शामिल करता है और अनिश्चितता

के तहत समय के साथ आर्थिक एजेंटों के बीच तालमेल का पता लगाता है। वे प्राथमिकताओं, प्रौद्योगिकी और नीतिगत नियमों जैसे संरचनात्मक मापदंडों के आधार पर प्राकृतिक दर का आकलन करने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करते हैं। विशेष रूप से, ये मॉडल व्यापार चक्र पर प्राकृतिक दर का अनुमान लगाते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक दर पर नज़र रखने वाला केंद्रीय बैंक नाममात्र घर्षण की अनुपस्थिति में मुद्रास्फीति को या तो सहवर्ती रूप से या मध्यम अवधि में स्थिर करता है (डेल नीग्रो एवं अन्य., 2017; नेरी और गेराली, 2019)।

**अर्ध-संरचनात्मक मॉडल**, जैसे कि लाउबैक-विलियम्स (एलडब्ल्यू) मॉडल, डीएसजीई मॉडल की तुलना में कम संरचनात्मक मान्यताओं का उपयोग करते हैं। वे आम तौर पर एक फिलिप्स वक्र (मुद्रास्फीति की गतिशीलता का वर्णन) और एक आईएस वक्र (आउटपुट अंतर का वर्णन) को जोड़ते हैं और इसे अनुमानित डेटा से संतुलित करते हैं ताकि प्राकृतिक दर का अनुमान लगा सकें (लाउबैक और विलियम्स, 2003; होल्स्टन एवं अन्य., 2023)। मुख्य अंतर्ज्ञान यह है कि बढ़ती मुद्रास्फीति आम तौर पर संकेत देती है कि वर्तमान ब्याज दरें प्राकृतिक दर से नीचे हैं। मॉडल एक प्रवृत्ति / चक्र अपघटन के माध्यम से अल्पकालिक व्यापार चक्र में उतार-चढ़ाव को हटा देता है और प्राकृतिक दर में परिवर्तन को प्रवृत्ति आउटपुट वृद्धि और एक अवशिष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराता है जो अन्य संभावित वाहकों का पता लगाता है।

### III.3 समय शृंखला मॉडल

ये मॉडल अर्थमितीय तकनीकों के माध्यम से प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और आउटपुट अंतराल पर ऐतिहासिक डेटा का उपयोग करते हैं। वेक्टर प्रतिगमन (वीएआर) और बायेसियन वीएआर सामान्य तरीके हैं जो चर के बीच तालमेल की अनुमति देते हैं और वास्तविक ब्याज दर के पांच से दस वर्ष आगे के पूर्वानुमान के रूप में प्राकृतिक दर का अनुमान प्रदान करते हैं (लुबिक और मैथेस, 2015; जारोसिंस्की, 2017)।

### III.4 बाजार आधारित दृष्टिकोण

**(ए) वित्तीय बाजार डेटा:** वित्तीय बाजार के आंकड़ों से प्राप्त अनुमान जैसे कि सरकारी बॉण्ड पर प्रतिफल भी प्राकृतिक दर में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकती है। बॉण्ड की कीमतों में अंतर्निहित

ब्याज दरों और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं की अवधि संरचना विशेष रूप से उपयोगी है (होर्डहल और ट्रिस्टानी, 2014)।

**(बी) दूरदेशी उपाय:** ये उपाय सर्वेक्षण या स्वैप दरों जैसे बाजार संकेतकों से भविष्य की आर्थिक स्थितियों के बारे में अपेक्षाओं का या प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए वायदा अनुबंध उपयोग करते हैं। अर्थशास्त्रियों और वित्तीय विश्लेषकों के सर्वेक्षण अक्सर दीर्घकालिक मुद्रास्फीति अपेक्षाओं और दीर्घकालिक नीति दरों के अनुमानों से प्राकृतिक दर का आम सहमति अनुमान प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग नीति दर पूर्वानुमानों से मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को हटाकर प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है।

### III.5 नीतिगत नियम

टेलर नियम नाममात्र ब्याज दर को लक्ष्य से वास्तविक मुद्रास्फीति के विचलन और इसकी क्षमता से वास्तविक उत्पादन से संबंधित करता है। नियम को पुनर्व्यवस्थित करके, प्राकृतिक दर का अनुमान ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों और आर्थिक स्थितियों के आधार पर प्राप्त किया जा सकता है।

प्रत्येक विधि की अपनी ताकत और सीमाएं होती हैं, और अक्सर, ब्याज की प्राकृतिक दर का सबसे मजबूत अनुमान प्रदान करने के लिए दृष्टिकोणों के संयोजन का उपयोग किया जाता है।

## IV. भारत में ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान

वैश्विक स्तर पर, ब्याज की प्राकृतिक दर के अनुभवजन्य अनुमान वैश्विक वित्तीय संकट के बाद और महामारी के बाद अपने स्तर में बड़े बदलाव की ओर इशारा करते हैं (देखें होल्स्टन एवं अन्य., 2023; ब्रांड एवं अन्य., 2023; ओब्सटफेल्ड, 2023; बेनिग्नो एवं अन्य., 2024)। सांख्यिकीय फिल्टर के अनुप्रयोग से प्राप्त भारत में वास्तविक नीति दर के प्रवृत्ति स्तर में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद 200 आधार अंकों से अधिक की गिरावट आई है (पेरेल्ली और रोशे, 2014)। वैश्विक संकट के बाद एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में प्राकृतिक दरों में गिरावट आई है, जो घरेलू स्तर पर कम जीडीपी वृद्धि और कम वैश्विक तटस्थ दर को दर्शाती है (आईएमएफ, 2015)<sup>3</sup>। तीन अलग-अलग तरीके - सैद्धांतिक अंशांकन; अर्ध-संरचनात्मक मॉडलिंग; और एक विस्तारित टेलर नियम - वैश्विक संकट के बाद भारत की प्राकृतिक दर में क्रमशः 2.6 प्रतिशत, 4.2 प्रतिशत और 1.1 प्रतिशत की गिरावट की ओर

<sup>3</sup> एशिया और प्रशांत के लिए क्षेत्रीय आर्थिक आउटलुक, 2015

इशारा करते हैं। आईएमएफ के अनुमान बताते हैं कि प्राकृतिक दर घटकर लगभग 1 प्रतिशत हो गई है (आईएमएफ, 2023बी)। जबकि मुद्रास्फीति के विभिन्न उपायों (यानी, हेडलाइन और कोर सीपीआई) का उपयोग करके ब्याज की प्राकृतिक दर के एलडब्ल्यू-आधारित अनुमान ति3: 2021-22 के लिए 0.8 प्रतिशत (जब कोर सीपीआई मुद्रास्फीति को अपस्फीतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया गया था) से 1.0 प्रतिशत (जब हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति को अपस्फीतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया गया था) रहे, वित्तीय चक्र को शामिल करने वाले संबंधित संशोधित एलडब्ल्यू अनुमान 2.0 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत रहे

(पटनायक एवं अन्य., 2022)। इस प्रकार, भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान व्यापक विविधताओं को दर्शाता है (सारणी 1)

पहले के अभ्यासों में चित्रित कार्यप्रणाली (पटनायक एवं अन्य, 2022) का उपयोग करते हुए, जो मौलिक कार्य (लाउबाच और विलियम्स, 2003) और इसके विस्तारित संस्करण (बोरियो एवं अन्य, 2019) पर आधारित है, भारत के लिए प्राकृतिक दर के अनुमानों को इस खंड में अपडेट किया गया है। एलडब्ल्यू ढांचे में, मानक नवीन कीनेसियन प्रणाली जिसमें एक आईएस वक्र, एक फिलिप्स वक्र और एक नीति नियम शामिल हैं, को संभावित

**सारणी 1: भारत के लिए प्राकृतिक ब्याज दर का अनुमान**

लेखक (कों) और अध्ययन का वर्ष	वास्तविक ब्याज दर की गणना के लिए अपस्फीतिकारक का उपयोग	अध्ययन की अवधि	पद्धति	प्राकृतिक दर का अनुमान
दास और भोले (2011)	हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मांग मुद्रा दर पर लागू की गई। खाद्येतर विनिर्माण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मांग मुद्रा दर पर लागू की गई है।	1986-87 से 2010-11 तक के वार्षिक आंकड़े	राज्य क्षेत्र ढांचा जिनका अवलोकन नहीं हुआ	2000-2011 के लिए 2.01 प्रतिशत; 1995-2000 के लिए 3.37 प्रतिशत; 1986-1995 के लिए 4.08 प्रतिशत. 2000-2011 के लिए 4.93; 1995-2000 के लिए 3.98 प्रतिशत; 1986-1995 के लिए 9.11 प्रतिशत.
आईएमएफ (2015)	सीपीआई	2008 की चौथी तिमाही से 2014 की तीसरी तिमाही तक का तिमाही डेटा	केलिब्रेटेड यूलर समीकरण  लाउबेक और विलियम्स (2003)	2001-08 में 3.7 प्रतिशत; 2009-14 में 2.6 प्रतिशत.  2001-08 में 5.4 प्रतिशत; 2009-14 में 4.2 प्रतिशत.
गोयल और अरोड़ा (2016) <sup>#</sup>	एक अवधि आगे तिमाही-दर-तिमाही गैर-खाद्य विनिर्माण डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति मांग मुद्रा दर पर लागू की गई है।	1990 की दूसरी तिमाही से 2011 की चौथी तिमाही तक तिमाही डेटा	लाउबेक-विलियम (2003) दृष्टिकोण;  अधिकतम संभावना अनुमान	2011 की चौथी तिमाही के लिए मामूली रूप से नकारात्मक 5 प्रतिशत से ऊपर:  पूर्ण नमूना अवधि के लिए -15 प्रतिशत से 15 प्रतिशत।
बेहरा एवं अन्य., (2017)	विश्व आर्थिक सर्वेक्षण से एक वर्ष आगे अपेक्षित मुद्रास्फीति के आंकड़े।  अपेक्षित मुद्रास्फीति एक रोलिंग एआर (1) मॉडल से प्राप्त होती है।  91 दिनों के टी-बिल और नीतिगत रेपो दर पर लागू	1996 की दूसरी तिमाही से 2015 की पहली तिमाही तक तिमाही डेटा	लाउबेक-विलियम (2003) दृष्टिकोण; अधिकतम संभावना अनुमान	वास्तविक ब्याज दर के सभी मॉडल और विभिन्न उपाय: 2015 की पहली तिमाही के लिए 0.6 प्रतिशत से 3.1 प्रतिशत।  कोर अनुमान: 2015 के लिए 1.6 प्रतिशत से 1.8 प्रतिशत: ति1 (एलडब्ल्यू दृष्टिकोण)।
पटनायक एवं अन्य (2022)	सीपीआई-सी मुद्रास्फीति से प्राप्त मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ 91 दिनों के टी-बिल प्रतिफल पर लागू की गई हैं।	1996 से तिमाही डेटा: ति2 से 2021: ति4	लाउबेक-विलियम (2003) दृष्टिकोण; संशोधित एलडब्ल्यू दृष्टिकोण वित्तीय चक्र के प्रभावों को शामिल करता है; अधिकतम संभावना अनुमान	2021 के लिए 0.8 प्रतिशत से 1.0 प्रतिशत: ति4 (एलडब्ल्यू दृष्टिकोण)।  2021 के लिए 2.0 प्रतिशत से 2.1 प्रतिशत: ति4 (संशोधित एलडब्ल्यू दृष्टिकोण)।

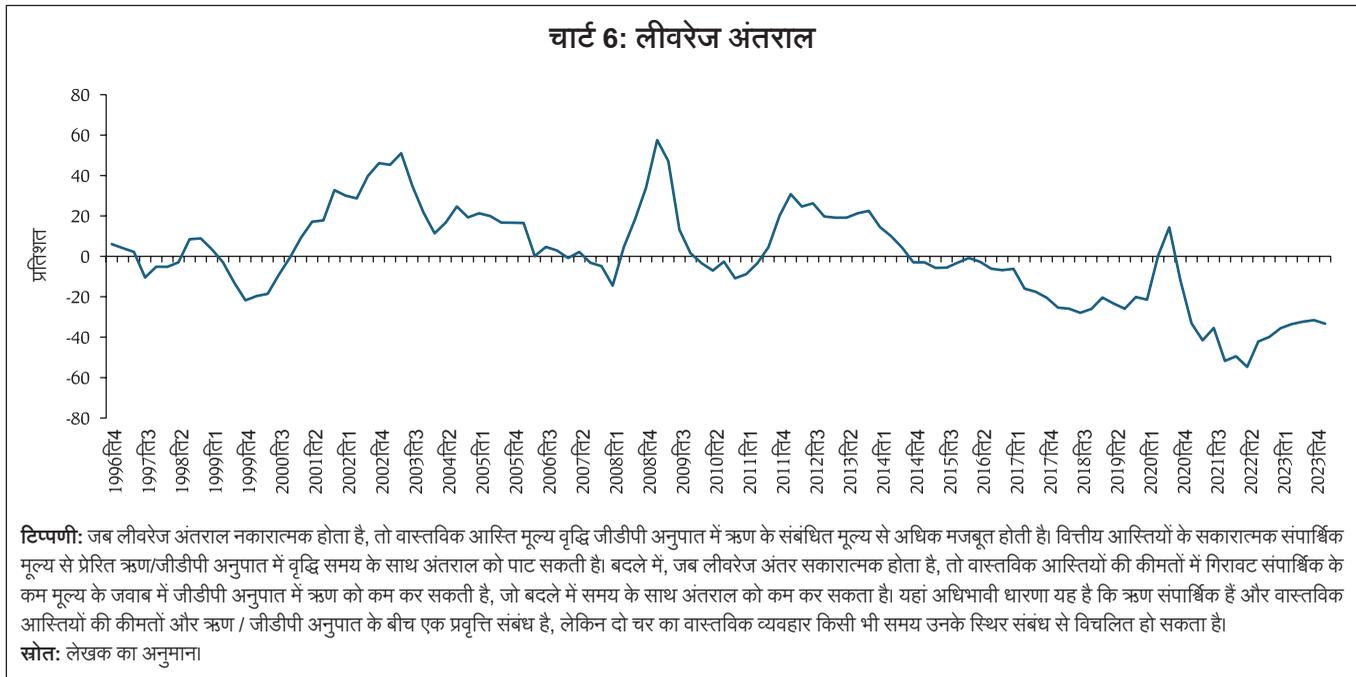
#: पेपर में प्रस्तुत चार्ट से लगाया गया अनुमान।

आउटपुट वृद्धि के एक प्रकार्य के रूप में प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए नियोजित किया जाता है और कई अन्य निर्धारक 'जेड' नामक कम आवृत्ति चर में शामिल होते हैं<sup>4</sup> यह दृष्टिकोण प्राकृतिक दर को वास्तविक ब्याज दर के स्तर के रूप में मानता है जो कुल मांग और समग्र आपूर्ति के लिए क्षणिक आघात की अनुपस्थिति में अपने संभावित स्तर पर आउटपुट और लक्ष्य पर मुद्रास्फीति के अनुरूप है। संशोधित एलडब्ल्यू विधि अतिरिक्त रूप से वित्तीय चक्र के लिए प्रॉक्सी के रूप में लीवरेज गैप के साथ आईएस वक्र को बढ़ाती है और वित्तीय चक्र के साथ मौद्रिक नीति की बातचीत को शामिल करने के लिए लीवरेज अंतर के लिए एक अलग समीकरण जोड़ा जाता है (जुसेलियस एवं अन्य., 2016 और बोरियो एवं अन्य., 2019)। लीवरेज अंतराल का अनुमान एक सह-एकीकृत प्रतिगमन द्वारा लगाया जाता है (पटनायक एवं अन्य., 2022)।

1996 की दूसरी तिमाही से 2024 की पहली तिमाही तक की अवधि के लिए प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए वास्तविक जीडीपी, सीपीआई मुद्रास्फीति, 3 महीने के खज़ाना

बिल प्रतिफल, बैंक क्रेडिट और बीएसई सेंसेक्स (भारत की इक्विटी कीमतों के प्रॉक्सी के रूप में) पर तिमाही समय शृंखला डेटा का उपयोग प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है<sup>5</sup>। मॉडल में उपयोग की जाने वाली वास्तविक ब्याज दर (आर) की गणना 3-माह के खज़ाना बिल प्रतिफल और पूर्व-प्रत्याशित मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के बीच अंतर को मौसमी रूप से समायोजित सीपीआई में तिमाही-दर-तिमाही परिवर्तनों की चार-तिमाही गतिशील औसत की प्रवृत्ति के रूप में की जाती है। भारत के लिए अनुमानित लीवरेज अंतराल ऋण में तेज़ वृद्धि और आस्ति कीमत में उतार-चढ़ाव की घटनाओं का सही से पता लगाता है (चार्ट 6)। एक ऋणात्मक लीवरेज अंतराल से पता चलता है कि महामारी को छोड़कर, हाल के वर्षों में क्रेडिट-जीडीपी अनुपात की तुलना में आस्तियों (इक्विटी) की कीमतें अपेक्षाकृत अधिक हैं।

अधिकतम संभावना अनुमान (एमएलई) विधियों में समस्याओं को दूर करने के लिए और समस्याओं के बढ़ने से बचने के लिए<sup>7</sup>, हम अपेक्षाकृत कम पूर्वगामी के साथ बायेसियन



<sup>4</sup> मूल लाउबाक और विलियम्स (2005) में, प्राकृतिक दर ( $r_t^*$ ) इस प्रकार दी गई है :  $r_t^* = c g_t + z_t$

जहां  $c$  जोखिम से बचने का मापदंड स,  $g_t$  भावित वृद्धि है और  $z_t$  संभावित वृद्धि में शामिल नहीं की गई प्राकृतिक दर का अन्य निर्धारक है।

<sup>5</sup> डेटा और उनके स्रोतों के बारे में विवरण के लिए कृपया पटनायक एवं अन्य., (2022) देखें।

<sup>6</sup> पेसकाटोरी और टुरुनेन (2016) में यह भी दिखाया गया है कि एक बायसियन दृष्टिकोण एलडब्ल्यू मॉडल में एमएलई की तुलना में अधिक प्रशंसनीय परिणाम उत्पन्न करने के लिए अन्य जानकारी दी गई है।

<sup>7</sup> प्रवृत्ति-चक्र अपघटन के मानक अधिकतम संभावना अनुमान में, जमा होने की समस्या तब होती है जब प्रवृत्ति के लिए एक आघात का मानक विचलन शून्य की ओर पक्षपाती होता है।

विधियों को नियोजित करते हैं, अर्थात्, सभी चर गुणांक के लिए बीटा वितरण और आघात प्रसरण के लिए गामा वितरण विभिन्न मापदंडों के पीछे के अनुमानों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। पूर्वगामी के साधनों और मानक विचलनों को निर्दिष्ट करने की धारणाएं अधिकांशतः साहित्य में भारत के लिए मौजूदा अनुमानों के साथ-साथ विभिन्न चरों की एचपी फ़िल्टर्ड शृंखला के अनुमानों से प्रेरित होती हैं, जहां भी पैरामीटर अनुमान साहित्य में उपलब्ध नहीं हैं। हम साहित्य के अनुरूप 0.99 के बराबर मान के साथ समय प्राथमिकता ( $\rho$ ) की दर को जांचते हैं। जैसा कि हमने गैर-स्थिर चर के साथ मॉडल का अनुमान लगाया है, हम मॉडल का अनुमान लगाने के लिए मेट्रोपोलिस-हेस्टिंग्स एल्गोरिथ्म के साथ एक विस्तृत कलमैन फ़िल्टर का उपयोग करते हैं। परिणामों का प्रत्येक सेट 10,000 की बर्न-इन अवधि के बाद 10,000 पोस्टीरियर ड्रॉ पर आधारित है। प्रत्येक सीमांत संभावना मूल्य की गणना के लिए, हम 50,000 महत्वपूर्ण नमूना ड्रॉ का उपयोग करते हैं।

#### IV.1 परिणाम

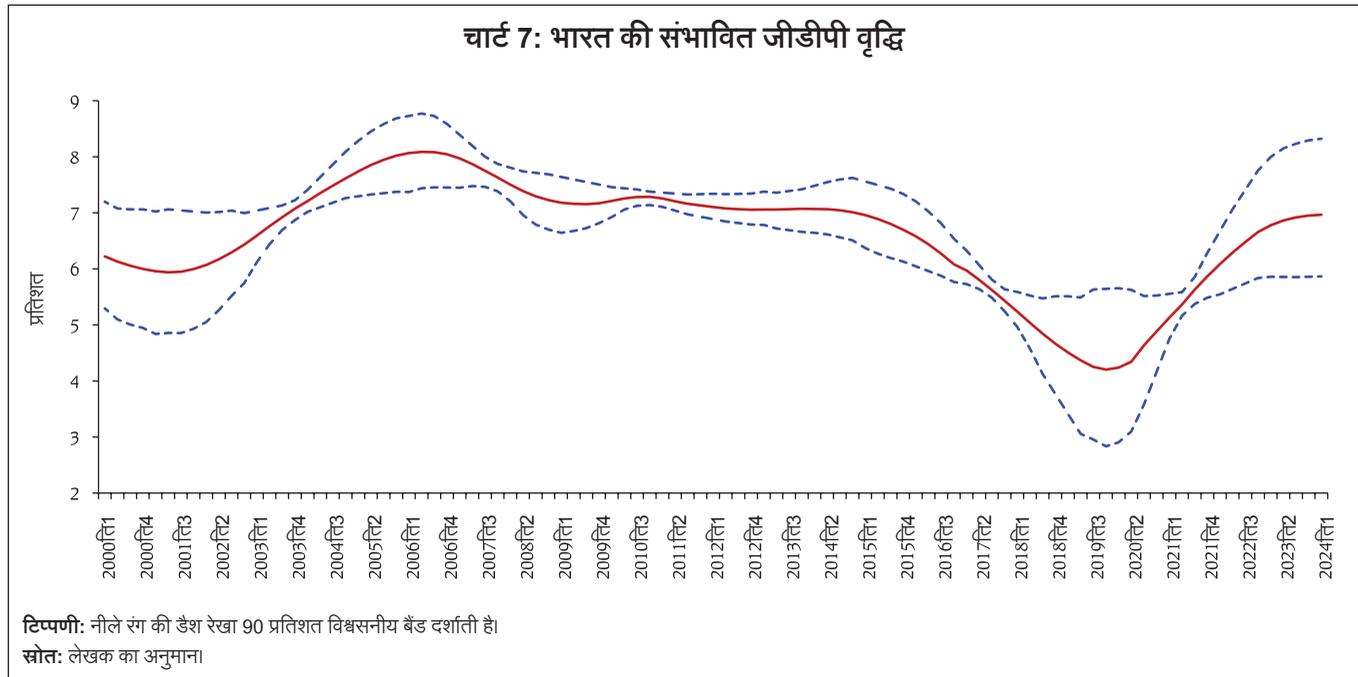
मॉडल में मापदंडों के पश्चगामी के अनुमान पूर्वगामी से अलग पाए जाते हैं, जिससे वे प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए

उपयोग के उपयुक्त हो जाते हैं (सारणी 2)। पश्चगामी अनुमानों से संकेत मिलता है कि आउटपुट अंतराल लीवरेज अंतराल से प्रभावित है (ए ला जुसेलियस एवं अन्य., 2016)। हालांकि, कुछ चेतावनियों को पहचानने की आवश्यकता है। सबसे पहले, आईएस वक्र समीकरण में लीवरेज अंतराल को शामिल करने से आउटपुट अंतराल की दृढ़ता बढ़ जाती है, जो मांग की स्थिति (या आउटपुट अंतराल) पर मौद्रिक नीति (या वास्तविक ब्याज दर अंतर) के कमजोर प्रभाव को दर्शाता है। दूसरा, लीवरेज अंतराल उच्च स्तर की दृढ़ता प्रदर्शित करता है। तीसरा, हमें भारत में वित्तीय चक्रों को प्रभावित करने में मौद्रिक नीति की प्रमुख भूमिका नहीं मिली क्योंकि लीवरेज अंतराल समीकरण में वास्तविक ब्याज दर अंतर ( $Y_2$ ) का गुणांक छोटा है।

पश्चगामी माध्य अनुमानों से संकेत मिलता है कि महामारी के बाद की अवधि में भारत के संभावित उत्पादन में गिरावट में उल्टा रुख देखा गया (चार्ट 7)। ति4: 2023-24 के लिए संभावित उत्पादन की वृद्धि लगभग 7 प्रतिशत अनुमानित है। विभिन्न चरणों में व्यापक विश्वसनीय बैंड अनुमानों के बारे में बड़ी अनिश्चितता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार, वर्तमान में संभावित उत्पादन की वृद्धि 5.9 प्रतिशत से 8.3 प्रतिशत के बीच हो सकती है।

सारणी 2: लीवरेज गैप के साथ और उसके बिना पैरामीटर अनुमान

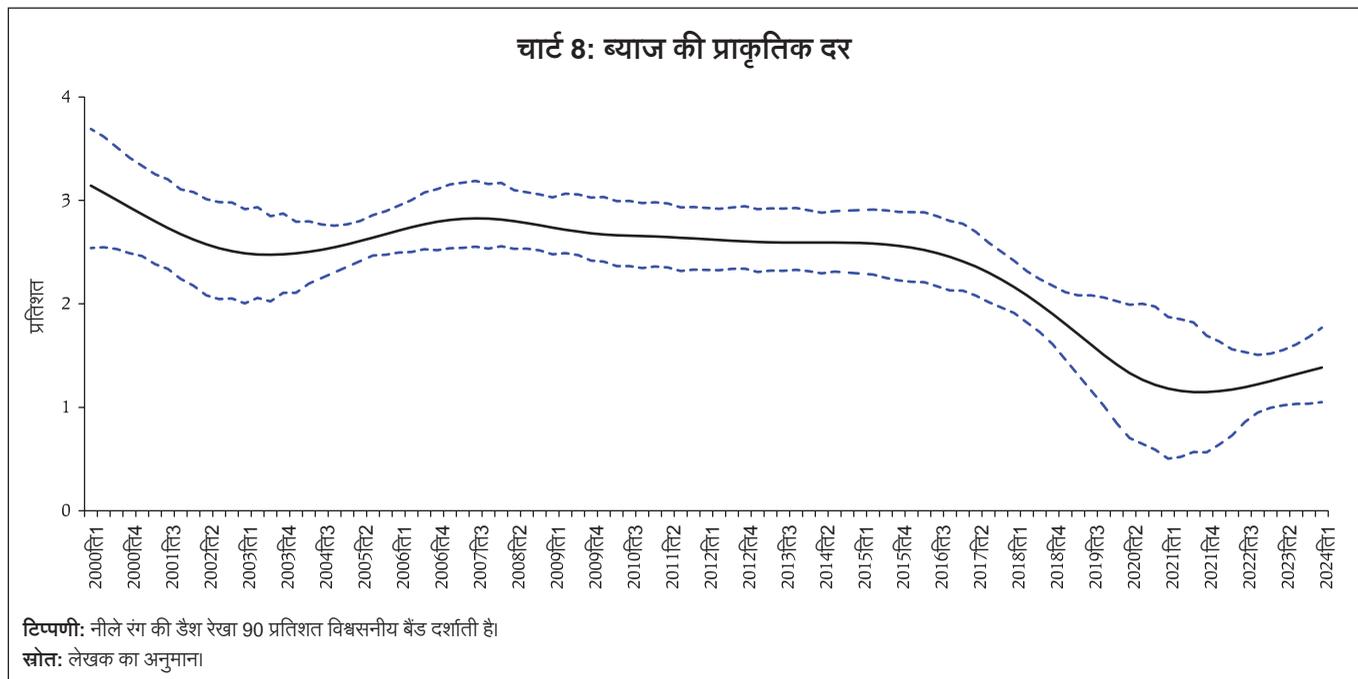
समीकरण	पैरामीटर	चर	लीवरेज गैप के बिना				लीवरेज गैप के साथ			
			पूर्व माध्य	पूर्व एस.डी.	पश्च माध्य	पश्च एस.डी.	पूर्व माध्य	पूर्व एस.डी.	पश्च माध्य	पश्च एस.डी.
आईएस वक्र	$\phi_1$	$(Y_{t-1} - Y_{t-1}^e)$	0.6	0.15	0.571	0.116	0.6	0.15	0.575	0.108
	$\phi_2$	$(Y_{t-2} - Y_{t-2}^e)$	0.3	0.15	0.087	0.050	0.3	0.15	0.084	0.047
	$\gamma_1$	$(r_{t-1} - r_{t-1}^e)$	0.3	0.15	0.142	0.077	0.3	0.15	0.141	0.077
	$\phi_3$	$levg_{t-1}$					0.2	0.07	0.211	0.068
फिलिप्स वक्र	$b_1$	$(Y_t - Y_t^e)$	0.13	0.05	0.064	0.021	0.13	0.05	0.065	0.021
	$b_2$	$(Y_{t-1} - Y_{t-1}^e)$	0.11	0.05	0.054	0.021	0.11	0.05	0.055	0.021
टेलर नियम	$\beta_9$	$i_{t-1}$	0.8	0.19	0.872	0.032	0.8	0.19	0.873	0.032
	$\beta_{10}$	$(\pi_t^{ov} - \pi_t^e)$	1.5	0.1	1.503	0.100	1.5	0.1	1.506	0.099
	$\beta_{11}$	$Y_t$	0.3	0.07	0.310	0.069	0.3	0.07	0.334	0.080
प्राकृतिक दर	$\beta_1$	$r_{t-1}^e$	0.95	0.025	0.911	0.027	0.95	0.025	0.924	0.021
लीवरेज अंतराल	$\beta_2$	$levg_{t-1}$					0.5	0.2	0.901	0.031
	$\gamma_2$	$(r_t - r_t^e)$					0.3	0.2	0.003	0.002



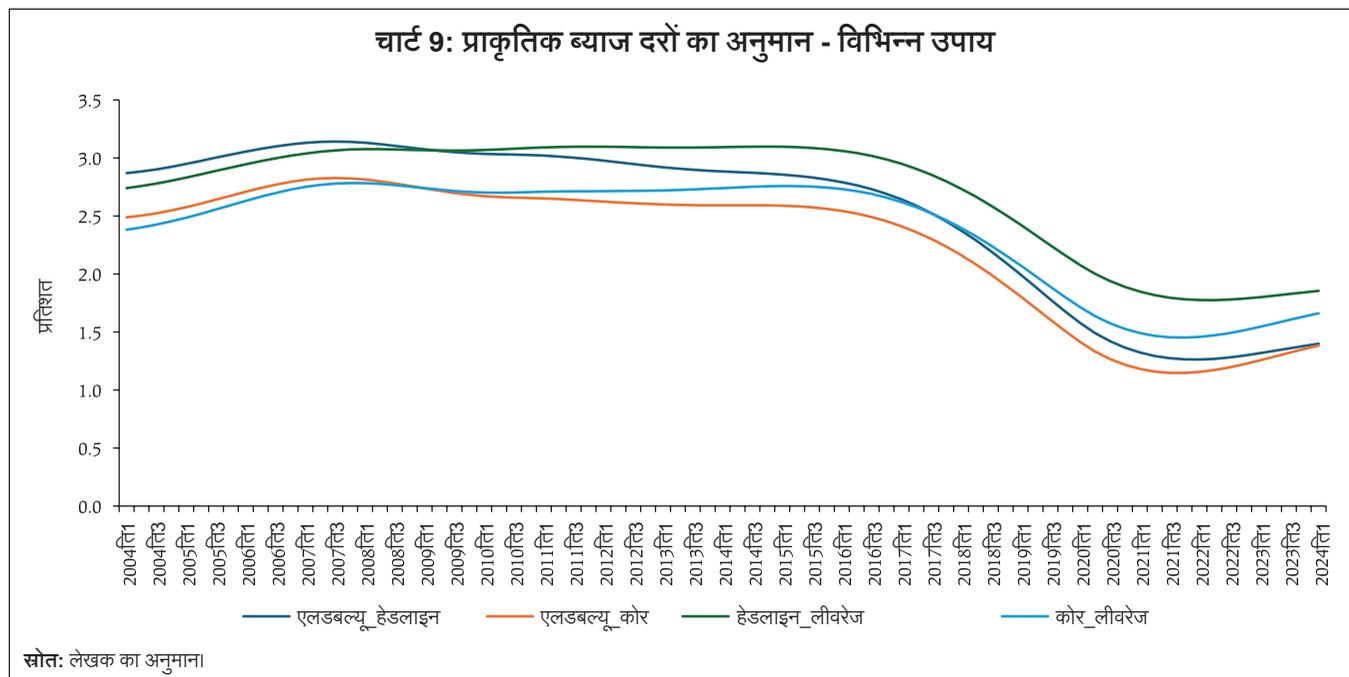
इसके अनुरूप, प्राकृतिक दर 1.4 प्रतिशत अनुमानित है, जो महामारी के बाद भी बढ़ने लगी है। महामारी के दौरान व्यापक विश्वसनीय बैंड हाल ही में संकुचित हो गए हैं (चार्ट 8)।

महामारी के बाद की अवधि में भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर का अनुमान एक ऊपर की ओर बढ़ने को दर्शाता

है, जो संभावित उत्पादन में मजबूत वृद्धि से प्रेरित है। ति3: 2021-22 के लिए पहले अनुमानित ब्याज की प्राकृतिक दर को 0.8 -1.0 प्रतिशत से 1.1-1.3 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है, जो जीडीपी डेटा में संशोधन को दर्शाता है। वर्तमान अनुमान ति4: 2023-24 के लिए 1.4-1.9 प्रतिशत के बीच एक विस्तृत शृंखला का सुझाव देते हैं (चार्ट 9)<sup>8</sup>



<sup>8</sup> कोविड-19 प्रभाव के लिए स्पष्ट रूप से पता करने के लिए होलस्टन एवं अन्य., (2023) दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, ति4:2023-24 के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर 1.4 प्रतिशत अनुमानित है।



## V. निष्कर्ष

महामारी के बाद के आंकड़ों के साथ भारत के लिए ब्याज की प्राकृतिक दर के अनुमानों को अपडेट करते हुए, हम संभावित उत्पादन की वृद्धि से प्रेरित एक ऊपर की ओर बदलाव पाते हैं। ति4: 2023-24 के लिए प्राकृतिक दर का अनुमान ति3: 2021-22 के लिए 0.8-1.0 प्रतिशत के अनुमानों की तुलना में 1.9 प्रतिशत तक की व्यापक सीमा की निचली सीमा के रूप में 1.4 प्रतिशत है। महामारी के बाद हमारे वर्तमान अनुमानों के आसपास व्यापक विश्वसनीय बैंड से हटकर, प्राकृतिक दर को समझने और नियमित अपडेट के साथ इसे सटीक रूप से मापने के महत्व पर अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है। नीति निर्माताओं और वित्तीय बाजार सहभागियों को प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए अपने दृष्टिकोण को लगातार परिष्कृत करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह उन नीतियों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शिका बनी रहे जिनका लक्ष्य धारणीय आर्थिक वृद्धि और स्थिरता प्राप्त करना है।

## संदर्भ

Behera, H. K., Pattanaik, S., and Kavediya, R. (2017). Natural Interest Rate: Assessing the Stance of India's Monetary Policy under Uncertainty. *Journal of Policy Modeling*, 39(3), 482-498.

Benigno, G., Hofmann, B., Barrau, G.N. and Sandri, D. (2024). Quo vadis,  $r^*$ ? The Natural Rate of Interest after the Pandemic. *BIS Quarterly Review*, March, 17-30.

Boocker, S., Ng, M. and Wessel, D. (2023). What is the Neutral Rate of Interest? Commentary, Brookings, URL: <https://www.brookings.edu/articles/the-hutchins-center-explains-the-neutral-rate-of-interest/>

Borio, C., Disyatat, P. and Rungcharoenkitkul, P. (2019). What Anchors for the Natural Rate of Interest? BIS Working Papers, No 777, March.

Borio, C., Disyatat, P. Juselius, M. and Rungcharoenkitkul, P. (2022). Why So Low for So Long? A Long-term View of Real Interest Rates. *International Journal of Central Banking*, 18(3), 47-87.

Brand, C., Lisack, N. and Mazelis, F. (2023). Estimates of the Natural Interest Rate for the Euro Area: An Update. *ECB Economic Bulletin*, Issue 8, 66-69.

Dash, P. and Bhole, L. M. (2011). Measuring the Natural Rate of Interest for India. *The Indian Economic Journal*, 59(3), 38-55.

Del Negro, M., Giannone, D., Giannoni, M. and Tambalotti, A. (2017). Safety, Liquidity, and the

- Natural Rate of Interest. *Brookings Papers on Economic Activity*, 48, Spring, 235–316.
- Goyal, A. and Arora, S. (2016). Estimating the Indian Natural Interest Rate: A Semi-structural Approach. *Economic Modelling*, 58, 141-153.
- Holston, K., Laubach, T., and Williams, J. C. (2023). Measuring the Natural Rate of Interest after COVID-19. Federal Reserve Bank of New York Staff Reports, No. 1063.
- Hördahl, P. and Tristani, O. (2014). Inflation Risk Premia in the Euro Area and the United States. *International Journal of Central Banking*, September, 1-47.
- International Monetary Fund (2015). Regional Economic Outlook: Asia and Pacific, April.
- (2023a). The Natural Rate of Interest: Drivers and Implications for Policy. In: *World Economic Outlook: Chapter 2*, April, 45-67.
- (2023b). India: 2023 Article IV Consultation Report, Country Report No. 426, December.
- Jarocinski, M. (2017). VAR-based Estimation of the Euro Area Natural Rate of Interest. ECB Draft Paper.
- Jordà, Ò., Singh, S. R., and Taylor, A. M. (2020). The Long Economic Hangover of Pandemics. *Finance & Development*, 57(2), 12-15.
- Jordan, T.J. (2024). The Natural Rate of Interest ( $r^*$ ) as a Reference Point for Monetary Policy - A Practitioner's View. Keynote speech at the 2024 Bank of Korea International Conference, Seoul, May 30.
- Juselius, M., Borio, C., Disyatat, P. and Drehmann, M. (2016). Monetary Policy, the Financial Cycle and Ultra-low Interest Rates. BIS Working Papers, No. 569.
- Lubik, T and Matthes, C. (2015). Calculating the Natural Rate of Interest: A Comparison of Two Alternative Approaches. Federal Reserve Bank of Richmond, Economic Brief, No 15-10, October.
- Neri, S., and Gerali, A. (2019). Natural Rates Across the Atlantic. *Journal of Macroeconomics*, 62, 103019.
- Patra, M.D. (2024). The Indian Economy - Opportunities and Challenges. Keynote Address at Nomura's 40th Central Bankers Seminar, Kyoto, 25 March.
- Pattanaik, Behera, H. and Sharma, S. (2022). Revisiting India's Natural Rate of Interest. *RBI Bulletin*, June, 89-99.
- Perrelli, R. and Roache, S.K. (2014). Time-Varying Neutral Interest Rate – The Case of Brazil. IMF Working Paper, No. 84, May.
- Powell, J.H. (2023). Inflation: Progress and the Path Ahead. Speech delivered at "Structural Shifts in the Global Economy," An Economic Policy Symposium sponsored by the Federal Reserve Bank of Kansas City, Jackson Hole, Wyoming, August 25.
- Pescatori, A. and Turunen, J. (2016). Lower for Longer: Neutral Rate in the US. *IMF Economic Review*, 64, 708-731.
- Schnabel, I. (2024). R(ising) star? Speech delivered at The ECB and its Watchers XXIV Conference Session on: Geopolitics and Structural Change: Implications for Real Activity, Inflation and Monetary Policy, March 20.
- Summers, L. (2016). The Age of Secular Stagnation: What It Is and What to Do About It. *Foreign Affairs*, February 15.
- Tanaka, K., Ibrahim, P., and Brekermans, S. (2021). The Natural Rate of Interest in Emerging Asia: Long-term Trends and the Impact of Crises. ADBI Working Paper Series, No. 1263.
- Wicksell, K. (1898). *Interest and Prices*, London, Macmillan (translation by R.F. Kahn published in 1936).

### परिशिष्ट: अनुभवजन्य मॉडल

इस आलेख में लॉबैक और विलियम्स (2003, अब से एलडबल्यू) के मौलिक कार्य को अपनाया गया है, जिसमें टेलर-प्रकार के नियम और इसके विस्तारित संस्करण को शामिल करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया गया है (जुसेलियस एवं अन्य., 2016)। एलडबल्यू फ्रेमवर्क ब्याज की प्राकृतिक दर ( $r_t^*$ ) को संभावित (या प्रवृत्ति) वृद्धि ( $g_t$ ) और बचत-निवेश संतुलन ( $z_t$ ) को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों के योग के रूप में परिभाषित करता है:

$$r_t^* = cg_t + z_t \quad \dots (1)$$

जहां  $c$  जोखिम से बचने का पैरामीटर है और इसे सामान्यतः एक माना जाता है।

समीकरण (1) का एक संशोधित संस्करण, जो प्राकृतिक दर के उतार-चढ़ाव में धीमी समायोजन प्रक्रिया पर विचार करता है, इसे इस रूप में लिखा जा सकता है:

$$r_t^* = \beta_1 r_{t-1}^* + (1 - \beta_1)(cg_t + z_t) \quad \dots (2)$$

अप्रमाणित संभावित आउटपुट ( $y_t^*$ ) और इसकी वृद्धि दर ( $g_t$ ) को संचालित करने वाले गति के नियमों को क्रमशः स्टोकेस्टिक ड्रिफ्ट और एक यादृच्छिक वॉक प्रक्रिया के साथ यादृच्छिक वॉक के रूप में निर्दिष्ट किया गया है:

$$y_t^* = y_{t-1}^* + g_{t-1} + \varepsilon_t^{y^*} \quad \dots (3)$$

$$g_t = g_{t-1} + \varepsilon_t^g \quad \dots (4)$$

$z_t$  एक यादृच्छिक वॉक प्रक्रिया का अनुसरण करता है;

$$z_t = z_{t-1} + \varepsilon_t^z \quad \dots (5)$$

जहाँ  $\varepsilon_t^{y^*}$ ,  $\varepsilon_t^g$  और  $\varepsilon_t^z$  क्रमिक और समसामयिक रूप से असंबद्ध त्रुटि पद हैं।

मॉडल में एक समग्र मांग (आईएस वक्र) और न्यू कीनेसियन ढांचे के अनुरूप एक फिलिप्स वक्र संबंध भी शामिल है:

$$\tilde{y}_t = (y_t - y_t^*) = \phi_1 \tilde{y}_{t-1} - \phi_2 \tilde{y}_{t-2} - \gamma_1 (r_{t-1} - r_{t-1}^*) + \varepsilon_t^{\tilde{y}} \quad \dots (6)$$

$$(\pi_t - \pi_t^*) = b_1 \tilde{y}_{t-1} + b_2 \tilde{y}_{t-2} + \varepsilon_t^\pi \quad \dots (7)$$

$$\text{मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के साथ : } \pi_t^* = \pi_{t-1}^* + \varepsilon_t^\pi \quad \dots (7)$$

जहाँ  $\tilde{y}_t$  आउटपुट अंतराल है।  $r_t$  वास्तविक ब्याज दर है,  $\pi_t^*$  मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ हैं जो इससे प्राप्त होती हैं

इसकी अंतर्निहित प्रवृत्ति जो एक यादृच्छिक वॉक की प्रक्रिया का अनुसरण करती है। कुल मांग (उत्पादन अंतराल) वास्तविक ब्याज दर में परिवर्तन (अल्पावधि में नाममात्र ब्याज दर में परिवर्तन के माध्यम से प्राप्त) पर प्रतिक्रिया करती है, जो बदले में ति-द-ति वार्षिक मुद्रास्फीति ( $\pi_t$ ) को प्रभावित करती है। यह दिए गए  $r_t^*$  के लिए समय-भिन्न ( $\pi_t^*$ ) और ( $y_t - y_t^*$ ) पर आधारित एक फीडबैक नियम का पालन करता है।

एलडबल्यू फ्रेमवर्क को कुल मांग निर्धारित करने के लिए आईएस वक्र में वित्तीय चक्र के प्रॉक्सी के रूप में लीवरेज अंतराल द्वारा संवर्धित किया जाता है और लीवरेज अंतराल के लिए एक अलग समीकरण जोड़ा जाता है (जुसेलियस एवं अन्य., 2016 और बोरियो एवं अन्य., 2019)।

संशोधित आईएस वक्र:

$$\tilde{y}_t = \phi_1 \tilde{y}_{t-1} - \phi_2 \tilde{y}_{t-2} - \gamma_1 (r_{t-1} - r_{t-1}^*) - \phi_3 \text{lev}g_{t-1} + \varepsilon_t^{\tilde{y}} \quad \dots (8)$$

लीवरेज अंतराल का उद्भव :

$$\text{lev}g_t = \beta_2 \text{lev}g_{t-1} + \gamma_2 (r_{t-1} - r_{t-1}^*) + \varepsilon_t^{\text{lev}} \quad \dots (9)$$

जब लीवरेज अंतराल ऋणात्मक होता है, तो यह इंगित करता है कि आस्तियों की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और घनात्मक संपार्श्विक मूल्यांकन प्रभाव के माध्यम से, जीडीपी अनुपात में ऋण बढ़ सकता है, जिससे उत्पादन में वृद्धि होगी। मौद्रिक नीति वास्तविक ब्याज दर अंतर ( $r_{t-1} - r_{t-1}^*$ ) के माध्यम से लीवरेज अंतराल ( $\text{lev}g_t$ ) को प्रभावित करती है और इस प्रकार

आउटपुट अंतराल को भी जैसा समीकरण (8) के अनुसार है। वास्तविक ब्याज दर नाममात्र नीतिगत दर ( $i_t$ ) और मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं ( $\pi_t^*$ ), के बीच का अंतर है, जहाँ  $i_t$  टेलर-प्रकार के नियम पर आधारित है;

टेलर-प्रकार नियम:

$$\text{यहाँ } \pi_t^{yoy} \text{ वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति है।}$$

अध्ययन समीकरण (1) से (7) के साथ समीकरण (10) का उपयोग एलडबल्यू फ्रेमवर्क में और (1) से (10) केवल (7) को छोड़कर का उपयोग संशोधित एलडबल्यू फ्रेमवर्क में प्राकृतिक दर का अनुमान लगाने के लिए करता है।



## भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का अनुमान लगाना

अनुपम प्रकाश, सूरज एस, ईशू ठाकुर और मौसमी प्रियदर्शिनी<sup>^</sup> द्वारा

यह अध्ययन जून 2011 से मार्च 2023 तक भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति का तिमाही अनुमान प्रस्तुत करता है, जिसमें संपत्ति की कीमतों में बदलाव के लिए सूचीबद्ध इक्विटी लेखांकन में उनके निवेश भी शामिल हैं। मार्च 2023 के अंत में, घरेलू वित्तीय संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद का 135.0 प्रतिशत थी जबकि उनकी वित्तीय देयताएं सकल घरेलू उत्पाद का 37.8 प्रतिशत थीं; इस प्रकार उनकी निवल वित्तीय संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद का 97.2 प्रतिशत थी। घनिष्ठ संपर्क सेवाओं पर प्रतिबंध और देयताओं में धीमी वृद्धि के बीच कोविड-19 महामारी के दौरान वित्तीय संपत्तियों में बढ़ोतरी के कारण मार्च 2020 के अंत और मार्च 2023 के अंत के बीच निवल वित्तीय संपत्ति में 12.6 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई। 2011-12 से 2022-23 तक इक्विटी और परिवारों के निवेश फंड में 1.5 गुना से अधिक बढ़ोतरी हुई। इस अवधि के दौरान घरेलू ऋण और वित्तीय आस्तियों का अनुपात स्थिर रहा है।

### परिचय

उपभोग, बचत और समग्र आर्थिक गतिविधि के प्रमुख चालक के रूप में परिवार<sup>1</sup> किसी भी समष्टि आर्थिक ढांचे का आधार बनते हैं। घरेलू उपभोग उनकी आय के साथ-साथ संपत्ति पर भी निर्भर करता है। इस संदर्भ में, घरेलू वित्तीय स्थिति की निगरानी न केवल उनकी स्वयं की भलाई का बेहतर मूल्यांकन प्रदान करती है, बल्कि दूरदर्शी मौद्रिक नीति के लिए विकसित हो रही निजी खपत और आर्थिक गतिविधि की समझ को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकती है (लेटौ एट अल. 2002; लुडविग और स्लोक,

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग से हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

<sup>1</sup> अध्ययन में उल्लिखित परिवार में परिवारों के साथ-साथ परिवारों के सेवा प्रदाता गैर-लाभकारी संस्थान (एनपीआईएसएच) अर्थात्, इसमें वे कानूनी संस्थाएं शामिल हैं, जो मुख्य रूप से परिवारों या बड़े पैमाने पर समुदाय के लिए गैर-बाजार सेवाओं के उत्पादन में लगी हुईं और जिनके मुख्य संसाधन स्वैच्छिक योगदान हैं (एसएनए, 2008)।

2004)। आवधिक बचत या बचत के अलावा, परिवारों की निवल संपत्ति, जिसे कुल आस्ति धारिता (वित्तीय और गैर-वित्तीय) और उस अवधि के दौरान संचयित देनदारियों के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है, लाभ या हानि (पुनर्मूल्यांकन) और मात्रा<sup>2</sup> में अन्य परिवर्तनों से भी प्रभावित होती है (ओईसीडी, 2017)। देनदारियों के निवल वित्तीय आस्तियों के भंडार पर ध्यान केंद्रित करने वाली निवल वित्तीय संपत्ति (एनएफडब्ल्यू) का विकसित प्रक्षेपवक्र संभावित वित्तीय कमजोरियों और घरेलू ऋण स्थिरता के लिए आशय का आकलन करने में मदद कर सकता है।

अधिकांश देशों में घरेलू संपत्ति का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख डेटा स्रोत (i) यह घरेलू संपत्ति सर्वेक्षण और (ii) घरेलू तुलन पत्र (एचबीएस) हैं। सर्वेक्षण, हालांकि गैर-वित्तीय आस्तियों के अनुमान सहित संपत्ति वितरण प्रस्तुत करने में अधिक व्यापक हैं, विशेष रूप से धनी परिवारों द्वारा प्रतिक्रिया न देने और कम रिपोर्टिंग से प्रभावित हो सकते हैं (शॉर्रोक्स एट अल., 2023)। इस संदर्भ में, क्षेत्रीय तुलन पत्र डेटा घरेलू वित्तीय स्थिति का समय पर और अधिक विश्वसनीय स्रोत प्रदान कर सकता है<sup>3</sup>। तदनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2011-12 से डेटा को कवर करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय भण्डार और धन प्रवाह (एफएसएफ) के रूप में धन डेटा के प्रवाह के साथ-साथ वित्तीय आस्तियों और देयताओं का क्षेत्र-वार भण्डार 2019 से प्रकाशित किया (एनएससी (2018), प्रकाश एट अल., 2019)।<sup>4</sup> इसके बाद, घरेलू क्षेत्र की चुनिंदा वित्तीय संपत्तियों और देयताओं का बकाया भण्डार तिमाही आधार पर जारी किया गया है, जिसमें 2018 से आरबीआई बुलेटिन में प्रकाशित डेटा शामिल है (प्रकाश एट अल., 2018)। इन पहलों को जारी रखते हुए, यह

<sup>2</sup> आस्तियों की मात्रा (ओसीवी) में अन्य परिवर्तन विनाशकारी घटनाओं, गैर-भुगतान के कारण ऋणों को बढ़े खाते में डालने, जब्ती आदि के कारण होने वाले नुकसान से उत्पन्न हो सकते हैं।

<sup>3</sup> 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के कारण क्षेत्रीय कमजोरियों के आकलन की आवश्यकता तीव्र होने के कारण, जी-20 डेटा गैप इनिशिएटिव (डीजीआई) ने राष्ट्रों को क्षेत्रीय खातों पर उच्च आवृत्ति डेटा के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय प्रवाह को ट्रैक करने की सिफारिश की।

<sup>4</sup> राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), 2008 द्वारा प्रदान किए गए वर्गीकरण के आधार पर, एफएसएफ में क्षेत्रीय खातों में पांच क्षेत्रों, अर्थात् वित्तीय निगमों, गैर-वित्तीय निगमों, सामान्य सरकार, परिवारों और परिवारों के सेवा प्रदाता गैर-लाभकारी संस्थान (एनपीआईएसएच) और शेष विश्व के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

लेख त्रैमासिक घरेलू वित्तीय तुलन पत्र<sup>5</sup> यानी, जून 2011 से मार्च 2023 तक वित्तीय आस्तियों और देयताओं के भण्डार प्रस्तुत करता है। पीछे जाते हुए, जून 2011 तक के डेटा को लेते हुए, यह लेख घरेलू निवेश को सूचीबद्ध इक्विटी के साथ-साथ पेंशन स्टॉक और भविष्य निधि<sup>6</sup> में शामिल करते हुए इसका दायरा बढ़ाता है।

लेख का शेष भाग इस प्रकार संरचित है: घरेलू संपत्ति को मापने के वर्तमान दृष्टिकोण, उपलब्ध डेटा स्रोतों के साथ-साथ इक्विटी संपत्ति के अनुमान पर अनुभाग II में चर्चा की गई है। खंड III उभरती संरचना और प्रवृत्तियों के साथ घरेलू वित्तीय संपत्ति पर त्रैमासिक श्रृंखला के अनुमान प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड घरेलू संपत्ति के आकलन में मौजूदा मुद्दों और घरेलू वित्त की अधिक मजबूत निगरानी की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके के साथ समाप्त होता है।

## II. डेटा और कार्यप्रणाली

वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर संस्थागत क्षेत्रीय प्रवाह और तुलन पत्र डेटा के संकलन और प्रसार को जी-20 डेटा गैप इनिशिएटिव (डीजीआई-2) की सिफारिश II.8<sup>7</sup> में

रेखांकित किया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा रिपोर्ट किए गए आंकड़ों के आधार पर, 42 देश तिमाही आधार पर वित्तीय तुलन पत्र (गैर-समेकित) डेटा प्रदान करते हैं (सारणी1)।

एक विकासशील अर्थव्यवस्था में, घरेलू आस्तियों का बड़ा हिस्सा गैर-वित्तीय होता है, लेकिन जैसे-जैसे बाजार अर्थव्यवस्था की ओर संक्रमण होता है, वित्तीय संपत्तियों की हिस्सेदारी बढ़ने लगती है (शोरॉक एट अल., 2019)। डेटा उपलब्धता के मुद्दों को देखते हुए, यह अध्ययन भारतीय परिवारों की वित्तीय संपत्ति<sup>8</sup> पर केंद्रित है। हालाँकि, ऋण के गैर-संस्थागत स्रोतों, यानी, जमींदार, कृषि साहूकार, पेशेवर साहूकार, इनपुट आपूर्तिकर्ता, रिश्तेदार और दोस्त, चिट फंड, बाजार कमीशन एजेंट/व्यापारी, आदि से संबन्धित डेटा शामिल नहीं किया गया है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि अखिल भारतीय ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एनएसओ, 2021) के अनुसार, गैर-संस्थागत ऋण एजेंसियों से आईओआई में गिरावट के साथ-साथ संस्थागत ऋण एजेंसियों से ऋणग्रस्तता की घटनाओं (आईओआई)<sup>9</sup> में एआईडीआईएस

### सारणी 1: ओईसीडी को डेटा रिपोर्ट करने वाले देश

आवृत्ति	वित्तीय तुलनपत्र (स्टॉक)		वित्तीय खाते (प्रवाह)	
	गैर-समेकित	समेकित	गैर-समेकित	समेकित
वार्षिक	44	40	45	40
त्रैमासिक	42	35	40	35

**नोट:** 1. समेकित डेटा एक साथ समूहीकृत संस्थागत इकाइयों जैसे कि वे एक एकल इकाई का गठन करते हो, के बीच की स्टॉक स्थिति और प्रवाह को समाप्त कर देता है, 2. भारत के लिए डेटा वार्षिक वित्तीय तुलन पत्र में गैर-समेकित और वित्तीय खातों में गैर-समेकित है। 3. देशों की गणना 31 मई 2024 तक है।

**स्रोत:** ओईसीडी आँकड़े।

<sup>5</sup> वित्तीय खातों के संदर्भ में तुलन पत्र "वित्तीय तुलन पत्र" को संदर्भित करता है जो वित्तीय आस्तियों और देयताओं के स्टॉक को दिखाता है, न कि कुल तुलन पत्र को जो गैर-वित्तीय आस्तियों के स्टॉक को भी दिखाता है।

<sup>6</sup> पेंशन और भविष्य निधि के संबंध में, आरबीआई बुलेटिन सारणी 50बी में केवल सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) पर स्टॉक डेटा शामिल है।

<sup>7</sup> डीजीआई II.8 सिफारिश में कहा गया है, "जी20 अर्थव्यवस्थाओं को अन्य (गैर-बैंक) वित्तीय निगमों के क्षेत्र से संबन्धित डेटा सहित, आंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमत टेम्पलेट के आधार पर, त्रैमासिक और वार्षिक आवृत्ति पर क्षेत्रीय खातों के प्रवाह और तुलन पत्र डेटा को संकलित और प्रसारित करें, और तुलन पत्र विश्लेषण का समर्थन करने के लिए लेनदेन और स्टॉक दोनों के लिए किससे-किसके मैट्रिक्स विकसित करें। आईएजी, राष्ट्रीय लेखा पर अंतर-सचिवालय कार्य समूह (आईएसडब्ल्यूजीएनए) के सहयोग जी20 अर्थव्यवस्थाओं की प्रगति को प्रोत्साहित करें और उसकी निगरानी करें। 2021 तक के लक्ष्य में वार्षिक और त्रैमासिक आधार पर गैर-वित्तीय और वित्तीय खातों और तुलन पत्र का डेटा प्रसार शामिल है। अधिक उन्नत महत्वाकांक्षाओं में किससे-किसके आधार पर प्रस्तुत वार्षिक और त्रैमासिक वित्तीय क्षेत्र के खाते और वार्षिक गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता आँकड़े शामिल हैं।

<sup>8</sup> परिवारों द्वारा भौतिक निवेश पर डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) द्वारा वार्षिक आधार पर जारी किया जाता है।

<sup>9</sup> ऋणग्रस्तता की घटना (आईओआई) किसी भी बकाया ऋण वाले परिवारों का प्रतिशत है।

2013 के परिणाम<sup>10</sup> की तुलना में वृद्धि हुई है। आरबीआई बुलेटिन में जारी वार्षिक एफएसएफ खातों में परिवारों के इक्विटी निवेश शामिल हैं, उनके मूल्य का अनुमान भुगतान की गई इक्विटी पूंजी के आधार पर लगाया गया है और बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के कारण होने वाले बदलावों को शामिल नहीं किया गया है। यह लेख घरेलू आस्ति धारिता पर मूल्यांकन परिवर्तनों के प्रभाव को शामिल करने का प्रयास करता है। लेख में रोजगार से जुड़ी पेंशन और भविष्य निधि आस्तियां भी शामिल हैं, इस प्रकार उपलब्ध समय श्रृंखला का अवधि और विस्तार दोनों में फैलाव होता है (परिशिष्ट सारणी 1)।

### II.1 डेटा स्रोत और वर्गीकरण

परिवारों से संबन्धित प्राथमिक डेटा के अभाव में, उनके खातों का अनुमान प्रतिपक्ष क्षेत्रों के डेटा के माध्यम से लगाया जाता है। भारत के मामले में, यह प्रतिपक्ष जानकारी आरबीआई, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी), पेंशन फंड विनियामक और

विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए), भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया (एएमएफआई), लेखा महानियंत्रक (सीजीए), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), आदि सहित विभिन्न एजेंसियों/ विनियामक द्वारा अच्छी तरह से परिभाषित और नियमित रूप से प्रकाशित की जाती है। इन संस्थाओं का डेटा मूल रूप से घरेलू वित्तीय तुलन पत्र और वित्तीय खाते दोनों के संकलन का आधार बनता है। वर्तमान अध्ययन जून 2011 के अंत (ति1:2011-12) से मार्च 2023 के अंत (ति4:2022-23)<sup>11</sup> तक तिमाही आधार पर परिवारों का वित्तीय तुलन पत्र प्रदान करता है। वित्तीय आस्तियों और देयताओं के घटकों को संबंधित स्रोतों और लिखत-वार वर्गीकरण के साथ सारणी 2 में सूचीबद्ध किया गया है।

वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण मौद्रिक और वित्तीय सांख्यिकी मैनुअल और संकलन मार्गदर्शिका

### सारणी 2: वित्तीय आस्तियां और देयताएं

क्रम संख्या	वित्तीय आस्ति	स्रोत	वर्गीकरण
1	मुद्रा	आरबीआई, एनएचबी	मुद्रा
2	बैंक जमा		जमाशियां
3	गैर-बैंक जमा (एनबीएफसी और एचएफसी)		
4	लघु बचत	सीजीए	इक्विटी और निवेश फंड
5	इक्विटी (सूचीबद्ध फर्म)	सीएमआईई प्रोवेस	
6	म्यूचुअल फंड	एएमएफआई, सेबी	
7	जीवन बीमा निधि	आईआरडीएआई	बीमा निधि
8	पेंशन योजनाएं (एपीवाई और एनपीएस)	पीएफआरडीए	पेंशन योजनाएं
9	ईपीएफओ भविष्य और पेंशन फंड	ईपीएफओ	
10	राज्य भविष्य निधि	सीजीए, आरबीआई	
11	ऋण प्रतिभूतियाँ	आरबीआई	ऋण प्रतिभूतियाँ
	<b>देयताएं</b>	<b>स्रोत</b>	<b>वर्गीकरण</b>
1	बैंक क्रेडिट	आरबीआई	ऋण
2	गैर-बैंक ऋण (एनबीएफसी, एचएफसी और बीमा)	आरबीआई, एनएचबी, आईआरडीएआई	

नोट: एनबीएफसी - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, एचएफसी - हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, एपीवाई - अटल पेंशन योजना, एनपीएस - राष्ट्रीय पेंशन योजना।

स्रोत: लेखकों का संकलन।

<sup>10</sup> मल्होत्रा (2021) में संकलित भारतीय घरेलू तुलन पत्र में, लेखक एआईडीआईएस के विभिन्न दौरों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर गैर-संस्थागत से संस्थागत घरेलू ऋण के अनुपात की गणना करके घरेलू गैर-संस्थागत देयताओं के अनुमान शामिल करता है।

<sup>11</sup> तिमाही डेटा का अनुमान जून के अंत (ति1), सितंबर के अंत (ति2), दिसंबर के अंत (ति3) और मार्च के अंत (ति4) में लगाया गया है।

(आईएमएफ, 2016) और एसएनए 2008<sup>12</sup> में उल्लिखित मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र के आंकड़ों के ढांचे के अनुसार संरेखित किया गया है। जमा, जो मानक गैर-परक्राम्य अनुबंध हैं, वह बाद में आहरण के लिए रखी गई धनराशि है जिसमें बैंक और गैर-बैंक जमा के साथ-साथ सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ), राष्ट्रीय बचत जमा (एनएसडी) एवं राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (एनएससी) सहित लघु बचत निधि (एसएसएफ) शामिल हैं। चूंकि पीपीएफ की प्रकृति रोजगार आधारित भविष्य निधि के बजाय व्यक्तिगत निवेश योजना की है, इसलिए इसे पेंशन और भविष्य निधि के बजाय जमा का हिस्सा माना गया है। एनएससी, एक गैर-परक्राम्य जमा प्रमाणपत्र होने के कारण, इसे ऋण प्रतिभूतियों के बजाय जमा के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैंक और गैर-बैंक<sup>13</sup> जमाओं का डेटा आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग आंकड़ों से प्राप्त किया जाता है, जबकि छोटी बचत से संबंधित आंकड़ें सीजीए द्वारा जारी मासिक लेखा द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

पेंशन योजनाओं में अपने नियोक्ता के पास कर्मचारियों के मौजूदा और भविष्य के दावे, या सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों को मुआवजा देने के लिए नियोक्ता द्वारा नामित एक फंड शामिल है। इस श्रेणी के अंतर्गत तीन रोजगार-आधारित पेंशन योजनाएं : (i) ईपीएफओ प्रबंधित भविष्य और पेंशन निधि योजनाएं, (ii) एपीवाई और एनपीएस की प्रबंधन के तहत आस्ति (एयूएम), और (iii) केंद्र और राज्य सरकारों की राज्य भविष्य निधियां (एसपीएफ) शामिल हैं। जबकि एपीवाई, एनपीएस और केंद्र सरकार एसपीएफ के आंकड़े मासिक आधार पर उपलब्ध हैं, ईपीएफओ निधि और राज्य सरकार एसपीएफ का वार्षिक डेटा क्रमशः एनपीएस और केंद्र सरकार के आंकड़ों में त्रैमासिक रुझानों के आधार पर त्रैमासिक आवंटित किया जाता है। सूचीबद्ध कॉरपोरेट्स में परिवारों की इक्विटी धारिता का बाजार

<sup>12</sup> एसएनए 2008 के अनुसार वित्तीय संपत्तियों की (i) मौद्रिक स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकांश (एसडीआर), (ii) मुद्रा और जमा, (iii) ऋण प्रतिभूतियां, (iv) ऋण, (v) इक्विटी और निवेश निधि, (vi) बीमा, पेंशन और मानकीकृत गारंटी योजनाएं, (vii) वित्तीय डेरिवेटिव और कर्मचारी स्टॉक विकल्प (ईएसओ) और (viii) अन्य प्राप्य/देय खाते यह मुख्य श्रेणियां हैं।

<sup>13</sup> 2011-12 से 2013-14 के लिए एचएफसी के पास जमा के आंकड़े वार्षिक आधार पर उपलब्ध हैं और 2014-15 से 2016-17 के औसत तिमाही शेरों के आधार पर तिमाहियों में आवंटित किए गए हैं।

मूल्य (अगले उप-अनुभाग में चर्चा की गई है), म्यूचुअल फंड में निवेश के स्टॉक के साथ मिलकर, इक्विटी और निवेश फंड बनाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश को सितंबर 2014 यानी, ति2: 2014-15 से तिमाही आधार पर एएमएफआई द्वारा प्रकाशित योजना-वार एयूएम<sup>14</sup> के योग के रूप में लिया है। इससे पहले, एएमएफआई द्वारा अर्ध-वार्षिक आधार पर डेटा प्रकाशित किया जाता था जिसे प्रक्षेपित किया जाता है। जीवन बीमा निधि में निवेश आईआरडीएआई द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित उद्योग-व्यापी आंकड़ों से लिया जाता है; त्रैमासिक श्रृंखला तैयार करने के लिए नमूना जीवन बीमा कंपनियों के त्रैमासिक डेटा का उपयोग किया जाता है। खजाना बिल और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सहित सरकारी बॉन्ड में घरेलू निवेश ऋण प्रतिभूतियों का हिस्सा है।

## 11.2 सूचीबद्ध इक्विटी में घरेलू संपत्ति

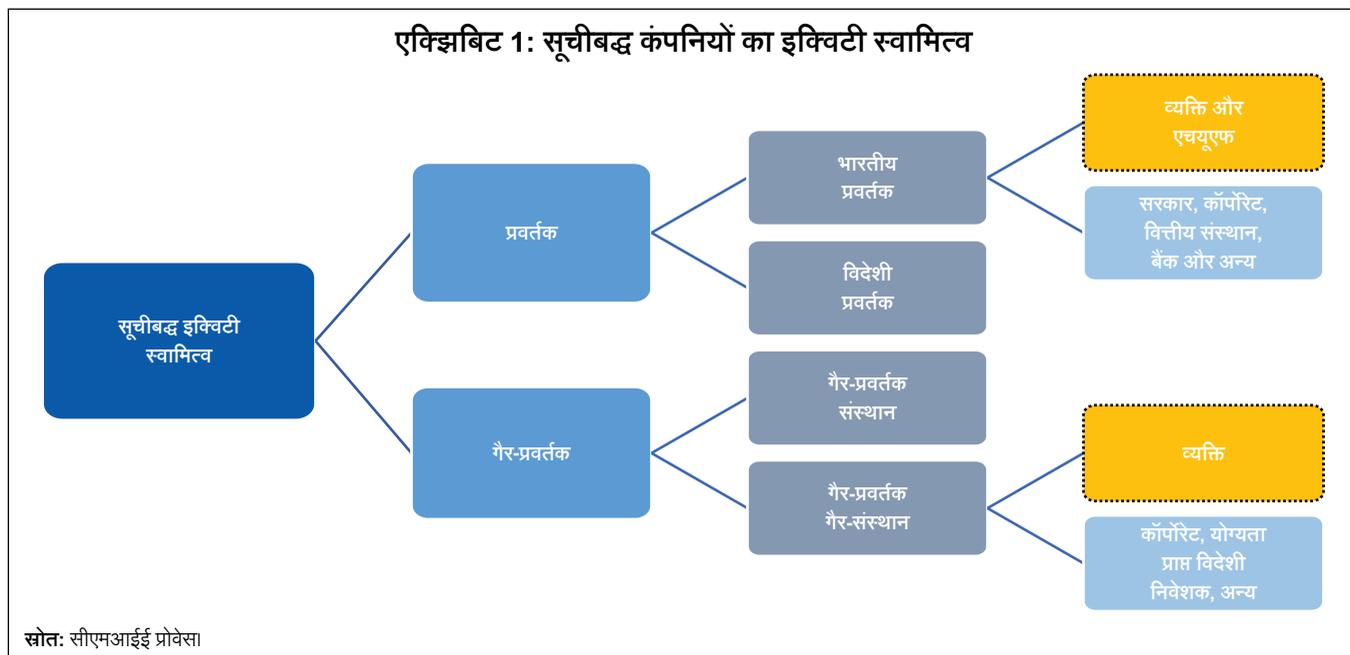
सूचीबद्ध फर्मों में इक्विटी के स्वामित्व से संबंधित डेटा तिमाही आधार पर सीएमआईई प्रोवेस डेटाबेस में उपलब्ध है। इसे मोटे तौर पर और आगे पृथक्करण के साथ दो समूहों यानी, प्रवर्तक और गैर-प्रवर्तक द्वारा स्वामित्व में विभाजित किया गया है, (एक्जिबिट 1)। परिवारों की इक्विटी संपत्ति का अनुमान दो समूहों : (i) भारतीय प्रवर्तक व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) - प्रवर्तक परिवार; और (ii) गैर-प्रवर्तक व्यक्ति - बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) में सूचीबद्ध कंपनियों के गैर-प्रवर्तक परिवार<sup>15</sup> की शेयर धारिता के अनुसार बाजार पूंजीकरण को जोड़कर लगाया जाता है<sup>16</sup>।

प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में घरेलू इक्विटी संपत्ति की गणना तिमाही स्तर पर कंपनी के कुल बाजार पूंजीकरण के साथ प्रवर्तक

<sup>14</sup> उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए एयूएम और विभिन्न योजनाओं के तहत खुदरा क्षेत्रों को परिवारों के लिए म्यूचुअल फंड एयूएम के रूप में एक साथ लिया जाता है।

<sup>15</sup> गैर-सूचीबद्ध इक्विटी को घरेलू वित्तीय संपत्ति के आकलन से बाहर रखा गया है।

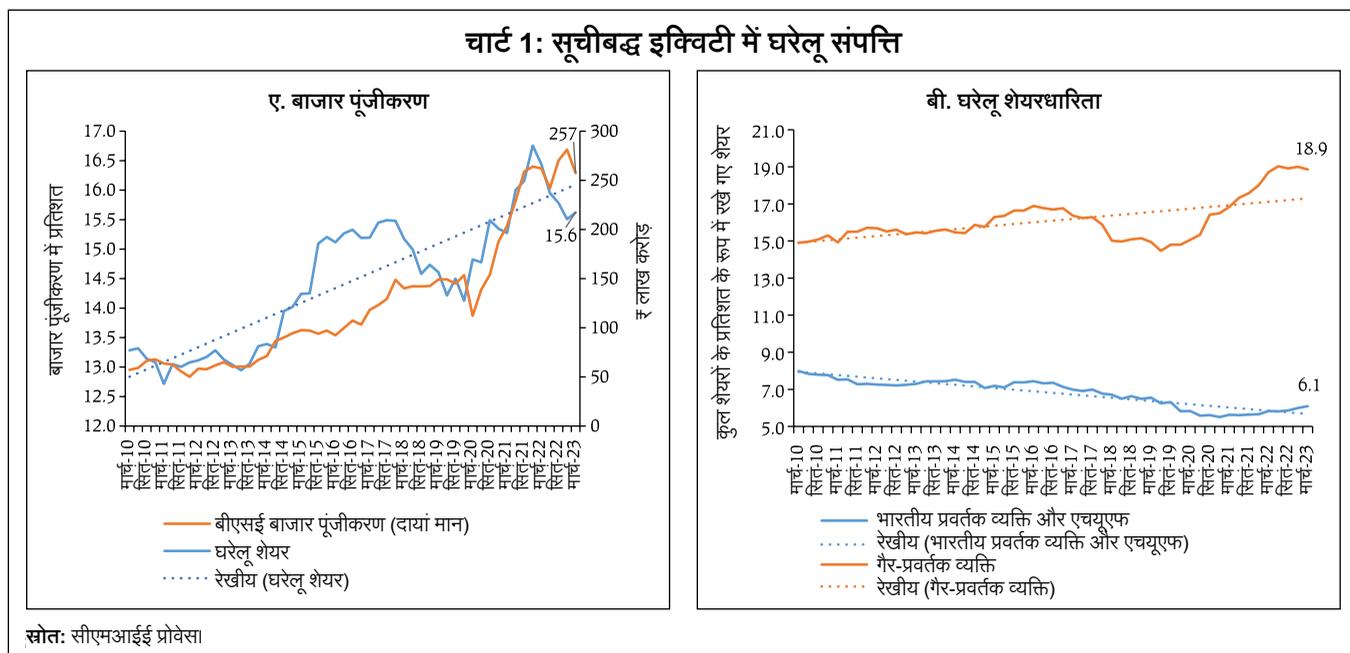
<sup>16</sup> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) द्वारा जारी इंडिया ओनरशिप ट्रैकर रिपोर्ट, एनएसई सूचीबद्ध कंपनियों का स्वामित्व विभाजन भी प्रदान करती है; हालांकि, 2023-24 की दूसरी तिमाही से पहले की अवधि के लिए समान विवरण में त्रैमासिक आधार पर उपलब्ध नहीं है। 2023-24 से पहले की अवधि के लिए, ट्रैकर केवल व्यापक विभाजन जैसे, (i) निजी भारतीय प्रवर्तक, (ii) सरकार, (iii) विदेशी प्रवर्तक, (iv) घरेलू म्यूचुअल फंड, (v) बैंक, एफआई और बीमा, (vi) विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), (vii) गैर-प्रवर्तक कॉर्पोरेट, और (viii) खुदरा प्रदान करता है।

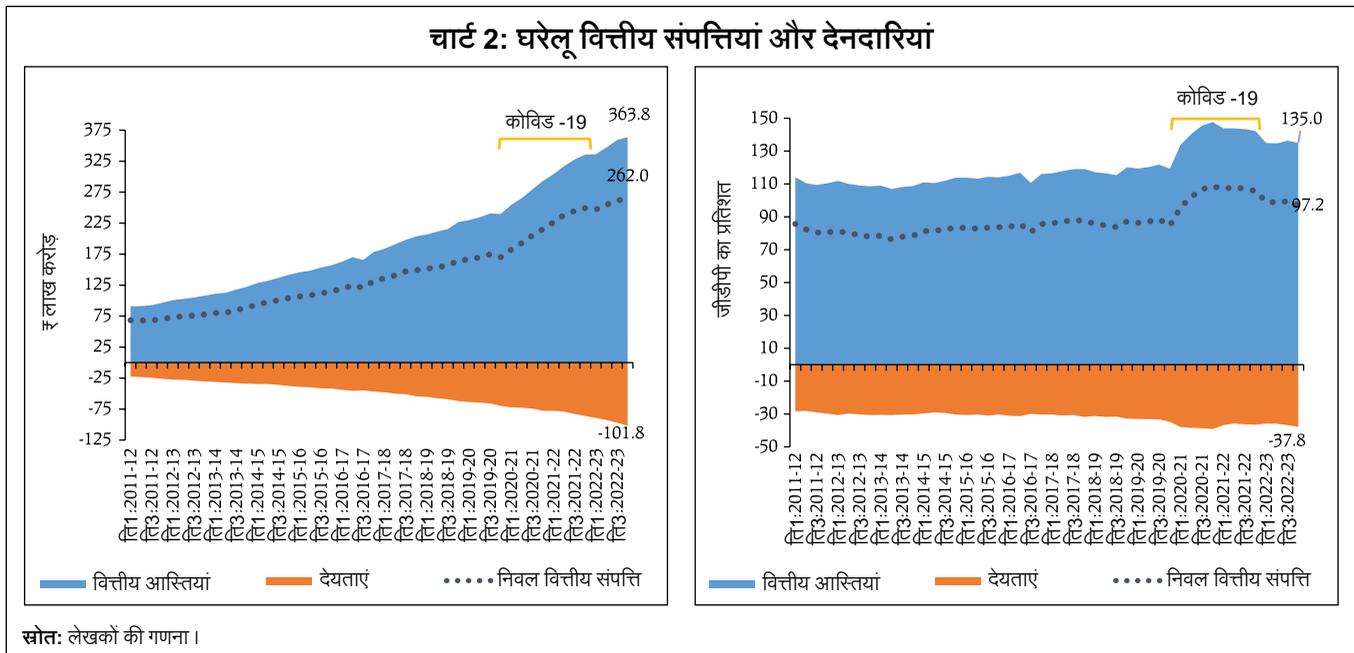


और गैर-प्रवर्तक घरेलू समूहों द्वारा धारित शेयरों के अनुपात को गुणा करके की जाती है। तदनुसार, कुल इक्विटी संपत्ति सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए कंपनी स्तर की घरेलू इक्विटी धारिता एकत्रित करके निकाली जाती है (समीकरण 1)।

$$\text{घरेलू इक्विटी संपत्ति} = \sum_i [(\text{प्रवर्तक परिवारों और गैर-प्रवर्तक परिवारों द्वारा धारित शेयरों का अनुपात})_i \times \text{बाजार पूंजीकरण}]_i, \text{ जहां } i = \text{बीएसई सूचीबद्ध कंपनी} \quad (1)$$

मार्च 2010 से मार्च 2023 के दौरान कुल बाजार पूंजीकरण में परिवारों की हिस्सेदारी औसतन लगभग 14.5 प्रतिशत थी, जिसमें रुक-रुक कर उतार-चढ़ाव के साथ आम तौर पर बढ़ती प्रवृत्ति का अनुभव हुआ। शेयर बाजार में महामारी के बाद की रिकवरी कुल बाजार पूंजीकरण में घरेलू हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ हुई, जो मुख्य रूप से गैर-प्रवर्तक परिवारों की शेयरधारिता में तेजी से वृद्धि के कारण हुई (चार्ट 1)।





उपरोक्त अनुमान के अनुसार, 2011-12 की पहली तिमाही में परिवारों की इक्विटी संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद का 10.3 प्रतिशत थी, जो 2021-22 की तीसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 19.4 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई, और फिर बाद में 2022-23 की चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद के 14.9 प्रतिशत तक नीचे आ गई।

### III. भारत में घरेलू वित्तीय संपत्ति में रुझान

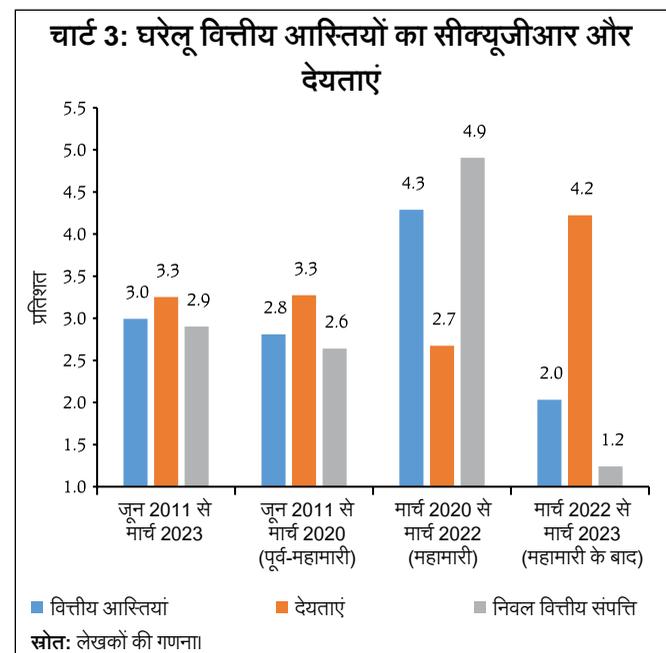
मार्च 2023 तक, कुल घरेलू वित्तीय संपत्ति ₹363.8 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 135.0 प्रतिशत के बराबर है। इसके विपरीत, बकाया देयताएं ₹101.8 लाख करोड़ थीं, जो सकल घरेलू उत्पाद का 37.8 प्रतिशत है। परिणामी, एनएफडब्ल्यू ₹262.0 लाख करोड़ (जीडीपी का 97.2 प्रतिशत) अनुमानित है। महामारी की अवधि में मार्च 2020 से मार्च 2022 तक दो साल की अवधि के लिए वित्तीय आस्तियों और एनएफडब्ल्यू में उछाल देखा गया (चार्ट 2)। 2022-23 में, सामान्य आर्थिक गतिविधियों की बहाली के साथ, वित्तीय संपत्तियों में अपेक्षाकृत संयत वृद्धि के साथ - साथ बैंक व गैर-बैंक ऋण दोनों में मजबूत पुनःप्रवर्तन के कारण परिवारों के लिए एनएफडब्ल्यू भी सामान्य हो गया।

जून 2011 से मार्च 2023 तक अध्ययन की पूरी अवधि के लिए, वित्तीय आस्तियां 3.0 प्रतिशत की चक्रवृद्धि त्रैमासिक वृद्धि

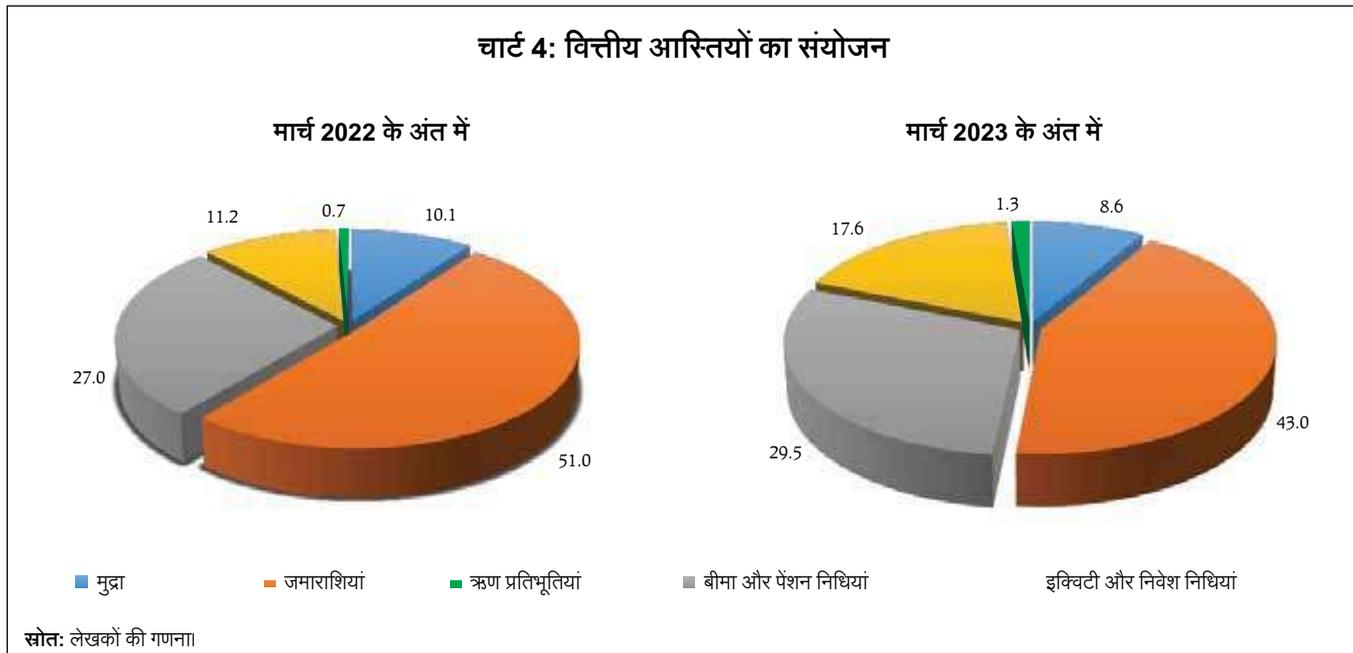
दर (सीक्यूजीआर) से बढ़ीं, जबकि देयताएं 3.3 प्रतिशत की सीक्यूजीआर से बढ़ीं; इसी अवधि के दौरान एनएफडब्ल्यू ने 2.9 प्रतिशत का सीक्यूजीआर दर्ज किया (चार्ट 3)।

#### III.1 वित्तीय आस्तियों में संरचनात्मक बदलाव

यद्यपि, अन्य निवेश साधनों, जैसे कि इक्विटी और निवेश फंड और बीमा और पेंशन फंड के लिए बढ़ते ब्याज के साथ, पिछले दशक में कुल वित्तीय संपत्ति में जमारारियों ने अपना



**चार्ट 4: वित्तीय आस्तियों का संयोजन**



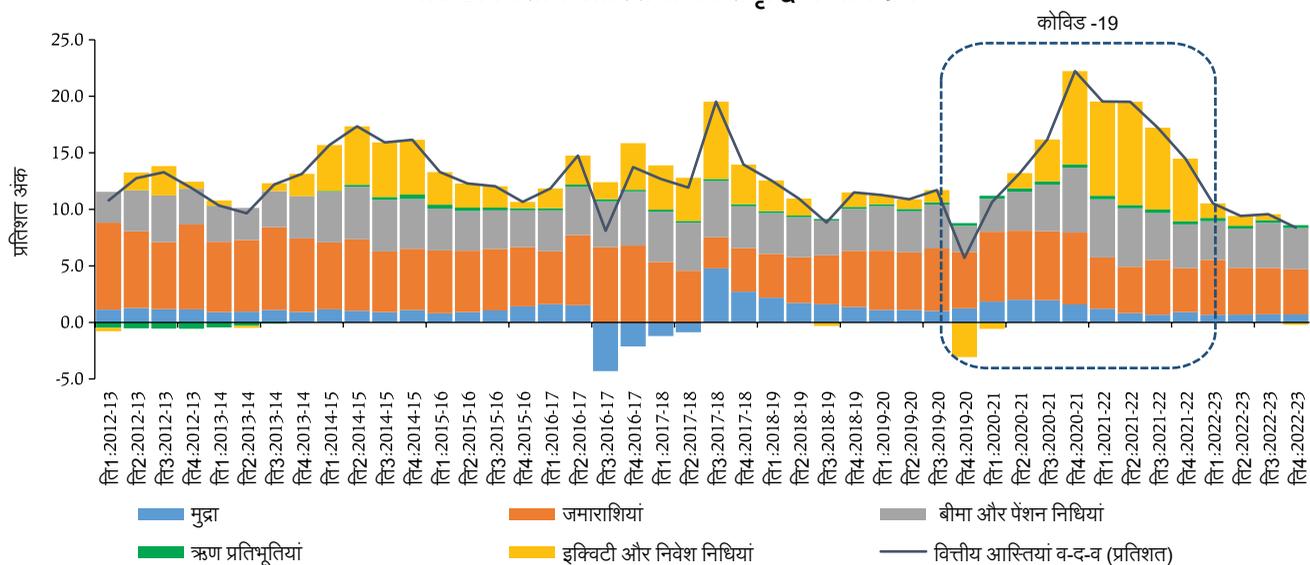
प्रभुत्व बनाए रखा है। 2011-12 और 2022-23 के बीच कुल वित्तीय संपत्ति में इक्विटी और निवेश फंड की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई। डिजिटल भुगतान में तेजी से वृद्धि के बीच, घरेलू वित्तीय आस्तियों में मुद्रा हिस्सेदारी कम हो गई है (चार्ट 4 और 5)।

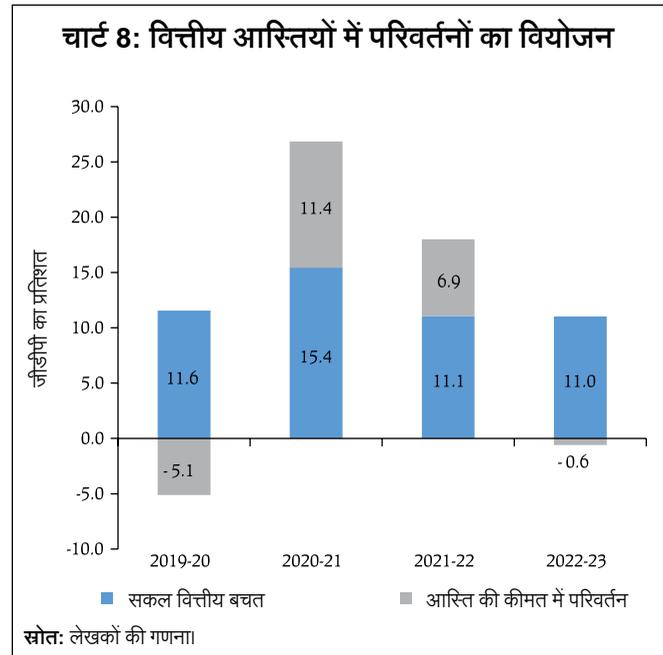
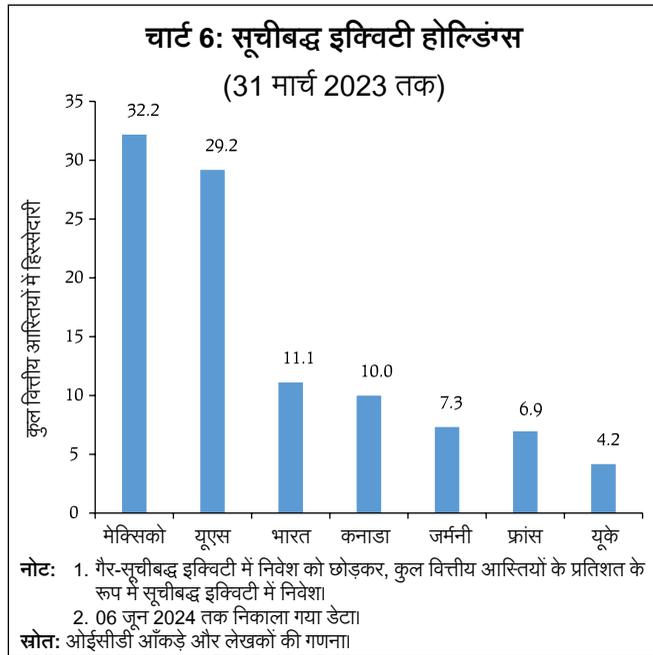
इक्विटी बाजार में भारतीय घरेलू भागीदारी समय के साथ बढ़ी है जिसमें कुल डीमैट खाते 2018-19 में 3.6 करोड़ से

बढ़कर 2022-23 में 11.4 करोड़ तक पहुंच गए हैं (सेबी, 2023)। मार्च 2023 तक भारतीय परिवारों की कुल वित्तीय आस्तियों में सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स की हिस्सेदारी 11.1 प्रतिशत थी (चार्ट 6)।

महामारी की शुरुआत के बाद, शेयर बाजार में गिरावट से 2019-20 की चौथी तिमाही में परिवारों की निवल वित्तीय संपत्ति को पिछली तिमाही की तुलना में लगभग 3.0 प्रतिशत कम कर

**चार्ट 5: वित्तीय आस्तियों की संवृद्धि में योगदान**



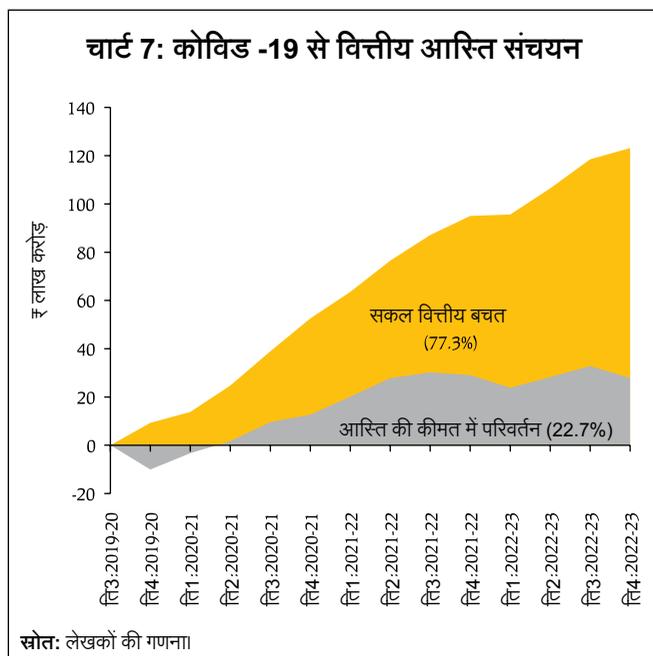


दिया। महामारी के कारण खर्च पर लगे प्रतिबंधों और उसके बाद शेयर बाजार के पुनःप्रवर्तन के कारण 2020-21 में बचत और जमा के संचय से यह गिरावट कहीं अधिक थी। संचयी आधार पर, दिसंबर 2019 को समाप्त तिमाही और मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के बीच परिवारों की वित्तीय आस्ति ₹123.2 लाख करोड़ बढ़ गई; इस वृद्धि का लगभग 23 प्रतिशत आस्ति मूल्य में वृद्धि

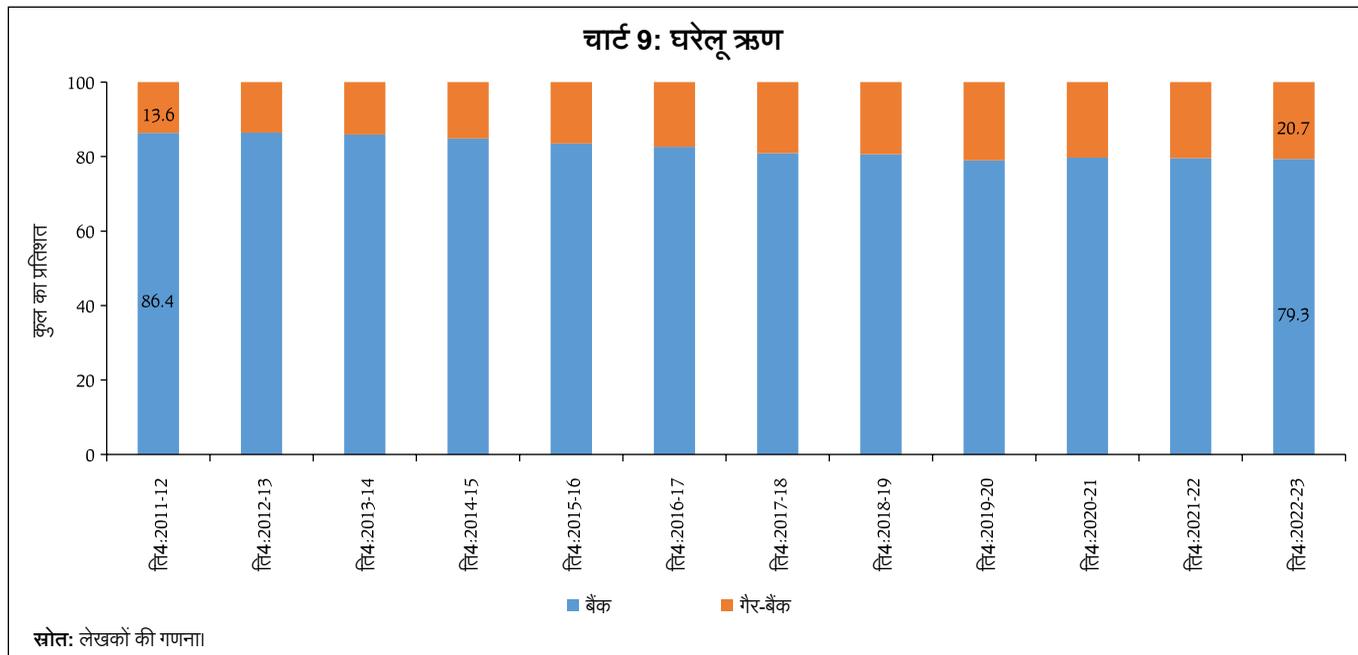
के कारण था और शेष वृद्धिशील वित्तीय बचत<sup>17</sup> (चार्ट 7 और 8) के कारण था।

### III.2 घरेलू ऋण की संरचना

बंधक उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में घरेलू ऋण का बड़ा हिस्सा (50 प्रतिशत से अधिक) बनाते हैं, जबकि उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में गैर-बंधक ऋण कुल का कम से कम दो-तिहाई होता है (आईएमएफ, 2017)। बाद वाले में सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तिगत ऋण जैसे वाहन ऋण, शिक्षा ऋण, क्रेडिट कार्ड बकाया, उद्योग के लिए व्यवसाय ऋण, व्यापार, परिवहन, वित्त और कृषि के लिए ऋण शामिल हैं। अन्य ईएमई के समान, भारत में बैंकिंग क्षेत्र कुल ऋण में लगभग 80 प्रतिशत शेयर के साथ परिवारों के लिए ऋण आपूर्तिकर्ता के रूप में हावी है; गैर-बैंक संस्थाएं यानी एचएफसी और एनबीएफसी भी हाल के वर्षों में ऋण के स्रोत के रूप में तेजी से उभर रही हैं। मार्च 2012 के अंत से मार्च 2023 के अंत तक गैर-बैंक ऋण की हिस्सेदारी में लगभग 7.0 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई (चार्ट 9)।



<sup>17</sup> वित्तीय आस्तियों में कुल परिवर्तन को सकल वित्तीय बचत और आस्तियों की कीमतों में परिवर्तन में विभाजित किया जा सकता है। संबन्धित अवधि के दौरान की गई बचत में कटौती के बाद, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड और जीवन बीमा फंड की इक्विटी और एयूएम में परिवर्तन को आस्ति मूल्य परिवर्तनों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

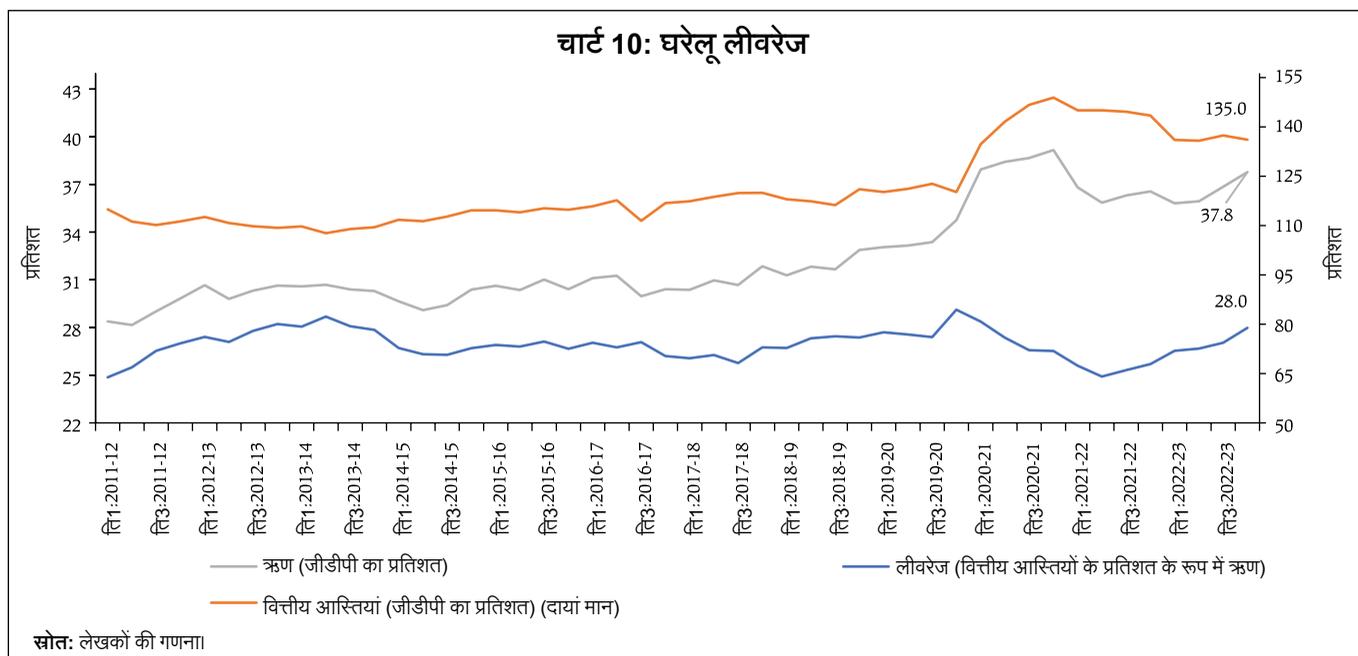


ऊंचे ऋण स्तर की मौजूदगी में प्रतिकूल आय झटके बढ़ सकते हैं (मियां एट अल., 2017, ज़ाबाई, 2017)। जबकि भारतीय परिवारों की ऋणग्रस्तता वित्तीय गहराई को दर्शाते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है, इसे उनकी वित्तीय आस्तियों में वृद्धि के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। घरेलू "लीवरेज" अनुपात - जिसे घरेलू ऋण और वित्तीय आस्तियों के अनुपात के रूप में

परिभाषित किया गया है - 2011-12 से काफी हद तक समतल और सीमित बना हुआ है (चार्ट 10)।

#### IV. आगे बढ़ने की राह

यह लेख 2011-12 से 2022-23 के लिए परिवारों के तिमाही वित्तीय तुलन पत्र और उनकी निवल वित्तीय संपत्ति का



अनुमान प्रस्तुत करता है। हालांकि बाजार-आधारित लिखतों की हिस्सेदारी बढ़ रही है लेकिन विश्लेषण से संकेत मिलता है कि जमा अभी भी बचत का सबसे पसंदीदा साधन है। देयताओं में धीमी वृद्धि के साथ-साथ गतिशीलता और खर्च पर महामारी-प्रेरित प्रतिबंधों के कारण, 2020-21 में वित्तीय आस्तियों और निवल वित्तीय संपत्ति का संचयन बढ़ गया; स्थिति सामान्य होने पर घरेलू खपत में बढ़ोतरी हुई है, तब से निवल वित्तीय संपत्ति में कुछ सामान्यता देखी गई है।

इस पेपर में घरेलू वित्तीय संपत्ति के अनुमान में डेटा उपलब्धता के मुद्दों के कारण, विशेष रूप से गैर-सूचीबद्ध कॉर्पोरेट क्षेत्र में उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों द्वारा किए गए निवेश को शामिल नहीं किया गया है। वैश्विक स्तर पर, गैर-सूचीबद्ध इक्विटी होल्डिंग्स में घरेलू वित्तीय संपत्ति सूचीबद्ध इक्विटी संपत्ति से अधिक है, जो फ्रांस, कनाडा और यूके में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः लगभग 36.6 प्रतिशत, 23.5 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत है<sup>18</sup>। भारत में, मई 2024 के अंत तक सूचीबद्ध केवल 6,658 कंपनियों की तुलना में 17.1 लाख सक्रिय गैर-सूचीबद्ध/प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां मौजूद हैं; इन गैर-सूचीबद्ध कंपनियों में घरेलू हिस्सेदारी की जानकारी और उनके मूल्यांकन में स्थिरता से इस अध्ययन<sup>19</sup> में प्रस्तुत वित्तीय संपत्ति के अनुमान को मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, भारत में महत्वपूर्ण घरेलू निवेश अभी भी गैर-वित्तीय आस्तित्व जैसे रियल एस्टेट, स्वर्ण और कीमती धातुओं में प्रवाहित होता है। नियमित और व्यापक घरेलू संपत्ति सर्वेक्षण वित्तीय और भौतिक आस्तियों और देयताओं दोनों को शामिल करते हुए, घरेलू कुल संपत्ति के अनुमान को बढ़ा सकता है।

### संदर्भ:

IMF (2016). Monetary and Financial Statistics Manual and Compilation Guide, 2016.

Ludwig, A., and Sløk, T. (2004). The relationship between stock prices, house prices and

consumption in OECD countries. *Contributions in Macroeconomics*, 4(1), 20121017.

Mian, A., Sufi, A., & Verner, E. (2017). Household debt and business cycles worldwide. *The Quarterly Journal of Economics*, 132(4), 1755-1817.

NSC (2018). Report of the Committee on Financial Sector Statistics. National Statistical Commission. May 2018.

NSO(2021). All India Debt and Investment Survey 2019, NSS 77th Round, National Statistical Office, Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.

OECD (2017). *Understanding Financial Accounts*. OECD Publishing.

Prakash, A., Shukla, A. K., Ekka, A. P., Priyadarshi, K. and Bhowmick, C. (2019). Financial Stocks and Flows of the Indian Economy 2011-12 to 2017-18. RBI Bulletin, July, Reserve Bank of India.

Prakash, A., Shukla, A. K., Ekka, A. P. and Priyadarshi, K. (2018). Quarterly Estimates of Households' Financial Assets and Liabilities. RBI Bulletin, March, Reserve Bank of India.

RBI (2023). Annual Report 2022-23. Reserve Bank of India.

SEBI (2023). Annual Report 2022-23. Securities and Exchange Board of India.

Shorrocks, A., Lluberias, R., Davies, J., Waldenström, D. (2023). Global Wealth Report 2023. Credit Suisse Research Institute (CSRI), Credit Suisse AG, UBS.

SNA (2008). System of National Accounts 2008. United Nations.

Zabai, A. (2017). Household debt: recent developments and challenges. *BIS Quarterly Review*, December.

<sup>18</sup> डेटा ओईसीडी ऑकडे - त्रैमासिक गैर-समेकित वित्तीय तुलन पत्र (त्रैमासिक सारणी 720) - मार्च 2023 तक एसएनए 2008 से प्राप्त किया गया है।

<sup>19</sup> सक्रिय कंपनियों का डेटा कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के मई 2024 के मासिक सूचना बुलेटिन पर आधारित है।

**परिशिष्ट सारणी 1: घरेलू वित्तीय संपत्ति और देयताएं**

(जीडीपी का प्रतिशत)

तिमाही	वित्तीय आस्तियां	देयताएं	निवल वित्तीय संपत्ति
जून-11	114.1	28.4	85.7
सितम्बर-11	110.5	28.2	82.3
दिसंबर-11	109.4	29.0	80.4
मार्च-12	110.5	29.8	80.6
जून-12	111.8	30.7	81.2
सितम्बर-12	110.0	29.8	80.2
दिसंबर-12	109.1	30.3	78.8
मार्च-13	108.6	30.6	77.9
जून-13	109.0	30.6	78.4
सितम्बर-13	107.0	30.7	76.3
दिसंबर-13	108.2	30.4	77.8
मार्च-14	108.8	30.3	78.5
जून-14	111.0	29.6	81.4
सितम्बर-14	110.5	29.1	81.5
दिसंबर-14	111.9	29.4	82.5
मार्च-15	113.8	30.4	83.4
जून-15	113.8	30.6	83.2
सितम्बर-15	113.2	30.4	82.9
दिसंबर-15	114.4	31.0	83.4
मार्च-16	114.0	30.4	83.6
जून-16	115.0	31.1	83.9
सितम्बर-16	116.9	31.3	85.6
दिसंबर-16	110.7	30.0	80.7
मार्च-17	116.0	30.4	85.6
जून-17	116.5	30.4	86.1
सितम्बर-17	117.9	31.0	86.9
दिसंबर-17	119.0	30.7	88.4
मार्च-18	119.1	31.8	87.2
जून-18	117.1	31.3	85.9
सितम्बर-18	116.5	31.8	84.7
दिसंबर-18	115.4	31.7	83.7
मार्च-19	120.1	32.9	87.3
जून-19	119.3	33.1	86.3
सितम्बर-19	120.3	33.2	87.1
दिसंबर-19	121.8	33.4	88.5
मार्च-20	119.3	34.7	84.6
जून-20	133.7	37.9	95.8
सितम्बर-20	140.4	38.4	102.0
दिसंबर-20	145.5	38.7	106.8
मार्च-21	147.7	38.9	108.8
जून-21	143.8	36.6	107.3
सितम्बर-21	143.9	35.6	108.3
दिसंबर-21	143.4	36.1	107.3
मार्च-22	142.3	36.5	105.7
जून-22	134.9	35.8	99.2
सितम्बर-22	134.7	35.9	98.8
दिसंबर-22	136.3	36.8	99.5
मार्च-23	135.0	37.8	97.2



## भारत में सकल मूल्य संवर्धन में श्रम संरचना के योगदान का आकलन – मानव पूंजी दृष्टिकोण

श्रीरूपा सेनगुप्ता और विनीत कुमार श्रीवास्तव द्वारा <sup>^</sup>

यह आलेख श्रम खातों के क्लेम्स ढांचे को शामिल करता है और भारत में जीवीए वृद्धि के प्रक्षेप पथ पर श्रम और उसकी संरचना की भूमिका की पड़ताल करता है। कृषि से निर्माण और सेवाओं में रोजगार में संरचनात्मक बदलाव हुआ है और विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल का नियमितिकरण बढ़ा है। शिक्षा श्रेणियों में कार्यबल वितरण शैक्षिक प्राप्ति के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। 1980-81 से 2021-22 के दौरान श्रम इनपुट ने उत्पादन वृद्धि में औसतन तीस प्रतिशत योगदान दिया; इसमें से रोजगार ने पच्चीस प्रतिशत का योगदान दिया और अतिरिक्त पांच प्रतिशत योगदान का श्रेय श्रम गुणवत्ता में सुधार को जाता है।

### परिचय

संवृद्धि और लोकहित पर मुख्य नीतिगत बहसों उत्पादन प्रक्रिया और श्रम बाजार के मध्य होती हैं। निरंतर उच्च आर्थिक संवृद्धि में श्रम उत्पादकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संदर्भ में, कई कारणों से श्रम संरचना (या श्रम गुणवत्ता) का आकलन आवश्यक है। सबसे पहले, श्रम और पूंजी उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले आवश्यक कारक इनपुट हैं, लेकिन पूंजी के बरक्स, राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएसएस) में श्रम का अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है। दूसरा, चूंकि कौशल की सीमा तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए भारत ने विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र में नियमित रोजगार में वृद्धि देखी है। गुणवत्ता के लिए समायोजित नहीं किए गए श्रम इनपुट में कौशल आयाम पर विचार नहीं किया जाता है। श्रम

<sup>^</sup> लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), मुंबई से हैं। इस शोधपत्र का संक्षिप्त संस्करण 23-25 अप्रैल, 2024 को जिनेवा में आयोजित यूरोप के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक आयोग (यूएनईसीडी) के राष्ट्रीय लेखा पर विशेषज्ञों के समूह की बैठक में प्रस्तुत किया गया था। बैठक में प्राप्त टिप्पणियों को विधिवत शामिल किया गया। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

उत्पादकता वृद्धि के पारंपरिक उपाय केवल श्रम को एक समरूप इकाई के रूप में देखकर रोजगार की प्रति इकाई उत्पादन को मापते हैं। “परिणामस्वरूप, एक अत्यधिक अनुभवी सर्जन द्वारा काम किए गए एक घंटे और एक फास्ट-फूड रेस्तरां में एक नए काम पर रखे गए किशोर द्वारा काम किए गए एक घंटे को समान मात्रा में श्रम माना जाता है” (ओईसीडी, 2001)। इसलिए, श्रम संरचना सूचकांक को मापना आवश्यक है जो उत्पादन वृद्धि पर श्रम गुणवत्ता के प्रभाव का आकलन करेगा। इसके अलावा, श्रम संरचना सूचकांक को मापना अमूर्त निवेश के प्रभाव को मापने और मानव पूंजी सूचकांक के निर्माण के लिए एक प्रारंभिक बिंदु हो सकता है, जो लोकहित और स्थिरता का एक महत्वपूर्ण मापांक है।

इस पृष्ठभूमि में, इस पत्र का उद्देश्य श्रम इनपुट वृद्धि की दीर्घकालिक प्रवृत्ति को प्रस्तुत करना है - जो भारत की कार्यशील आबादी के लिए मानव पूंजी का एक अंतर्निहित संकेतक है। श्रम इनपुट के दो घटक हैं: रोजगार और श्रम गुणवत्ता सूचकांक। रोजगार अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों द्वारा नियोजित व्यक्तियों की संख्या को मापता है, जबकि श्रम गुणवत्ता सूचकांक ज्ञान और कौशल के योगदान को दर्शाता है जो कार्यशील आबादी को आर्थिक संवृद्धि और उत्पादकता को चलाने के लिए सशक्त बनाता है। श्रम गुणवत्ता सूचकांक स्पष्ट रूप से कार्यबल की विविधता के लिए जिम्मेदार है, जो कि शैक्षणिक योग्यता और उद्योग के प्रकार से जुड़े उनके वेतन श्रेयों के आधार पर विभिन्न श्रमिकों को भार प्रदान करता है। श्रम इनपुट अनुमान में श्रम गुणवत्ता को शामिल करके, कम-कुशल से उच्च-कुशल श्रमिकों के अनुपात में परिवर्तन नियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि की तुलना में श्रम या उत्पादकता में वृद्धि को इंगित करता है।

भारत में, उत्पादन और आउटपुट से संबंधित आँकड़े एनएसएस से प्राप्त किए जाते हैं। दूसरी ओर, श्रम बाजार के आँकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा किए गए घरेलू स्तर के रोजगार सर्वेक्षण दौरों से उपलब्ध हैं। एनएसएस में श्रम खातों के बारे में व्यापक जानकारी नहीं है, और इसलिए, एनएसएस के साथ श्रम बाजार के आँकड़ों को एकीकृत करना समावेशी संवृद्धि, वितरण

और उत्पादकता के मुद्दों पर महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्नों को समझने में सहायक होगा। यह आलेख भारत क्लेम्स ढाँचा प्रस्तुत करता है जो एनएएस के अनुरूप श्रम खातों का निर्माण करता है और भारत में जीवीए वृद्धि के प्रक्षेप पथ पर श्रम और इसकी संरचना की भूमिका की जाँच करता है। एनएएस ढाँचे के साथ भारत के श्रम खातों को डिज़ाइन करने में विभिन्न माप चुनौतियाँ हैं। सबसे पहले, एनएएस डेटा सालाना प्रकाशित होते हैं, जबकि 2017-18 से पहले भारत में श्रम बल सर्वेक्षण पाँच साल के अंतराल पर किए गए थे। इसके अलावा, स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए आय या आय डेटा एनएएस में अलग से उपलब्ध नहीं हैं और उन्हें मिश्रित आय में शामिल किया गया है। इस अंतर को भरने के लिए, भारत के एलईएमएस डेटाबेस में उद्योगों के एनएएस वर्गीकरण के अनुरूप श्रम खातों की वार्षिक समय शृंखला बनाने का प्रयास किया गया है। श्रम इनपुट खातों की गणना अर्थव्यवस्था के समग्र और उप-क्षेत्रों के लिए की जाती है। अध्ययन की समय अवधि 1980-81 से 2021-22 है। संवृद्धि लेखांकन ढाँचे का पालन करते हुए, यह पत्र जीवीए वृद्धि में श्रम इनपुट और इसकी संरचना (श्रम गुणवत्ता) के योगदान का विश्लेषण करता है।

कृषि से निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार में उल्लेखनीय बदलाव आया है और विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल का नियमितीकरण बढ़ा है। आंकड़ों विश्लेषण से पता चलता है कि कुल अर्थव्यवस्था के लिए, 1980-81 से 2021-22 तक श्रम गुणवत्ता में औसतन 0.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है। सभी श्रमिकों के लिए शिक्षा के स्तर में सामान्य वृद्धि हुई है, विशेष रूप से पूंजी-गहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए। श्रम गुणवत्ता सूचकांक पूंजी-गहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में उच्च वृद्धि दर्शाता है, जबकि निर्माण और कृषि क्षेत्र कम-कुशल श्रमिकों की व्यापकता के कारण कम वृद्धि प्रदर्शित करते हैं। संवृद्धि लेखांकन अभ्यास से पता चलता है कि रोजगार ने उत्पादन वृद्धि में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें श्रम गुणवत्ता ने 1980-81 से 2021-22 तक औसतन उत्पादन वृद्धि में अतिरिक्त पांच प्रतिशत का योगदान दिया।

आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है। खंड II भारत में श्रम इनपुट सूचकांक के निर्माण के लिए उपयोग की जाने

वाली क्लेम्स पद्धति और डेटा स्रोतों का वर्णन करता है। खंड III 1980-81 से 2021-22 के दौरान भारत में श्रम गुणवत्ता पर कुछ शैलीगत तथ्य प्रस्तुत करता है। खंड IV समग्र और विघटित क्षेत्रों के लिए उत्पादन वृद्धि में श्रम इनपुट और इसकी संरचना के योगदान पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। अंतिम खंड एनएएस ढाँचे के साथ क्लेम्स के श्रम खातों को एकीकृत करने के संबंध में कुछ पुराने मुद्दों की चर्चा करता है।

## II. कार्यप्रणाली और डेटासेट

जॉर्जेनसन और अन्य (1987) और यूरोपीय संघ के एलईएमएस मैनुअल के बाद, भारत के एलईएमएस ढाँचे ने श्रम इनपुट सूचकांक तैयार किया है जो गुणवत्ता के लिए समायोजित रोजगार वृद्धि का अनुमान लगाता है (केएलईएमएस मैनुअल, 2024)। यह ढाँचा प्रत्येक श्रमिक प्रकार को श्रमिकों द्वारा प्राप्त शिक्षा के स्तर के आधार पर एक अलग-अलग भार देता है। श्रम इनपुट सूचकांक की वृद्धि इस प्रकार दी गई है -

$$\Delta \ln L = \sum \bar{v}_i \Delta \ln H_{ijt} \quad (1)$$

जहाँ  $L$  समग्र श्रम सूचकांक है,  $H_{ijt}$  अवधि 't' में उद्योग 'j' में एक विशेष शिक्षा प्रकार 'i' द्वारा काम किए गए कुल व्यक्तियों को इंगित करता है।

$i = 1, 2, \dots, n$  और शिक्षा श्रेणियों की संख्या को दर्शाता है।

$j = 1, 2, \dots, n$  और उद्योगों की संख्या को दर्शाता है।

$\sum$  सभी शिक्षा श्रेणियों का योग दर्शाता है।

$\bar{v}_i$  श्रम मुआवज़ा मूल्य का औसत अनुपात है जो रोजगार की प्रत्येक श्रेणी की ओर जाता है। इसे इस प्रकार दिया गया है-

$$\bar{v}_i = \frac{1}{2} [v_i + v_{i-1}] \text{ and } v_i = w_i H_i / \sum w_i H_i$$

यहाँ,  $v_i$ ,  $i^{\text{th}}$  शिक्षा श्रेणी के लिए श्रम का मूल्य हिस्सा है।  $w_i$ ,  $i^{\text{th}}$  शिक्षा श्रेणी के लिए श्रम की मजदूरी दर है।

भार संरचना का तात्पर्य यह है कि जिन श्रमिकों को अधिक वेतन मिलता है, उनका श्रम इनपुट सूचकांक पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव होगा।

समीकरण (1) से यह निष्कर्ष निकलता है कि श्रम गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है।

$$\Delta \ln QI_t = \sum \bar{v}_i \Delta \ln H_{ijt} - \Delta \sum \ln H_{jt} \quad (2)$$

जहाँ  $QI_t$  श्रम का गुणवत्ता सूचकांक है। समीकरण (2) में, दाएँ हाथ की ओर पहला आइटम श्रम इनपुट में परिवर्तन को दर्शाता है, जबकि दूसरा शब्द कर्मचारियों की कुल संख्या में परिवर्तन को दर्शाता है। दोनों के बीच का अंतर श्रम गुणवत्ता सूचकांक देता है, जो देश के श्रम बल की शैक्षिक प्राप्ति में परिवर्तन के प्रभाव को मापता है।

एक बार रोजगार और श्रम संरचना (या श्रम गुणवत्ता) सूचकांक का निर्माण हो जाने के बाद, जॉर्जेनसन और अन्य (2005) द्वारा संवृद्धि लेखांकन ढांचे का पालन करते हुए, उत्पादन वृद्धि में रोजगार और श्रम गुणवत्ता के सापेक्ष योगदान का अनुमान लगाया जाता है। किसी उद्योग की उत्पादन वृद्धि की गणना कारक इनपुट वृद्धि और कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) वृद्धि के भारित हिस्से के रूप में की जाती है। कारक इनपुट के मुआवजे का उपयोग भार के रूप में किया जाता है। उत्पादन वृद्धि लेखांकन अपघटन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है:

$$\Delta \ln Y_t = \bar{v}_K \Delta \ln K_t + \bar{v}_L \Delta \ln L_t + \bar{v}_{LQ} \Delta \ln LQ_t + TFP_t \quad (3)$$

जहाँ  $\Delta \ln Y_t$  कुल अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन वृद्धि में वृद्धि है।  $\Delta \ln K_t$  और  $\Delta \ln L_t$  प्राथमिक कारक इनपुट- पूंजी (K) और श्रम (L) की वृद्धि को दर्शाता है।  $\Delta \ln LQ_t$  श्रम गुणवत्ता की वृद्धि को दर्शाता है।  $\bar{v}$  सकल मूल्य वर्धित में कारक इनपुट (श्रम और पूंजी) का दो-अवधि औसत मुआवजा हिस्सा है।  $TFP_t$  कुल कारक उत्पादकता वृद्धि है। सभी चर समय  $t$  के साथ अनुक्रमित हैं। समीकरण (3) को लागू करके, हम उत्पादन वृद्धि के अनुपात की गणना कर सकते हैं जो क्रमशः रोजगार, श्रम गुणवत्ता, पूंजी और  $TFP_t$  वृद्धि में वृद्धि द्वारा हिसाब में लिया जाता है।

श्रम गुणवत्ता सूचकांक की गणना के लिए, विभिन्न उद्योगों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या और श्रमिकों की शैक्षिक योग्यता के अनुसार आय (श्रम मुआवजा) का डेटा आवश्यक है। यह

ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत के लिए रोजगार और आय के आंकड़ों की एक सुसंगत समय शृंखला के निर्माण में कई मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए, रोजगार के आंकड़ों की पिछली शृंखला एनएसएसओ के पंचवर्षीय रोजगार सर्वेक्षण दौर पर आधारित है, जो 1980 से 2011 तक पांच साल के अंतराल पर प्रकाशित हुए थे; 2017 के बाद से, पीएलएफएस वार्षिक रोजगार शृंखला प्रदान करता है। इसके अलावा, भारत में एक बड़ा अनौपचारिक श्रम बाजार है, और विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों, विशेष रूप से स्व-नियोजित श्रमिकों की आय की जानकारी एनएसएस और श्रम बल सर्वेक्षण दौर में लगातार उपलब्ध नहीं है। इस अंतर को भरने के लिए, क्लेम्स ढांचे में निम्नलिखित उपचार किए जाते हैं:

(ए) रोजगार समय शृंखला के लिए, कार्यकर्ता भागीदारी दरें एनएसएसओ (32वें से 68वें दौर) द्वारा प्रकाशित सात इकाई-स्तरीय रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूस) दौर और पांच आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) (2017-18 से 2021-22) से ली गई हैं। चूंकि विभिन्न श्रम बल सर्वेक्षण दौर अलग-अलग राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण (एनआईसी) का उपयोग करते हैं, इसलिए एनआईसी 1970, एनआईसी 1987, एनआईसी 1998 और एनआईसी 2007 उद्योग वर्गीकरणों के बीच एक सामंजस्य स्थापित किया गया है। फिर प्रासंगिक अवधि के लिए जनगणना से जनसंख्या अनुमानों में ईयूस से कार्यकर्ता भागीदारी दरों को लागू करके नियोजित लोगों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। प्रमुख रोजगार दौरों के बीच के वर्षों के लिए, रोजगार अनुमान प्रक्षेप द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। गैर-जनगणना वर्षों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण डेटा विश्व बैंक के अनुमानों से प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय लेखा अनुमानों के साथ मेल खाने के लिए, प्रक्षेप अक्टूबर के आसपास केंद्रित है, जो भारतीय वित्तीय वर्ष (अप्रैल- मार्च) (केएलईएमएस मैनुअल 2024) का मध्य बिंदु है।

(बी) जब रोजगार की समय शृंखला प्राप्त हो जाती है, तो अगला कदम श्रमिक समूहों की विविधता को ध्यान में रखना होता है। भारत केएलईएमएस ढांचे में कौशल को शैक्षिक विशेषताओं के संदर्भ में मापा जाता है। शैक्षिक श्रेणियां हैं: (i)

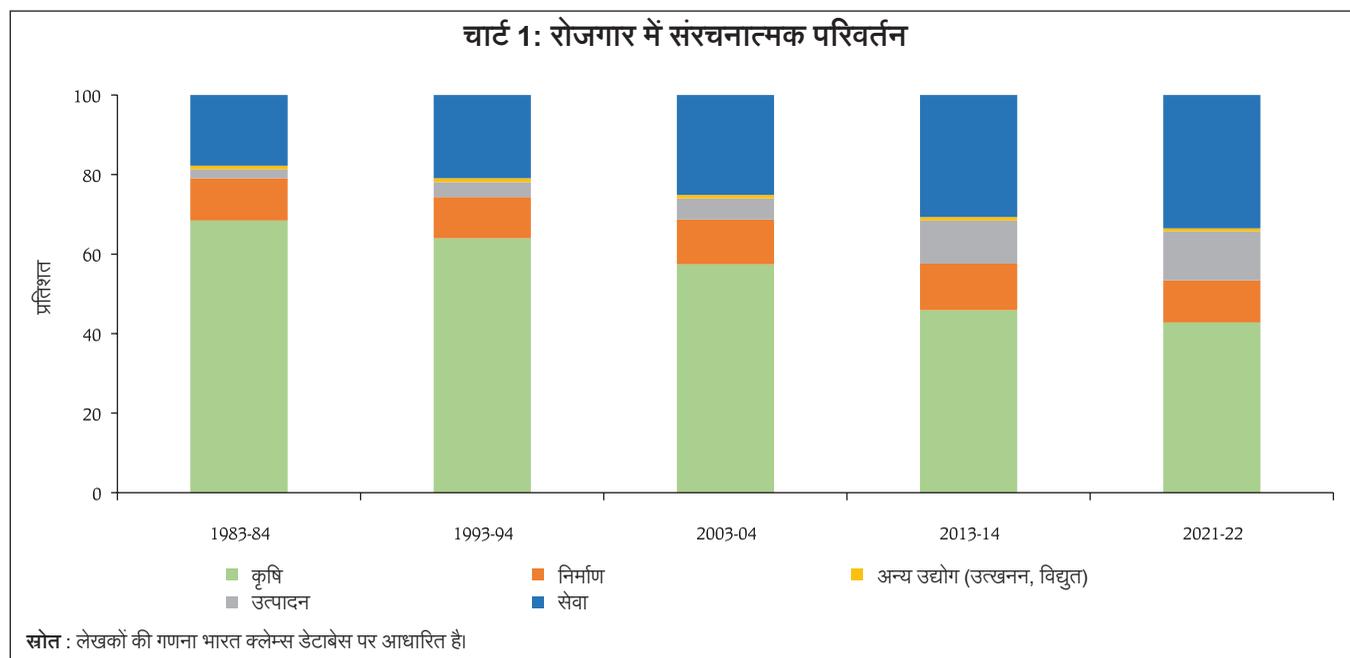
प्राथमिक से नीचे (ii) प्राथमिक (iii) मध्य, (iv) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक, और (v) उच्चतर माध्यमिक से ऊपर।<sup>1</sup>

(सी) शिक्षा के स्तर के आधार पर अस्थायी और नियमित श्रमिकों की मजदूरी रोजगार सर्वेक्षण दौर से प्राप्त की जाती है। हालाँकि, स्व-नियोजित श्रमिकों की आय सीधे नहीं देखी जा सकती है और इसका अनुमान अर्थमितीय रूप से लगाया जाना चाहिए। स्व-नियोजित व्यक्तियों की आय निकालने के लिए, यूरोपीय संघ के क्लेम्स पद्धति में मानक अभ्यास का पालन भारत के क्लेम्स में किया जाता है, जहाँ सबसे पहले हेकमैन की दो-चरणीय तकनीक (हेकमैन, 1976) का उपयोग करके नमूना चयन पूर्वाग्रह को ठीक किया जाता है। उसके बाद, अस्थायी और नियमित श्रमिकों की कमाई पर मिन्सर वेतन फ़ंक्शन का उपयोग किया गया है। परिणामी डेटा का उपयोग समान लक्षणों वाले स्व-नियोजित श्रमिकों की संबंधित आय का पता लगाने के लिए किया जाता है (अग्रवाल और एरुम्बन, 2013)। प्रतिगमन में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण चर आयु, वैवाहिक स्थिति, ग्रामीण या शहरी स्थान, लिंग और घर के प्रकार पर डमी चर हैं।

अंत में, जब अस्थायी, नियमित और स्व-नियोजित श्रमिकों के लिए शैक्षिक वितरण के अनुसार मजदूरी प्राप्त की जाती है, तो ऊपर बताए गए समीकरणों (1) और (2) का उपयोग करके श्रम गुणवत्ता सूचकांक की गणना की जाती है।

### III. रोजगार गुणवत्ता पर स्थापित तथ्य

पिछले कुछ वर्षों में भारत में रोजगार संरचना में एक स्पष्ट बदलाव आया है। कृषि क्षेत्र सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता बना हुआ है, हालांकि कृषि में रोजगार का हिस्सा 1983-84 में 68.5 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 42.8 प्रतिशत हो गया। कृषि से दूर जाने वाले कार्यबल को गैर-कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से निर्माण और सेवाओं में अवसर मिले (गोल्डर और अन्य, 2017)। 1983-84 में निर्माण क्षेत्र में कुल अर्थव्यवस्था के रोजगार का 2.3 प्रतिशत हिस्सा था और 2021-22 में इसका हिस्सा बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया। इसी अवधि के दौरान सेवा क्षेत्र का रोजगार हिस्सा 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 33.5 प्रतिशत हो गया। विनिर्माण रोजगार का हिस्सा सीमित रहा (चार्ट 1)।



<sup>1</sup> एनएसएसओ और पीएलएफएस में शिक्षा श्रेणियों के साथ-साथ घरेलू सर्वेक्षण दौरों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: जो व्यक्ति औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से साक्षर हैं और अभी तक प्राथमिक मानक शिक्षा पास नहीं कर पाए हैं, उन्हें प्राथमिक से नीचे के रूप में परिभाषित किया गया है। जो व्यक्ति कक्षा V पास कर चुके हैं, उन्हें प्राथमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो लोग कक्षा VIII पास कर चुके हैं, उन्हें मध्यम के रूप में, जो लोग कक्षा X और XII पूरी कर चुके हैं, उन्हें माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है और जो लोग स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा पूरी कर चुके हैं, उन्हें उच्चतर माध्यमिक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

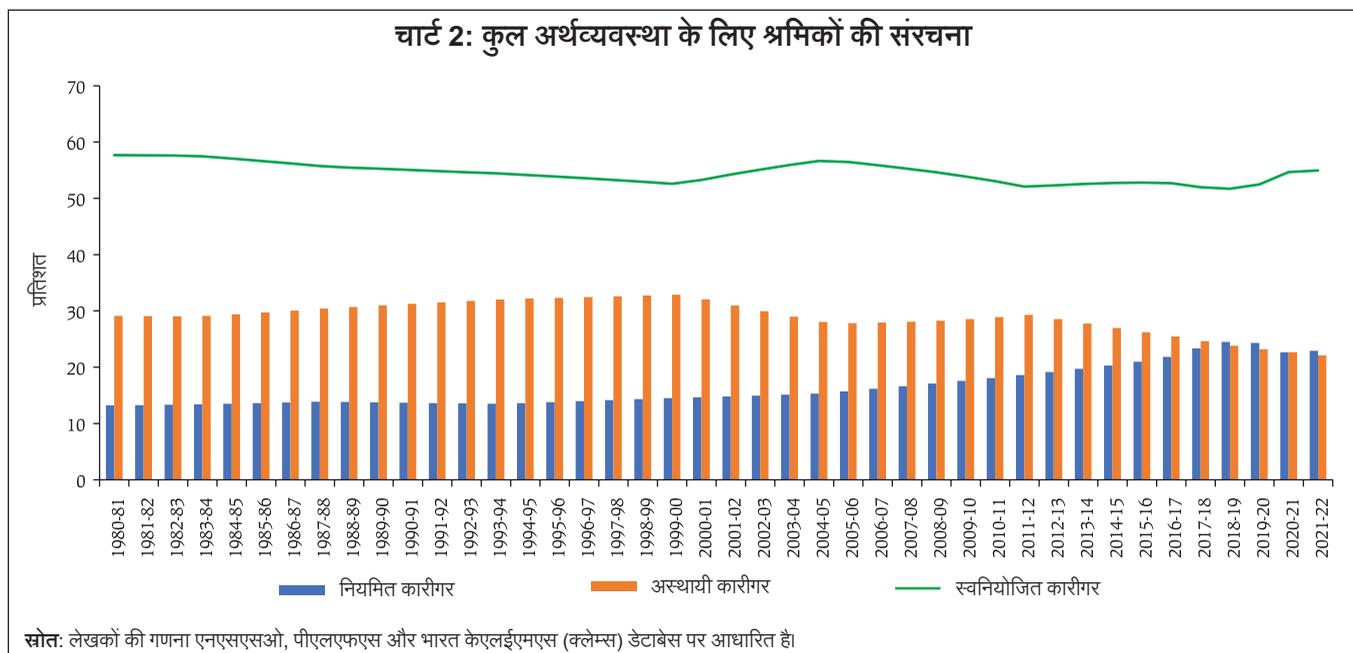
इसके बाद, हम अर्थव्यवस्था के उप-क्षेत्रों में रोजगार की गुणवत्ता की जांच करते हैं। चयनित विशेषताएँ हैं: क) रोजगार की प्रकृति, ख) श्रमिकों की शिक्षा प्रोफाइल, और ग) श्रमिकों को दिया जाने वाला मुआवजा। विकासशील देशों में नौकरी की गुणवत्ता को मापने के लिए रोजगार की प्रकृति एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रॉक्सी है। भारत में श्रम बाजार में तीन प्रकार के श्रमिक हैं - नियमित, अस्थायी और स्व-नियोजित। नियमित रोजगार को अस्थायी और स्व-रोजगार की तुलना में अधिक स्थिर और बेहतर गुणवत्ता वाला माना जाता है क्योंकि अधिकांश नियमित श्रमिकों के पास लिखित नौकरी अनुबंध होते हैं (नय्यर, 2012; दीवान और पीक, 2007; पापोला और शर्मा; 2015)। श्रमिकों की शैक्षिक योग्यता को नौकरी की गुणवत्ता का संकेतक माना जाता है, क्योंकि उच्च शिक्षा वाले श्रमिक नौकरी की सुरक्षा, लाभ और उच्च मजदूरी के मामले में बेहतर गुणवत्ता वाली नौकरियां हासिल करते हैं (अग्रवाल और गोल्डर, 2019)।

### III.1 रोजगार की प्रकृति

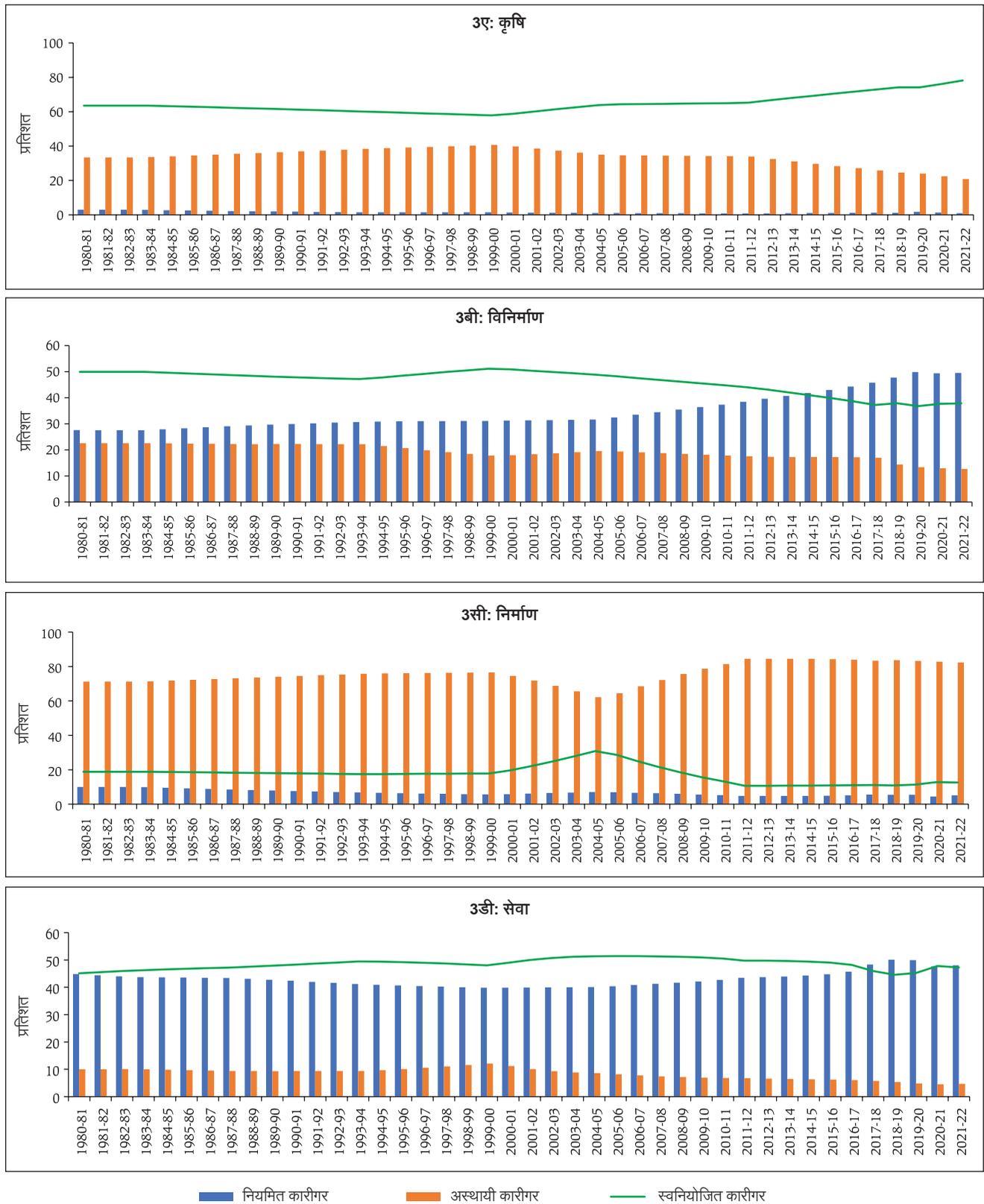
नौकरी की गुणवत्ता का पहला पहलू रोजगार की प्रकृति से संबंधित है। श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक/असंगठित

क्षेत्र में लगा हुआ है। नियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और अस्थायी और स्वरोजगार श्रमिकों की हिस्सेदारी समय के साथ घट रही है। स्वरोजगार और अस्थायी श्रमिकों की संयुक्त हिस्सेदारी 1980-81 में 86.8 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 77 प्रतिशत हो गई। इसके विपरीत, नियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी 1980-81 में 13.2 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 22.9 प्रतिशत हो गई (चार्ट 2)।

कार्यबल के अधिक नियमितीकरण पर देखा गया पैटर्न विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों से आया है। विनिर्माण क्षेत्र में, नियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी 1980-81 में 27.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 49.9 प्रतिशत हो गई। सेवा क्षेत्र में, नियमित श्रमिकों की हिस्सेदारी 1980-81 में 44.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 48.1 प्रतिशत हो गई। कृषि और निर्माण क्षेत्रों में अनौपचारिक श्रमिकों की हिस्सेदारी अधिक है। कृषि में, स्व-नियोजित श्रमिकों की हिस्सेदारी 1980-81 में 63.6 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 78.2 प्रतिशत हो गई। निर्माण क्षेत्र, जो रोजगार सृजन के मामले में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक बन गया है, में ज्यादातर अस्थायी श्रमिक हैं। निर्माण क्षेत्र में अस्थायी कार्यबल की हिस्सेदारी 1980-81 में 71.2 प्रतिशत थी, जो 2021-22 में बढ़कर 82.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट 3)।



चार्ट 3: व्यापक क्षेत्रों में श्रमिकों की संरचना



स्रोत: लेखकों की गणना एनएसएसओ, पीएलएफएस और भारत के एलईएमएस डेटाबेस पर आधारित है।

### III.2 श्रमिकों की शिक्षा प्राप्ति

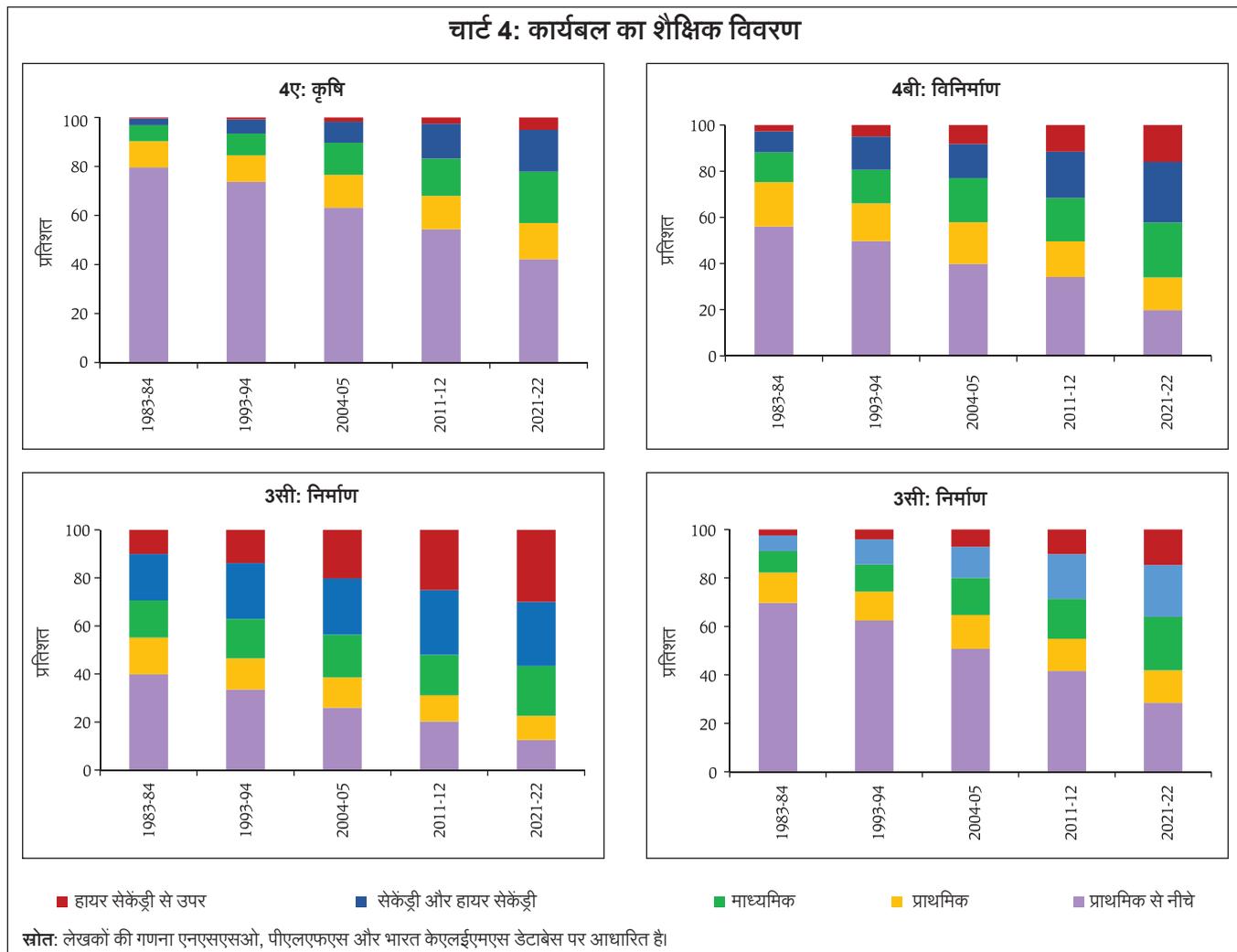
नौकरी की गुणवत्ता का दूसरा गुण श्रमिकों की शैक्षिक प्राप्ति है। जब हम 1983-84 से 2021-22 तक व्यापक शिक्षा श्रेणियों द्वारा कार्यबल के वितरण का विश्लेषण करते हैं, तो यह देखा जाता है कि सभी श्रमिकों के लिए शिक्षा का सामान्य स्तर बढ़ा है। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक से नीचे की शिक्षा वाले श्रमिकों की हिस्सेदारी में कमी आई है और उच्चतर माध्यमिक या तृतीयक शिक्षा से ऊपर के श्रमिकों की हिस्सेदारी में इसी तरह की वृद्धि हुई है। अलग-अलग क्षेत्रों में, क्षेत्रों की कौशल तीव्रता काफी अलग है। कृषि क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा वाले सबसे बड़े कार्यबल हैं। दूसरी ओर, विनिर्माण क्षेत्र में मध्य, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक डिग्री वाले श्रमिकों की

संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र में तृतीयक-शिक्षित श्रमिकों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से ऊपर के सेवा क्षेत्र में रोजगार का हिस्सा 1983-84 में लगभग 10 प्रतिशत था जो 2021-22 में बढ़कर 30 प्रतिशत हो गया। इससे पता चलता है कि सेवा क्षेत्र की नौकरियाँ उच्च कौशल गहन प्रकृति की होती जा रही हैं, जबकि विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी की आवश्यकताएं मध्यम कौशल गहन बनी हुई हैं (चार्ट 4)।

### III.3 श्रम आय का हिस्सा

नौकरी की गुणवत्ता का तीसरा पहलू श्रमिकों के मुआवजे से संबंधित है। 1981-82 में, जीवीए में श्रम आय का हिस्सा निर्माण क्षेत्र में 80 प्रतिशत से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में 38 प्रतिशत तक

चार्ट 4: कार्यबल का शैक्षिक विवरण



## सारणी 1: श्रम आय का क्षेत्रवार हिस्सा

(प्रतिशत)

	1981-82	1991-92	2001-02	2021-22
कुल अर्थव्यवस्था	54.1	53.6	50.8	51.9
कृषि	57.5	56.2	55.2	56.1
खनन और उत्खनन	37.3	32.1	34.2	24.6
विनिर्माण	37.9	33.9	32.0	31.5
निर्माण	80.0	80.3	77.9	77.3
सेवाएँ	57.0	58.6	53.2	54.4

टिप्पणी: श्रम और पूंजी आय का योग 100 होता है।

स्रोत: भारत क्लेम्स डेटाबेस पर आधारित लेखकों की गणना।

था (सारणी 1)। संरचनात्मक परिवर्तन और विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी तीव्रता में वृद्धि के कारण, 1981-82 से 2021-22 के बीच कुल अर्थव्यवस्था के लिए श्रम आय का हिस्सा 2.2 प्रतिशत, कृषि के लिए 1.4 प्रतिशत, खनन और उत्खनन के लिए 12.7 प्रतिशत, विनिर्माण के लिए 6.4 प्रतिशत, निर्माण के लिए 2.7 प्रतिशत और सेवा क्षेत्रों के लिए 2.6 प्रतिशत घट गया (सारणी 1)। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) (2014) ने पाया कि विकसित और उभरते देशों में, यदि वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर श्रम उत्पादकता वृद्धि की तुलना में धीमी है, तो श्रम आय का हिस्सा घट जाता है। भारत के लिए मजदूरी उत्पादकता डेटा की जांच करते हुए, गोलडार और दास (2020) ने पाया कि भारत के लिए कुल अर्थव्यवस्था और उप-क्षेत्रों के लिए वास्तविक मजदूरी वृद्धि श्रम उत्पादकता वृद्धि से पीछे है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र में विचलन सबसे अधिक है।

इसके बाद, हम अलग-अलग क्षेत्रों के लिए नौकरी की गुणवत्ता की तीन विशेषताओं को जोड़ते हैं और उन क्षेत्रों की पहचान करते हैं जिनमें कुशल श्रमिकों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, उच्च वेतन देते हैं और नियमित श्रमिकों को अधिक रोजगार देते हैं। विनिर्माण के भीतर, रसायन, मशीनरी और लुगदी और कागज उत्पादों जैसे पूंजी-गहन उद्योग अपेक्षाकृत उच्च कुशल श्रमिकों को रोजगार देते हैं। सेवा क्षेत्र के भीतर, व्यवसाय और वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूरसंचार रोजगार की उच्च गुणवत्ता प्रदान करते हैं, जिसे शिक्षा के स्तर,

सारणी 2: रोजगार की गुणवत्ता और  
क्षेत्रीय वितरण - 2021-22

उच्च कुशल श्रमिकों की अपेक्षाकृत उच्च हिस्सेदारी वाले क्षेत्र	नियमित श्रमिकों का अनुपात	प्रतिदिन औसत वेतन
1 लुगदी, कागज, मुद्रण और प्रकाशन	उच्च	उच्च
2 कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद	उच्च	निम्न
3 रसायन और रासायनिक उत्पाद	उच्च	उच्च
4 रबर और प्लास्टिक उत्पाद	उच्च	निम्न
5 मूलभूत और निर्मित धातु उत्पाद	उच्च	निम्न
6 मशीनरी	उच्च	उच्च
7 विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण	उच्च	निम्न
8 परिवहन उपकरण	उच्च	निम्न
9 बिजली, गैस और जल आपूर्ति	उच्च	उच्च
10 डाक और दूरसंचार	उच्च	उच्च
11 वित्तीय सेवाएँ	उच्च	उच्च
12 व्यावसायिक सेवाएँ	उच्च	उच्च
13 लोक प्रशासन और रक्षा	उच्च	निम्न
14 शिक्षा	उच्च	उच्च
15 स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य	उच्च	उच्च

टिप्पणी: जब शिक्षा का स्तर, नियमित श्रमिकों का अनुपात और मजदूरी दर कुल अर्थव्यवस्था औसत से ऊपर होती है, तो क्षेत्रों को उच्च के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसी तरह, यदि उच्च शिक्षा का स्तर उच्च है, अस्थायी श्रमिकों का अनुपात कम है, और औसत मजदूरी राष्ट्रीय औसत से कम है, तो क्षेत्रों को निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

स्रोत: भारत के एलईएमएस डेटाबेस से लेखकों की गणना।

नियमित श्रमिकों के अनुपात और प्रति दिन औसत वेतन (सारणी 2) के संदर्भ में मापा जाता है।

## IV. श्रम गुणवत्ता वृद्धि और जीवीए वृद्धि में इसका योगदान

## IV.1 रोजगार में वृद्धि

यह देखा गया है कि 1980-81 से 2021-22 के दौरान कुल अर्थव्यवस्था के लिए औसत रोजगार वृद्धि 2.7 प्रतिशत प्रति वर्ष थी, जो मुख्य रूप से निर्माण और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित थी। सभी सेवा उप-क्षेत्रों में औसतन 3 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक रोजगार वृद्धि दर्ज की गई। सेवा क्षेत्रों में, व्यावसायिक सेवाओं, निर्माण, विद्युत और ऑप्टिकल उपकरण, और वित्तीय सेवा उप-क्षेत्रों में रोजगार वृद्धि सबसे तेज़ थी (सारणी 3 और चार्ट 5)।

## IV.2 श्रम गुणवत्ता सूचकांक में वृद्धि

कुल अर्थव्यवस्था के लिए, श्रम गुणवत्ता सूचकांक 1980-81 से 2021-22 तक औसतन 0.7 प्रतिशत प्रति वर्ष बढ़ा है।

### सारणी 3: रोजगार वृद्धि: व्यापक क्षेत्र

(वार्षिक औसत, प्रतिशत)

उपक्षेत्र	1980-81 से 1999-00	2000-01 से 2021-22	1980-81 से 2021-22
कुल अर्थव्यवस्था	2.8	2.5	2.7
कृषि	1.0	-0.1	0.4
विनिर्माण	2.6	2.0	2.3
निर्माण	5.9	6.2	6.1
खनन और उत्खनन	2.8	-1.8	0.5
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	1.8	3.6	2.7
सेवाएँ	3.5	2.9	3.2

स्रोत: भारत के एलईएमएस डेटाबेस से लेखकों की गणना।

व्यापक क्षेत्रों में, विनिर्माण और खनन के लिए श्रम गुणवत्ता सूचकांक की वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक रही है (सारणी 4)। विघटित उद्योग स्तर पर, रसायन, मशीनरी और परिवहन उपकरण जैसे पूंजी-गहन विनिर्माण क्षेत्रों में श्रम गुणवत्ता में सुधार सबसे तेज था। सेवा क्षेत्र में, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य और दूरसंचार जैसे उप-क्षेत्रों ने श्रम गुणवत्ता सूचकांक में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की (चार्ट 6)। हालांकि, व्यवसाय, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं जैसे उप-क्षेत्रों ने गुणवत्ता सूचकांक में धीमी वृद्धि दर्ज की क्योंकि इन क्षेत्रों में पहले से ही कुशल श्रमिकों की हिस्सेदारी बहुत अधिक है (कृष्णा और अन्य, 2016)।

### सारणी 4: श्रम गुणवत्ता वृद्धि: व्यापक क्षेत्र

(वार्षिक औसत, प्रतिशत)

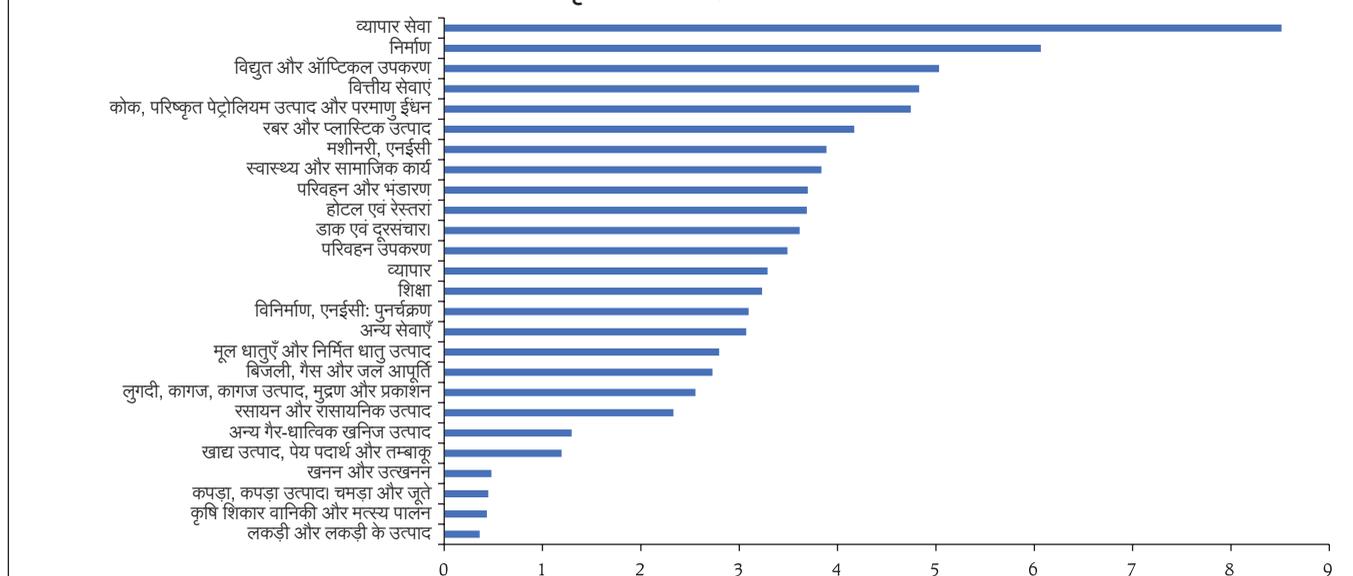
उपक्षेत्र	1980-81 से 1999-00	2000-01 से 2021-22	1980-81 से 2021-22
कुल अर्थव्यवस्था	0.72	0.60	0.66
कृषि	0.28	0.34	0.32
विनिर्माण	0.87	0.63	0.74
निर्माण	0.46	0.33	0.39
खनन और उत्खनन	0.74	1.58	1.19
बिजली, गैस और जल आपूर्ति	0.83	0.44	0.62
सेवाएँ	0.55	0.59	0.56

स्रोत: भारत के एलईएमएस डेटा 2024 से लेखकों की गणना।

### IV. 3 उत्पादन वृद्धि में श्रम इनपुट का योगदान

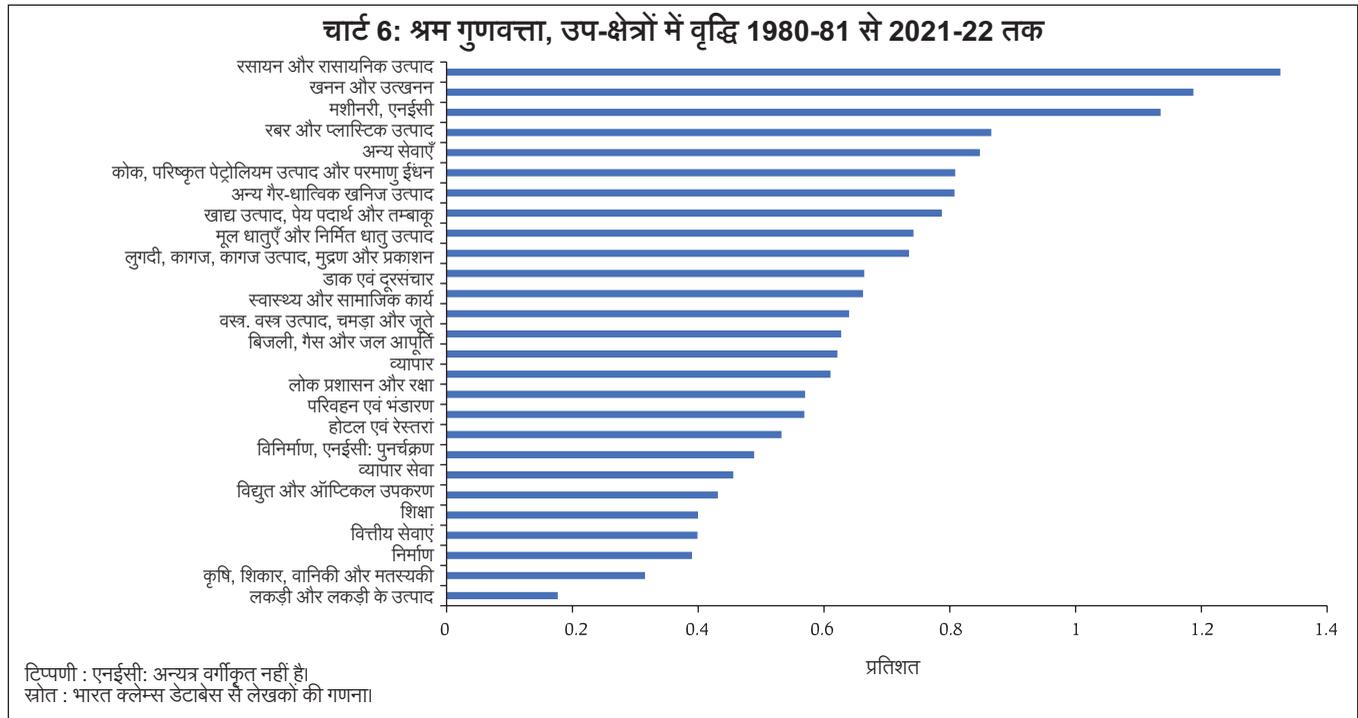
1980-81 से 2021-22 तक के संवृद्धि लेखांकन विघटन से पता चलता है कि श्रम गुणवत्ता सूचकांक ने औसतन उत्पादन वृद्धि में लगभग पाँच प्रतिशत का योगदान दिया। इसी अवधि के दौरान रोजगार ने उत्पादन वृद्धि में लगभग एक-चौथाई योगदान दिया। 1980 के दशक के दौरान श्रम का योगदान अपेक्षाकृत अधिक था, और 1990 के दशक के मध्य से, पूंजी गहनता उत्पादन वृद्धि में अग्रणी योगदानकर्ता बन गई है। श्रम इनपुट का योगदान अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है और अध्ययन अवधि के दौरान उत्पादन वृद्धि में इसका योगदान 30 प्रतिशत रहा (चार्ट 7)।

### चार्ट 5: रोजगार वृद्धि: उप क्षेत्र, 1980-81 से 2021-22



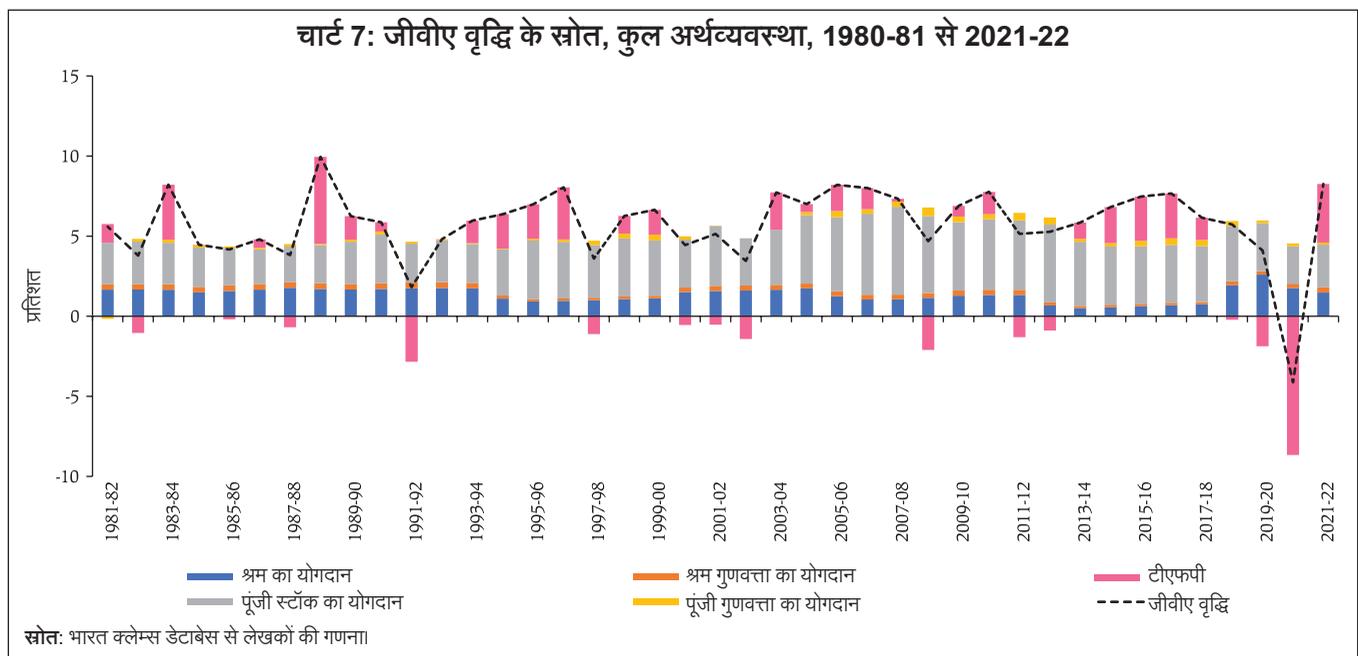
टिप्पणी: एनईसी: अन्यत्र वर्गीकृत नहीं।

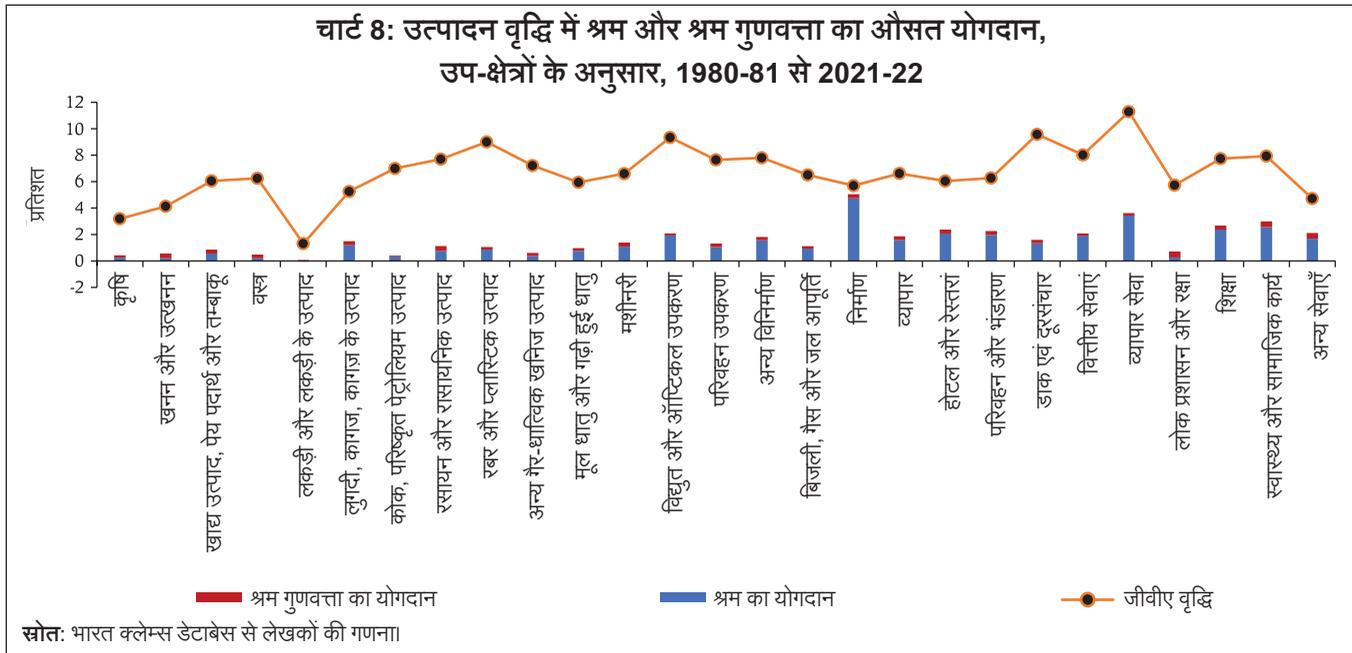
स्रोत: भारत क्लेम्स डेटाबेस से लेखकों की गणना।



विनिर्माण के क्षेत्र में, कपड़ा, लुगदी, कागज उत्पादों और मशीनरी और उपकरणों के लिए उत्पादन वृद्धि में श्रम गुणवत्ता का योगदान अधिक था। सेवाओं के क्षेत्र में, श्रम गुणवत्ता वृद्धि ने लोक प्रशासन और रक्षा के लिए उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अन्य सेवा उपक्षेत्र जहाँ श्रम गुणवत्ता का योगदान

अधिक था, उनमें स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, परिवहन और भंडारण तथा होटल और रेस्तरां शामिल हैं। इसके अलावा, खनन, उत्खनन और निर्माण क्षेत्रों में भी श्रम गुणवत्ता वृद्धि द्वारा संचालित उत्पादन का पाँच प्रतिशत से अधिक हिस्सा है (चार्ट 8)।





## V. निष्कर्ष

भारतीय श्रम बाजार में, कृषि से निर्माण और सेवा क्षेत्रों में रोजगार में उल्लेखनीय बदलाव हुआ है, साथ ही विनिर्माण क्षेत्र में कार्यबल का नियमितीकरण भी बढ़ा है। शैक्षिक श्रेणियों में कार्यबल वितरण का विश्लेषण सभी श्रमिकों के लिए शिक्षा के स्तर में सामान्य वृद्धि दर्शाता है। रसायन और मशीनरी जैसे पूंजी-गहन उद्योग उच्च शिक्षा स्तर, उच्च औसत मजदूरी और कम अस्थायी श्रमिकों वाले श्रमिकों को रोजगार देते हैं। सेवा क्षेत्रों में, व्यवसाय और वित्तीय सेवाएँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक प्रशासन और रक्षा उप-क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार प्रदर्शित करते हैं। कार्यबल की शैक्षिक विशेषताओं के आधार पर गणना किए गए श्रम गुणवत्ता सूचकांक से पता चलता है कि 1980-81 से 2021-22 तक श्रम गुणवत्ता में औसतन 0.7 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, जो स्वास्थ्य और सामाजिक कार्य, अन्य सेवाओं और दूरसंचार जैसे पूंजी-गहन विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों द्वारा संचालित है।

क्लेम्स ढांचे में संवृद्धि लेखांकन अभ्यास से पता चलता है कि रोजगार ने उत्पादन वृद्धि में लगभग 25 प्रतिशत का योगदान दिया, जिसमें श्रम गुणवत्ता ने 1980-81 से 2021-22 के दौरान

औसतन उत्पादन वृद्धि में अतिरिक्त पांच प्रतिशत का योगदान दिया। इस प्रकार, श्रम इनपुट (संयुक्त रोजगार और गुणवत्ता) ने 1980-81 से 2021-22 के दौरान समग्र उत्पादन वृद्धि का 30 प्रतिशत हिस्सा लिया। विनिर्माण क्षेत्र में, श्रम गुणवत्ता ने कपड़ा, लुगदी, कागज उद्योग और मशीनरी में उत्पादन वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवाओं में, लोक प्रशासन, रक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कार्य, परिवहन और भंडारण, और होटल और रेस्तरां जैसे उप-क्षेत्रों में श्रम गुणवत्ता से उत्पादन वृद्धि में पर्याप्त योगदान देखा गया।

आगे बढ़ते हुए, क्लेम्स ढांचे से प्राप्त भारत के श्रम डेटा को एनएस डेटा के साथ एकीकृत करने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि क्लेम्स ढांचा एनएस के साथ संगति बनाए रखता है। नीदरलैंड, स्विटजरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने पहले ही अपने राष्ट्रीय खातों की प्रणाली (एसएनए) में श्रम खाते प्रकाशित कर दिए हैं। एसएनए ढांचे (2023) को बढ़ाने और व्यापक बनाने के लिए मार्गदर्शन पर रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि एसएनए में श्रम खातों में चार चतुर्भुज सारणियां होनी चाहिए, जिसमें नौकरियों, नियोजित व्यक्तियों की संख्या (नियमित, अस्थायी और स्व-नियोजित श्रमिकों सहित), मात्रा (यानी काम किए गए घंटे) और

भुगतान की जानकारी शामिल हो। भारत के लिए, प्रतिष्ठान-आधारित या उद्यम-स्तरीय सर्वेक्षणों से नौकरी और रिक्तियों की पोस्टिंग के आँकड़ों पर विचार करने का प्रयास किया जा सकता है। श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रोजगार परिदृश्य पर त्रैमासिक रिपोर्ट ने 2021 से उद्यम-वार रिक्तियों का विवरण प्रदान करना शुरू कर दिया है। एक अन्य डेटा चुनौती स्व-नियोजित व्यक्तियों के वेतन का अनुमान लगाना है, जो भारत में नियोजित व्यक्तियों का बहुमत है। भुगतान क्वांट एनएएस में उपलब्ध है, जहाँ स्व-नियोजित व्यक्तियों के भुगतान को मिश्रित आय के अंतर्गत रखा जाता है। मिश्रित आय में स्व-नियोजित व्यक्तियों के उत्पादन और श्रम आय से अर्जित अधिशेष शामिल होता है। क्लेम्स खातों के साथ एकीकरण राष्ट्रीय खातों में पूंजी की आय और स्व-नियोजित, नियमित और अस्थायी श्रमिकों की आय के बीच मिश्रित आय के पृथक्करण की सुविधा प्रदान कर सकता है।

### संदर्भ

Aggarwal, S. C., and Goldar, B. (2019). Structure and growth of employment: Evidence from India KLEMS data. *Indian Growth and Development Review*, 12(2), 202-228.

Aggarwal, S. C., and Erumban, A. A. (2013). Labour input for measuring productivity growth in India: methodology and estimates. *paper presented at the Second India KLEMS Annual Workshop*, April 26, 2012. New Delhi: ICRIER.

Dewan, S. and Peek, P. (2007). Beyond the employment/unemployment dichotomy: measuring the quality of employment in low income countries. *Working Paper No. 83*, Policy Integration and Statistics Department, ILO, Geneva.

Goldar, B., Krishna, K. L., Aggarwal, S. C., Das, D. K., Erumban, A. A., & Das, P. C. (2017). Productivity growth in India since the 1980s: the KLEMS approach. *Indian Economic Review*, 52, 37-71.

Jackson, A., and Kumar, P. (1998). Measuring and monitoring the quality of jobs and the work

environment in Canada. In *Proceedings of the Centre for the Study of Living Standards Conference on the State of Living Standards and Quality of Life*, Ottawa, AB, Canada (pp. 30-31).

Jorgenson, D. W., Ho, M. S., and Stiroh, K. J. (2005). *Productivity, Volume 3: Information technology and the American growth Resurgence*. MIT Press Books.

Jorgenson, D. W., Gollop, F. M., and Barbara, M. Fraumeni. 1987. *Productivity and US economic growth*, 580.

KLEMS Manual (2024). Measuring Productivity at Industry Level- The India KLEMS database. Reserve Bank of India.

Krishna, K. L., Das, D. K., Erumban, A. A., Aggarwal, S., and Das, P. C. (2016). Productivity dynamics in India's service sector: an industry-level perspective. *Working Paper 261*. CDE, Delhi School of Economics

Nayyar, Gaurav (2012). *The Service Sector in India's Development*, Cambridge University Press, New York.

OECD. Publishing. (2001). *Measuring productivity-OECD Manual: Measurement of Aggregate and Industry-Level Productivity Growth*. Organisation for Economic Co-operation and Development.

Papola, T. S., and Sharma, A. N. (2015). Labour and Employment in Fast Growing India: Issues of employment and inclusiveness. *Indian Economy Since Independence*. New Delhi: Academic Foundation, 725-806.

Quarterly report on employment scenario extracted from [https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/Fourth\\_QES.pdf](https://labourbureau.gov.in/uploads/pdf/Fourth_QES.pdf)

SNA (2023). Guidance on enhancing and broadening the SNA framework for household well-being and sustainability prepared by Advisory Expert Group on NationalAccounts. [https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2023/M23/M23\\_02\\_01\\_WS1\\_GN\\_Framework\\_HH\\_Wellbeing\\_Sustainability.pdf](https://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/aeg/2023/M23/M23_02_01_WS1_GN_Framework_HH_Wellbeing_Sustainability.pdf)

## हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजकोषीय कार्य-निष्पादन

पी. एस. रावत, एट्टेम अभिग्न यादव,  
अत्रि मुखर्जी<sup>1</sup>

यह अध्ययन हाल की अवधि में 11 हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) की राजकोषीय स्थिति का गहन विश्लेषण करता है। उनके राजकोषीय घाटे में तेजी से वृद्धि हुई है और ऋण वहनीयता संकेतकों की स्थिति बिगड़ रही है। चूंकि इन राज्यों की स्वयं के राजस्व संसाधन जुटाने की क्षमता सीमित है, इसलिए 2015 में उनकी विशेष श्रेणी की स्थिति समाप्त होने के बाद भी उन्हें केंद्र से बड़े हस्तांतरण प्राप्त होते हैं। हालांकि, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के व्यय की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में कुछ सुधार देखा गया है, भले ही उनके ऋण का स्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक बना हुआ है।

### भूमिका

भारत विविध स्थलाकृति का देश है, जिसमें ऊंचे पहाड़, व्यापक पठार, व्यापक मैदान और लंबी तटरेखा है। स्थलाकृतिक विविधता के परिणामस्वरूप राज्यों में अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास हुआ है। ग्यारह हिमालयी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश<sup>1</sup> - अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर<sup>2</sup>, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड - अपने पहाड़ी इलाकों के कारण, भौगोलिक अलगाव, अल्प संसाधन आधार और खराब बुनियादी ढांचे<sup>3</sup> जैसी विभिन्न नुकसानों से पीड़ित हैं।

<sup>1</sup> लेखक आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को दर्शाते हों।

<sup>2</sup> नीति आयोग ने 'हिमालयी राज्य क्षेत्रीय परिषद' का गठन करते समय 'हिमालयी राज्य' शब्द गढ़ा है, जिसमें सभी पूर्ववर्ती विशेष श्रेणी के राज्यों को शामिल किया गया है, जो 15 नवंबर 2018 को वेब लिंक <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1552917> पर अपनी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से है। नीति आयोग की तर्ज पर इस अध्ययन में 'हिमालयी राज्य' शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

<sup>3</sup> जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत, 'जम्मू और कश्मीर' को 31 अक्टूबर 2019 से कानून के साथ केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था।

इन बाधाओं के परिणामस्वरूप इन राज्यों में रहने वाले लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है (भट्टाचार्य, 2014)। जबकि हिमालयी राज्यों के सामने आने वाली चुनौतियाँ कई हैं, इन राज्यों की लागत अक्षमता और सीमित संसाधन विन्यास के कारण उपलब्ध समाधान कम हैं (बाल्दी, 2014)।

केंद्र सरकार ने उन्हें 'विशेष श्रेणी' का दर्जा देकर और केंद्रीय निधियों तक तरजीही पहुंच के माध्यम से उनके आर्थिक पिछड़ेपन की समस्याओं को हल करने की परिकल्पना करके इस विषयता को दूर करने की कोशिश की। हालांकि, 14वें वित्त आयोग (एफसी-एक्सआईवी) ने 2015 में विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी ढंग से हटा दिया, जिसके परिणामस्वरूप सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इन राज्यों की केंद्रीय सहायता में निरंतरता नहीं रही। इसके बजाय, अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करने के लिए कर हस्तांतरण और अनुदान के माध्यम से राज्यों को संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए।

हाल की अवधि में, दुनिया भर में सरकारी वित्त महामारी, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, लगातार उच्च मुद्रास्फीति, समकालिक मौद्रिक नीति कठोरता और वैश्विक विकास मंदी के रूप में कई वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के कारण गंभीर दबाव में आ गया। अप्रैल 2024 में प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की राजकोषीय निगरानी रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक सार्वजनिक ऋण 2019 में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 84.2 प्रतिशत से बढ़कर 2020 में लगभग 100 प्रतिशत हो गया और 2024 में इसके 93.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। भारत में, सामान्य सरकारी ऋण स्तर 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद का 89.3 प्रतिशत हो गया और तब से 2023-24 में घटकर 81.6 प्रतिशत हो गया। भारत में राज्य सरकारों की समेकित देयताएँ मार्च 2021 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद के 15 वर्ष के उच्च स्तर

<sup>3</sup> जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने के बाद लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019 को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। इस अध्ययन में शामिल 2010-11 से 2023-24 की अवधि के लिए लद्दाख के लिए अलग से राजकोषीय डेटा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार, लद्दाख को एक अलग संघ राज्य क्षेत्र के रूप में इस अध्ययन में शामिल नहीं किया गया है।

31.0 प्रतिशत पर पहुंच गई। हालांकि मार्च 2024 के अंत में राज्यों का ऋण स्तर घटकर सकल घरेलू उत्पाद का 27.6 प्रतिशत हो गया, लेकिन कुछ राज्यों का ऋण-से-जीएसडीपी<sup>4</sup> अनुपात 40 प्रतिशत से अधिक है।

इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख इस बात की जांच करता है कि कैसे हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों ने हाल की अवधि में अपने राजकोषीय प्रदर्शन के गहन विश्लेषण के माध्यम से अपने सीमित संसाधन आधार के साथ महामारी और भू-राजनीतिक दबावों से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला किया। आलेख 5 खंडों में विभाजित है। खंड II भारत में केंद्र-राज्य राजकोषीय हस्तांतरण तंत्र का वर्णन करता है। खंड III हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति से संबंधित शैलीबद्ध तथ्यों को प्रस्तुत करता है। हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राजकोषीय स्थिति सूचकांक खंड IV में है, जबकि निष्कर्ष खंड V में है।

## II. केंद्र से राज्यों को राजकोषीय हस्तांतरण

राजकोषीय हस्तांतरण का उद्देश्य ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज असंतुलन को ठीक करना है। केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को हस्तांतरण का उद्देश्य ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन को ठीक करना है। दूसरी ओर, राज्य सरकारों के बीच आवंटन का उद्देश्य क्षैतिज असंतुलन को ठीक करना है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत, प्रत्येक राज्य संघ सूची में सभी केंद्रीय करों के हिस्से का हकदार है। केंद्रीय करों का यह विभाज्य पूल संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर पांच वर्ष में एक बार गठित वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। 15वें वित्त आयोग (एफ़सी-एक्सवी) की सिफारिश के अनुसार, वर्तमान में, केंद्रीय करों का 41 प्रतिशत राज्यों को हस्तांतरित किया जाता है। इस केंद्रीय हस्तांतरण में अलग-अलग राज्यों के हिस्से को एक सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाता है जो जनसंख्या, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, आय असमानता, भूमि क्षेत्र, कर प्रयास और वन आवरण जैसे विभिन्न कारकों को उचित महत्व देता है।

<sup>4</sup> जीएसडीपी सकल राज्य घरेलू उत्पाद को संदर्भित करता है।

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के अलावा, राज्यों को केंद्र से अनुदान के रूप में भी धन प्राप्त होता है, जिसे योजना और गैर-योजना दोनों उद्देश्यों के लिए वितरित किया जाता है। योजना अनुदानों में राज्यों की अपनी योजना स्कीमों, केन्द्रीय योजना स्कीमों और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के लिए अलग-अलग अनुदान होते हैं। गैर-योजना अनुदान अनुच्छेद 275 के तहत वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं और इसमें राज्यों के गैर-योजना राजस्व घाटे को वित्त पोषित करने के लिए सांविधिक अनुदान, प्रशासन के आधुनिकीकरण के साथ-साथ प्राकृतिक आपदाओं और अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों से राहत शामिल है। इसके अलावा, राज्य केंद्र से भी धन उधार ले सकते हैं (भट्टाचार्य, 2014)।

5वें वित्त आयोग (एफ़सी-वी) ने 1969 में कुछ वंचित राज्यों को तरजीही वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये 'विशेष दर्जा श्रेणी' की अवधारणा पेश की, जो उनकी अंतर्निहित विशेषताओं कम संसाधन आधार और विकास के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं जुटा पाने के कारण है।

विशेष श्रेणी का दर्जा देने के मानदंड थे: (i) पहाड़ी और दुर्गम इलाके; (ii) कम जनसंख्या घनत्व या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा; (iii) पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं के साथ कार्यनीतिक स्थान; (iv) आर्थिक और ढांचागत पिछड़ापन; और (v) राज्य वित्त की अव्यवहार्य प्रकृति। इन मानदंडों के आधार पर, सभी हिमालयी राज्यों को 1969-2001 की अवधि के दौरान समय के साथ विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था (सारणी 1)। इन विशेष श्रेणी राज्यों (एससीएस) ने अन्य राज्यों की तुलना में कुछ अतिरिक्त वित्तीय लाभों का आनंद लिया<sup>5</sup>।

हिमालयी राज्यों को दिया गया विशेष श्रेणी का दर्जा, हालांकि, कोई संवैधानिक समर्थन नहीं था (भारत सरकार, 2010)। एफ़सी-एक्सआईवी ने 2015 में विशेष श्रेणी के दर्जे की अवधारणा को प्रभावी ढंग से हटा दिया, इस आधार पर कि

<sup>5</sup> अतिरिक्त लाभों में केंद्रीय धन प्राप्त करने में प्राथमिकता शामिल है; राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के लिए उत्पाद शुल्क में रियायत; ऋण-स्वैपिंग और ऋण राहत योजनाओं का लाभ; निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट कर, आयकर और अन्य करों से छूट; और एक वित्तीय वर्ष में किसी भी खर्च न की गई धनराशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने की सुविधा।

## सारणी 1: भारत के हिमालयी राज्य

क्रम सं.	राज्य का नाम	एससीएस प्रदान करने का वर्ष	पूर्व स्थिति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
1	असम	1969	असम
2	जम्मू और कश्मीर	1969	जम्मू और कश्मीर
3	नागालैंड	1969	असम का हिस्सा
4	हिमाचल प्रदेश	1971	केंद्र शासित प्रदेश
5	मेघालय	1972	असम का हिस्सा
6	मणिपुर	1972	केंद्र शासित प्रदेश
7	त्रिपुरा	1972	केंद्र शासित प्रदेश
8	सिक्किम*	1975	रियासत
9	मिजोरम	1987	केंद्र शासित प्रदेश
10	अरुणाचल प्रदेश	1987	केंद्र शासित प्रदेश
11	उत्तराखंड	2001	उत्तर प्रदेश का हिस्सा

\* 1975 से पहले, सिक्किम एक रियासत थी। 16 मई, 1975 को, सिक्किम भारत का 22 वां राज्य बन गया और बाद में इसे विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया।

स्रोत : संबंधित राज्य सरकारों की वेबसाइटों

अंतरराज्यीय असमानताओं को दूर करने के लिए कर हस्तांतरण और अनुदान के माध्यम से राज्यों को पर्याप्त संसाधन आवंटित किए जाएंगे। समिति ने 2015 से 2020 की अवधि के लिए केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की। यह भी निर्णय लिया गया कि कुछ राज्यों के लिए राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाएगा जिनके लिए अकेले हस्तांतरण अपर्याप्त होगा।

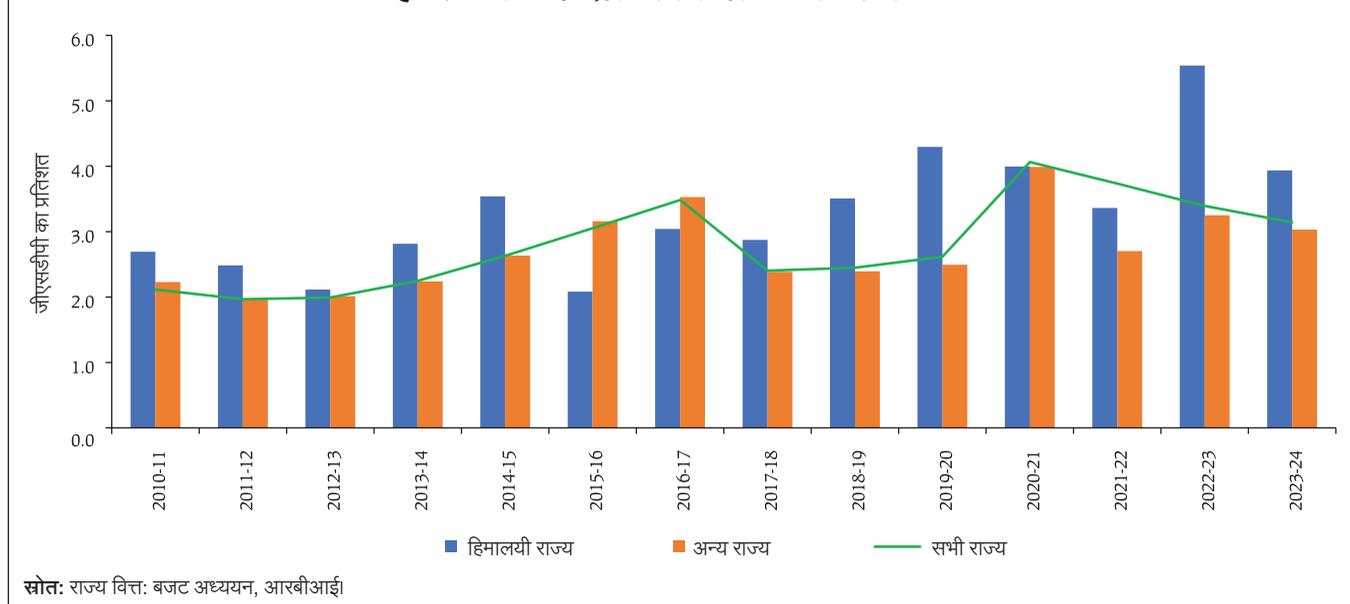
## III. शैलीबद्ध तथ्य

## III.1 प्रमुख घाटे के संकेतक

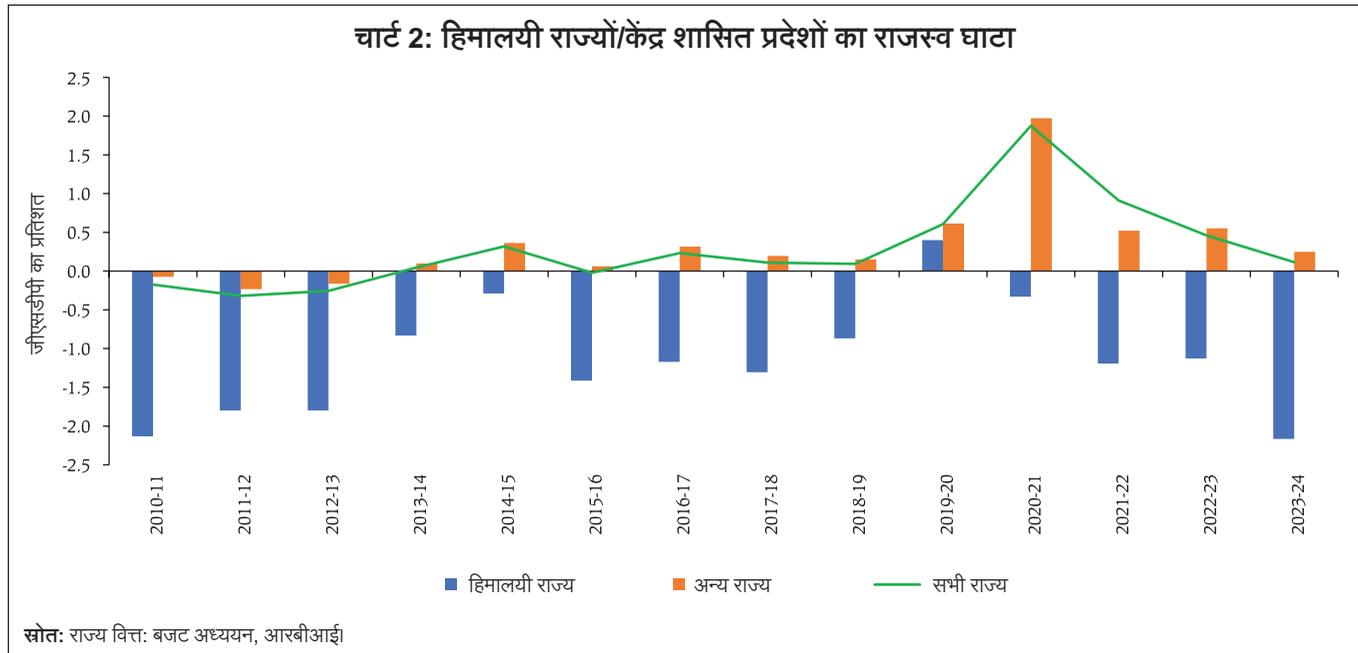
हिमालयी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) 2010-11 से 2017-18 की अवधि के दौरान (2014-15 को छोड़कर) जीएसडीपी के 3 प्रतिशत की एफआरबीएम सीमा के भीतर रहा। हालांकि, उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई और जीएफडी 2018-19 के बाद से प्रत्येक वर्ष में 3 प्रतिशत के स्तर को पार कर गया। अधिकांश वर्षों में, हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का जीएफडी 2015-16 और 2016-17 को छोड़कर अन्य राज्यों के समेकित जीएफडी से ऊपर रहा है। जबकि एफआरबीएम अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद घाटे के प्रबंधन में अधिकांश भारतीय राज्यों के प्रदर्शन में सुधार हुआ, हिमालयी राज्यों के लिये सुधार कम स्पष्ट था (सैकिया, 2022)। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य राज्यों के जीएफडी के बीच अंतर पिछले पांच वर्षों में काफी बढ़ गया है (चार्ट 1)<sup>6</sup>।

दिलचस्प बात यह है कि हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने 2019-20 को छोड़कर अध्ययन के तहत पूरी अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष बनाए रखा। कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में उच्च राजस्व अधिशेष उनकी राजस्व प्राप्तियों में केंद्रीय हस्तांतरणों के बड़े हिस्से को दर्शाता है। इसके विपरीत, अन्य राज्यों ने अधिकांश वर्षों में राजस्व घाटा दर्ज किया (चार्ट 2)।

चार्ट 1: हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का सकल राजकोषीय घाटा



<sup>6</sup> अध्ययन की अवधि के डेटा में 2021-22 के लिए वास्तविक, 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान और 2023-24 के लिए बजट अनुमान शामिल हैं।

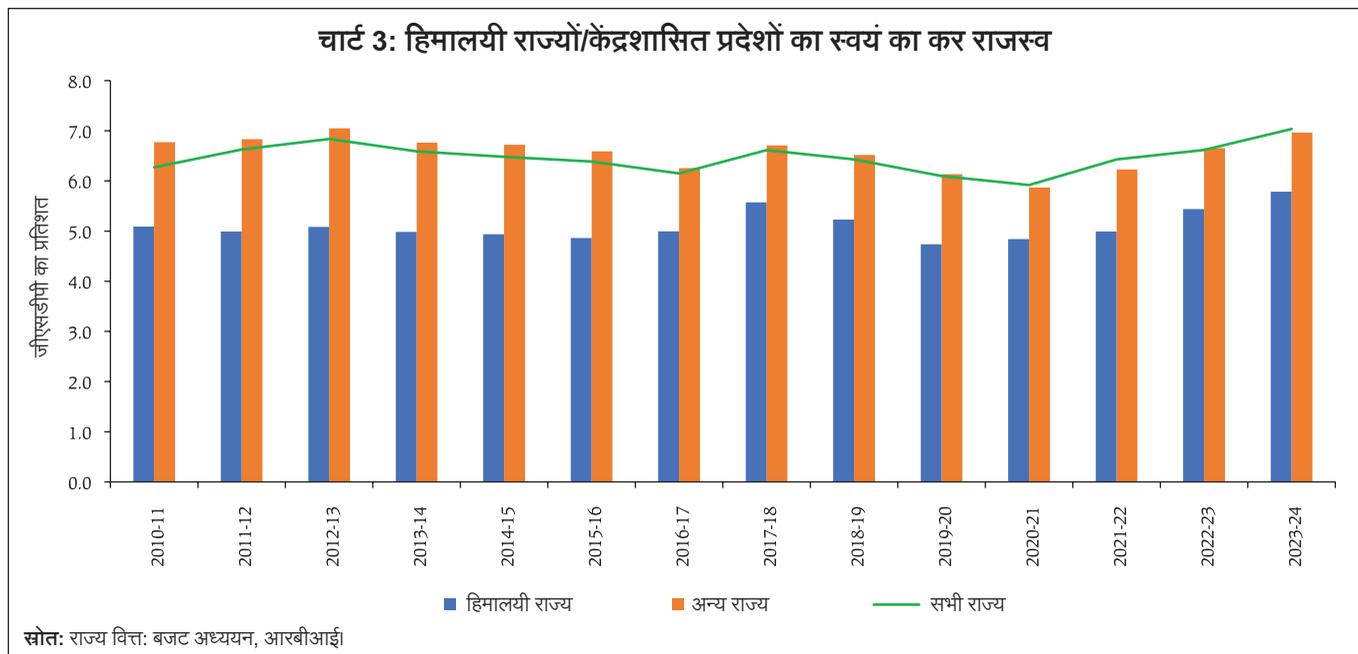


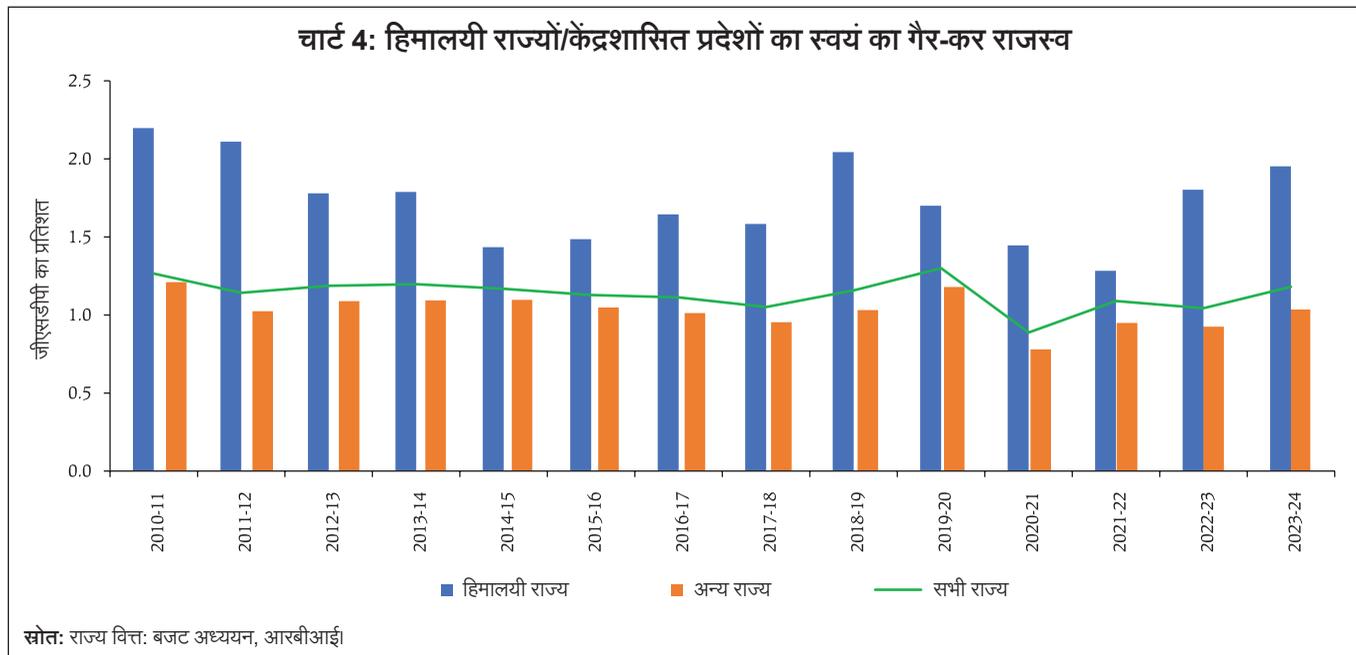
### III.2 राजस्व जुटाना

#### III.2.1 स्वयं का कर राजस्व

भारतीय राज्यों के स्वयं कर राजस्व में आम तौर पर स्टैम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क; भूमि राजस्व; पेशेवर कर; संपत्ति कर; बिक्री कर; उत्पाद शुल्क; और राज्य माल और सेवा कर (एसजीएसटी) से संग्रह शामिल होता है। कम आर्थिक गतिविधि के कारण हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की

अपने कर राजस्व जुटाने की क्षमता सीमित है। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की औसत वार्षिक प्रति व्यक्ति आय 2021-22 में 1,76,551 रुपये अनुमानित है, जो अखिल भारतीय औसत 1,98,147 रुपये से कम है। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का स्वयं कर राजस्व आम तौर पर अध्ययन के तहत अधिकांश अवधि (2010-11 से 2023-24) के दौरान जीएसडीपी का लगभग 5 प्रतिशत रहा, जबकि अन्य राज्यों के लिए 6-7 प्रतिशत (चार्ट 3)। उत्तर-पूर्वी राज्य जीएसटी





व्यवस्था के सबसे बड़े लाभार्थी रहे हैं, जिन्होंने सभी राज्यों के लिए 14.8 प्रतिशत की तुलना में इसके कार्यान्वयन के बाद से 27.5 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक जीएसटी राजस्व वृद्धि दर दर्ज की है (आरबीआई 2023)।

### III.2.2 स्वयं का गैर-कर राजस्व

अधिकांश भारतीय राज्यों के लिए, गैर-कर राजस्व के मुख्य स्रोतों में ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और लाभ और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर शुल्क शामिल हैं। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का गैर-कर राजस्व अध्ययन अवधि के दौरान जीएसडीपी के 1.3-2.2 प्रतिशत की सीमा में मामूली रहा (चार्ट 4)।

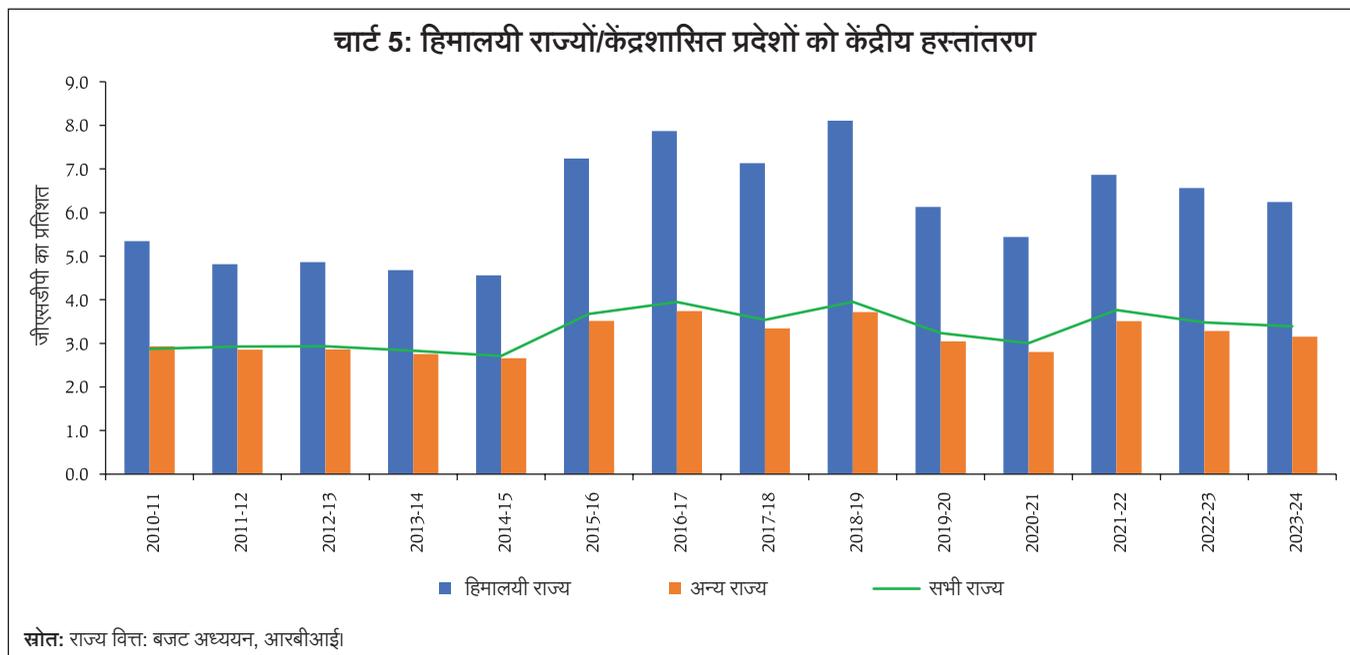
### III.2.3 केंद्र से संसाधन हस्तांतरण

राज्यों को केंद्र के वर्तमान हस्तांतरण में कर हस्तांतरण और अनुदान शामिल हैं, जो इस तरह के व्यय के वित्तपोषण के लिए राज्यों की व्यय प्रतिबद्धताओं और अपने स्वयं के संसाधनों के बीच संसाधन अंतर को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अध्ययन के तहत अवधि के दौरान, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अन्य राज्यों की तुलना में केंद्र से अधिक हस्तांतरण प्राप्त हुआ (चार्ट 5)। 14वें वित्त वर्ष द्वारा 2015 में विशेष श्रेणी का दर्जा हटाए जाने के बाद भी इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उच्च हस्तांतरण प्राप्त होते रहे।

राजस्व के लिए केंद्र पर हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की यह भारी निर्भरता उन्हें और असहाय बनाती है। पहला, केंद्र सरकार के राजस्व बंटवारे के पैटर्न में अचानक गिरावट उनके व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। दूसरा, केंद्र द्वारा हस्तांतरित निधि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा विशिष्ट उद्देश्यों से जुड़ा होता है, जिससे व्यय में राज्यों का लचीलापन सीमित हो जाता है। ये कारक राज्य की क्षमता को कमजोर कर सकते हैं, और सामाजिक, आर्थिक और सामान्य सेवाओं के वितरण को प्रभावित कर सकते हैं (प्रधान 2023)। तदनुसार, हिमालयी राज्यों को राजस्व के नए स्रोतों की पहचान करके और/या अपने कर प्रशासन को मजबूत करने के साथ-साथ मौजूदा स्रोतों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाकर केंद्र से हस्तांतरण के बजाय स्वयं कर राजस्व पर अधिक निर्भर होने से लाभ होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं/उपयोगिताओं के लिए ली जाने वाली मौजूदा दरों को संशोधित करके राज्य अपने गैर-कर राजस्व को भी बढ़ा सकते हैं (प्रधान 2023)।

### III.3 व्यय की गुणवत्ता

हिमालयी राज्यों, विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी राज्यों में, सार्वजनिक व्यय आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि निजी निवेश नगण्य है (सरमा और नायक 2006; नायक और रथ, 2016)। तदनुसार, हिमालयी राज्यों के जीएसडीपी

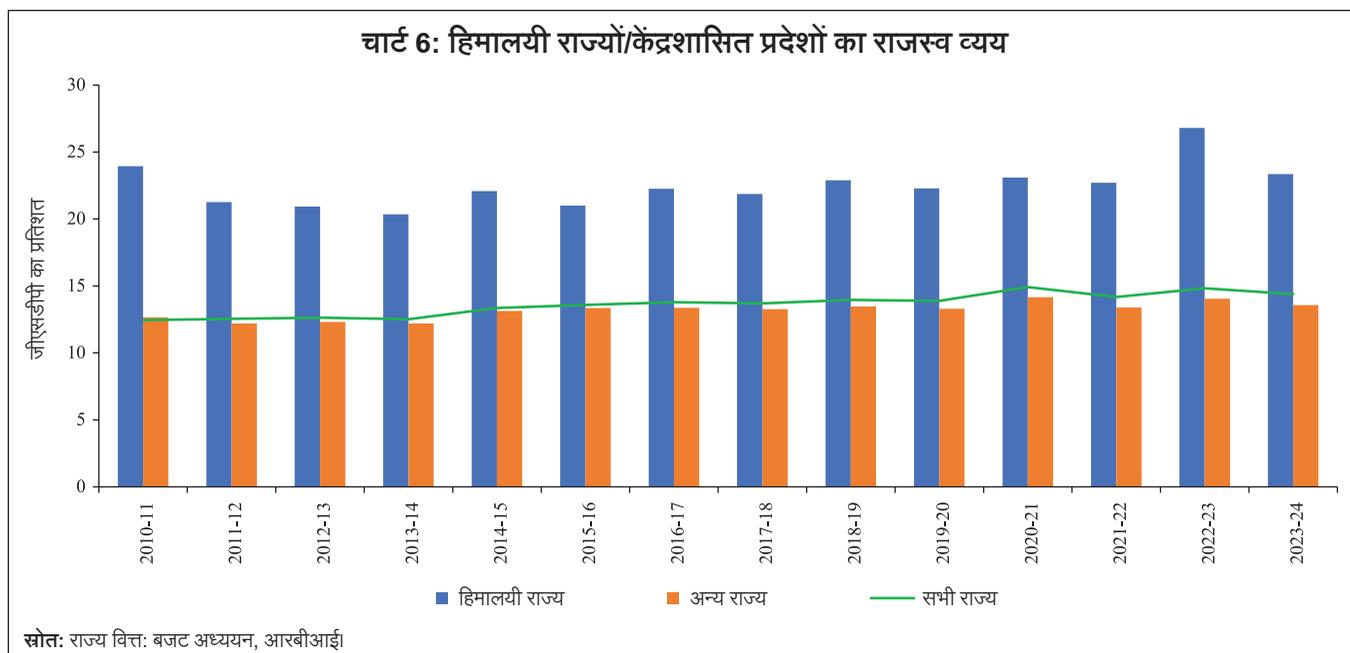


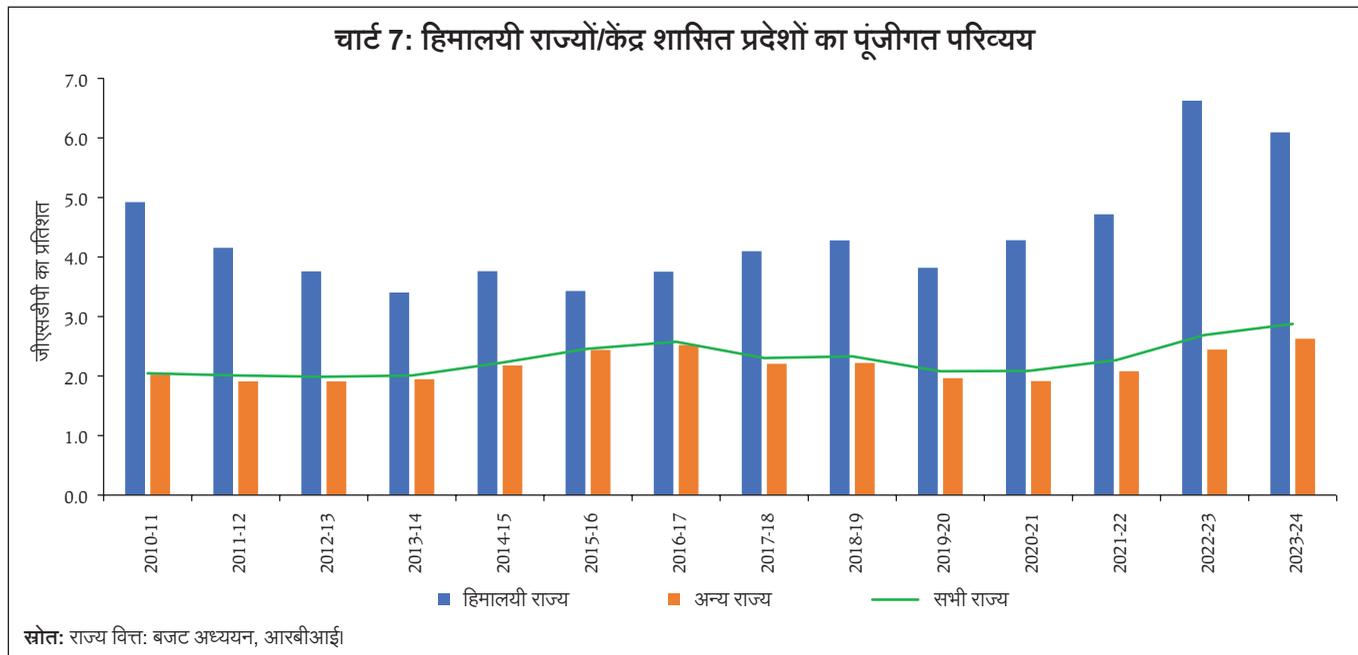
में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है।

### III.3.1 राजस्व व्यय

हिमालयी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का जीएसडीपी (आरई-जीएसडीपी) और राजस्व व्यय का अनुपात हाल की अवधि में अंतर बढ़ने के साथ अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक है (चार्ट 6)। हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की

आरई-जीएसडीपी, जो अध्ययन अवधि के दौरान 20-24 प्रतिशत के दायरे में बढ़ी है, 2022-23 के संशोधित अनुमानों में 26 प्रतिशत को पार कर गई थी। दूसरी ओर, अन्य राज्यों का आरई-जीएसडीपी 12-14 प्रतिशत के दायरे में बना हुआ है। राजस्व व्यय के अधिकांश उप-घटक, अर्थात् ब्याज भुगतान, पेंशन और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक व्यय अन्य राज्यों की तुलना में अधिक थे।





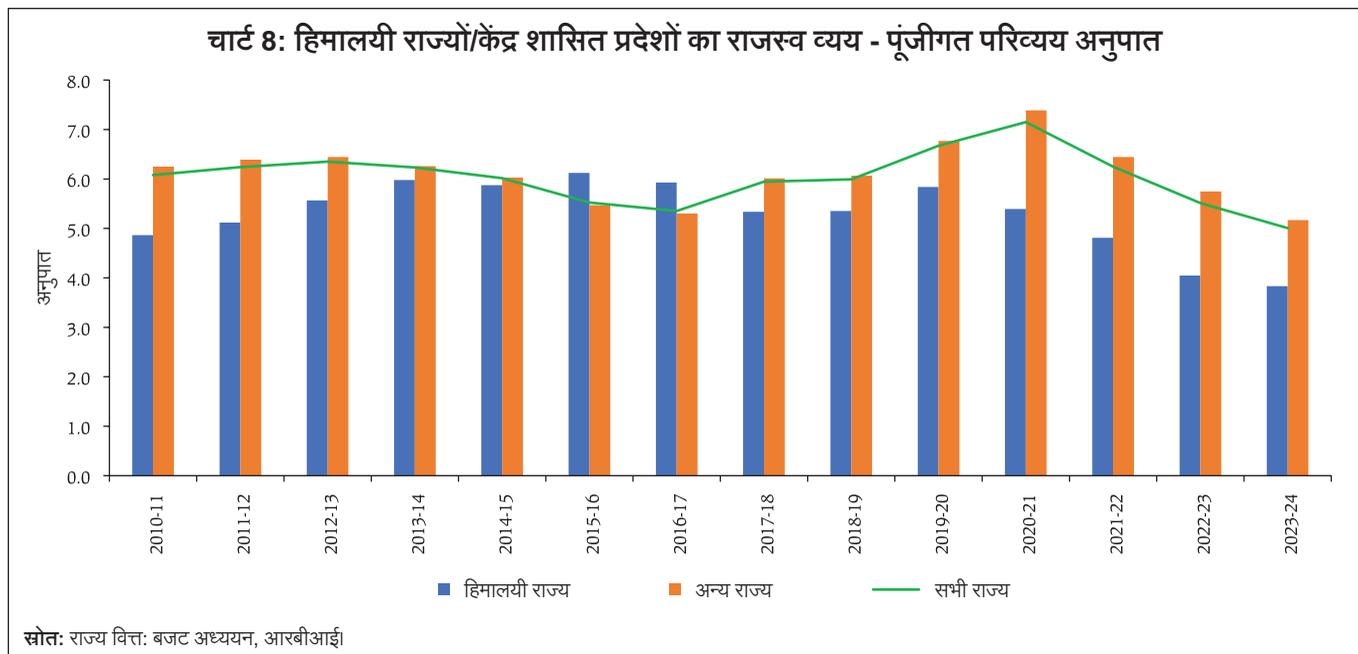
### III.3.2 पूंजी परिव्यय

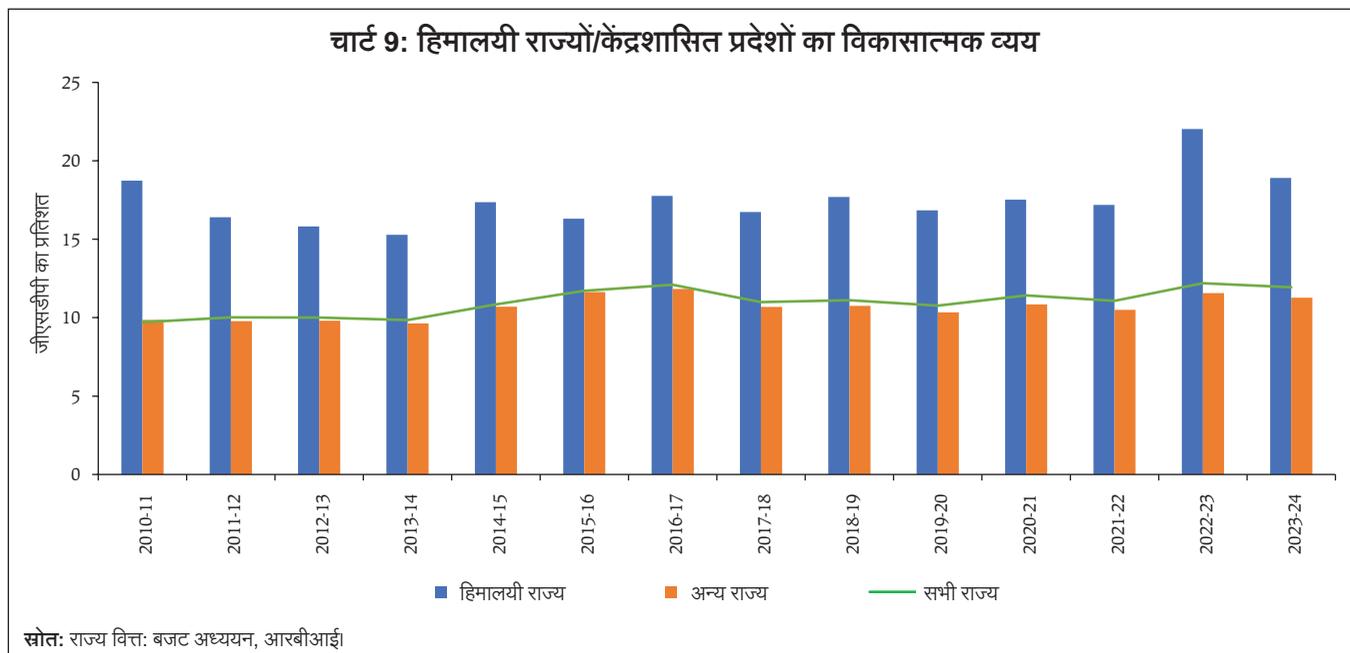
राजस्व व्यय के मामले की तरह, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का पूंजीगत परिव्यय भी अध्ययन अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक रहा है। कोविड के बाद की अवधि में हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पूंजीगत परिव्यय में तेजी से वृद्धि हुई, जिसे आंशिक रूप से 2020-21 और 2021-22 के लिए 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों के लिए

पूंजीगत व्यय परियोजनाओं पर जोर दिए जाने की वजह से है (चार्ट 7)।

### III.3.3 राजस्व व्यय और पूंजी परिव्यय अनुपात

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात - व्यय गुणवत्ता का एक संकेतक - अधिकांश अध्ययन अवधि के दौरान अन्य राज्यों की तुलना में मामूली रूप से कम था (चार्ट 8)। हिमालयी राज्यों/





केंद्रशासित प्रदेशों के लिए आरईसीओ अनुपात में 2020-21 के बाद से भारी गिरावट देखी गई, जो महामारी के बाद की अवधि में उनके व्यय की गुणवत्ता में और सुधार का संकेत देता है।

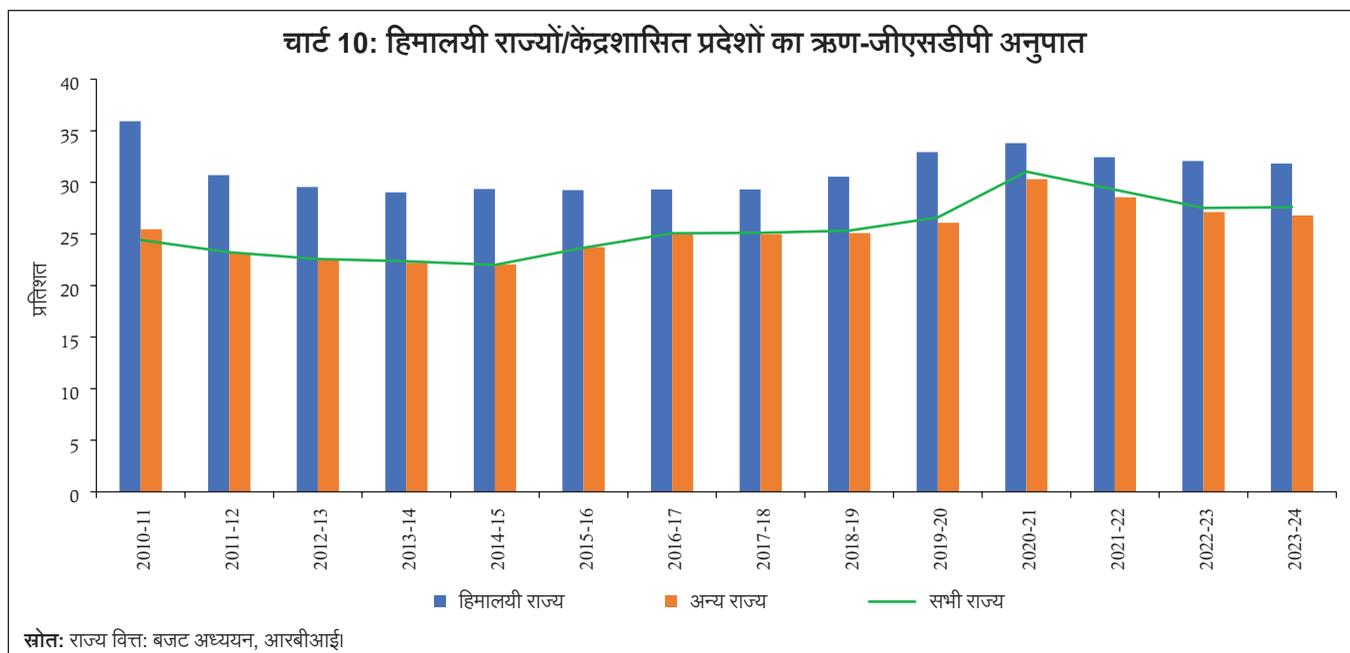
राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विकासात्मक व्यय अध्ययन के तहत अवधि के दौरान जीएसडीपी के 15-22 प्रतिशत की सीमा में ही रहा, जबकि अन्य राज्यों के लिए 9-12 प्रतिशत रहा (चार्ट 9)।

**III.3.4 विकासात्मक व्यय**

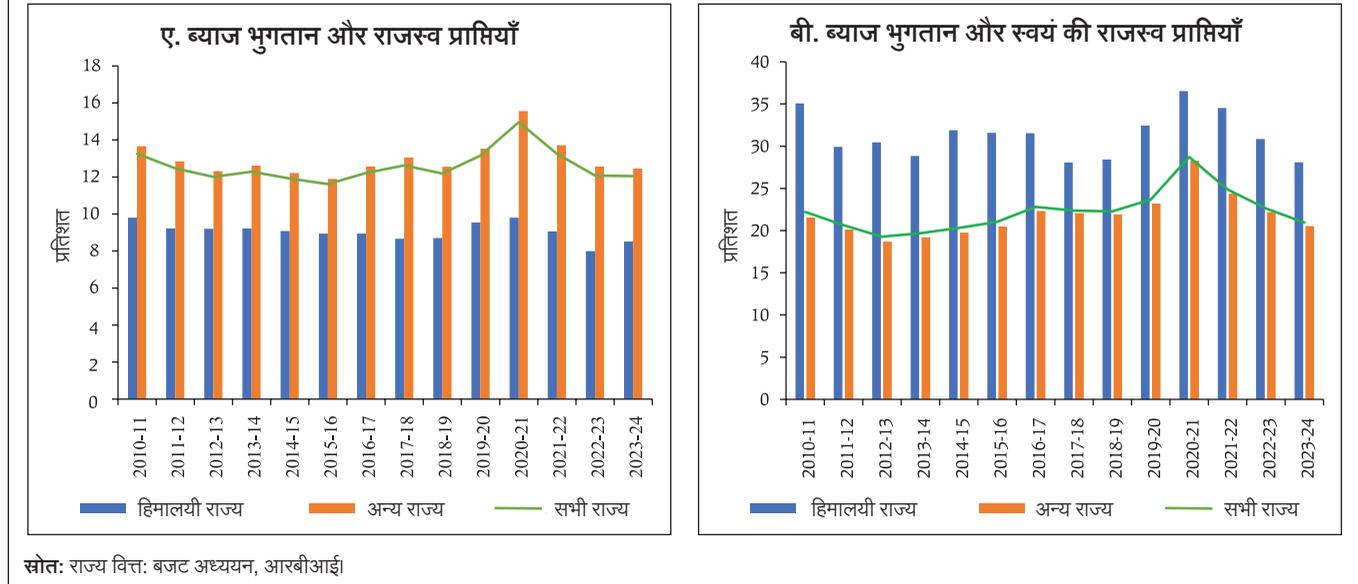
हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का विकासात्मक व्यय अन्य राज्यों की तुलना में उनकी अधिक सामाजिक-आर्थिक विकास आवश्यकताओं के अनुरूप काफी अधिक है। हिमालयी

**III.4 ऋण की स्थिति**

इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात, जो 2012-13 से 2017-18 की अवधि के दौरान लगभग 29 प्रतिशत था, 2018-19 के बाद से 30 प्रतिशत को



चार्ट 11: हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों का ऋण सेवा अनुपात



पार कर गया है (चार्ट 10), जो उच्च राजकोषीय घाटे और कम वृद्धि दर के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है। नायक और रथ (2016) ने पाया कि लंबे समय में, असम को छोड़कर किसी भी हिमालयी राज्य में स्थायी ऋण-जीएसडीपी अनुपात नहीं है। ढोलकिया एवं अन्य (2004) ने इन राज्यों के लिए सहनीय ऋण-जीएसडीपी अनुपात प्राप्त करने के लिए प्राथमिक व्यय को कम करने के साथ-साथ उच्च वृद्धि दर की सिफारिश की।

हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ऋण सेवा अनुपात (राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान) अध्ययन के तहत अवधि के दौरान 8.0-9.8 प्रतिशत की सीमा में काफी स्थिर रहा। दूसरी ओर, अन्य राज्यों का ऋण सेवा अनुपात इसी अवधि के दौरान 12-16 प्रतिशत की उच्च सीमा में चला गया (चार्ट 11 ए)। हालांकि, हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी राजस्व प्राप्तियों के लिए ब्याज भुगतान का अनुपात अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक था, जो कम संसाधन आधार को दर्शाता है (चार्ट 11 बी)।

#### IV. राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक

ढोलकिया और सोलंकी (2001), भिडे और पांडा (2002) और ढोलकिया (2005) के आधार पर कई अध्ययनों ने राजस्व दक्षता, व्यय गुणवत्ता और ऋण स्थिरता जैसे मापदंडों का पता लगाने के लिए भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय प्रदर्शन

सूचकांक विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए, वेंकटरमण (2003) ने छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय घाटा और प्रति व्यक्ति आय शामिल है, जबकि दास और बेग (2014) ने कर्ज के बोझ और राजस्व जुटाने सहित चार महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। मोहंती और मिश्रा (2016) द्वारा प्रस्तावित ढांचे पर विस्तार करते हुए, वर्तमान अध्ययन हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राजकोषीय स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों को पांच प्रमुख शीर्षों के तहत व्यवस्थित करता है, अर्थात्, (ए) घाटे के संकेतक, (बी) राजस्व प्रदर्शन संकेतक, (सी) व्यय संकेतकों की गुणवत्ता, (डी) ऋण बोझ संकेतक और (ई) ऋण स्थिरता संकेतक और हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (एफएचआई) का निर्माण।

विश्लेषणात्मक सुविधा के लिए, अध्ययन अवधि 2010-11 से 2023-24 को दो उप अवधियों में विभाजित किया गया है: (i) अवधि 1 (2010-11 से 2014-15) – एफसी-एक्सआईवी से पहले की अवधि; और (ii) अवधि 2 (2015-16 से 2023-24) – एफसी-एक्सआईवी के बाद की अवधि (सारणी 2)। इस अवधि का उद्देश्य हिमालयी राज्यों की 'विशेष श्रेणी' की स्थिति को समाप्त करने के एफसी-एक्सआईवी के निर्णय के वित्तीय प्रभाव का निरीक्षण करना है।

सारणी 2: वित्त आयोग और उनकी अवधि	
वित्त आयोग	परिचालन अवधि
13वां	2010-11 से 2014-15
14वां	2015-16 से 2019-20
15वां	2020-21 से 2025-26

स्रोत: भारत सरकार।

#### IV.1 एफएचआई के घटक

एफएचआई के विभिन्न घटक और उप-घटक इस प्रकार हैं:

##### (ए) घाटे के संकेतक

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में राजस्व घाटा।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में सकल राजकोषीय घाटा।

##### (बी) राजस्व प्रदर्शन संकेतक

- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं का कर राजस्व।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में स्वयं का गैर-कर राजस्व।

##### (सी) व्यय संकेतकों की गुणवत्ता

- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में विकास राजस्व व्यय।
- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में पूंजीगत व्यय का विकास।

##### (डी) ऋण बोझ संकेतक

- राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतान।
- जीएसडीपी के अनुपात के रूप में ऋण स्टॉक।

##### (ई) ऋण स्थिरता संकेतक

- जीएसडीपी की वृद्धि दर और ऋण स्टॉक में वृद्धि दर के बीच अंतर के रूप में प्राप्त ऋण प्रसार संकेतक।
- जीएसडीपी की वृद्धि दर और उधार लेने की औसत लागत के बीच अंतर के रूप में प्राप्त दर प्रसार संकेतक। किसी विशेष वर्ष के उधार की औसत लागत प्रभावी ब्याज दर को दर्शाती है,

अर्थात्, पिछले वर्ष के ऋण स्टॉक और चालू वर्ष के ब्याज भुगतान का अनुपात।

#### IV.2 पद्धति

यह अध्ययन राजकोषीय स्थिति सूचकांक के निर्माण के लिए सापेक्ष दूरी पद्धति का उपयोग करता है। सापेक्ष दूरी पद्धति में अवलोकनों या चरों की तुलना उनके निरपेक्ष मूल्यों के बजाय डेटासेट के भीतर उनकी सापेक्ष स्थिति के संदर्भ में करना शामिल है। यह दृष्टिकोण डेटा बिंदुओं के बीच पैटर्न, समानताएं और अंतर की पहचान करने में मदद करता है। दो डेटा बिंदुओं के बीच की दूरी को पैरामीट्रिक और गैर-पैरामीट्रिक दोनों विधियों के माध्यम से मापा जा सकता है। जबकि पैरामीट्रिक विधियां डेटा के अंतर्निहित वितरण के बारे में विशिष्ट धारणाएं बनाती हैं, गैर-पैरामीट्रिक विधियां उसी के बारे में न्यूनतम धारणाएं बनाती हैं। पैरामीट्रिक विधियां अक्सर कम्प्यूटेशनल रूप से कुशल और व्याख्या करने में आसान होती हैं, लेकिन अंतर्निहित मान्यताओं का उल्लंघन होने पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं। गैर-पैरामीट्रिक विधियों का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब वितरण अज्ञात होता है या किसी विशिष्ट रूप का पालन करने के लिए नहीं माना जा सकता है। गैर-पैरामीट्रिक विधियां डेटा के अंतर्निहित वितरण के लिए मजबूत हैं, लेकिन खासकर बड़े डेटासेट के लिए कम्प्यूटेशनल रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। इस प्रकार, पैरामीट्रिक और गैर-पैरामीट्रिक दोनों विधियों के अपने फायदे और नुकसान हैं, और उनके बीच का चुनाव अक्सर डेटा की प्रकृति और उस समय की विशिष्ट समस्या पर निर्भर करता है। यह अध्ययन राजकोषीय स्थिति सूचकांक<sup>7</sup> के निर्माण के लिए डेटा बिंदुओं को स्केल करने या सामान्य करने की न्यूनतम-अधिकतम (गैर-पैरामीट्रिक) विधि के साथ सापेक्ष दूरी का उपयोग करता है।

<sup>7</sup> सापेक्ष दूरी पद्धति, चाहे पैरामीट्रिक या गैर-पैरामीट्रिक को विभिन्न पूर्वाग्रहों के अधीन किया जा सकता है जो उनके परिणामों की सटीकता और वैधता को प्रभावित करते हैं। सापेक्ष दूरी में ऊपर की ओर पूर्वाग्रह, डेटा बिंदुओं के बीच की गणना की गई दूरी को लगातार कम करके आंकने या बढ़ाने की एक व्यवस्थित प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। यह पूर्वाग्रह इस धारणा को मिटा सकता है कि अंक एक-दूसरे से कितने भिन्न या दूर हैं, संभावित रूप से गलत विश्लेषण या निष्कर्ष की ओर ले जाते हैं। सापेक्ष दूरी में ऊपर की ओर पूर्वाग्रह को संबोधित करने के लिए बूटस्ट्रैपिंग तकनीक में बूटस्ट्रैप रीसैप्लिंग, कंप्यूटिंग सापेक्ष दूरी, पूर्वाग्रह सुधार, आत्मविश्वास अंतराल, सत्यापन और संवेदनशीलता विश्लेषण शामिल हैं। बूटस्ट्रैपिंग का दायरा, हालांकि, इस अध्ययन में संभव नहीं है क्योंकि रीसैप्लिंग में सीमा है।

पहले चरण में, ऊपर वर्णित प्रत्येक संकेतक का स्तर 0 से 100 तक के सूचकांक मान के लिए सामान्यीकृत होता है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (पीक्यूएलआई) (मॉरिस, 1982) और मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति के समान है। यह विधि एक सूचकांक बनाने के लिए अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मापदंडों को ले सकती है। अनुकूल संकेतकों के लिए बनाए गए सूचकांक को सुधार सूचकांक कहा जाता है। प्रतिकूल मापदंडों को लेकर बनने वाले सूचकांक को अभाव सूचकांक कहा जाता है। दोनों सूचकांकों का मान 0 और 100 के बीच होगा।

$$\text{अभाव सूचकांक (डी)} = \frac{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{एक्स}] * 100}{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{न्यूनतम (एक्स)}}$$

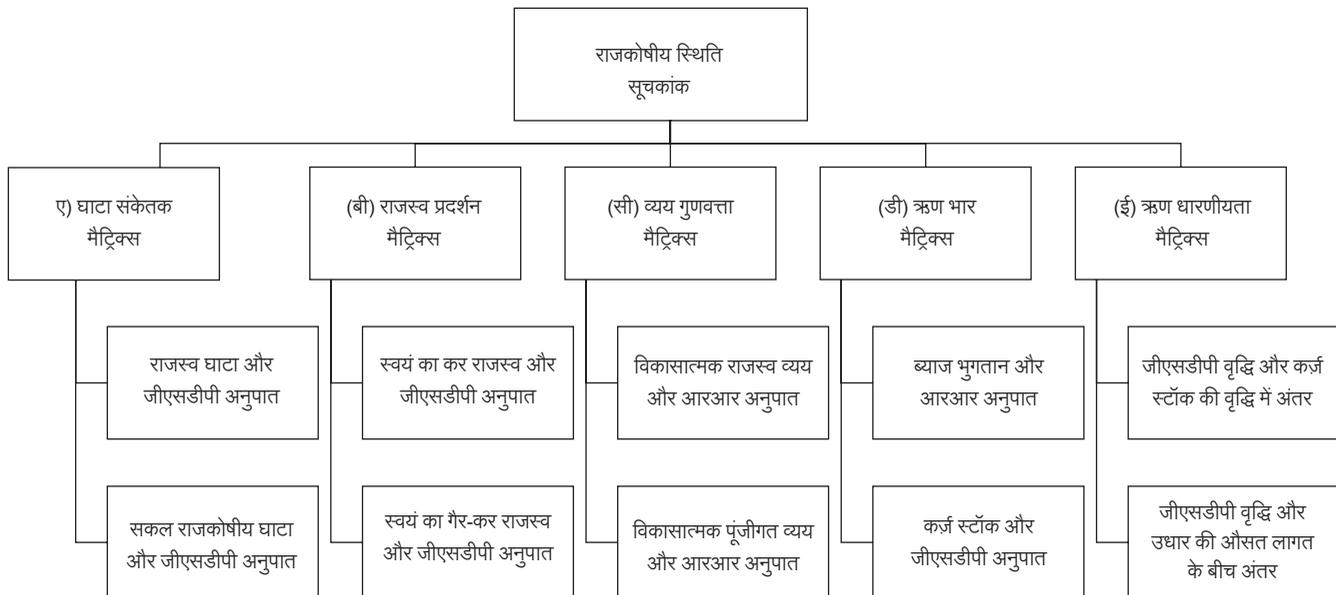
$$\text{सुधार सूचकांक} = \frac{[\text{एक्स} - \text{न्यूनतम (एक्स)}] * 100}{[\text{अधिकतम (एक्स)} - \text{न्यूनतम (एक्स)}}$$

जहां, एक्स किसी दिए गए राज्य के लिए पैरामीटर के वास्तविक मान को संदर्भित करता है। अधिकतम (एक्स) और न्यूनतम (एक्स) एक निर्दिष्ट अवधि में राज्यों में पैरामीटर का

अधिकतम और न्यूनतम मान हैं। डी और आई का मान 0 से 100 के पैमाने पर होगा जहां 0 सबसे खराब प्रदर्शन को दर्शाता है और 100 का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन।

इस अध्ययन में, सामान्यीकरण के लिए, अभाव सूचकांक के फार्मूले को घाटे के संकेतकों और ऋण बोझ संकेतकों पर लागू किया जाता है क्योंकि वे राज्य के राजकोषीय स्थिति से नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं। दूसरी ओर, सुधार सूचकांक के लिए सूत्र राजस्व प्रदर्शन संकेतकों, व्यय संकेतकों की गुणवत्ता और ऋण स्थिरता संकेतकों पर लागू किया जाता है क्योंकि वे राजकोषीय प्रदर्शन से सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं। अगले चरण में, पांच अलग-अलग शीर्षों में से प्रत्येक के तहत सामान्यीकृत संकेतकों के औसत की गणना पांच अलग-अलग मैट्रिक्स प्राप्त करने के लिए की जाती है: घाटा संकेतक मैट्रिक्स, राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स, व्यय गुणवत्ता मैट्रिक्स, ऋण बोझ मैट्रिक्स और ऋण वहनीयता मैट्रिक्स। इन पांच मैट्रिक्स का साधारण औसत समग्र राजकोषीय स्थिति सूचकांक (एफएचआई) प्रदान करता है (सारणी 3)।

### सारणी 3: राजकोषीय स्थिति सूचकांक की संरचना



स्रोत: लेखकों की व्याख्या।

### IV.3 परिणाम

एफएचआई से हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की राजकोषीय स्थिति में बड़े उतार-चढ़ाव का पता चलता है (सारणी 4)। अवधि -1 में, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शीर्ष चार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हिमालयी राज्यों के रूप में उभरे। इस अवधि के दौरान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का एफएचआई मान त्रिपुरा के लिए 55 से जम्मू और कश्मीर के लिए 40 तक था। दूसरी ओर, अवधि -2 में, मिजोरम, असम और त्रिपुरा हिमालयी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के बीच शीर्ष तीन स्थानों पर रहे। मेघालय, जो अवधि 1 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक था, अवधि 2 में 8 वें स्थान पर खिसक गया। अधिकांश हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एफएचआई मान में अवधि 2 में गिरावट आई, जो उनके राजकोषीय स्थिति पर दबाव को दर्शाता है (चार्ट 12)। मेघालय (14 अंक) के मामले में यह सबसे तेज गिरावट है, इसके बाद उत्तराखंड (12 अंक) और त्रिपुरा (7 अंक) का स्थान है। एकमात्र अपवाद असम है जिसने एफएचआई मान में 2 अंकों का सुधार देखा है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य राज्यों के एफएचआई में भी अवधि 1 और अवधि 2 के बीच गिरावट आई, मुख्य रूप से कम कर राजस्व, उच्च व्यय और घाटे के संकेतकों में परिणामी वृद्धि के संदर्भ में राज्य वित्त पर कोविड 19 महामारी के प्रभाव के कारण (चार्ट 12)। तथापि,

अन्य राज्यों के एफएचआई मान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक बने रहे।

अधिकांश हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, अवधि 2 में घाटे के संकेतक मैट्रिक्स में गिरावट आई है (परिशिष्ट सारणी ए); इसका श्रेय कोविड-19 महामारी को दिया जा सकता है, जिसने भारतीय राज्यों के समेकित जीएफडी को 2020-21 में जीडीपी के 4.1 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचा दिया।

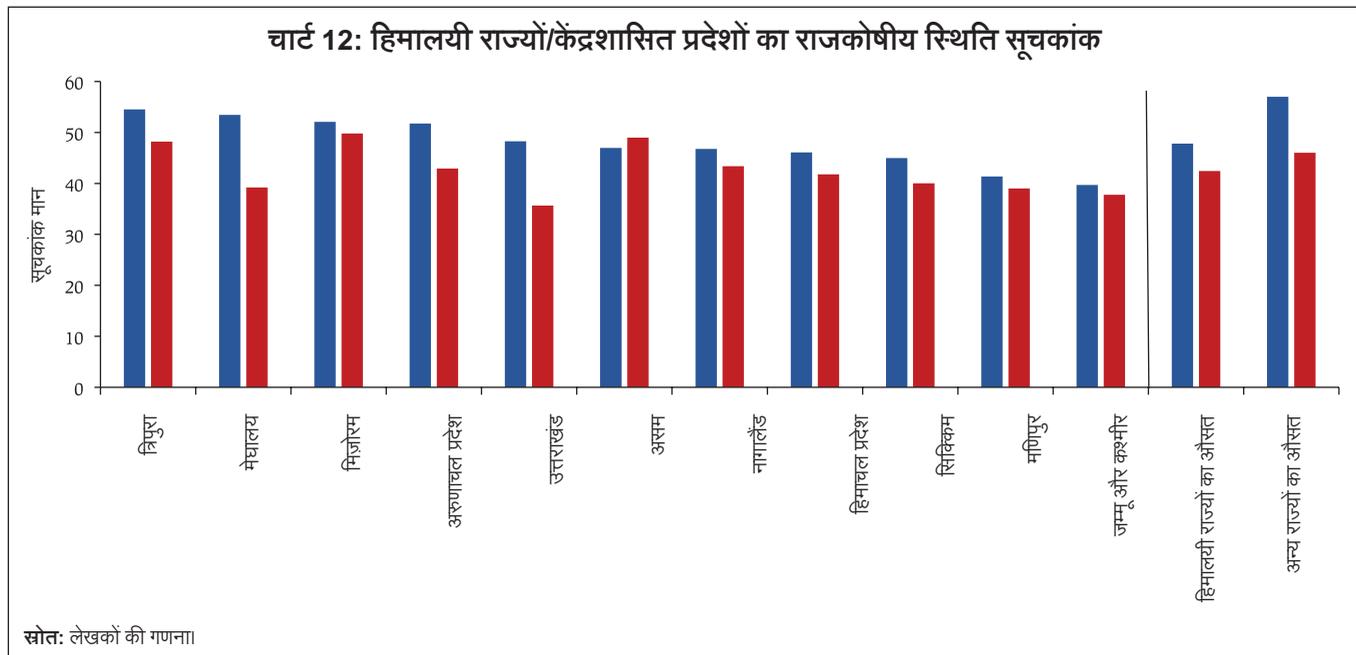
राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स के संदर्भ में हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का प्रदर्शन तुलनात्मक रूप से बेहतर था क्योंकि छह राज्यों ने अवधि 2 (परिशिष्ट सारणी बी) में अपने स्कोर में सुधार किया था। मेघालय का अवधि 2 में सबसे अच्छा राजस्व प्रदर्शन था, इसके बाद उत्तराखंड और मिजोरम थे। व्यय मैट्रिक्स की गुणवत्ता के संदर्भ में, पांच राज्यों ने व्यय की गुणवत्ता में सुधार दिखाया और छह राज्यों ने अवधि 2 में गिरावट दिखाई (परिशिष्ट सारणी सी)।

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण बोझ मैट्रिक्स एक मिश्रित तस्वीर दिखाता है, जिनमें से छह ने अवधि 1 की तुलना में अवधि 2 में उच्च स्कोर दर्ज किया (परिशिष्ट सारणी डी)। दूसरी ओर, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और सिक्किम जैसे राज्यों के लिए मैट्रिक्स मूल्य 30 से कम के साथ सभी हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण स्थिरता मैट्रिक्स अवधि 2 में कम हो गया (परिशिष्ट सारणी ई)।

**सारणी 4: हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के एफएचआई मान**

अवधि 1 (2010-11 से 2014-15)			अवधि 2 (2015-16 से 2023-24)		
श्रेणी	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	श्रेणी	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 2
1	त्रिपुरा	55	1	मिजोरम	50
2	मेघालय	53	2	असम	49
3	मिजोरम	52	3	त्रिपुरा	48
4	अरुणाचल प्रदेश	52	4	नागालैंड	43
5	उत्तराखंड	48	5	अरुणाचल प्रदेश	43
6	असम	47	6	हिमाचल प्रदेश	42
7	नागालैंड	47	7	सिक्किम	40
8	हिमाचल प्रदेश	46	8	मेघालय	39
9	सिक्किम	45	9	मणिपुर	39
10	मणिपुर	41	10	जम्मू और कश्मीर	38
11	जम्मू और कश्मीर	40	11	उत्तराखंड	36

स्रोत: लेखकों की गणना।



## V. निष्कर्ष

हिमालयी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की समग्र राजकोषीय स्थिति ने पिछले पाँच वर्षों में दबाव प्रदर्शित किया, उनके समेकित जीएफडी ने 2019-20, 2020-21 और 2022-23 में जीएसडीपी के 4 प्रतिशत का उल्लंघन किया। इस अवधि के दौरान हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य राज्यों के जीएफडी के बीच अंतर बढ़ गया है। हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की स्वयं कर राजस्व जुटाने की क्षमता उनकी आर्थिक और भौगोलिक संरचना से उत्पन्न चुनौतियों के कारण बाधित रहती है। हिमालयी राज्यों के आर्थिक विकास में सार्वजनिक व्यय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इन राज्यों में निजी निवेश सीमित है। तदनुसार, इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जीएसडीपी में सार्वजनिक व्यय का हिस्सा भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अधिक है। आरईसीओ अनुपात के संदर्भ में मापे गए हिमालयी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के व्यय की गुणवत्ता में पिछले कुछ वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है।

हिमालयी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का ऋण स्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में लगातार अधिक रहा है। अलग-अलग स्तर पर, हिमालयी राज्यों के राजकोषीय प्रदर्शन में

बड़े अंतर-राज्यीय अंतर हैं और इनमें से अधिकांश राज्यों के राजकोषीय स्थिति सूचकांक मान में हाल की अवधि में गिरावट आई है। राजकोषीय निष्पादन के विभिन्न संकेतकों में से घाटे और ऋण वहनीयता संकेतकों ने राजकोषीय स्थिति को देखते हुए राजकोषीय समेकन की बढ़ती मांग में सर्वाधिक योगदान दिया है। हिमालयी राज्यों का 2015 में उनकी विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त होने के बाद भी केंद्र से उच्च हस्तांतरण प्राप्त करना जारी है। इससे खर्च में उनका लचीलापन कम हो सकता है और इसलिए इन राज्यों को राजस्व के नए स्रोतों की पहचान करने, मौजूदा स्रोतों का अधिक प्रभावी ढंग से लाभ उठाने और उच्च संसाधन जुटाने के लिए अपने कर प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है।

## संदर्भ

Baldi, S. (2014). Policy issues in revenue generation and expenditure management in hill states with special reference to Himachal Pradesh. *Journal of Governance & Public Policy*, 4(1), 57.

Bhattacharjee, G. (2014). The Reality of Special Category Status. *Economic and Political Weekly*, 49(40), October 4, 2014.

- Bhide, S., & Panda, M. (2002). Evaluating Quality of Budgets with a Composite Index. *Economic and Political Weekly*, March 30.
- Bose, S., Noopur, A., Sri Hari Nayudu. (2022). Intergovernmental Fiscal transfers and Expenditure on Education in India: State level analysis, 2005 to 2020. No. 377, March 2022, *National Institute of Public Finance and Policy*, New Delhi.
- Das, & Baig. (2014). India's State Finances: Declining Debt but Weak Fundamentals. *Deutsche Bank Research*, January 30.
- Dholakia, A., & Solanki, T. (2001). Ranking States on Fiscal Performance. Paper presented at seminar on Economic Reforms, Gujarat University, Ahmedabad, March.
- Dholakia, A. (2005). Measuring Fiscal Performance of States: An Alternative Approach. *Economic and Political Weekly*, July 30.
- GoI (2010), Available at: <https://sansad.in/getFile/annex/221/Au2559.pdf?source=pqars>
- Mohanty, A. R., & Mishra, B. R. (2016). Fiscal Performance Index of the States in India. *NIBM*, Pune.
- Nayak, S. K., and Rath, S. S. (2016). A Study on Debt Problem of the Special Category States. Study Conducted for the 13th Finance Commission, Government of India.
- Pradhan (2013). <https://www.thehindu.com/data/data-the-risk-of-small-states-heavy-reliance-on-the-union-government/article67095283.ece>
- RBI 2023, State Finances: A Study of Budgets of 2022-23, Reserve Bank of India, January 2023.
- Saikia, B., Roy, C. S., & Shah, S. (2022). FRBM Act and fiscal performance of the special category states of India: A trend analysis. *Social Change and Development*, 1-17.
- Sarma, A., & Nayak, S. K. (2006). Growth and Equity in the Post-Reform Period: Experience of the North Eastern States. Paper presented at the Silver Jubilee Conference of the CESS, Hyderabad, January 7th-8th.
- The Gazette of India, Ministry of Home Affairs. (2019, August 09). NOTIFICATION (Department of Jammu and Kashmir Affairs). *New Delhi*.
- Venkatraman, K. (2003). Towards a Fiscal Responsibility Index: Some Preliminary Analysis. *Vishleshan*, 28(4), October-December.

## परिशिष्ट सारणियाँ

## ए. घाटा सूचकांक मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	49	59	10
2	असम	64	55	-9
3	हिमाचल प्रदेश	60	66	6
4	जम्मू और कश्मीर	49	46	-3
5	मणिपुर	52	38	-14
6	मेघालय	59	53	-6
7	मिजोरम	27	58	31
8	नागालैंड	69	48	-21
9	सिक्किम	77	48	-30
10	त्रिपुरा	81	31	-49
11	उत्तराखंड	61	38	-23

स्रोत: लेखकों की गणना।

## बी. राजस्व प्रदर्शन मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	23	31	8
2	असम	58	41	-17
3	हिमाचल प्रदेश	58	29	-29
4	जम्मू और कश्मीर	27	42	16
5	मणिपुर	36	31	-6
6	मेघालय	39	51	11
7	मिजोरम	29	46	18
8	नागालैंड	24	43	19
9	सिक्किम	58	29	-29
10	त्रिपुरा	60	26	-33
11	उत्तराखंड	19	47	28

स्रोत: लेखकों की गणना।

## सी. व्यय मैट्रिक्स की गुणवत्ता

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	54	39	-15
2	असम	24	54	30
3	हिमाचल प्रदेश	25	30	5
4	जम्मू और कश्मीर	43	42	-1
5	मणिपुर	38	51	13
6	मेघालय	58	50	-8
7	मिजोरम	66	44	-22
8	नागालैंड	50	42	-8
9	सिक्किम	20	49	29
10	त्रिपुरा	34	49	16
11	उत्तराखंड	54	34	-19

स्रोत: लेखकों की गणना।

## डी. कर्ज भार मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	60	70	10
2	असम	63	58	-4
3	हिमाचल प्रदेश	43	65	21
4	जम्मू और कश्मीर	43	57	14
5	मणिपुर	37	69	32
6	मेघालय	83	44	-40
7	मिजोरम	25	80	54
8	नागालैंड	31	62	31
9	सिक्किम	80	49	-31
10	त्रिपुरा	63	61	-2
11	उत्तराखंड	73	44	-29

स्रोत: लेखकों की गणना।

## ई. कर्ज धारणीयता मैट्रिक्स

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	अवधि 1	अवधि 2	परिवर्तन
1	अरुणाचल प्रदेश	79	47	-33
2	असम	65	41	-23
3	हिमाचल प्रदेश	62	34	-27
4	जम्मू और कश्मीर	37	24	-13
5	मणिपुर	42	24	-18
6	मेघालय	52	37	-15
7	मिजोरम	72	56	-16
8	नागालैंड	41	34	-8
9	सिक्किम	48	25	-24
10	त्रिपुरा	65	60	-5
11	उत्तराखंड	54	24	-29

स्रोत: लेखकों की गणना।



# वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक  
भारतीय रिज़र्व बैंक  
मुद्रा और बैंकिंग  
मूल्य और उत्पादन  
सरकारी खाते और खज़ाना बिल  
वित्तीय बाजार  
बाह्य क्षेत्र  
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ  
आवसरिक शृंखलाएं



## विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	133
	<b>भारतीय रिज़र्व बैंक</b>	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	134
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	135
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	136
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	137
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	137
	<b>मुद्रा और बैंकिंग</b>	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	138
7	मुद्रा स्टॉक (एम <sub>3</sub> ) के स्रोत	139
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	140
9	कुल चलनिधि राशियाँ	141
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	142
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	142
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	143
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	143
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	144
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	145
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	146
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	147
	<b>मूल्य और उत्पादन</b>	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	148
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	148
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	148
21	थोक मूल्य सूचकांक	149
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	153
	<b>सरकारी खाते और खज़ाना बिल</b>	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	153
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	154
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	154
	<b>वित्तीय बाजार</b>	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	155
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	156
28	वाणिज्यिक पत्र	156
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	156
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	157

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
<b>बाह्य क्षेत्र</b>		
31	विदेशी व्यापार	158
32	विदेशी मुद्रा भंडार	158
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	158
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	159
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	159
36	भारतीय रुपये की वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	160
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	161
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	162
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	163
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	164
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	165
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	166
<b>भुगतान और निपटान प्रणालियाँ</b>		
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	167
<b>आवसरिक शृंखलाएं</b>		
44	लघु बचत	169
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	170
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	171
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	172
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	173
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियां	174
50(ए)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	175
50(बी)	हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	178

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

-- = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

## सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2022-23		2023-24	
		ति3	ति4	ति3	ति4
	1	2	3	4	5
<b>1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)</b>					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	7.2	4.8	6.0	6.8	6.3
1.1.1 कृषि	1.4	5.2	7.6	0.4	0.6
1.1.2 उद्योग	9.3	-2.8	1.7	10.8	8.3
1.1.3 सेवाएं	7.9	7.5	7.3	7.5	7.0
1.1ए अंतिम खपत व्यय	3.8	2.4	3.5	3.1	3.4
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	9.0	5.0	3.8	9.7	6.5
	2023-24	2023		2024	
	1	अप्रै.	मई	अप्रै.	मई
		2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	4.6	5.7	5.0	5.9
<b>2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)</b>					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9 (13.5)	10.1	11.4	12.0 (12.6)	12.2 (12.7)
2.1.2 ऋण#	16.3 (20.2)	15.7	15.3	15.5 (19.2)	16.1 (19.8)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3 (20.2)	15.9	15.5	15.5 (19.2)	16.2 (19.8)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1 (12.8)	13.1	14.8	10.7 (12.3)	8.8 (10.3)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	10.2	8.1	5.8	5.8
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1	9.5	10.1	10.9 (11.4)	12.1 (12.5)
<b>3 अनुपात (%)</b>					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0 (5.0)	5.3	5.3	5.4 (5.3)	5.0 (4.9)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1 (80.3)	75.1	75.2	77.4 (79.5)	77.5 (79.6)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8 (113.4)	46.5	50.4	37.4 (34.4)	59.2 (57.2)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5 (29.8)	29.5	30.0	29.2 (29.5)	29.1 (29.3)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8 (28.4)	10.0	28.5	8.1 (6.9)	13.4 (12.6)
<b>4 ब्याज दरें (%)</b>					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
4.6 आधार दर	9.10/10.25	8.75/10.10	8.75/10.10	9.10/10.25	9.10/10.25
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	7.90/8.50	7.90/8.50	8.00/8.60	8.00/8.60
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारत औसत)	6.85	6.70	6.36	6.65	6.56
4.11 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	6.82	6.78	6.92	6.85
4.12 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	6.97	6.90	7.04	7.01
4.13 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.00	6.89	7.07	7.04
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.12	7.05	7.16	7.01
<b>5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम</b>					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	81.78	82.72	83.34	83.30
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	90.08	88.79	89.43	90.12
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम					
1-माह (%)	1.00	1.73	1.45	1.16	1.08
3-माह (%)	1.11	1.82	1.55	1.26	1.22
6-माह (%)	1.31	1.98	1.62	1.37	1.34
<b>6 मुद्रास्फीति (%)</b>					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	4.7	4.3	4.8	4.8
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	5.1	4.4	3.9	3.9
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	-0.8	-3.6	1.2	2.6
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	1.9	-1.9	5.2	7.2
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	1.0	-9.2	-0.9	1.3
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-2.3	-3.0	-0.1	0.8
<b>7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)</b>					
7.1 आयात	-5.7	-15.5	-6.0	10.7	7.4
7.2 निर्यात	-3.1	-12.8	-10.4	2.1	12.8

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग त्रुटियों के लिए समायोजित किया जाता है। कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

\*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशनी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

## भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां\*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार तक						
	2023-24	2023	2024				
			जून	मे 31	जून 07	जून 14	जून 21
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1 निर्गम विभाग</b>							
<b>1.1 देयताएं</b>							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3329493	3537514	3553714	3552720	3546362	3528937
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	12	14	12	13	13	11
<b>1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां</b>	<b>3482344</b>	<b>3329505</b>	<b>3537528</b>	<b>3553727</b>	<b>3552732</b>	<b>3546375</b>	<b>3528948</b>
<b>1.2 आस्तियां</b>							
1.2.1 स्वर्ण	162996	135772	174725	175437	172110	175092	172686
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3193298	3362365	3377902	3380284	3370995	3356024
1.2.3 रुपया सिक्का	463	435	437	388	338	288	237
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
<b>2 बैंकिंग विभाग</b>							
<b>2.1 देयताएं</b>							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1468566	1733922	1711732	1749231	1811359	1729450
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	101	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	-	-	-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	871167	951109	971898	983708	979126	973455
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	9040	8555	8467	8271	8379	8453
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	4436	5224	5480	5486	5169	5259
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	46583	49246	49086	48699	49106	49202
2.1.1.8 अन्य	545400	450334	589411	542849	559645	630212	564106
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	86862	130234	133811	143278	139224	128832
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1484223	1612560	1657071	1650398	1661240	1635592
<b>2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां</b>	<b>3587080</b>	<b>2952789</b>	<b>3346482</b>	<b>3368804</b>	<b>3399629</b>	<b>3472599</b>	<b>3365042</b>
<b>2.2 आस्तियां</b>							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	12	14	13	13	13	11
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1165073	1456002	1466287	1456893	1463672	1459215
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	0	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	9835	10723	28204	7994	4039	7286
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	50867	71305	57955	111102	196095	102741
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	0	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	3319	9311	9311	9311	9311	9061
2.2.3.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थाएं	162650	86409	129564	134194	143799	139897	129258
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1406348	1365532	1365698	1367029	1350797	1349978
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	230926	304031	307143	303488	308775	307492
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	223813	296897	299702	295583	300703	298664

\* डेटा अनंतिम हैं।

## सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन- शील रेपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
मई 1, 2024	-	-	-	-	13931	77288	-	-	-	-63357
मई 2, 2024	-	-	-	-	861	110670	854	-	-	-108955
मई 3, 2024	-	-	157698	-	6561	102972	21	-	-	61308
मई 4, 2024	-	-	-	-	246	67139	-	-	-	-66893
मई 5, 2024	-	-	-	-	255	46197	-	-	-	-45942
मई 6, 2024	-	-	-	26045	1871	48059	-740	-	-	-72973
मई 7, 2024	-	-	-	-	11078	45944	-	-	-	-34866
मई 8, 2024	-	-	25005	-	7249	53784	807	-	-	-20723
मई 9, 2024	-	-	50003	-	1471	48045	-116	-	-	3313
मई 10, 2024	-	-	-	-	11788	62465	-	-	-	-50677
मई 11, 2024	-	-	-	-	8639	38017	-	-	-	-29378
मई 12, 2024	-	-	-	-	8853	40190	-	-	-	-31337
मई 13, 2024	-	-	25004	-	878	59342	-	-	-	-33460
मई 14, 2024	-	-	50002	-	1034	100550	-818	-	-	-50332
मई 15, 2024	-	-	-	-	83	128802	968	-	-	-127751
मई 16, 2024	-	-	-	-	593	153885	-1425	-	-	-154717
मई 17, 2024	-	-	125009	-	29999	58450	1424	-	-	97982
मई 18, 2024	-	-	-	-	29396	36291	-	-	-	-6895
मई 19, 2024	-	-	-	-	27565	25853	-	-	-	1712
मई 20, 2024	-	-	-	-	51757	37271	-	-	-	14486
मई 21, 2024	-	-	125002	-	31450	41763	-	-	-	114689
मई 22, 2024	-	-	71830	-	2283	102810	-	-	-	-28697
मई 23, 2024	-	-	-	-	1947	95138	-	-	-	-93191
मई 24, 2024	-	-	125008	-	1662	74754	-	-	-	51916
मई 25, 2024	-	-	-	-	10341	63339	-	-	-	-52998
मई 26, 2024	-	-	-	-	7072	62723	-	-	-	-55651
मई 27, 2024	-	-	75007	-	6481	68714	-	-	-	12774
मई 28, 2024	-	-	-	-	1747	79677	-	-	-	-77930
मई 29, 2024	-	-	-	-	6967	73513	-	-	-	-66546
मई 30, 2024	-	-	-	-	2776	117462	0	-	-	-114686
मई 31, 2024	-	-	50004	-	14601	84702	-	-	-	-20097

## सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

## i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

	2023-24	2023	2024	
		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	7371	-3647	4222
1.1 क्रय (+)	194296	7371	8006	23647
1.2 विक्रय (-)	153025	0	11653	19425
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	60342	-30488	35160
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	15075	-3647	575
(₹ करोड़)	339528	123675	-30488	4672
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	19268	-16257	-10360

## ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2023	2024	
		मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	0	1519	2287
1.2 विक्रय (-)	7930	0	1519	2287
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	0	-2424	-1812

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)  
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	31 मई 2024 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	1478	9378	-7900
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	2460	-2460
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	0	0
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
<b>कुल (1+2+3+4)</b>	<b>1478</b>	<b>11838</b>	<b>-10360</b>

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2023-24	2023	2024					
			जून 30	जन. 26	फर. 23	मार्च 22	अप्रै. 19	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	31256	32611	144270	49906	3238	14601	46848
2 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	9900	4900	4900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	3319	3174	9066	9810	8770	9311	9061
4 अन्य								
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	34575	35785	153336	59716	12008	23912	55909

## मुद्रा और बैंकिंग

## सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	2023	2024		
		मई 19	मई 03	मई 19	मई 31
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410042	3371391	3469795	3488012	3468476
1.1 संचलन में नोट	3477795	3447924	3537464	3550164	3537190
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	29739	32889	32889	33115
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101419	107088	101580	96125	102896
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2328896	2672973	2639502	2742637
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2260902	2583928	2552107	2651468
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	67994	89045	87395	91169
<b>3 एम1 (1+2)</b>	<b>6091466</b>	<b>5700287</b>	<b>6142769</b>	<b>6127514</b>	<b>6211113</b>
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	200257	200257	200257	200257	200257
<b>5 एम2 (3+4)</b>	<b>6291723</b>	<b>5900544</b>	<b>6343026</b>	<b>6327771</b>	<b>6411370</b>
6 बैंकों के पास भीयादी जमाराशियाँ	18739918	17066523	19217976	19126188	19303478
	<b>(18848160)</b>		<b>(19320614)</b>	<b>(19225635)</b>	<b>(19398657)</b>
7 एम3 (3+6)	24831384	22766810	25360745	25253702	25514591
	<b>(24939627)</b>		<b>(25463383)</b>	<b>(25353150)</b>	<b>(25609770)</b>
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1113230	1113230	1113230	1113230	1113230
<b>9 एम4 (7+8)</b>	<b>25944614</b>	<b>23880040</b>	<b>26473975</b>	<b>26366932</b>	<b>26627821</b>
	<b>(26052857)</b>		<b>(26576613)</b>	<b>(26466380)</b>	<b>(26723000)</b>

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम<sub>3</sub>) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		मई 19	मई 03	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
<b>1 सरकार को निवल बैंक ऋण</b>	<b>7512016</b>	<b>7135938</b>	<b>7578908</b>	<b>7530022</b>	<b>7370024</b>
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)		(7664268)	(7615419)	(7454906)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	1284068	1138507	1109883	966036
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1434729	1378156	1379146	1374629
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1422535	1358401	1361522	1363906
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	12194	19755	17624	10723
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	150661	239649	269263	408593
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	150619	239606	269221	408551
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	5851870	6440402	6420140	6403988
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)		(6525761)	(6505536)	(6488870)
<b>2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण</b>	<b>16672145</b>	<b>14633072</b>	<b>16879026</b>	<b>16850449</b>	<b>17035758</b>
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)		(17396143)	(17365107)	(17546837)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	5863	11272	11374	11372
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	14627209	16867754	16839075	17024387
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण (विलय सहित)	(17188425)		(17384871)	(17353733)	(17535465)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	13893970	16114603	16086356	16271321
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)		(16631720)	(16601014)	(16782399)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	716536	734717	734338	734587
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	16703	18434	18381	18479
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)		(18434)	(18381)	(18479)
<b>3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)</b>	<b>5540381</b>	<b>5062969</b>	<b>5502904</b>	<b>5557260</b>	<b>5588617</b>
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5240824	4738559	5203347	5257703	5289060
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4738819	5203604	5257962	5289319
3.1.2 विदेशी देयताएं	259	260	257	259	259
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	299557	324410	299557	299557	299557
<b>4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं</b>	<b>33432</b>	<b>30482</b>	<b>33632</b>	<b>33632</b>	<b>33858</b>
<b>5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं</b>	<b>4926589</b>	<b>4095651</b>	<b>4633725</b>	<b>4717661</b>	<b>4513665</b>
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5440588)		(5133564)	(5218268)	(5014447)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1789875	1553290	1769178	1830757	1610257
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3136714	2542361	2864548	2886904	2903409
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3650713)		(3364387)	(3387511)	(3404191)
एम <sub>3</sub> (1+2+3+4-5)	<b>24831384</b>	<b>22766810</b>	<b>25360745</b>	<b>25253702</b>	<b>25514591</b>
एम <sub>3</sub> (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939627)		(25463383)	(25353150)	(25609770)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		मई 19	मई 03	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
<b>समग्र मौद्रिक राशियाँ</b>					
एनएम <sub>1</sub> (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091466	5700287	6142769	6116403	6211113
एनएम <sub>2</sub> (एनएम <sub>1</sub> + 1.2.2.1)	14424621	13303603	14688269	14619550	14792897
एनएम <sub>2</sub> (एनएम <sub>1</sub> + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473330)		(14734455)	(14664302)	(14835727)
एनएम <sub>3</sub> (एनएम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25384097	23050135	25913002	25788060	26020669
एनएम <sub>3</sub> (एनएम <sub>2</sub> + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25492339)		(26015639)	(25887508)	(26115848)
<b>1 घटक</b>					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410042	3371391	3469795	3475251	3468476
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105010	19157161	21573927	21447990	21722100
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)		(21676565)	(21547438)	(21817278)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2260902	2583928	2552107	2651468
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	16896259	18989999	18895883	19070631
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)		(19092637)	(18995331)	(19165810)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	7603316	8545500	8503147	8581784
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)		(8591687)	(8547899)	(8624615)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	369399	297389	380236	367426	364274
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	9292942	10444500	10392736	10488847
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)		(10500950)	(10447432)	(10541196)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	67994	89045	89045	91169
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	774509	453589	780234	775774	738925
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	25295986	22885452	25554596	25518945	25522957
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)		(26157073)	(26118999)	(26118918)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7135938	7578908	7558646	7370024
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)		(7664268)	(7644043)	(7454906)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1284068	1138507	1138507	966036
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	5851870	6440402	6420140	6403988
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)		(6525761)	(6505536)	(6488870)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	15749514	17975688	17960299	18152933
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)		(18492805)	(18474957)	(18664012)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	5863	11272	11272	11372
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	15743651	17964416	17949027	18141561
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)		(18481533)	(18463685)	(18652640)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ)	1089184	1096183	1077302	1089455	1097950
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	30482	33632	33632	33858
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5110820	4770991	5114375	5168445	5157953
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5240824	4738559	5203347	5203347	5289060
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	-130004	32432	-88972	-34903	-131107
2.4 पूंजी खाता	3912897	3761071	4110893	4223458	4252145
2.5 अन्य मदें (निवल)	1657243	875719	1178548	1210110	942735

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2023	2024		
		मई	मार्च	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
<b>1 एनएम<sub>3</sub></b>	<b>25386437</b>	<b>23050135</b>	<b>25386437</b>	<b>25701274</b>	<b>26020669</b>
	(25494679)		(25494679)	(25807257)	(26115848)
2 डाकघर जमाराशियाँ	702174	672051	702174	702174	702174
<b>3 एल<sub>1</sub> (1 + 2)</b>	<b>26088611</b>	<b>23722186</b>	<b>26088611</b>	<b>26403448</b>	<b>26722843</b>
	(26196853)		(26196853)	(26509431)	(26818022)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	65082	85150	78167	72510
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	1802	2375	1858	1324
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	53485	70245	63595	58570
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	9795	12531	12713	12616
<b>5 एल<sub>2</sub> (3 + 4)</b>	<b>26173761</b>	<b>23787268</b>	<b>26173761</b>	<b>26481615</b>	<b>26795353</b>
	(26282004)		(26282004)	(26587597)	(26890532)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	91373	..	91373	..	..
<b>7 एल<sub>3</sub> (5 + 6)</b>	<b>26265135</b>	<b>..</b>	<b>26265135</b>	<b>..</b>	<b>..</b>

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।  
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		मई 19	मई 3	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3478479	3571376	3571376	3571371
1.2 आरबीआई के पास बैंकों की जमा राशियाँ	1025449	913455	1025548	1025548	1014134
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	852417	961717	961717	951109
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमा राशियाँ	94536	67994	89045	89045	91169
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4459928	4685969	4685969	4676674
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1244177	1218168	1218168	964014
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	1284068	1138507	1138507	966036
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	1271916	1118795	1118795	955355
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1422300	1357964	1357964	1363469
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1363369	1422300	1357964	1357964	1363469
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	235	437	437	438
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमा राशियाँ	177172	150619	239606	239606	408551
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	12151	19712	19712	10681
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	-45754	68389	68389	-13394
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	-45754	68389	68389	-13394
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	5863	11272	11272	11372
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	3800	9210	9210	9311
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	30482	33632	33632	33858
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5240824	4738559	5203347	5203347	5289060
2.3.1 स्वर्ण	439319	373000	457902	457902	471621
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	4801522	4365577	4745463	4745463	4817456
2.4 पूंजी खाता	1589134	1692762	1700252	1721228	1767903
2.5 अन्य मदें (निवल)	200741	-139472	68925	47949	-157646

## सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
	2023-24	2023	2024				
		मई 26	मई 3	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4421992	4685969	4686804	4685093	4722027	4676674
<b>1 घटक</b>							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3442197	3571376	3590534	3584138	3583833	3571371
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमा राशियाँ	1025449	911321	1025548	1008277	1013560	1050705	1014134
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमा राशियाँ	94536	68474	89045	87992	87395	87489	91169
<b>2 स्रोत</b>							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	1293643	1138507	1097030	1109883	856288	966036
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	-94537	68389	114166	103258	183657	-13394
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	4420	11272	11180	11374	11342	11372
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	5240824	4698223	5203347	5229351	5257703	5225853	5289060
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	30692	33632	33632	33632	33632	33858
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1789875	1510449	1769178	1798555	1830757	1588746	1610257

## सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2023	2024		
		मई 19	मई 3	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
<b>1 घटक</b>					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188 (20253430)	18206092	20607767 (20710404)	20485027 (20584475)	20759181 (20854359)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2121659	2437590	2407754	2506493
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334 (17809577)	16084433	18170177 (18272814)	18077273 (18176721)	18252688 (18347866)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7237995	8176579	8134773	8213709
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	369399	297389	380236	367426	364274
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	8846438	9993597	9942500	10038978
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	777942	453589	780234	775774	738925
<b>2 स्रोत</b>					
2.1 देशी ऋण	23019606 (23641847)	20553041	23337895 (23940372)	23301851 (23901905)	23482010 (24077971)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054 (6105610)	5550541	6134212 (6219572)	6113276 (6198672)	6097590 (6182473)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551 (17536238)	15002499	17203683 (17720800)	17188575 (17703233)	17384420 (17895499)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477 (16432164)	13893970	16114603 (16631720)	16086356 (16601014)	16271321 (16782399)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397 (16409083)	13857621	16076823 (16593941)	16045082 (16559740)	16231062 (16742141)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	20522	19623	20760	19488
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	786	1117	966	1029
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1087221	1068340	1080493	1092582
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियाँ (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	32432	-88972	-34903	-131107
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियाँ	241661	281276	299060	349927	259269
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	170264	227977	230305	232847
2.2.3 ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार	149868	78580	160055	154524	157529
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	993529	982806	977352	1055398
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	852417	961717	961717	951109
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	95358	89479	84025	90895
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	-45754	68389	68389	-13394
2.4 पूंजी खाता	2299592	2044138	2386470	2478059	2476644
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	506230	875182	457260	505440	431552
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	716422	742714	756667	809829
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	47685	184685	168869	180030

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2023	2024		
		मई 19	अप्रै. 19	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियाँ	6106558 (6015003)	5551328	6148210 (6060907)	6199638 (6114242)	6183502 (6098620)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	181210	165537	156469	156423
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	60463	47918	49424	43225
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सरकारी उद्यम	8475	9618	12835	13002	12972
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	77722	71151	88509	91996	91821
4.3 अन्य	5624	4640	7378	6937	7012
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक उद्यम	103070	86545	115109	111658	116195
5.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	287596	298605	249472	253898	243691
5.3 अन्य	124690	106619	125034	138305	142718
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	83743	85830	98744	96688
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	184627	175705	160059	181836

टिप्पणी : कॉलम सं. (1), (2) व (3) में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं. (4) व (5) में दिया गया डेटा अंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

**सं.14 : भारत में व्यवसाय – सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक**

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2024			2023-24	2023	2024	
		मई	अप्रै.	मई		मई	अप्रै.	मई
1	2	3	4	5	6	7	8	
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	211	209	208	137	136	136	135
<b>1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं</b>	<b>554117</b>	<b>368137</b>	<b>541798</b>	<b>527766</b>	<b>549351</b>	<b>364828</b>	<b>537356</b>	<b>523457</b>
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	252104	296469	287696	294471	249575	292303	283850
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	55182	170567	163135	182429	55063	170542	163095
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	60851	74763	76934	72452	60190	74511	76511
<b>2 अन्य के प्रति देयताएं</b>	<b>22664868</b>	<b>20190454</b>	<b>22917159</b>	<b>23268652</b>	<b>22190597</b>	<b>19733714</b>	<b>22440579</b>	<b>22793490</b>
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	18932570	21264492	21544610	20475226	18494388	20804308	21087206
	(20823825)		(21160334)	(21449431)	(20366984)		(20700150)	(20992028)
2.1.1 माँग	2492916	2227143	2530730	2556468	2443853	2182711	2480773	2506493
2.1.2 मीयादी	18439151	16705427	18733762	18988142	18031373	16311677	18323535	18580713
2.2 उधार	782260	461474	789091	743310	777942	456685	784526	738925
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	796410	863576	980731	937428	782642	851745	967358
<b>3 रिज़र्व बैंक से उधार</b>	<b>222716</b>	<b>67278</b>	<b>209301</b>	<b>71305</b>	<b>222716</b>	<b>67278</b>	<b>209301</b>	<b>71305</b>
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	67278	209301	71305	222716	67278	209301	71305
<b>4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि</b>	<b>1043272</b>	<b>992732</b>	<b>1131231</b>	<b>1064380</b>	<b>1020916</b>	<b>970799</b>	<b>1108501</b>	<b>1042004</b>
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	121620	93173	93275	89433	118608	90784	90895
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	871113	1038058	971105	931483	852191	1017716	951109
<b>5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियाँ</b>	<b>455057</b>	<b>397181</b>	<b>435794</b>	<b>430971</b>	<b>374474</b>	<b>331007</b>	<b>363001</b>	<b>362914</b>
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	240749	244270	233895	198327	197927	193978	185598
5.1.1 चालू खाते में	12010	17218	12215	10712	8971	12803	9388	8068
5.1.2 अन्य खातों में	234373	223532	232055	223183	189357	185124	184590	177529
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	36430	30878	27885	12355	18894	13390	13028
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	40670	48078	54040	48368	38116	45925	51888
5.4 अन्य आस्तियाँ	117734	79331	112568	115150	115424	76070	109708	112401
<b>6 निवेश</b>	<b>6256962</b>	<b>5688037</b>	<b>6281775</b>	<b>6336009</b>	<b>6106558</b>	<b>5543545</b>	<b>6129440</b>	<b>6183502</b>
	(6165407)		(6194450)	(6251126)	(6015003)		(6042115)	(6098620)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियाँ	6249319	5682020	6274221	6328175	6105610	5542758	6128369	6182473
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	7643	6016	7553	7834	949	787	1070	1029
<b>7 बैंक ऋण</b>	<b>16866336</b>	<b>14305765</b>	<b>16981402</b>	<b>17218547</b>	<b>16432164</b>	<b>13902450</b>	<b>16545337</b>	<b>16782399</b>
	(16335650)		(16462061)	(16707468)	(15901477)		(16025997)	(16271321)
7ए खाद्यान्न ऋण	75472	85546	81990	90882	23081	33571	28213	40259
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	14046367	16662862	16901681	16134303	13646019	16230106	16468877
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	42089	65609	64372	60467	42075	64286	64367
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	172767	212417	210953	197358	170441	211116	208274
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	18105	19194	16346	16412	17930	18965	16125
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	26437	21320	25195	23624	25985	20865	24756

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अंतिम है।

1. जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			मई 19	अप्रै. 19		
	1	2	3	4	%	%
<b>I. बैंक ऋण (II+III)</b>	<b>16434662</b>	<b>14009695</b>	<b>16494283</b>	<b>16781420</b>	<b>2.1</b>	<b>19.8</b>
	(15903976)		(15973464)	(16270342)	(2.3)	(16.1)
<b>II. खाद्यान्न ऋण</b>	<b>23081</b>	<b>36753</b>	<b>18090</b>	<b>40259</b>	<b>74.4</b>	<b>9.5</b>
<b>III. गैर-खाद्यान्न ऋण</b>	<b>16411581</b>	<b>13972942</b>	<b>16476192</b>	<b>16741162</b>	<b>2.0</b>	<b>19.8</b>
	(15880895)		(15955374)	(16230083)	(2.2)	(16.2)
<b>1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां</b>	<b>2071251</b>	<b>1759075</b>	<b>2115986</b>	<b>2139047</b>	<b>3.3</b>	<b>21.6</b>
<b>2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)</b>	<b>3652804</b>	<b>3386088</b>	<b>3655455</b>	<b>3703160</b>	<b>1.4</b>	<b>9.4</b>
	(3635810)		(3639138)	(3687080)	(1.4)	(8.9)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	637395	731994	736404	1.4	15.5
2.2 मध्यम	303998	271423	309427	313398	3.1	15.5
2.3 बड़े	2622490	2477270	2614034	2653358	1.2	7.1
<b>3. सेवाएं</b>	<b>4592227</b>	<b>3800500</b>	<b>4605915</b>	<b>4681338</b>	<b>1.9</b>	<b>23.2</b>
	(4490467)		(4509188)	(4587710)	(2.2)	(20.7)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	196453	234760	243074	5.6	23.7
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	24359	24774	25787	-0.5	5.9
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	77513	68712	77054	78408	1.2	14.1
3.4 शिपिंग	7067	6575	6884	6908	-2.2	5.1
3.5 विमानन	43248	31010	44998	45556	5.3	46.9
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	140735	173429	179919	7.6	27.8
3.7 व्यापार	1025752	896234	1020885	1054824	2.8	17.7
3.7.1 थोक व्यापार <sup>1</sup>	538744	470183	537086	556014	3.2	18.3
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	426051	483799	498810	2.4	17.1
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013	329653	468803	479120	2.2	45.3
	(400470)		(402521)	(415390)	(3.7)	(26.0)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) <sup>2</sup> जिसमें से	1548027	1351257	1564519	1568073	1.3	16.0
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	325626	319133	330115	331251	1.7	3.8
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएँ (पीएफआई)	226963	175666	232074	226676	-0.1	29.0
3.10 अन्य सेवाएँ <sup>3</sup>	998281	755513	989810	999668	0.1	32.3
	(978198)		(969994)	(980290)	(0.2)	(29.8)
<b>4. व्यक्तिगत ऋण</b>	<b>5331290</b>	<b>4238928</b>	<b>5346354</b>	<b>5456633</b>	<b>2.4</b>	<b>28.7</b>
	(4852210)		(4863453)	(4995156)	(2.9)	(17.8)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	21469	23577	24683	4.1	15.0
4.2 आवास	2718715	2009750	2741455	2786598	2.5	38.7
	(2264677)		(2283135)	(2349060)	(3.7)	(16.9)
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	125239	111972	121868	123334	-1.5	10.1
4.4 शेयर्स और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	7614	8472	9262	9.1	21.6
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	212410	259641	267979	4.3	26.2
4.6 शिक्षा	119380	97492	119125	121102	1.4	24.2
4.7 वाहन ऋण	589251	510800	594034	602270	2.2	17.9
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	90036	101552	116777	13.9	29.7
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1386921	1177385	1376631	1404629	1.3	19.3
	(1362113)		(1352213)	(1380790)	(1.4)	(17.3)
<b>5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)</b>						
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ <sup>4</sup>	2081856	1693835	2060244	2078112	-0.2	22.7
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम	1974191	1693042	1964032	2030754	2.9	19.9
(iii) मध्यम उद्यम	490703	428591	498958	502496	2.4	17.2
(iv) आवास	755222	624463	753576	762822	1.0	22.2
	(660572)		(659843)	(670883)	(1.6)	(7.4)
(v) शिक्षा ऋण	62235	59109	61027	61277	-1.5	3.7
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	4733	5712	5923	-1.1	25.1
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2596	2619	2674	2.3	3.0
(viii) निर्यात ऋण	11256	13628	13433	11218	-0.3	-17.7
(ix) अन्य	61336	64151	75152	62047	1.2	-3.3
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1336978	1605821	1670313	1.4	24.9

## टिप्पणियाँ:

- डेटा अनतिम है। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण डेटा थारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) शामिल हैं, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण डेटा क्षेत्र वार और उद्योग वार बैंक क्रेडिट (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं जिसमें चुनिंदा बैंकों के लेखांकन के आधार पर महीने के आखिरी रिपोर्टिंग शुरूवार से संबंधित सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण के लगभग 95 प्रतिशत को शामिल किया गया है।
- 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।
  - शोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर के खाद्य खरीद ऋण शामिल हैं।
  - एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएँ (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
  - "अन्य सेवाओं" के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल है और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
  - प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

## सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2023	2024		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			मई 19	अप्रै. 19		
	1	2	3	4	%	%
<b>2 उद्योग (2.1 से 2.19)</b>	3652804 (3635810)	3386088	3655455 (3639138)	3703160 (3687080)	1.4 (1.4)	9.4 (8.9)
<b>2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)</b>	54166	56369	55315	55370	2.2	-1.8
<b>2.2 खाद्य प्रसंस्करण</b>	208864	181148	210714	207369	-0.7	14.5
2.2.1 चीनी	26383	22501	27896	26622	0.9	18.3
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	18469	20149	18763	-4.8	1.6
2.2.3 चाय	5692	5434	5721	5677	-0.3	4.5
2.2.4 अन्य	157089	134744	156948	156307	-0.5	16.0
<b>2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू</b>	31136	23602	31592	30995	-0.5	31.3
<b>2.4 वस्त्र</b>	256048	233730	253819	255653	-0.2	9.4
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	91559	97390	97916	-1.3	6.9
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	3781	4266	4254	-0.6	12.5
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	38611	44282	44848	-0.6	16.2
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	99779	107882	108635	1.1	8.9
<b>2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद</b>	12588	11807	12488	12437	-1.2	5.3
<b>2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद</b>	23839	21131	23840	24301	1.9	15.0
<b>2.7 कागज और कागज से बने उत्पाद</b>	46426	43728	46270	46961	1.2	7.4
<b>2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक ईंधन</b>	132356	134882	133967	139876	5.7	3.7
<b>2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद</b>	249347	225645	251949	256275	2.8	13.6
2.9.1 उर्वरक	37569	38959	36872	39055	4.0	0.2
2.9.2 औषधि और दवाइयाँ	81036	70225	81941	83250	2.7	18.5
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	21483	25666	25091	8.3	16.8
2.9.4 अन्य	107584	94979	107470	108881	1.2	14.6
<b>2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद</b>	90420	82848	88937	88414	-2.2	6.7
<b>2.11 कांच और कांच के सामान</b>	12090	9293	12199	12224	1.1	31.5
<b>2.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद</b>	59757	54652	58089	59706	-0.1	9.2
<b>2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद</b>	384447	341792	381616	389190	1.2	13.9
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	228337	269936	275226	0.5	20.5
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	113454	111680	113964	3.0	0.4
<b>2.14 सभी अभियांत्रिकी</b>	196643	180118	197017	199049	1.2	10.5
2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	43175	42277	44296	43835	1.5	3.7
2.14.2 अन्य	153468	137842	152722	155215	1.1	12.6
<b>2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपकरण</b>	113185	102755	111469	111779	-1.2	8.8
<b>2.16 रत्न और आभूषण</b>	84860	78206	83491	82752	-2.5	5.8
<b>2.17 निर्माण</b>	133520	125232	131369	136280	2.1	8.8
<b>2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर</b>	1304096	1247567	1322295	1337749	2.6	7.2
2.18.1 बिजली	644042	617951	647359	658087	2.2	6.5
2.18.2 दूरसंचार	138192	127757	137366	134410	-2.7	5.2
2.18.3 सड़क	318072	305638	331069	335702	5.5	9.8
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7810	7443	7556	3.8	-3.3
2.18.5 बंदरगाह	6681	7477	6342	6412	-4.0	-14.2
2.18.6 रेलवे	13062	10618	13138	13203	1.1	24.3
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	170317	179580	182380	3.2	7.1
<b>2.19 अन्य उद्योग</b>	259016	231582	249019	256777	-0.9	10.9

टिप्पणियाँ: 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

## सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2023		2024					
		अप्रै. 28	फर. 23	मार्च 08	मार्च 22	मार्च 29	अप्रै. 05	अप्रै. 19	अप्रै. 26
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	33	33	33	33	33	33	33
<b>1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)</b>	<b>138788.9</b>	<b>135132.5</b>	<b>132042.0</b>	<b>133671.4</b>	<b>137649.9</b>	<b>138788.9</b>	<b>138798.4</b>	<b>137357.2</b>	<b>135856.4</b>
2 मांग और मीयादी देयताएं									
<b>2.1 मांग देयताएं</b>	<b>30226.7</b>	<b>27666.5</b>	<b>27356.3</b>	<b>29378.9</b>	<b>28442.9</b>	<b>30226.7</b>	<b>28549.4</b>	<b>28302.3</b>	<b>28654.1</b>
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	8403.6	7498.1	7823.5	7854.4	9101.3	8044.1	8096.3	7965.2
2.1.1.2 अन्य	15000.4	14616.2	14122.7	15294.8	14769.1	15000.4	14969.9	14869.0	14417.9
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0			655.0		130.0	440.7		679.5
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	4646.7	5735.6	5605.6	5819.4	5995.0	5094.7	5337.0	5591.5
<b>2.2 मीयादी देयताएं</b>	<b>198141.8</b>	<b>175563.3</b>	<b>178609.9</b>	<b>180631.5</b>	<b>191843.2</b>	<b>198141.8</b>	<b>195944.6</b>	<b>192115.1</b>	<b>189681.3</b>
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	53288.9	57905.0	59140.7	66034.5	72308.4	70753.2	67955.0	66557.0
2.2.1.2 अन्य	123788.5	120516.3	117919.3	118376.6	122880.8	123788.5	123828.5	122488.2	121438.5
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	843.1	1582.3	1862.5	1535.4	673.6	652.8	652.8	652.8
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	915.1	1203.2	1251.7	1392.5	1371.3	710.1	1019.1	1033.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0		135.0	135.0	100.0				
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	72437.7	86889.8	86640.9	90240.5	95914.5	89985.8	87425.2	86593.2
4.1 मांग	27317.7	19096.3	22632.6	21291.8	24187.7	27317.7	25417.7	24184.6	23967.7
4.2 मीयादी	68596.8	53341.1	64257.3	65349.1	66052.8	68596.8	64568.1	63240.6	62625.5
<b>5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि</b>	<b>16263.7</b>	<b>11764.2</b>	<b>11568.9</b>	<b>12032.2</b>	<b>13922.4</b>	<b>16263.7</b>	<b>15725.0</b>	<b>13393.3</b>	<b>12135.1</b>
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	763.2	758.7	748.3	808.9	960.0	726.3	874.7	777.3
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	11001.0	10810.2	11283.9	13113.5	15303.7	14998.7	12518.6	11357.8
<b>6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि</b>	<b>2088.1</b>	<b>2745.1</b>	<b>1819.0</b>	<b>1739.7</b>	<b>1793.1</b>	<b>2088.1</b>	<b>2751.6</b>	<b>1725.5</b>	<b>1625.6</b>
<b>7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश</b>	<b>77700.5</b>	<b>74288.0</b>	<b>74035.2</b>	<b>74120.7</b>	<b>74662.6</b>	<b>77700.5</b>	<b>75562.7</b>	<b>75605.0</b>	<b>75501.1</b>
<b>8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा</b>	<b>34355.3</b>	<b>22225.7</b>	<b>24428.3</b>	<b>26467.0</b>	<b>33159.5</b>	<b>34355.3</b>	<b>30264.5</b>	<b>26097.0</b>	<b>23246.7</b>
<b>9 बैंक ऋण (10.1+11)</b>	<b>135141.9</b>	<b>121128.0</b>	<b>133623.3</b>	<b>139496.2</b>	<b>132560.6</b>	<b>135141.9</b>	<b>134343.5</b>	<b>134755.3</b>	<b>137382.4</b>
10 अग्रिम									
<b>10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट</b>	<b>134936.8</b>	<b>121063.0</b>	<b>133448.3</b>	<b>139327.4</b>	<b>132372.0</b>	<b>134936.8</b>	<b>134130.7</b>	<b>134570.3</b>	<b>137200.4</b>
10.2 बैंकों से प्राप्त राशि	142185.2	121140.9	137852.4	130707.1	138216.3	142185.2	139090.4	136863.1	136586.9
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	65.0	175.0	168.8	188.6	205.1	212.8	185.0	182.0

# कीमत और उत्पादन

## सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	जून 23	मे 24	मार्च 24 (अ)	जून 23	मे 24	जून 24 (अ)	जून 23	मे 24	जून 24 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1 खाद्य और पेय पदार्थ</b>	<b>185.9</b>	<b>192.7</b>	<b>188.4</b>	<b>180.5</b>	<b>190.6</b>	<b>195.5</b>	<b>187.6</b>	<b>197.6</b>	<b>203.5</b>	<b>183.1</b>	<b>193.2</b>	<b>198.4</b>
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	174.4	188.7	190.1	175.7	189.0	190.0	174.8	188.8	190.1
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	220.4	226.5	231.5	226.6	236.3	240.4	222.6	229.9	234.6
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	181.1	184.9	188.4	185.4	189.1	192.9	182.8	186.5	190.1
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	180.1	184.1	185.1	179.8	184.3	185.8	180.0	184.2	185.4
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	167.2	160.5	162.2	159.7	155.2	156.1	164.4	158.6	160.0
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	167.0	180.4	179.3	177.8	187.4	190.0	172.0	183.7	184.3
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	165.9	190.7	216.0	210.8	233.2	269.7	181.1	205.1	234.2
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	180.9	203.7	208.8	183.2	209.7	215.1	181.7	205.7	210.9
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	122.8	128.9	130.0	124.9	131.3	132.1	123.5	129.7	130.7
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	226.3	229.2	229.2	216.8	223.6	224.8	223.1	227.3	227.7
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	179.2	182.4	183.0	166.7	170.8	171.3	174.0	177.6	178.1
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	191.6	196.6	197.4	198.4	205.5	206.5	194.8	200.7	201.6
<b>2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ</b>	<b>202.0</b>	<b>207.1</b>	<b>203.3</b>	<b>200.4</b>	<b>205.5</b>	<b>206.1</b>	<b>204.6</b>	<b>211.5</b>	<b>212.2</b>	<b>201.5</b>	<b>207.1</b>	<b>207.7</b>
<b>3 कपड़ा और जूते</b>	<b>192.9</b>	<b>181.5</b>	<b>188.4</b>	<b>191.4</b>	<b>195.7</b>	<b>196.3</b>	<b>179.9</b>	<b>184.7</b>	<b>185.1</b>	<b>186.8</b>	<b>191.3</b>	<b>191.9</b>
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	191.9	196.5	197.2	182.0	186.7	187.3	188.0	192.6	193.3
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	188.5	191.1	191.4	168.5	173.0	173.3	180.2	183.6	183.9
<b>4 आवास</b>	<b>--</b>	<b>176.7</b>	<b>176.7</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>174.4</b>	<b>180.1</b>	<b>179.1</b>	<b>174.4</b>	<b>180.1</b>	<b>179.1</b>
<b>5 ईंधन और बिजली</b>	<b>183.0</b>	<b>178.9</b>	<b>181.4</b>	<b>181.8</b>	<b>180.3</b>	<b>180.4</b>	<b>184.7</b>	<b>169.3</b>	<b>169.3</b>	<b>182.9</b>	<b>176.1</b>	<b>176.2</b>
<b>6 विविध</b>	<b>181.7</b>	<b>173.7</b>	<b>177.8</b>	<b>180.0</b>	<b>185.9</b>	<b>186.3</b>	<b>172.2</b>	<b>177.3</b>	<b>177.9</b>	<b>176.2</b>	<b>181.7</b>	<b>182.2</b>
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	180.4	183.9	184.1	170.4	174.8	175.2	175.7	179.6	179.9
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	188.5	195.7	196.0	182.8	190.0	190.8	186.3	193.5	194.0
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	169.9	171.8	172.0	160.8	161.5	161.9	165.1	166.4	166.7
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	174.3	178.5	178.6	169.8	173.3	173.8	171.8	175.6	175.9
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	181.9	186.9	188.1	177.1	182.4	183.7	179.1	184.3	185.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	184.4	198.6	199.1	185.2	200.6	200.7	184.7	199.4	199.8
<b>सामान्य सूचकांक (सभी समूह)</b>	<b>185.6</b>	<b>182.4</b>	<b>184.1</b>	<b>181.9</b>	<b>189.4</b>	<b>192.2</b>	<b>179.9</b>	<b>185.7</b>	<b>187.8</b>	<b>181.0</b>	<b>187.7</b>	<b>190.2</b>

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अर्न्तम

## सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2024				
				मई	फर.	मार्च	अप्रै.	मई
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	134.7	139.2	138.9	139.4	139.9
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1186	1258	1259	1263	1269
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1197	1269	1270	1275	1281

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2023		2024	
		मई	अप्रै.	मई	अप्रै.
	1	2	3	4	
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	60583	71353	72135	
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	73015	80778	86866	

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भार	2023-24	2024				
			2023		2024		
			जून	मार्च	अप्रै.	मई (पी)	जून (पी)
1	2	3	4	5	6	7	
<b>1 सभी पण्य</b>	<b>100.000</b>	<b>151.4</b>	<b>148.9</b>	<b>151.4</b>	<b>152.9</b>	<b>153.3</b>	<b>153.9</b>
<b>1.1 प्राथमिक वस्तुएं</b>	<b>22.618</b>	<b>183.0</b>	<b>176.1</b>	<b>183.2</b>	<b>187.1</b>	<b>187.7</b>	<b>191.6</b>
<b>1.1.1 खाद्य वस्तुएं</b>	<b>15.256</b>	<b>191.3</b>	<b>184.9</b>	<b>191.4</b>	<b>196.8</b>	<b>199.1</b>	<b>205.0</b>
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	185.2	202.3	202.5	204.1	206.7
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	193.9	197.2	215.0	220.5	245.1
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	178.3	184.2	185.3	183.7	184.3
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	180.0	168.9	172.6	178.4	174.5
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	209.7	233.5	228.5	236.8	237.3
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	180.5	198.8	207.6	205.9	208.5
<b>1.1.2 खाद्योत्पन्न वस्तुएं</b>	<b>4.119</b>	<b>162.4</b>	<b>158.9</b>	<b>160.0</b>	<b>157.7</b>	<b>156.3</b>	<b>155.8</b>
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	170.1	165.0	161.5	159.9	159.8
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	186.2	178.7	179.5	179.4	180.0
1.1.2.3 अन्य खाद्योत्पन्न वस्तुएं	1.960	134.9	132.4	133.7	131.1	130.9	132.6
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	217.6	291.0	279.3	260.7	228.8
<b>1.1.3 खनिज</b>	<b>0.833</b>	<b>217.7</b>	<b>207.4</b>	<b>221.6</b>	<b>224.0</b>	<b>224.0</b>	<b>227.3</b>
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	193.3	212.6	214.4	214.4	219.7
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	257.0	253.2	257.9	257.9	254.2
<b>1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस</b>	<b>2.410</b>	<b>153.6</b>	<b>138.6</b>	<b>157.1</b>	<b>162.7</b>	<b>156.9</b>	<b>156.0</b>
<b>1.2 ईंधन और बिजली</b>	<b>13.152</b>	<b>152.0</b>	<b>146.2</b>	<b>152.1</b>	<b>151.4</b>	<b>150.6</b>	<b>147.7</b>
<b>1.2.1 कोयला</b>	<b>2.138</b>	<b>136.4</b>	<b>137.6</b>	<b>135.8</b>	<b>135.9</b>	<b>135.8</b>	<b>135.8</b>
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.8	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	279.8	236.0	236.0	236.0	236.0
<b>1.2.2 खनिज तेल</b>	<b>7.950</b>	<b>159.0</b>	<b>152.8</b>	<b>159.4</b>	<b>159.5</b>	<b>159.5</b>	<b>155.7</b>
<b>1.2.3 बिजली</b>	<b>3.064</b>	<b>145.0</b>	<b>135.2</b>	<b>144.6</b>	<b>141.1</b>	<b>137.8</b>	<b>135.5</b>
<b>1.3 विनिर्मित उत्पाद</b>	<b>64.231</b>	<b>140.2</b>	<b>139.9</b>	<b>140.1</b>	<b>141.2</b>	<b>141.7</b>	<b>141.9</b>
<b>1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>9.122</b>	<b>160.5</b>	<b>158.8</b>	<b>162.1</b>	<b>164.0</b>	<b>163.2</b>	<b>165.6</b>
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	143.6	151.3	153.5	153.6	156.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	140.8	149.6	143.6	143.3	143.9
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	130.8	130.2	132.1	132.2	132.1
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	145.0	145.7	147.8	147.4	148.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	178.6	178.8	178.9	179.3	180.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	168.7	182.7	182.4	182.6	184.7
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	150.7	166.2	163.8	162.8	164.9
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	165.1	165.8	165.9	165.9	165.4
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	131.1	136.7	137.6	139.5	139.2
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	138.9	142.4	143.9	145.5	152.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	149.4	148.8	151.7	147.0	150.2
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	190.5	161.9	194.8	168.1	198.8
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	187.8	195.5	195.4	192.0	193.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	144.7	146.9	148.2	149.1	152.9
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	181.4	174.9	174.1	179.2	181.4
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	206.1	203.9	203.8	204.3	206.6
<b>1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण</b>	<b>0.909</b>	<b>131.5</b>	<b>130.7</b>	<b>132.5</b>	<b>132.9</b>	<b>133.4</b>	<b>133.4</b>
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	133.3	132.1	134.1	133.9	134.5	134.1
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	134.5	136.6	137.0	137.8	139.0
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोटलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	125.6	126.7	128.1	128.1	127.9
<b>1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>0.514</b>	<b>173.5</b>	<b>173.7</b>	<b>176.3</b>	<b>176.3</b>	<b>175.4</b>	<b>174.9</b>
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	173.7	176.3	176.3	175.4	174.9

## सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भार	2023-24	2023	2024			
				जून	मार्च	अप्रै.	मई (पी)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3.4 वस्त्र विनिर्माण</b>	<b>4.881</b>	<b>134.6</b>	<b>134.8</b>	<b>134.3</b>	<b>135.7</b>	<b>135.9</b>	<b>136.4</b>
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	120.1	119.8	121.8	122.0	122.0
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	158.1	156.3	156.5	157.1	158.1
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	120.0	120.6	123.2	123.2	124.5
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	156.2	158.7	159.9	159.5	159.2
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	139.6	137.6	138.3	138.9	139.3
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	129.7	131.6	131.9	131.9	133.7
<b>1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण</b>	<b>0.814</b>	<b>150.8</b>	<b>149.7</b>	<b>151.5</b>	<b>153.1</b>	<b>152.5</b>	<b>152.2</b>
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	148.5	148.7	150.2	150.0	150.3
1.3.5.2 बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	152.9	159.0	160.7	159.3	157.3
<b>1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>0.535</b>	<b>124.1</b>	<b>124.7</b>	<b>123.7</b>	<b>123.6</b>	<b>123.9</b>	<b>124.1</b>
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ट्रेसिंग; ट्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	111.4	104.8	104.7	104.2	103.7
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	140.4	140.7	140.9	141.0	141.1
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	126.9	128.1	128.0	128.6	129.1
<b>1.3.7 लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>0.772</b>	<b>146.6</b>	<b>145.2</b>	<b>149.1</b>	<b>149.4</b>	<b>149.3</b>	<b>149.8</b>
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	138.1	139.4	138.7	139.5	139.7
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	143.3	149.0	149.7	149.2	149.8
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	206.4	207.3	214.1	214.3	215.3	215.4
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	141.6	140.0	139.9	140.3	140.9
<b>1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>1.113</b>	<b>140.3</b>	<b>143.6</b>	<b>138.0</b>	<b>137.9</b>	<b>138.9</b>	<b>138.3</b>
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	150.6	144.5	144.6	145.0	144.5
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	139.0	143.4	143.4	144.3	144.5
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	137.1	121.8	121.6	123.5	122.0
<b>1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन</b>	<b>0.676</b>	<b>182.3</b>	<b>179.9</b>	<b>184.6</b>	<b>185.4</b>	<b>185.6</b>	<b>185.2</b>
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	179.9	184.6	185.4	185.6	185.2
<b>1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>6.465</b>	<b>136.9</b>	<b>137.9</b>	<b>135.6</b>	<b>135.7</b>	<b>135.8</b>	<b>136.4</b>
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	141.4	136.5	136.7	137.3	137.9
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	144.3	142.6	143.3	143.4	143.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	133.0	132.4	132.4	131.9	134.0
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	132.8	134.0	130.5	127.1	127.9	127.3
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	143.0	141.0	139.2	140.4	140.6
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	140.8	138.0	139.1	138.7	138.8
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	135.0	134.5	135.1	134.5	135.5
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	103.5	103.6	104.9	104.9	106.9
<b>1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण</b>	<b>1.993</b>	<b>142.9</b>	<b>143.4</b>	<b>143.4</b>	<b>143.5</b>	<b>144.6</b>	<b>144.0</b>
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	143.4	143.4	143.5	144.6	144.0
<b>1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.299</b>	<b>127.5</b>	<b>127.1</b>	<b>128.2</b>	<b>128.1</b>	<b>128.2</b>	<b>128.8</b>
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.6	113.8	113.6	113.3	113.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	106.3	108.6	109.2	109.1	110.4
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	136.8	138.2	137.9	138.3	138.7
<b>1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.202</b>	<b>134.7</b>	<b>134.7</b>	<b>133.1</b>	<b>132.6</b>	<b>132.2</b>	<b>131.5</b>
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	164.0	163.9	164.0	163.8	162.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	119.0	119.7	119.0	119.2	118.6
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	130.0	119.9	118.1	120.2	116.2
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	121.3	124.4	124.5	124.8	124.4
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	137.4	134.3	133.6	132.6	131.7

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भार	2023-24	2023	2024			
				जून	मार्च	अप्रै.	मई (पी)
	1	2	3	4	5	6	7
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	137.3	137.2	138.9	139.3	139.7
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	127.1	131.7	131.9	131.4	132.3
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	105.2	100.9	96.5	97.0	97.4
<b>1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण</b>	<b>9.646</b>	<b>141.0</b>	<b>141.6</b>	<b>138.7</b>	<b>141.4</b>	<b>144.1</b>	<b>143.1</b>
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	142.0	134.6	136.7	142.4	139.6
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	156.3	147.4	149.4	154.5	152.1
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	121.8	117.0	118.4	120.1	120.2
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	141.7	138.9	142.3	144.5	143.9
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	144.5	138.7	138.5	140.6	140.5
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	139.7	134.3	137.9	142.2	141.7
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	141.5	131.1	139.6	140.6	133.1
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	169.7	169.8	168.0	166.6	166.7
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	144.2	146.4	152.4	156.5	157.5
1.3.14.10 कार्बिडिंग	0.925	141.0	134.0	146.1	145.0	143.9	145.0
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	172.2	170.8	171.2	173.1	174.4
<b>1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>3.155</b>	<b>138.6</b>	<b>139.3</b>	<b>136.2</b>	<b>136.0</b>	<b>136.3</b>	<b>135.7</b>
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	132.2	130.6	130.6	131.2	130.0
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	160.4	155.3	151.0	152.9	151.3
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	106.3	109.4	106.0	108.1	109.4	109.5
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	139.3	136.8	136.5	133.1	134.1
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	108.8	101.5	101.9	102.0	101.5
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	145.0	142.3	144.8	145.6	145.4
<b>1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण</b>	<b>2.009</b>	<b>119.3</b>	<b>118.3</b>	<b>120.4</b>	<b>121.6</b>	<b>122.0</b>	<b>122.0</b>
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	114.9	115.5	116.6	117.3	117.8
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.1	135.3	135.3	135.3	135.3
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	131.5	139.5	146.3	146.3	145.9
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	104.1	103.7	103.9	103.3	103.3
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	111.6	118.2	115.0	119.8	117.8
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	154.7	159.9	162.9	163.8	163.0
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	107.3	108.4	109.3	109.4	113.6
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	103.6	105.2	104.1	104.1	109.9
<b>1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण</b>	<b>2.930</b>	<b>131.4</b>	<b>130.5</b>	<b>131.9</b>	<b>132.3</b>	<b>133.4</b>	<b>133.5</b>
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	128.2	130.6	131.2	131.5	131.3
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	137.8	136.8	140.4	139.8	140.8	140.7
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	123.7	121.2	120.1	118.0	121.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	146.1	145.5	146.9	149.9	153.9	155.5
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	117.0	117.6	117.6	118.9	119.4
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	134.5	133.3	132.1	131.9	132.1
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	120.7	121.8	120.8	124.8	122.2
<b>1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>4.789</b>	<b>129.0</b>	<b>128.0</b>	<b>129.9</b>	<b>130.4</b>	<b>130.9</b>	<b>130.7</b>
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	127.1	130.6	130.6	131.3	132.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	131.6	132.3	133.3	133.4	133.7
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	117.0	117.7	117.5	117.7	117.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	126.5	129.6	127.7	128.6	128.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	83.0	85.3	86.2	85.2	86.5
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने - उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	127.4	129.9	130.3	129.9	130.3

**सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)**  
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भार	2023-24	2023	2024			
				जून	मार्च	अप्रै.	मई (अ)
	1	2	3	4	5	6	7
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	143.4	144.6	147.4	151.5	148.3
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	141.4	143.9	145.3	145.2	145.0
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	121.9	122.4	122.4	122.4	122.4
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	88.4	89.3	89.5	89.7	89.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.9	124.4	124.6	125.3	125.8
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	135.0	137.7	137.9	137.3	134.9
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	143.9	146.4	146.2	146.3	146.3
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	71.3	69.7	70.1	70.0	69.6
<b>1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण</b>	<b>4.969</b>	<b>128.4</b>	<b>127.8</b>	<b>129.9</b>	<b>129.6</b>	<b>129.7</b>	<b>129.8</b>
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	127.0	130.6	130.5	130.4	130.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	128.7	129.0	128.7	128.9	129.3
<b>1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण</b>	<b>1.648</b>	<b>143.1</b>	<b>142.1</b>	<b>143.6</b>	<b>144.3</b>	<b>143.9</b>	<b>143.9</b>
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली - वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	163.7	177.9	177.9	177.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	105.9	108.5	108.2	108.3	108.3
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	143.7	145.3	145.0	144.6	144.6
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	137.0	137.6	136.7	136.0	135.5
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	158.1	158.5	161.3	163.6	162.8
<b>1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण</b>	<b>0.727</b>	<b>159.6</b>	<b>160.1</b>	<b>158.4</b>	<b>158.8</b>	<b>158.8</b>	<b>158.8</b>
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	160.1	158.4	158.8	158.8	158.8
<b>1.3.22 अन्य विनिर्माण</b>	<b>1.064</b>	<b>158.2</b>	<b>157.7</b>	<b>164.1</b>	<b>176.4</b>	<b>178.2</b>	<b>177.1</b>
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	157.3	164.3	177.5	179.4	178.3
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	181.1	192.0	199.3	199.3	201.9
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	154.8	154.5	158.3	159.2	161.7
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	159.6	159.7	160.0	161.2	161.4	161.0
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामान	0.049	163.1	164.5	161.2	160.2	159.1	159.1
<b>2 खाद्य सूचकांक</b>	<b>24.378</b>	<b>179.8</b>	<b>175.1</b>	<b>180.4</b>	<b>184.6</b>	<b>185.7</b>	<b>190.3</b>

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

## सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रै-मई		मई	
				2023-24	2024-25	2023	2024
				1	2	3	4
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	143.2	151.0	145.6	154.2
<b>1 क्षेत्रवार वर्गीकरण</b>							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	125.4	133.7	128.1	136.5
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.6	141.0	147.0	143.1	149.7
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	197.0	220.7	201.6	229.3
<b>2 उपयोग आधारित वर्गीकरण</b>							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	146.1	156.6	149.9	160.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.5	97.5	100.1	102.6	105.2
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.2	154.5	158.9	156.9	160.8
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	171.5	184.3	173.2	185.1
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	111.9	124.4	115.6	129.8
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.8	152.3	152.1	149.8	153.3

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

## सरकारी लेखा और खजाना बिल

## सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

मद	वित्तीय वर्ष		अप्रैल-मई		
	2024-25 बजट अनुमान	2024-25 वास्तविक	2023-24 वास्तविक	बजट अनुमान का प्रतिशत	
				2024-25	2023-24
1	2	3	4	5	
<b>1 राजस्व प्राप्तियां</b>	<b>3001275</b>	<b>570758</b>	<b>412700</b>	<b>19.0</b>	<b>15.7</b>
1.1 कर राजस्व (निवल)	2601574	319036	278045	12.3	11.9
1.2 करेतर राजस्व	399701	251722	134655	63.0	44.6
<b>2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्तियां</b>	<b>79000</b>	<b>2087</b>	<b>2991</b>	<b>2.6</b>	<b>3.6</b>
2.1 ऋण की वसूली	29000	2083	2941	7.2	12.8
2.2 अन्य प्राप्तियां	50000	4	50	0.0	0.1
<b>3 कुल प्राप्तियां (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)</b>	<b>3080275</b>	<b>572845</b>	<b>415691</b>	<b>18.6</b>	<b>15.3</b>
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3654657	479835	458189	13.1	13.1
4.1 ब्याज भुगतान	1190440	123810	110663	10.4	10.2
5 पूंजी व्यय	1111111	143625	167789	12.9	16.8
<b>6 कुल व्यय (4+5)</b>	<b>4765768</b>	<b>623460</b>	<b>625978</b>	<b>13.1</b>	<b>13.9</b>
7 राजस्व घाटा (4-1)	653383	-90923	45489	-13.9	5.2
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1685494	50615	210287	3.0	11.8
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	495054	-73195	99624	-14.8	14.1

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2024-25।

## सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023		2024				
		जून 2	अप्रै. 26	मई 3	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 91-दिवसीय</b>								
1.1 बैंक	18054	9503	8989	7004	8819	6311	5175	7219
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	27226	22711	28043	34018	35417	34953	28830
1.3 राज्य सरकारें	5701	28041	31670	31670	31069	30927	37927	37927
1.4 अन्य	88670	113971	114700	115353	111563	117072	111972	110051
<b>2 182-दिवसीय</b>								
2.1 बैंक	84913	64795	77964	71949	74770	78064	72514	66301
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	130977	78906	77834	76385	75042	69402	69388
2.3 राज्य सरकारें	4070	15929	7406	8906	9329	9480	9152	9842
2.4 अन्य	102311	119228	114134	120221	117849	114899	122088	124315
<b>3 364-दिवसीय</b>								
3.1 बैंक	91819	92279	91933	93628	98996	98535	97274	96254
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	149673	160059	160331	154440	155541	152797	152028
3.3 राज्य सरकारें	41487	47090	37488	40490	41005	41005	41120	41131
3.4 अन्य	165095	155048	164008	162041	162564	161924	161929	159718
<b>4 14-दिवसीय मध्यवर्ती</b>								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	92562	223837	165239	197225	188244	200174	180187
4.4 अन्य	442	928	537	1563	834	40	390	1700
<b>कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#</b>	<b>871662</b>	<b>953759</b>	<b>909968</b>	<b>917470</b>	<b>920806</b>	<b>924216</b>	<b>916304</b>	<b>903004</b>

# 14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।  
टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

## सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>91-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
मई 2	12000	77	19168	1962	54	11938	1962	13900	98.29	6.9972
मई 8	12000	134	30069	1050	53	11950	1050	13000	98.28	6.9997
मई 15	12000	123	34251	442	57	11958	442	12400	98.29	6.9885
मई 22	4000	104	32088	8331	11	3969	8331	12300	98.32	6.8536
मई 29	4000	70	14436	1529	13	3971	1529	5500	98.32	6.8478
<b>182-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
मई 2	7000	110	20425	1524	24	6976	1524	8500	96.61	7.0393
मई 8	7000	96	14017	1512	79	6911	1512	8423	96.59	7.0802
मई 15	7000	119	15785	187	81	6964	187	7151	96.59	7.0847
मई 22	4000	90	11060	2020	36	3980	2020	6000	96.62	7.0140
मई 29	4000	112	15743	1034	21	3966	1034	5000	96.62	7.0080
<b>364-दिवसीय खज़ाना बिल</b>										
<b>2024-25</b>										
मई 2	8000	120	22440	3263	55	7948	3263	11211	93.41	7.0797
मई 8	8000	127	20079	565	93	7963	565	8528	93.40	7.0890
मई 15	8000	96	22951	73	21	7975	73	8048	93.41	7.0797
मई 22	4000	114	18337	141	23	3978	141	4119	93.46	7.0218
मई 29	4000	104	13643	32	43	3979	32	4011	93.44	7.0364

## वित्तीय बाजार

## सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
मई 02 ,2024	5.10-6.65	6.52
मई 03 ,2024	5.40-6.50	6.43
मई04 ,2024	5.50-6.50	6.16
मई 06 ,2024	5.40-6.75	6.46
मई 07 ,2024	5.80-6.66	6.54
मई 08 ,2024	5.40-6.80	6.61
मई 09 ,2024	5.40-6.90	6.69
मई 10 ,2024	5.40-6.85	6.72
मई 13 ,2024	5.50-6.90	6.72
मई 14 ,2024	5.10-6.85	6.70
मई 15 ,2024	5.40-6.55	6.48
मई 16 ,2024	4.75-6.65	6.48
मई 17 ,2024	5.40-6.85	6.69
मई 18 ,2024	5.50-6.35	6.11
मई 21 ,2024	5.10-6.85	6.75
मई22 ,2024	5.40-6.85	6.74
मई 24 ,2024	5.40-7.00	6.72
मई 27 ,2024	4.75-6.77	6.67
मई 28 ,2024	5.40-6.60	6.49
मई 29 ,2024	5.40-6.60	6.49
मई30 ,2024	5.40-6.55	6.47
मई 31 ,2024	5.40-6.80	6.66
जून 01 ,2024	5.00-6.24	5.96
जून 03 ,2024	5.10-6.55	6.46
जून 04 ,2024	5.10-6.60	6.46
जून 05 ,2024	5.10-6.60	6.52
जून 06 ,2024	5.40-6.70	6.50
जून 07 ,2024	5.40-6.60	6.51
जून 10 ,2024	5.40-6.60	6.51
जून 11 ,2024	5.40-6.65	6.52
जून 12 ,2024	5.40-6.60	6.52
जून 13 ,2024	5.40-6.58	6.48
जून 14 ,2024	5.40-6.80	6.68
जून 15 ,2024	5.50-6.72	6.31

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित।

**सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र**

मद	2023	2024			
	मई 19	अप्रै. 19	मई 3	मई 17	मई 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	302117.26	372841.80	380093.01	367450.64	369203.22
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	41744.11	16991.88	14503.74	33905.56	44822.51
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.76-7.32	6.95-7.83	6.98-7.21	7.05-7.28	7.00-7.49

**सं. 28: वाणिज्यिक पत्र**

मद	2023	2024			
	मई 31	अप्रै. 15	अप्रै. 30	मई 15	मई 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	433543.35	397251.00	411533.60	421150.90	403970.00
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	81179.55	23663.00	60407.45	52596.55	80921.75
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.73-16.31	6.90-13.85	6.89-12.59	7.06-11.96	7.05-13.92

**सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार**

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2023	2024					
		जून 2	अप्रै. 26	मई 03	मई 10	मई 17	मई 24	मई 31
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	13814	18120	19039	18513	19191	20332	19446
2 नोटिस मुद्रा	2550	3234	655	5216	1495	4595	408	4362
3 मीयादी मुद्रा	871	523	969	1327	1348	522	1212	1154
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	505108	628164	631845	514261	628141	535322	720037
5 बाजार रेपो	574534	581054	570483	674219	543732	679566	506526	671501
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	314	3178	4333	3972	4382	3625	3762
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	98063	120418	117639	90191	97290	113570	113440
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	97132	73593	102300	112121	111137	123616	96496
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	5212	4343	5604	4097	4977	5060	3779
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	9419	4848	3792	5313	6544	7696	2928
10.2 182-दिवसीय	6079	7717	6214	5021	7316	6388	7204	5660
10.3 364-दिवसीय	4307	4183	4593	3788	3946	1700	2954	1838
10.4 नकदी प्रबंधन बिल		0	0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	123662	93592	120504	132792	130746	146530	110701
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	162	16	33	183	568	331	32

## सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (अप्रै.-मई)		2024-25 (अप्रै.-मई) *		मई 2023		मई 2024 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1 इक्विटी शेयर</b>	<b>339</b>	<b>80942</b>	<b>28</b>	<b>9255</b>	<b>73</b>	<b>37659</b>	<b>14</b>	<b>7274</b>	<b>38</b>	<b>12289</b>
1ए प्रीमियम	328	76319	25	8953	70	20507	12	7052	36	11773
1.1 पब्लिक	272	65832	18	5594	53	33861	8	4484	26	10133
1.1.1 प्रीमियम	272	62791	18	5526	53	17092	8	4462	26	9855
1.2 राइट्स	67	15110	10	3661	20	3798	6	2790	12	2155
1.2.1 प्रीमियम	56	13527	7	3427	17	3415	4	2590	10	1918
<b>2 अधिमान शेयर</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3 बॉण्ड और डिबेंचर</b>	<b>44</b>	<b>16342</b>	<b>7</b>	<b>2036</b>	<b>7</b>	<b>1894</b>	-	-	<b>3</b>	<b>1207</b>
3.1 परिवर्तनीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.1 पब्लिक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अपरिवर्तनीय	44	16342	7	2036	7	1894	-	-	3	1207
3.2.1 पब्लिक	44	16342	7	2036	7	1894	-	-	3	1207
3.2.2 राइट्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4 कुल (1+2+3)</b>	<b>383</b>	<b>97284</b>	<b>35</b>	<b>11290</b>	<b>80</b>	<b>39553</b>	<b>14</b>	<b>7274</b>	<b>41</b>	<b>13496</b>
4.1 पब्लिक	316	82174	25	7630	60	35754	8	4484	29	11340
4.2 राइट्स	67	15110	10	3661	20	3798	6	2790	12	2155

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

\* : आंकड़े अनंतिम हैं।

## बाह्य क्षेत्र

## सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24		2024				
		2023		जन.	फर.	मार्च	अप्रै	मई
		1	2					
1 निर्यात	₹ करोड़	3619292	287810	310242	343518	346249	294710	328819
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	437113	34952	37324	41406	41718	35334	39430
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	48207	71607	68163	44950	59013	68391
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	84157	5854	8615	8216	5416	7075	8201
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922442	239603	238635	275356	301299	235697	260428
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	352956	29098	28709	33190	36302	28259	31229
2 आयात	₹ करोड़	5592877	473321	443420	498718	475374	452858	514984
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	675430	57481	53346	60113	57276	54296	61754
2.1 तेल	₹ करोड़	1487581	128242	129050	140134	142994	137649	166347
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	179618	15574	15526	16891	17229	16503	19947
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4105296	345079	314370	358584	332380	315209	348637
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	495812	41907	37821	43222	40047	37792	41807
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1973585	-185511	-133179	-155200	-129125	-158148	-186164
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-238317	-22529	-16022	-18707	-15558	-18961	-22324
3.1 तेल	₹ करोड़	-790731	-80036	-57443	-71972	-98044	-78636	-97955
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-95461	-9720	-6911	-8675	-11813	-9428	-11746
3.2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1182854	-105475	-75735	-83229	-31081	-79512	-88209
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-142856	-12809	-9111	-10032	-3745	-9533	-10577

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

## सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

Item	इकाई	2023		2024				
		जुला. 07	मई 24	मई 31	जून 07	जून 14	जून 21	जून 28
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	₹ करोड़	4933658	5373798	5438138	5468448	5455921	5460976	5436574
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	596280	646673	651510	655817	652895	653711	651997
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4376744	4715859	4779242	4805700	4798644	4796186	4776850
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	528968	567499	572564	576337	574240	574134	572881
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	364561	471279	471621	475139	467693	475795	471350
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	44060	56713	56501	56982	55967	56956	56528
1.3 एसडीआर	₹ करोड़	797.72	831.43	831.43	834.23	837.03	837.03	840.76
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	13674	13699	13699	13699	13699	13699	13699
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	150875	150703	151235	151432	151310	150781	150209
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	18235	18135	18118	18161	18107	18049	18014
	₹ करोड़	41479	35958	36039	36177	38274	38215	38165
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	5017	4326	4326	4336	4581	4572	4573

\* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।

टिप्पणी: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

## सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2023	2024		2023-24	2024-25
		मई	अप्रै.	मई (पी)	अप्रै.-मई	अप्रै.-मई (पी)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	151879	138779	153009	154718	623	2724
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	19887	26216	26840	524	1107
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	95228	99229	99850	-10	1136
1.3 एनआरओ	27522	23664	27564	28028	109	481

अ: अनंतिम।

## सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24		2024-25 (पी)	2023	2024 (पी)	
	1	अप्रै.-मई	अप्रै.-मई	मई	अप्रै.	मई
		2	3	4	5	6
<b>1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)</b>	<b>9790</b>	<b>3422</b>	<b>7142</b>	<b>665</b>	<b>3891</b>	<b>3251</b>
<b>1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.1.2)</b>	<b>26469</b>	<b>5395</b>	<b>9853</b>	<b>1484</b>	<b>4880</b>	<b>4972</b>
<b>1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश</b>	<b>70941</b>	<b>12346</b>	<b>15159</b>	<b>4959</b>	<b>7269</b>	<b>7891</b>
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	7997	10977	2785	5017	5960
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	40	91	15	11	80
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिजर्व बैंक	31826	6746	8520	2120	4733	3787
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	999	2153	543	167	1986
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	213	213	107	107	107
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	3027	3027	1514	1514	1514
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5355	1322	1155	661	738	417
<b>1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश</b>	<b>44472</b>	<b>6952</b>	<b>5307</b>	<b>3476</b>	<b>2389</b>	<b>2918</b>
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	6234	4868	3117	2235	2633
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	718	439	359	154	285
<b>1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)</b>	<b>16678</b>	<b>1972</b>	<b>2711</b>	<b>819</b>	<b>989</b>	<b>1722</b>
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	1385	1637	612	590	1046
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	964	964	482	482	482
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	615	815	221	376	439
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	992	705	496	459	246
<b>1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)</b>	<b>44081</b>	<b>8081</b>	<b>-4119</b>	<b>5986</b>	<b>-2663</b>	<b>-1456</b>
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	8320	-4199	6106	-2691	-1508
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	239	-80	119	-29	-51
<b>1 विदेशी निवेश अंतर्वाह</b>	<b>53872</b>	<b>11504</b>	<b>3023</b>	<b>6651</b>	<b>1229</b>	<b>1794</b>

अ: अनतिम।

## सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24		2023	2024	
	1	मई	मार्च	अप्रै.	मई
		2	3	4	5
<b>1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण</b>	<b>31735.74</b>	<b>2887.80</b>	<b>2302.36</b>	<b>2285.77</b>	<b>2420.58</b>
1.1 जमाराशियाँ	916.45	99.89	107.77	72.67	52.98
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	21.22	26.08	23.19	21.69
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	106.81	224.70	98.94	98.86
1.4 उपहार	3580.27	390.72	318.66	311.16	271.93
1.5 दान	11.31	0.98	1.11	1.70	0.58
1.6 यात्रा	17006.27	1495.35	1002.41	1144.31	1401.16
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्च	4611.53	490.73	394.13	391.69	320.80
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	5.19	8.17	10.38	7.66
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	247.33	197.02	208.02	210.99
1.10 अन्य	298.24	29.59	22.31	23.70	33.94

**सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और  
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक**

मद	2022-23	2023-24	2023	2024	
	1	2	जून	मई	जून
			3	4	5
<b>40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100 )</b>					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	91.27	90.76	90.34	92.22	92.43
1.2 रीर	102.86	103.73	102.90	104.68	106.54
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.03	93.13	92.60	94.67	95.02
2.2 रीर	101.12	101.23	100.57	101.62	103.53
<b>6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)</b>					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	85.93	83.65	84.12	83.66	83.73
1.2 रीर	101.80	101.79	101.18	102.42	103.81
2 आधार : 2021-22 = 100					
2.1 नीर	98.72	96.10	96.64	96.12	96.19
2.2 रीर	99.69	99.67	99.08	100.29	101.65

## सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2023-24	2023	2024	
		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	129	100	108
1.2 राशि	29461	2648	3891	3669
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	1	1	2
2.2 राशि	19748	5000	394	343
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	130	101	110
3.2 राशि	49209	7648	4285	4012
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.60	6.90	5.00	4.90
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारत औसत मार्जिन	1.66	2.41	1.32	2.05
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-12.00	0.00-10.50	0.00-11.67

उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	5570	410	497
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	924	1814	1366
ए) परिवहन	1505	97	43	0
बी) ऊर्जा	3513	96	380	434
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	0
डी) संचार	6309	170	0	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	46	56
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	300	550	0
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	261	795	876
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	47	18	138
IV. अन्य संस्थाएं	1728	0	0	0
ए) एसईजेड में इकाई	1	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1727	0	0	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	0
VII. एनबीएफसी	13361	1078	1875	1424
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	150	411	555
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	39	28	52
सी) एनबीएफसी - अन्य	5096	889	1436	817
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	29	168	587

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।  
 @ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेंचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) कर दिया गया है।

## सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (पी)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	391827	386248	5579	502210	471456	30754
1 चालू खाता (1.1+1.2)	238010	239366	-1356	253561	247879	5682
1.1 पण्य	115821	168408	-52587	121652	172546	-50894
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	122189	70959	51231	131909	75333	56576
1.2.1 सेवाएं	85833	46758	39075	89357	46672	42685
1.2.1.1 यात्रा	8445	7698	747	9961	8063	1898
1.2.1.2 परिवहन	7956	8091	-135	7772	7829	-57
1.2.1.3 बीमा	824	455	369	927	650	277
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	144	307	-163	129	315	-186
1.2.1.5 विविध	68464	30207	38256	70568	29814	40753
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	38473	4103	34370	41551	4908	36643
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	22260	16314	5945	22620	16388	6232
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2093	1303	790	1599	1269	330
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	2558	2217	341	498	506	-7
1.2.2 अंतरण	28650	3888	24762	32097	3378	28719
1.2.2.1 आधिकारिक	24	342	-318	51	282	-231
1.2.2.2 निजी	28627	3547	25080	32046	3096	28950
1.2.3 आय	7706	20312	-12606	10455	25283	-14828
1.2.3.1 निवेश आय	6010	19395	-13385	8523	24244	-15721
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1695	917	778	1932	1039	893
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	153422	146882	6540	248111	223578	24534
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	83781	79091	4691	158711	145366	13345
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	17084	10730	6355	19834	17881	1954
2.1.1.1 भारत में	15858	6538	9319	19128	11411	7718
2.1.1.1.1 इक्विटी	9708	6254	3454	12762	10934	1829
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	4976	0	4976	5332		5332
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1173	284	889	1034	477	557
2.1.1.2 विदेश में	1227	4191	-2964	706	6470	-5764
2.1.1.2.1 इक्विटी	1227	2123	-896	706	3208	-2503
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	1103	-1103	0	1446	-1446
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	965	-965	0	1815	-1815
2.1.2 संविभाग निवेश	66697	68361	-1664	138877	127485	11392
2.1.2.1 भारत में	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
2.1.2.1.1 एफआईआई	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	57476	59959	-2483	120154	112150	8004
2.1.2.1.1.2 ऋण	8640	7745	895	18063	14487	3575
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	580	657	-77	660	847	-187
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	26512	23457	3055	30700	28949	1751
2.2.1 बाह्य सहायता	3240	1522	1718	3587	1562	2025
2.2.1.1 भारत द्वारा	8	22	-14	8	31	-23
2.2.1.2 भारत को	3232	1500	1732	3579	1531	2048
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	7323	5698	1624	15113	13418	1695
2.2.2.1 भारत द्वारा	272	382	-110	3401	4308	-907
2.2.2.2 भारत को	7051	5316	1735	11711	9110	2601
2.2.3 भारत को अल्पावधि	15950	16237	-287	12000	13969	-1969
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	15950	13646	2305	12000	12865	-865
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	2592	-2592	0	1104	-1104
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	27997	32047	-4050	40722	33811	6911
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	27922	32047	-4125	39768	33811	5957
2.3.1.1 आस्तियां	4274	13260	-8986	9220	12330	-3110
2.3.1.2 देयताएं	23648	18787	4861	30548	21481	9067
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	21066	17485	3581	26041	20678	5363
2.3.2 अन्य	75	0	75	955	0	955
2.4 रुपया कर्ज चुकोती	0	7	-7		7	-7
2.5 अन्य पूंजी	15131	12280	2852	17978	15445	2533
3 भूल-घक	395	0	395	538	0	538
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	5579	-5579	0	30754	-30754
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां (वृद्धि - / कमी +)	0	5579	-5579		30754	-30754

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

## सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (पी)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	3223390	3177490	45899	4169720	3914381	255339
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1958005	1969160	-11155	2105253	2058074	47179
1.1 पण्य	952809	1385415	-432606	1010049	1432606	-422556
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	1005196	583745	421451	1095204	625468	469735
1.2.1 सेवाएं	706112	384660	321451	741908	387502	354406
1.2.1.1 यात्रा	69476	63331	6145	82705	66948	15758
1.2.1.2 परिवहन	65454	66565	-1111	64527	65002	-475
1.2.1.3 बीमा	6777	3740	3037	7699	5395	2304
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1185	2525	-1339	1073	2616	-1543
1.2.1.5 विविध	563219	248500	314719	585904	247541	338363
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	316497	33753	282744	344986	40752	304234
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	183122	134212	48910	187807	136067	51740
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	17215	10718	6497	13280	10537	2743
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	21041	18237	2804	4136	4197	-61
1.2.2 अंतरण	235693	31986	203706	266491	28049	238442
1.2.2.1 आधिकारिक	194	2810	-2616	423	2344	-1921
1.2.2.2 निजी	235499	29176	206322	266068	25705	240363
1.2.3 आय	63392	167098	-103707	86804	209917	-123113
1.2.3.1 निवेश आय	49444	159555	-110111	70763	201290	-130527
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	13948	7544	6404	16041	8627	7414
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1262134	1208330	53804	2060004	1856307	203698
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	689231	650644	38587	1317736	1206932	110803
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	428231	88268	52278	164679	148458	16220
2.1.1.1 भारत में	130453	53788	76665	158819	94741	64078
2.1.1.1.1 इक्विटी	79863	51450	28413	105963	90780	15183
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	40937	0	40937	44274	0	44274
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9652	2338	7315	8582	3960	4621
2.1.1.2 विदेश में	10093	34480	-24387	5860	53718	-47858
2.1.1.2.1 इक्विटी	10093	17465	-7372	5860	26638	-20778
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	9073	-9073	0	12009	-12009
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	7941	-7941	0	15071	-15071
2.1.2 संविभाग निवेश	548685	562376	-13691	1153057	1058474	94583
2.1.2.1 भारत में	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
2.1.2.1.1 एफआईआई	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	472831	493254	-20423	997608	931154	66454
2.1.2.1.1.2 ऋण	71080	63718	7363	149969	120285	29685
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	4774	5404	-631	5480	7035	-1555
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	218106	192973	25133	254894	240356	14538
2.2.1 बाह्य सहायता	26652	12519	14133	29784	12969	16816
2.2.1.1 भारत द्वारा	63	180	-117	66	255	-188
2.2.1.2 भारत को	26589	12339	14250	29718	12714	17004
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	60240	46876	13363	125478	111407	14071
2.2.2.1 भारत द्वारा	2237	3144	-907	28241	35769	-7528
2.2.2.2 भारत को	58003	43732	14271	97237	75638	21599
2.2.3 भारत को अल्पावधि	131214	133577	-2364	99631	115980	-16349
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	131214	112256	18958	99631	106817	-7185
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	21322	-21322	0	9163	-9163
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	230320	263635	-33315	338106	280721	57384
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	229701	263635	-33934	330180	280721	49459
2.3.1.1 आस्तियां	35162	109084	-73921	76548	102370	-25822
2.3.1.2 देयताएं	194539	154551	39988	253632	178351	75281
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	173302	143842	29461	216214	171683	44531
2.3.2 अन्य	619	0	619	7926	0	7926
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	60	-60	0	60	-60
2.5 अन्य पूंजी	124477	101018	23459	149269	128237	21033
3 भूल-चूक	3250	0	3250	4463	0	4463
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	45899	-45899	0	255339	-255339
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	45899	-45899	0	255339	-255339

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (पी)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)</b>	<b>238010</b>	<b>239346</b>	<b>-1336</b>	<b>253558</b>	<b>247857</b>	<b>5701</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)</b>	<b>201654</b>	<b>215166</b>	<b>-13512</b>	<b>211010</b>	<b>219218</b>	<b>-8208</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)</b>	<b>115821</b>	<b>168408</b>	<b>-52587</b>	<b>121652</b>	<b>172546</b>	<b>-50894</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	115268	161779	-46511	121353	162955	-41602
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	553	0	553	300	0	300
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	6629	-6629	0	9591	-9591
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>85833</b>	<b>46758</b>	<b>39075</b>	<b>89357</b>	<b>46672</b>	<b>42685</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इन्पुट पर विनिर्माण सेवाएं	327	52	275	352	18	335
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	56	644	-587	55	456	-401
1.अ.ख.3 परिवहन	7956	8091	-135	7772	7829	-57
1.अ.ख.4 यात्रा	8445	7698	747	9961	8063	1898
1.अ.ख.5 निर्माण	1099	705	394	1658	791	867
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	824	455	369	927	650	277
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2093	1303	790	1599	1269	330
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रमाण	290	2729	-2438	319	3365	-3046
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	41116	6606	34509	42137	5707	36430
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	22260	16314	5945	22620	16388	6232
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1045	1390	-346	1253	1496	-243
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	144	307	-163	129	315	-186
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	178	464	-286	575	324	251
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>7706</b>	<b>20312</b>	<b>-12606</b>	<b>10455</b>	<b>25283</b>	<b>-14828</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1695	917	778	1932	1039	893
1.आ.2 निवेश आय	4839	18772	-13934	6758	23566	-16808
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2156	10609	-8453	2518	13929	-11411
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	78	2755	-2676	94	2383	-2289
1.आ.2.3 अन्य निवेश	210	5246	-5035	874	7026	-6152
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	2393	163	2231	3272	229	3043
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1172	623	549	1765	678	1087
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>28650</b>	<b>3868</b>	<b>24782</b>	<b>32093</b>	<b>3356</b>	<b>28737</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तरेत निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	28627	3547	25080	32046	3096	28950
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	27984	2631	25352	31301	2324	28977
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	643	915	-272	745	772	-27
1.इ.2 सामान्य सरकार	23	321	-298	48	260	-212
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>272</b>	<b>260</b>	<b>12</b>	<b>182</b>	<b>138</b>	<b>44</b>
2.1 अनुत्पादित वित्तरेत आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	120	35	85	21	50	-30
2.2 पूंजी अंतरण	152	225	-73	161	87	74
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>153151</b>	<b>152222</b>	<b>929</b>	<b>247933</b>	<b>254216</b>	<b>-6283</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>17084</b>	<b>10730</b>	<b>6355</b>	<b>19834</b>	<b>17881</b>	<b>1954</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15858	6538	9319	19128	11411	7718
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14684	6254	8430	18095	10934	7161
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	9708	6254	3454	12762	10934	1829
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	4976	0	4976	5332	0	5332
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1173	284	889	1034	477	557
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1173	284	889	1034	477	557
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1227	4191	-2964	706	6470	-5764
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1227	3226	-1999	706	4655	-3949
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1227	2123	-896	706	3208	-2503
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	1103	-1103	0	1446	-1446
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	965	-965	0	1815	-1815
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	965	-965	0	1815	-1815
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>66697</b>	<b>68361</b>	<b>-1664</b>	<b>138877</b>	<b>127485</b>	<b>11392</b>
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	66117	67704	-1588	138217	126638	11579
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	57476	59959	-2483	120154	112150	8004
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	8640	7745	895	18063	14487	3575
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	580	657	-77	660	847	-187
<b>3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>3661</b>	<b>6332</b>	<b>-2671</b>	<b>6126</b>	<b>9280</b>	<b>-3154</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>65708</b>	<b>61219</b>	<b>4489</b>	<b>83096</b>	<b>68816</b>	<b>14280</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	21141	17485	3656	26996	20678	6318
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मुवमेंट; एनआरजी)	75	0	75	955	0	955
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	21066	17485	3581	26041	20678	5363
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	17418	21782	-4364	32426	28113	4313
3.4.3अ भारत को ऋण	17139	21378	-4239	29017	23774	5243
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	280	404	-125	3409	4339	-929
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	41	30	11	54	85	-31
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	15950	16237	-287	12000	13969	-1969
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	11157	5685	5472	11620	5972	5648
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>5579</b>	<b>-5579</b>	<b>0</b>	<b>30754</b>	<b>-30754</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5579	-5579	0	30754	-30754
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>153151</b>	<b>152222</b>	<b>929</b>	<b>247933</b>	<b>254216</b>	<b>-6283</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	77670	76458	1212	145795	137951	7844
4.2 ऋण लिखत	64323	64499	-176	90518	79539	10979
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	11157	11265	-107	11620	36725	-25105
<b>5. निवल भूल-शुद्ध</b>	<b>395</b>	<b>0</b>	<b>395</b>	<b>538</b>	<b>538</b>	<b>0</b>

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

## सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	जन.-मार्च 2023			जन.-मार्च 2024 (पी)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
<b>1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)</b>	<b>1958000</b>	<b>1968993</b>	<b>-10992</b>	<b>2105225</b>	<b>2057890</b>	<b>47336</b>
<b>1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)</b>	<b>1658921</b>	<b>1770076</b>	<b>-11155</b>	<b>1751957</b>	<b>1820108</b>	<b>-68150</b>
<b>1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)</b>	<b>952809</b>	<b>1385415</b>	<b>-432606</b>	<b>1010049</b>	<b>1432606</b>	<b>-422556</b>
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	948262	1330884	-382622	1007561	1352971	-345410
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4548	0	4548	2488	0	2488
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	54532	-54532	0	79635	-79635
<b>1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)</b>	<b>706112</b>	<b>384660</b>	<b>321451</b>	<b>741908</b>	<b>387502</b>	<b>354406</b>
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले मौलिक इन्पुट पर विनिर्माण सेवाएं	2689	425	2264	2923	146	2778
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	464	5295	-4831	455	3786	-3331
1.अ.ख.3 परिवहन	65454	66565	-1111	64527	65002	-475
1.अ.ख.4 यात्रा	69476	63331	6145	82705	66948	15758
1.अ.ख.5 निर्माण	9040	5797	3244	13763	6567	7196
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6777	3740	3037	7699	5395	2304
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	17215	10718	6497	13280	10537	2743
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	2389	22449	-20059	2648	27942	-25294
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	338240	54349	283891	349851	47384	302467
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	183122	134212	48910	187807	136067	51740
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	8596	11438	-2842	10404	12421	-2016
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1185	2525	-1339	1073	2616	-1543
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	1463	3817	-2354	4771	2691	2081
<b>1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)</b>	<b>63392</b>	<b>167098</b>	<b>-103707</b>	<b>86804</b>	<b>209917</b>	<b>-123113</b>
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	13948	7544	6404	16041	8627	7414
1.आ.2 निवेश आय	39805	154433	-114627	56107	195663	-139556
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	17740	87278	-69538	20904	115646	-94742
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	644	22661	-22016	782	19786	-19004
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1731	43156	-41425	7255	58332	-51077
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	19690	1338	18352	27166	1900	25266
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	9638	5122	4516	14656	5627	9029
<b>1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)</b>	<b>235688</b>	<b>31819</b>	<b>203869</b>	<b>266464</b>	<b>27865</b>	<b>238599</b>
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तलेख निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	235499	29176	206322	266068	25705	240363
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	230210	21647	208563	259885	19295	240591
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	5288	7529	-2241	6183	6410	-227
1.इ.2 सामान्य सरकार	189	2642	-2453	396	2160	-1764
<b>2. पूंजी खाता (2.1+2.2)</b>	<b>2237</b>	<b>2137</b>	<b>100</b>	<b>1509</b>	<b>1144</b>	<b>364</b>
2.1 अनुयायित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	986	288	698	171	419	-248
2.2 पूंजी अंतरण	1250	1849	-599	1338	725	613
<b>3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)</b>	<b>1259902</b>	<b>1252260</b>	<b>7643</b>	<b>2058523</b>	<b>2110686</b>	<b>-52163</b>
<b>3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)</b>	<b>140546</b>	<b>88268</b>	<b>52278</b>	<b>164679</b>	<b>16220</b>	<b>148458</b>
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	130453	53788	76665	158819	94741	64078
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	120800	51450	69350	150237	90780	59457
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	79863	51450	28413	105963	90780	15183
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	40937	0	40937	44274	0	44274
3.1.अ.2 ऋण लिखत	9652	2338	7315	8582	3960	4621
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	9652	2338	7315	8582	3960	4621
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	10093	34480	-24387	5860	53718	-47858
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	10093	26539	-16446	5860	38647	-32787
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	10093	17465	-7372	5860	26638	-20778
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	9073	-9073	0	12009	-12009
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	7941	-7941	0	15071	-15071
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	7941	-7941	0	15071	-15071
<b>3.2 संविभाग निवेश</b>	<b>548685</b>	<b>562376</b>	<b>-13691</b>	<b>1153057</b>	<b>1058474</b>	<b>94583</b>
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	543912	556972	-13060	1147577	1051439	96139
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	472831	493254	-20423	997608	931154	66454
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	71080	63718	7363	149969	120285	29685
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	4774	5404	-631	5480	7035	-1555
<b>3.3 वित्तीय डेबिटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन</b>	<b>30121</b>	<b>52094</b>	<b>-21973</b>	<b>50865</b>	<b>77053</b>	<b>-26187</b>
<b>3.4 अन्य निवेश</b>	<b>540550</b>	<b>503623</b>	<b>36927</b>	<b>689922</b>	<b>571362</b>	<b>118560</b>
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	173921	143842	30080	224139	171683	52457
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मुवमेंट; एनआरजी)	619	0	619	7926	0	7926
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	173302	143842	29461	216214	171683	44531
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	143291	179189	-35898	269228	233414	35814
3.4.3अ भारत को ऋण	140991	175865	-34873	240921	197391	43530
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2300	3324	-1024	28307	36024	-7717
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	337	245	92	448	704	-257
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	131214	133577	-2364	99631	115980	-16349
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	91787	46770	45017	96475	49580	46895
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
<b>3.5 आरक्षित आस्तियां</b>	<b>0</b>	<b>45899</b>	<b>-45899</b>	<b>0</b>	<b>255339</b>	<b>-255339</b>
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	45899	-45899	0	255339	-255339
<b>4. कुल आस्तियां / देयताएं</b>	<b>1259902</b>	<b>1252260</b>	<b>7643</b>	<b>2058523</b>	<b>2110686</b>	<b>-52163</b>
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	638957	628987	9970	1210498	1145373	65124
4.2 ऋण लिखत	529159	530604	-1445	751550	660393	91157
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	91787	92669	-883	96475	304919	-208444
<b>5. निवल भूल-भूक</b>	<b>3250</b>	<b>0</b>	<b>3250</b>	<b>4463</b>	<b>0</b>	<b>4463</b>

टिप्पणी: प्रा: प्रांभिक

## सं. 42: भारत के अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023				2024	
			मार्च		दिसं.		मार्च	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542516	225592	523322	236506	536795	242271	542516
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	142071	493896	149394	505572	153343	511142
1.2 अन्य पूंजी	88927	31374	83521	29426	87112	31223	88927	31374
2. संविभाग निवेश	10286	283804	13106	243561	10661	269154	10286	283804
2.1 इक्विटी	8518	168679	7449	138958	8438	161206	8518	168679
2.2 ऋण	1768	115126	5657	104603	2223	107948	1768	115126
3. अन्य निवेश	129328	563664	101420	518847	120558	552330	129328	563664
3.1 व्यापार ऋण	33450	118598	27507	124304	31689	120355	33450	118598
3.2 ऋण	13578	221964	9256	202334	14845	215009	13578	221964
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	52803	154787	33046	141133	44452	149326	52803	154787
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	29497	46404	31612	28815	29572	45438	29497	46404
4. आरक्षित निधियाँ	646419		578449		622452		646419	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1028304	1389984	918567	1285729	990178	1358280	1028304	1389984
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-361680		-367162		-368102		-361680

टिप्पणी: \* इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

## भुगतान और निपटान प्रणाली

## सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

## भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	वि. व. 2023-24	2023		2024		FY 2023-24	2023		2024	
		मई	अप्रै.	मई	अप्रै.		मई	अप्रै.	मई	
	1	-2	-1	0	5	2	3	4		
<b>ए. निपटान प्रणाली</b>										
<b>वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>										
<b>1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)</b>	43.04	4.03	3.53	4.07	259206893	22537634	22115118	22018913		
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	16.80	1.63	1.25	1.60	170464587	15227196	14132535	14632648		
1.1.1 आजटराइट	9.51	0.98	0.68	0.98	13463848	1326724	1023439	1363203		
1.1.2 रेपो	4.94	0.45	0.38	0.43	76718788	7732270	6510577	6669493		
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.19	0.19	80281951	6168201	6598519	6599952		
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.23	2.17	2.37	80984671	6189356	7343662	6780829		
1.3 रुपये डेरिवेटिव @	1.31	0.17	0.11	0.10	7757636	1121082	638922	605436		
<b>बी. भुगतान प्रणाली</b>										
<b>I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
<b>1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)</b>	2700.16	220.46	235.59	249.71	170886670	12882587	14433296	15186947		
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	219.21	234.46	248.49	152406168	11413321	12800746	13559606		
1.2 अंतर्बैंक लेनदेन	14.12	1.25	1.12	1.22	18480503	1469266	1632550	1627340		
<b>II खुदरा</b>										
<b>2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)</b>	1486106.89	107130.93	149083.29	156773.59	67542859	5196720	5845989	6279019		
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.34	0.29	0.31	261	23	19	18		
2.2 एपीबीएस \$	25888.17	1838.94	2535.32	2295.50	390743	31424	36959	37499		
2.3 आईएमपीएस	60053.35	5015.49	5503.65	5576.99	6495652	527558	592279	606167		
2.4 एनएसीएच जमा \$	16227.27	1227.66	964.06	1074.61	1525104	122239	121718	132404		
2.5 एनईएफटी	72639.50	4896.66	7040.03	7467.75	39136014	3026331	3130549	3457995		
2.6 यूपीआई @	1311294.68	94151.85	133039.94	140358.43	19995086	1489145	1964465	2044937		
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	1.75	1.52	1.62	352	21	18	17		
<b>3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)</b>	18249.53	1457.43	1644.10	1698.67	1687658	125654	159006	167035		
3.1 भीम आधार पे @	193.59	15.45	20.50	19.33	6112	535	563	506		
3.2 एनएसीएच नामे \$	16426.49	1288.88	1494.37	1539.23	1678769	124864	158223	166305		
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	153.10	129.23	140.11	2777	256	220	225		
<b>4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)</b>	58469.79	4974.51	4960.12	5105.17	2423563	193436	200409	208520		
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	2734.74	3441.51	3601.36	1831134	140660	156498	164955		
4.1.1 पीओएस आधारित \$	18614.08	1419.98	1843.36	1906.58	651911	50811	61982	63831		
4.1.2 अन्य \$	16996.08	1314.76	1598.15	1694.78	1179223	89849	94516	101124		
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.2)	22859.64	2239.77	1518.61	1503.82	592429	52776	43911	43565		
4.2.1 पीओएस आधारित \$	16477.95	1592.87	1126.33	1114.38	393589	35589	30022	29772		
4.2.2 अन्य \$	6381.69	646.89	392.28	389.44	198840	17187	13889	13793		
<b>5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)</b>	78775.40	7064.30	5288.79	5496.00	283048	24240	14964	16697		
5.1 वालेट	63256.69	5669.85	3993.29	4204.49	234353	20339	10507	11566		
<b>5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)</b>	15518.71	1394.45	1295.49	1291.51	48695	3901	4457	5131		
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8429.87	721.63	695.13	689.94	11247	1190	962	1027		
5.2.2 अन्य \$	7088.84	672.82	600.37	601.57	37447	2711	3495	4104		
<b>6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)</b>	6632.10	572.39	525.73	524.39	7212333	627772	667829	611518		
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	572.39	525.73	524.39	7212333	627772	667829	611518		
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-		
<b>कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	1648233.71	121199.56	161502.02	169597.82	79149461	6167822	6888198	7282789		
<b>कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)</b>	1650933.88	121420.02	161737.61	169847.53	250036131	19050409	21321494	22469736		
<b>कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)</b>	1644301.78	120847.63	161211.88	169323.14	242823799	18422637	20653665	21858218		

### भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2023-24	2023	2024		वित्तीय वर्ष 2023-24	2023	2024	
		मई	अप्रै.	मई		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ए. अन्य भुगतान चैनल</b>								
<b>1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)</b>	1252599.21	87100.70	128494.90	134522.21	30687088	2268479	2993601	3126317
1.1 अंतर्बैंक \$	83000.56	6127.73	8743.81	9224.51	5676805	424314	566077	585196
1.2 अंतर-बैंक \$	1169598.65	80972.97	119751.09	125297.71	25010283	1844165	2427524	2541120
<b>2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)</b>	45034.98	3598.99	3756.42	3771.12	102117736	7800962	8807528	8705212
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	916.90	964.52	1010.25	53247042	4116658	4498614	4276566
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2682.09	2791.90	2760.86	48870694	3684304	4308914	4428645
<b>बी. एटीएम</b>								
<b>3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)</b>	66440.72	5694.72	5240.40	5166.41	3259388	279621	265905	260240
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	95.80	7.73	9.07	8.63	4648	366	458	441
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	66001.01	5655.91	5207.60	5133.52	3241538	278080	264457	258785
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	343.90	31.09	23.73	24.26	13202	1175	990	1014
<b>4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)</b>	15.18	2.33	0.52	0.33	148	23	5	3
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	15.06	2.31	0.50	0.31	147	23	5	3
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.12	0.02	0.02	0.02	1	0	0	0
<b>5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @</b>	11754.95	979.64	919.05	879.79	314003	27469	24502	22804
5.1 ईपीएस @	11754.95	979.64	919.05	879.79	314003	27469	24502	22804

### भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024 तक	2023	2024	
		मई	अप्रै.	मई
	1	2	3	4
<b>भुगतान प्रणाली अवसंरचना</b>				
<b>1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)</b>	10667.22	10616.74	10719.55	10780.74
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	877.47	1025.40	1033.00
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9739.26	9694.15	9747.74
<b>2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)</b>	16743.63	16638.55	14716.82	14829.77
2.1 वालेट @	13381.80	13373.56	11294.83	11302.14
2.2 कार्ड @	3361.82	3264.98	3421.99	3527.63
<b>3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)</b>	2.58	2.56	2.57	2.57
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.20	2.23	2.22
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.35	0.36	0.35	0.36
<b>4 माइक्रो एटीएम की संख्या @</b>	17.55	14.66	17.37	15.62
<b>5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या</b>	89.03	79.61	88.39	88.04
<b>6 भारत क्यूआर @</b>	62.50	55.45	60.73	61.21
<b>7 यूपीआई क्यूआर *</b>	3462.03	2667.57	3195.01	3300.27

@: नवंबर 2019 से नया समावेश  
 #: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।  
 \$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मंदों का हिस्सा रहा होगा।  
 \*: सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।  
 टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।  
 1. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।  
 2. कार्ड फेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड फेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।  
 3. केवल फेमेंट वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, घातक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।  
 भाग I-ए. निपटान प्रणाली  
 1.1.3. प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-महीने के 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।  
 भाग I-बी. भुगतान प्रणाली  
 4.1.2. 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।  
 4.2.2. 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।  
 5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।  
 5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल है।  
 5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।  
 6.1: तीन घिड़ों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।  
 6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।  
 भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल  
 1: मोबाइल भुगतान -  
 4: बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।  
 5: जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।  
 2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।  
 भाग II-बी. एटीएम  
 3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।  
 भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना  
 3: अनुसूचित बाणिज्यिक बैंकों (एसबीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

# आवसरिक शृंखला

## सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

योजना		2022-23	2023		2024	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
<b>1. लघु बचत</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>173993</b>	<b>11210</b>	<b>16670</b>	<b>16076</b>	<b>14570</b>
	<b>बकाया</b>	<b>1636935</b>	<b>1599193</b>	<b>1789946</b>	<b>1805716</b>	<b>1819758</b>
<b>1.1 कुल जमाराशियां</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>125209</b>	<b>8093</b>	<b>12386</b>	<b>11340</b>	<b>10025</b>
	<b>बकाया</b>	<b>1137451</b>	<b>1113230</b>	<b>1247555</b>	<b>1258895</b>	<b>1268920</b>
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	20680	1170	2279	3014	1520
	बकाया	209112	200257	213964	216978	218498
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	29003	1965	2171	2130	2233
	बकाया	87787	77472	104859	106989	109222
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-244	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-20	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	6492	484	1713	1895	1927
	बकाया	242313	242198	263383	265278	267205
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	17971	1475	2197	2290	2153
	बकाया	137304	135986	169033	171323	173476
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	29155	1814	2429	2379	2632
	बकाया	280436	278939	297989	300368	303000
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	125951	125377	135196	136762	138552
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	9497	9282	11265	11483	11730
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7543	7380	8472	8628	8782
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	137445	136900	143056	143495	143936
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	21552	1203	1616	-344	-420
	बकाया	178422	176836	196491	196147	195727
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	288	-18	-19	-24	-20
	बकाया	1745	1439	1488	1464	1444
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	332	0	0	0	0
	बकाया	332	103	348	348	348
<b>1.2 बचत प्रमाणपत्र</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>33965</b>	<b>2504</b>	<b>3957</b>	<b>4247</b>	<b>3940</b>
	<b>बकाया</b>	<b>366317</b>	<b>363564</b>	<b>407244</b>	<b>411185</b>	<b>414597</b>
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	10793	658	1213	1581	1446
	बकाया	165836	164750	177154	178735	180181
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-1892	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	25064	1846	1568	1561	1428
	बकाया	199624	197646	216509	218070	219498
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	0	0	1176	1105	1066
	बकाया	0	0	15064	16169	17235
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	857	1168	-1483	-1789	-2317
<b>1.3 लोक भविष्य निधि</b>	<b>प्राप्तियां</b>	<b>14819</b>	<b>613</b>	<b>327</b>	<b>489</b>	<b>605</b>
	<b>बकाया</b>	<b>133167</b>	<b>122399</b>	<b>135147</b>	<b>135636</b>	<b>136241</b>

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं, अर्थात् सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023				2024
	मार्च	जून	सितं.	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(क) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>9645776</b>	<b>9898751</b>	<b>10383607</b>	<b>10538792</b>	<b>10740389</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	36.61	36.58	37.96	37.55	37.66
2. सहकारी बैंक	1.64	1.56	1.52	1.49	1.47
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.49	0.73	0.66	0.67	0.66
4. बीमाकृत कंपनियां	25.97	26.21	26.05	26.16	25.98
5. म्यूच्युअल फंड	2.81	2.69	3.02	3.03	2.90
6. भविष्य निधियां	4.71	4.59	4.42	4.57	4.47
7. पेंशन निधि	3.98	4.18	4.32	4.44	4.52
8. वित्तीय संस्थाएं	0.98	1.20	0.54	0.55	0.55
9. कॉरपोरेट	1.62	1.22	1.21	1.33	1.35
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.36	1.59	1.61	1.92	2.34
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	14.26	13.78	13.06	12.54	12.31
12. अन्य	5.57	5.67	5.64	5.74	5.79
12.1 राज्य सरकार	2.03	2.03	2.04	2.07	2.04

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023				2024
	मार्च	जून	सितं.	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(ख) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>4929079</b>	<b>5050874</b>	<b>5161642</b>	<b>5338587</b>	<b>5646219</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	33.91	34.13	33.87	33.90	34.14
2. सहकारी बैंक	3.64	3.68	3.60	3.53	3.39
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.62	0.50	0.61	0.63	0.60
4. बीमाकृत कंपनियां	26.80	26.73	26.97	26.64	26.14
5. म्यूच्युअल फंड	1.94	2.08	1.86	2.00	2.09
6. भविष्य निधियां	21.29	21.19	21.70	22.00	22.35
7. पेंशन निधि	4.81	4.84	4.82	4.56	4.76
8. वित्तीय संस्थाएं	1.84	1.82	1.65	1.63	1.59
9. कॉरपोरेट	2.00	1.92	1.87	2.03	2.02
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.72	0.70	0.69	0.66	0.63
12. अन्य	2.42	2.39	2.34	2.37	2.20
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2023				2024
	मार्च	जून	सितं.	दिसं.	मार्च
	1	2	3	4	5
<b>(ग) कुल (₹ करोड़ में)</b>	<b>823313</b>	<b>1012301</b>	<b>925317</b>	<b>849151</b>	<b>871662</b>
1. वाणिज्यिक बैंक	53.92	47.64	56.35	57.18	58.53
2. सहकारी बैंक	1.29	1.20	1.20	1.28	1.67
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	2.85	1.99	0.54	1.70	1.66
4. बीमाकृत कंपनियां	6.11	4.93	5.26	5.50	5.06
5. म्यूच्युअल फंड	15.30	17.04	12.74	11.21	11.89
6. भविष्य निधियां	0.10	1.46	1.52	0.08	0.15
7. पेंशन निधि	0.07	0.01	0.01	0.00	0.01
8. वित्तीय संस्थाएं	3.72	7.96	4.10	5.34	7.16
9. कॉरपोरेट	4.99	4.42	4.00	4.58	4.50
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.40	0.12	0.10	0.07	0.01
11. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	11.25	13.23	14.17	13.06	9.36
12.1 राज्य सरकार	7.16	10.33	11.36	9.26	5.88

नोट: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

## सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (सं.अ.)	2023-24 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
<b>1. कुल वितरण</b>	<b>5040747</b>	<b>5410887</b>	<b>6353359</b>	<b>7098451</b>	<b>8376972</b>	<b>9045119</b>
1.1 विकास संबंधी	2882758	3074492	3823423	4189146	5073367	5426440
1.1.1 राजस्व	2224367	2446605	3150221	3255207	3838714	3836447
1.1.2 पूंजी	596774	588233	550358	861777	1146013	1471534
1.1.3 ऋण	61617	39654	122844	72163	88639	118460
1.2 गैर-विकास संबंधी	2078276	2253027	2442941	2810388	3188699	3490946
1.2.1 राजस्व	1965907	2109629	2271637	2602750	2988556	3277722
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	894520	955801	1060602	1226672	1403183	1589435
1.2.2 पूंजी	111029	141457	169155	175519	196688	208268
1.2.3 ऋण	1340	1941	2148	32119	3455	4957
1.3 अन्य	79713	83368	86995	98916	114906	127733
<b>2. कुल प्राप्तियां</b>	<b>5023352</b>	<b>5734166</b>	<b>6397162</b>	<b>7156342</b>	<b>8258187</b>	<b>9149787</b>
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3797731	3851563	3688030	4823821	5706246	6337126
2.1.1 कर प्राप्तियां	3278947	3231582	3193390	4160414	4837048	5477428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2030050	2012578	2076013	2626553	2967610	3372525
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1246083	1216203	1114805	1530636	1865298	2100430
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2814	2800	2572	3225	4140	4473
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	518783	619981	494640	663407	869198	859698
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	36273	31137	33448	35250	37974	45199
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	140287	110094	64994	44077	88273	119373
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	44667	59515	16951	27665	25661	34501
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	95621	50578	48044	16412	62611	84872
<b>3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]</b>	<b>1102729</b>	<b>1449230</b>	<b>2600335</b>	<b>2230553</b>	<b>2582453</b>	<b>2588620</b>
<b>3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार</b>						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	387091	571872	890012	627255	687904	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	325987	190241	107493	350911	529	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	710119	868676	1640143	1567151	1870675	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
<b>3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार</b>						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1097210	1440548	2530155	2194406	2558579	2566503
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	795845	971378	1696012	1213169	1776747	1902862
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	88961	209232	458801	526693	403838	441189
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	51004	38280	41273	28100	36454	37114
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-18298	10411	4545	42153	3524	24429
3ख.1.5 जमा राशियां और अग्रिम	66289	-14227	25682	42203	82485	58404
3ख.1.6 नकद शेष	17395	-323279	-43802	-57891	118784	-104667
3ख.1.7 अन्य	96014	548753	347643	399980	136748	207172
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	5519	8682	70180	36147	23874	22118
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	26.7	26.9	32.0	30.1	31.1	30.0
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	26.6	28.5	32.2	30.3	30.6	30.3
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	20.1	19.2	18.6	20.4	21.2	21.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	17.3	16.1	16.1	17.6	17.9	18.2
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	5.8	7.2	13.1	9.5	9.6	8.6

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2023-24 के लिए जीडीपी केन्द्रीय बजट 2023-24 से है।

डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।

1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायतों राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।

2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।

3ए.1.1: आरबीआई रिकॉर्ड के अनुसार डेटा।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।

3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।

नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थापय अग्रिम शामिल हैं।

3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

## सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मई 2024 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	876.55	28	1402.47	21	1913.20	7
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	546.42	6	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	29.25	2	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	255.39	5	-	-
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	-	-	922.72	29	427.45	21
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	337.06	30	1006.89	30	467.15	5
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	15.43	28	165.66	28	72.14	9
17	मेघालय	195.55	9	115.42	8	-	-
18	मिज़ोरम	18.74	1	-	-	-	-
19	नगालैंड	94.45	6	49.04	4	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	1985.01	31	902.88	27	703.77	16
23	राजस्थान	7442.82	31	517.05	14	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	895.15	30	1104.34	29	684.01	10
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	250.88	19	163.87	5	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

- टिप्पणीयां :**
- 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
  - 2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
  - 3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
  - 4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
  - 5) -: नगण्य

**स्रोत :** भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मई 2024 की समाप्ति पर			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	10980	1083	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2518	6	0	500
3	असम	6490	86	0	0
4	बिहार	10349	-	0	5700
5	छत्तीसगढ़	7406	60	1	4661
6	गोवा	996	434	0	0
7	गुजरात	13576	634	0	11000
8	हरियाणा	2214	1616	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	0	0	0	0
11	झारखंड	2282	-	0	750
12	कर्नाटक	17346	527	0	47128
13	केरल	2957	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1215	0	0
15	महाराष्ट्र	66308	1656	0	0
16	मणिपुर	66	133	0	0
17	मेघालय	1208	103	0	0
18	मिज़ोरम	436	60	0	0
19	नगालैंड	1692	44	0	0
20	उड़ीसा	17218	1941	111	4092
21	पुदुचेरी	551	-	0	1500
22	पंजाब	8719	0	0	0
23	राजस्थान	-	-	129	9250
24	तमिलनाडु	3256	-	0	3995
25	तेलंगाना	7493	1640	0	0
26	त्रिपुरा	1160	25	0	325
27	उत्तरप्रदेश	4770	201	0	0
28	उत्तराखंड	7734	-	89	0
29	पश्चिम बंगाल	12332	931	239	0
	<b>कुल</b>	<b>210058</b>	<b>12394</b>	<b>569</b>	<b>88900</b>

- टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।  
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।  
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

## सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियां

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2023-24		2024-25				2024-25 में ली गई कुल राशि	
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	मार्च		एप्रिल		मई		सकल	निवल
						ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	-	-1750	7000	4834	14000	11084	21000	15918
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	232	182	-	-96	-	-50	-	-146
3	असम	17100	16105	18500	16000	2500	1000	1000	1000	2000	2000	3000	3000
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	3612	2488	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	10000	8913	-	-	-	-500	-	-500
6	गोवा	1350	500	2550	1560	250	160	-	-100	-	-	-	-100
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	-	-1500	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	8500	3350	1000	1000	2000	1000	3000	2000
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	1772	1772	1000	450	700	500	1700	950
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	1204	810	-	-300	2500	2350	2500	2050
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-1055	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	21000	21000	-	-	-	-1500	-	-1500
13	केरल	30839	15620	42438	26638	13608	12008	1000	-1000	5500	3800	6500	2800
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	-	-5236	-	-	-	-1000	-	-1000
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	30000	30000	10000	8900	-	-2200	10000	6700
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	326	176	-	-	200	200	200	200
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	-	-93	100	100	200	200	300	300
18	मिज़ोरम	1315	1129	901	641	81	81	-	-20	200	180	200	160
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	400	355	-	-135	-	-65	-	-200
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-	-	-500	-	-	-	-500
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	500	500	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	-	-1686	5500	3800	5700	4900	11200	8700
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	14575	8625	-	-1000	10500	9000	10500	8000
24	सिक्कीम	1414	1320	1916	1701	485	450	-	-	-	-	-	-
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	22000	18369	5000	1000	8000	5500	13000	6500
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	7718	5575	4000	3166	4000	916	8000	4082
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-200	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	34500	31472	-	-2000	-	-1000	-	-3000
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	2500	1500	900	900	-	-	900	900
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	17000	16000	-	-1800	2000	200	2000	-1600
	कुल	758392	518829	1007058	717140	192763	153267	36500	18199	57500	35515	94000	53714

- : शून्य.

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2020-21				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	583412.7	554437.6	463583.5	679174.4	2280608.2
जीडीपी का प्रतिशत	15.0	11.7	8.5	11.8	11.5
<b>I. वित्तीय आस्तियां</b>	<b>788786.3</b>	<b>592945.3</b>	<b>633317.9</b>	<b>1047276.1</b>	<b>3062325.6</b>
जीडीपी का प्रतिशत	20.3	12.5	11.6	18.2	15.4
जिसमें:					
<b>1. कुल जमाराशियां (ए+बी)</b>	<b>297412.4</b>	<b>278631.7</b>	<b>158172.2</b>	<b>506213.3</b>	<b>1240429.7</b>
(ए) बैंक जमाराशि	281191.3	264565.3	147096.0	507719.3	1200571.8
i. वाणिज्यिक बैंक	279010.5	262033.7	143558.6	462689.8	1147292.5
ii. सहकारी बैंक	2180.8	2531.6	3537.3	45029.5	53279.3
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	16221.1	14066.4	11076.3	-1506.0	39857.9
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	11040.9	8886.2	5896.0	-6686.2	19137.0
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	1441.0	3763.0	3514.8	3521.2	12240.0
ii. आवास वित्त कंपनियां	9599.9	5123.2	2381.3	-10207.3	6897.0
<b>2. जीवन बीमा निधियाँ</b>	<b>124387.9</b>	<b>143462.2</b>	<b>157535.1</b>	<b>142216.5</b>	<b>567601.8</b>
<b>3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)</b>	<b>114496.3</b>	<b>107087.9</b>	<b>105344.6</b>	<b>175769.3</b>	<b>502698.2</b>
<b>4. मुद्रा</b>	<b>202432.7</b>	<b>21286.9</b>	<b>91456.0</b>	<b>66800.5</b>	<b>381976.1</b>
<b>5. निवेश</b>	<b>6249.8</b>	<b>-12956.4</b>	<b>67659.3</b>	<b>63624.0</b>	<b>124576.7</b>
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	-16021.0	-28837.7	57675.4	51267.0	64083.8
(बी) इक्विटी	18599.4	8291.5	5307.1	6333.3	38531.2
<b>6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)</b>	<b>42751.6</b>	<b>54377.4</b>	<b>52095.1</b>	<b>91597.0</b>	<b>240821.1</b>
<b>II. वित्तीय देयताएँ</b>	<b>205373.6</b>	<b>38507.7</b>	<b>169734.4</b>	<b>368101.7</b>	<b>781717.4</b>
जीडीपी का प्रतिशत	5.3	0.8	3.1	6.4	3.9
<b>ऋण (उधार)</b>					
<b>1. वित्तीय निगम (ए+बी)</b>	<b>205490.3</b>	<b>38624.3</b>	<b>169851.0</b>	<b>368219.1</b>	<b>782184.7</b>
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	211058.8	13213.0	139622.0	276579.8	640473.6
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	211259.3	13213.8	140514.3	240050.4	605037.9
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-5568.6	25411.3	30229.0	91639.4	141711.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-15450.4	21627.1	15921.2	64881.1	86979.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	10516.6	2875.1	13048.5	25336.1	51776.2
iii. बीमा कंपनियाँ	-634.8	909.2	1259.3	1422.2	2955.9
<b>2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)</b>	<b>33.8</b>	<b>33.8</b>	<b>33.8</b>	<b>33.0</b>	<b>134.4</b>
<b>3. सामान्य सरकार</b>	<b>-150.4</b>	<b>-150.4</b>	<b>-150.4</b>	<b>-150.4</b>	<b>-601.7</b>

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	370115.8	334234.9	489774.4	503089.0	1696155.6
जीडीपी का प्रतिशत	7.2	6.0	7.9	7.7	7.2
I. वित्तीय आस्तियां	364661.7	527896.1	818355.4	887657.3	2597511.9
जीडीपी का प्रतिशत	7.1	9.4	13.1	13.6	11.1
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	-82726.1	204033.6	426977.3	277625.7	824852.1
(ए) बैंक जमाराशि	-106428.9	197105.1	422392.9	264882.9	777952.1
i. वाणिज्यिक बैंक	-107940.7	195441.8	418267.0	262326.1	768094.3
ii. सहकारी बैंक	1511.8	1663.4	4125.9	2556.8	9857.8
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	23702.8	6928.5	4584.5	12742.8	46900.0
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	16950.0	170.7	-2178.3	5960.0	20902.3
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4972.6	-765.5	73.3	4211.8	8492.2
ii. आवास वित्त कंपनियां	11977.3	936.2	-2251.6	1748.2	12410.1
2. जीवन बीमा निधियाँ	114711.5	127449.8	103248.6	121541.6	466951.5
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	127624.0	115463.1	98146.0	221372.4	562605.5
4. मुद्रा	128660.2	-68631.2	62793.3	146845.0	269667.4
5. निवेश	24929.6	82305.4	69760.9	50972.1	227967.9
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14573.0	63151.3	37912.2	44963.7	160600.1
(बी) इक्विटी	4502.5	13218.5	27808.2	3084.1	48613.3
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	50405.2	66218.1	56372.0	68243.2	241238.4
II. वित्तीय देयताएँ	-5454.1	193661.2	328581.0	384568.3	901356.3
जीडीपी का प्रतिशत	-0.1	3.5	5.3	5.9	3.8
ऋण (उधार)					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	-5562.3	193553.0	328472.8	384460.1	900923.7
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	21436.5	138722.6	267950.7	348360.4	776470.2
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26978.6	140268.7	265271.5	337009.8	769528.5
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	-26998.8	54830.4	60522.2	36099.7	124453.5
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	-34757.9	28876.8	29476.5	-2163.2	21432.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7132.0	24403.8	29494.8	37436.2	98466.8
iii. बीमा कंपनियाँ	627.1	1549.8	1550.9	826.7	4554.5
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	33.8	33.8	33.8	33.8	135.1
3. सामान्य सरकार	74.4	74.4	74.4	74.4	297.4

## सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				वार्षिक
	ति1	ति2	ति3	ति4	
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	297770.4	293705.1	279460.1	505937.8	1376873.5
जीडीपी का प्रतिशत	4.6	4.5	4.0	7.0	5.1
<b>I. वित्तीय आस्तियां</b>	<b>586920.5</b>	<b>646714.8</b>	<b>750856.7</b>	<b>974558.5</b>	<b>2959050.5</b>
जीडीपी का प्रतिशत	9.0	9.8	10.8	13.6	10.9
जिसमें:					
<b>1. कुल जमाराशियां (ए+बी)</b>	<b>183072.0</b>	<b>315216.2</b>	<b>276593.9</b>	<b>324746.6</b>	<b>1099628.6</b>
(ए) बैंक जमाराशि	163162.9	299545.0	256363.7	307491.6	1026563.1
i. वाणिज्यिक बैंक	158613.3	300565.0	248459.8	284968.0	992606.2
ii. सहकारी बैंक	4549.6	-1020.1	7903.8	22523.6	33956.9
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	19909.1	15671.3	20230.2	17255.0	73065.5
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	6314.4	2076.7	6635.6	3660.4	18687.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4040.2	3267.2	1800.9	5372.2	14480.5
ii. आवास वित्त कंपनियां	2274.2	-1190.5	4834.7	-1711.8	4206.6
<b>2. जीवन बीमा निधियाँ</b>	<b>73669.9</b>	<b>152049.5</b>	<b>167894.1</b>	<b>141206.6</b>	<b>534820.1</b>
<b>3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)</b>	<b>155604.2</b>	<b>132126.0</b>	<b>140204.4</b>	<b>235093.2</b>	<b>663027.7</b>
<b>4. मुद्रा</b>	<b>66438.9</b>	<b>-54579.3</b>	<b>76760.1</b>	<b>148990.2</b>	<b>237609.8</b>
<b>5. निवेश</b>	<b>51603.2</b>	<b>48630.6</b>	<b>49879.2</b>	<b>64168.5</b>	<b>214281.5</b>
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35443.5	44484.0	40205.9	58954.5	179087.8
(बी) इक्विटी	13560.9	1378.2	6434.1	1664.9	23038.1
<b>6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)</b>	<b>54375.1</b>	<b>51114.5</b>	<b>37367.7</b>	<b>58196.2</b>	<b>201053.5</b>
<b>II. वित्तीय देयताएँ</b>	<b>289150.0</b>	<b>353009.7</b>	<b>471396.5</b>	<b>468620.7</b>	<b>1582177.0</b>
जीडीपी का प्रतिशत	4.4	5.4	6.8	6.5	5.8
<b>ऋण (उधार)</b>					
<b>1. वित्तीय निगम (ए+बी)</b>	<b>289141.6</b>	<b>353001.2</b>	<b>471388.1</b>	<b>468612.3</b>	<b>1582143.3</b>
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	234845.3	263782.5	368167.4	349555.0	1216350.1
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	230283.8	261265.3	365304.6	331292.5	1188146.3
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	54296.3	89218.8	103220.8	119057.3	365793.1
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	29281.6	54439.6	75878.8	80295.9	239895.9
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22336.7	33031.2	24903.3	36745.8	117017.0
iii. बीमा कंपनियाँ	2678.0	1747.9	2438.7	2015.6	8880.3
<b>2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)</b>	<b>33.7</b>	<b>33.7</b>	<b>33.7</b>	<b>33.7</b>	<b>135.0</b>
<b>3. सामान्य सरकार</b>	<b>-25.3</b>	<b>-25.3</b>	<b>-25.3</b>	<b>-25.3</b>	<b>-101.3</b>

- टिप्पणियाँ:** 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसंपत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
2. 2022-23 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2021-22 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2022-23 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## 50(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
<b>वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)</b>	<b>20405824.2</b>	<b>21066027.8</b>	<b>21906338.5</b>	<b>22874301.5</b>
<i>जीडीपी का प्रतिशत</i>	<i>107.2</i>	<i>111.5</i>	<i>114.0</i>	<i>115.4</i>
<b>(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)</b>	<b>9977865.6</b>	<b>10242430.9</b>	<b>10389526.9</b>	<b>10897246.1</b>
i. वाणिज्यिक बैंक	9192702.5	9454736.2	9598294.8	10060984.6
ii. सहकारी बैंक	785163.1	787694.7	791232.1	836261.6
<b>(बी) गैर-बैंक जमा</b>				
<i>जिसमें से:</i>				
<b>अन्य वित्तीय संस्थान</b>	<b>180857.4</b>	<b>189743.6</b>	<b>195639.6</b>	<b>188953.5</b>
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	51463.0	55226.1	58740.8	62262.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	129394.4	134517.6	136898.8	126691.5
<b>(सी) जीवन बीमा निधि</b>	<b>4102000.7</b>	<b>4274424.9</b>	<b>4551882.0</b>	<b>4752932.3</b>
<b>(डी) मुद्रा</b>	<b>2434693.7</b>	<b>2455980.6</b>	<b>2547436.6</b>	<b>2614237.0</b>
<b>(ई) म्यूचुअल फंड</b>	<b>1343752.0</b>	<b>1443784.4</b>	<b>1648999.0</b>	<b>1730461.0</b>
<b>(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)</b>	<b>663478.0</b>	<b>671884.3</b>	<b>678997.2</b>	<b>742189.5</b>
<b>(जी) पेंशन निधि</b>	<b>464705.0</b>	<b>494930.0</b>	<b>548913.0</b>	<b>578025.0</b>
<b>(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)</b>	<b>1238471.7</b>	<b>1292849.1</b>	<b>1344944.2</b>	<b>1370257.1</b>
<b>वित्तीय देयताएँ (ए+बी)</b>	<b>7190710.8</b>	<b>7229335.1</b>	<b>7399186.1</b>	<b>7767405.3</b>
<i>जीडीपी का प्रतिशत</i>	<i>37.8</i>	<i>38.3</i>	<i>38.5</i>	<i>39.2</i>
<b>ऋण/उधार</b>				
<b>(ए) बैंकिंग क्षेत्र</b>	<b>5728735.3</b>	<b>5741948.3</b>	<b>5881570.2</b>	<b>6158150.0</b>
<i>जिसमें:</i>				
i. वाणिज्यिक बैंक	5226482.2	5239696.0	5380210.4	5620260.7
ii. सहकारी बैंक	500870.2	500865.3	499968.8	536494.1
<b>(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ</b>	<b>1461975.5</b>	<b>1487386.9</b>	<b>1517615.9</b>	<b>1609255.3</b>
<i>जिसमें:</i>				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	687643.6	709270.7	725191.9	790073.0
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	673118.3	675993.4	689041.8	714377.9
iii. बीमा निगम	101213.7	102122.8	103382.2	104804.4

## 50(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2020	सितं-2020	दिसं-2020	मार्च-2021
<b>वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)</b>	<b>23318920.4</b>	<b>23991428.3</b>	<b>24700622.2</b>	<b>25435684.2</b>
जीडीपी का प्रतिशत	110.7	109.3	108.7	108.4
<b>(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)</b>	<b>10790817.3</b>	<b>10987922.4</b>	<b>11410315.3</b>	<b>11675198.2</b>
i. वाणिज्यिक बैंक	9953043.9	10148485.7	10566752.7	10829078.8
ii. सहकारी बैंक	837773.4	839436.7	843562.6	846119.4
<b>(बी) गैर-बैंक जमा</b>				
जिसमें से:				
<b>अन्य वित्तीय संस्थान</b>	<b>205903.4</b>	<b>206074.1</b>	<b>203895.8</b>	<b>209855.7</b>
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67234.6	66469.1	66542.3	70754.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	138668.8	139605.0	137353.4	139101.6
<b>(सी) जीवन बीमा निधि</b>	<b>4929725.2</b>	<b>5142278.8</b>	<b>5213527.2</b>	<b>5357350.2</b>
<b>(डी) मुद्रा</b>	<b>2742897.3</b>	<b>2674266.1</b>	<b>2737059.4</b>	<b>2883904.4</b>
<b>(ई) म्यूचुअल फंड</b>	<b>1855000.1</b>	<b>2064363.5</b>	<b>2126112.0</b>	<b>2152140.5</b>
<b>(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)</b>	<b>757397.8</b>	<b>762264.0</b>	<b>767287.3</b>	<b>834147.6</b>
<b>(जी) पेंशन निधि</b>	<b>616517.0</b>	<b>667379.0</b>	<b>699173.0</b>	<b>736592.0</b>
<b>(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)</b>	<b>1420662.3</b>	<b>1486880.4</b>	<b>1543252.3</b>	<b>1586495.5</b>
<b>वित्तीय देयताएँ (ए+बी)</b>	<b>7755119.8</b>	<b>7868215.0</b>	<b>8256715.7</b>	<b>8668329.0</b>
जीडीपी का प्रतिशत	36.8	35.9	36.3	36.9
<b>ऋण/उधार</b>				
<b>(ए) बैंकिंग क्षेत्र</b>	<b>6172863.3</b>	<b>6231128.1</b>	<b>6559106.7</b>	<b>6934620.2</b>
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	5640516.1	5700327.0	6025626.4	6389789.3
ii. सहकारी बैंक	530937.1	529376.2	532040.6	543376.3
<b>(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ</b>	<b>1582256.5</b>	<b>1637086.9</b>	<b>1697609.1</b>	<b>1733708.8</b>
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	755315.1	784191.9	813668.4	811505.2
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	721510.0	745913.7	775408.5	812844.7
iii. बीमा निगम	105431.4	106981.2	108532.1	109358.8

## 50(बी): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
<b>वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)</b>	<b>25689017.4</b>	<b>26240728.5</b>	<b>27208717.9</b>	<b>28083947.0</b>
जीडीपी का प्रतिशत	103.2	101.5	102.4	103.1
<b>(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)</b>	<b>11911196.2</b>	<b>11956360.9</b>	<b>12421907.5</b>	<b>12701761.3</b>
i. वाणिज्यिक बैंक	11060527.2	11106712.0	11564354.7	11821685.0
ii. सहकारी बैंक	850669.0	849648.9	857552.8	880076.4
<b>(बी) गैर-बैंक जमा</b>				
जिसमें से:				
<b>अन्य वित्तीय संस्थान</b>	<b>216170.2</b>	<b>218246.9</b>	<b>224882.5</b>	<b>228542.9</b>
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74794.4	78061.6	79862.5	85234.7
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	141375.8	140185.3	145020.0	143308.2
<b>(सी) जीवन बीमा निधि</b>	<b>5325967.3</b>	<b>5559681.9</b>	<b>5786592.6</b>	<b>6038630.4</b>
<b>(डी) मुद्रा</b>	<b>2950343.2</b>	<b>2895763.9</b>	<b>2972524.0</b>	<b>3121514.2</b>
<b>(ई) म्यूचुअल फंड</b>	<b>2048097.3</b>	<b>2260209.7</b>	<b>2355315.8</b>	<b>2367792.5</b>
<b>(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)</b>	<b>851913.4</b>	<b>858591.1</b>	<b>864730.6</b>	<b>939814.6</b>
<b>(जी) पेंशन निधि</b>	<b>744459.2</b>	<b>799889.0</b>	<b>853412.0</b>	<b>898342.0</b>
<b>(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)</b>	<b>1640870.6</b>	<b>1691985.1</b>	<b>1729352.9</b>	<b>1787549.1</b>
<b>वित्तीय देयताएँ (ए+बी)</b>	<b>8957470.6</b>	<b>9310471.8</b>	<b>9781859.9</b>	<b>10253472.2</b>
जीडीपी का प्रतिशत	36.0	36.0	36.8	37.6
<b>ऋण/उधार</b>				
<b>(ए) बैंकिंग क्षेत्र</b>	<b>7169465.5</b>	<b>7433248.0</b>	<b>7801415.3</b>	<b>8153970.3</b>
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	6620073.1	6881338.5	7246643.0	7580935.6
ii. सहकारी बैंक	547894.8	550354.8	553201.4	571339.8
<b>(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ</b>	<b>1788005.1</b>	<b>1877223.8</b>	<b>1980444.6</b>	<b>2099501.9</b>
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	840786.9	895226.5	971105.3	1051401.1
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	835181.3	868212.5	893115.8	929861.7
iii. बीमा निगम	112036.9	113784.8	116223.5	118239.1

- टिप्पणियाँ:** 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2023 को जारी राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।  
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।  
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।  
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।  
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

## वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

### सारणी सं. 1

- 1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।  
3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।  
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।  
4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।  
4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।  
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।  
7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

### सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।  
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

### सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉरवर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

### सारणी सं. 5

अन्य अर्थात् एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

### सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।  
2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

### सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं।

### सारणी सं. 8

- एनएम<sub>2</sub> और एनएम<sub>3</sub> में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।  
2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।  
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

### सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एकजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।  
एल<sub>1</sub> और एल<sub>2</sub> मासिक आधार पर और एल<sub>3</sub> तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।  
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

### सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी सं. 14**

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

**सारणी सं. 17**

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

**सारणी सं. 24**

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

**सारणी सं. 30**

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

**सारणी सं. 32**

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

**सारणी सं. 34**

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

**सारणी सं. 35**

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

**सारणी सं. 36**

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर//रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

**सारणी सं. 37**

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

### सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

### सारणी सं. 43

भाग I-ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

○ इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।

○ जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉरपोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉरपोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

### सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं। सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

#### सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनः चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्ति सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

#### सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य।

#### सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डेटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका** में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2024	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2022-23	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2023-24 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2022-23	₹575 एक प्रति (काउंटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 44, सं. 1, 2023	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2022-23	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-दिसंबर 2024	आरबीआई बुलेटिन के पूरक के रूप में जारी किया गया जुलाई, 2024	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2024	आरबीआई बुलेटिन अप्रैल 2024 में शामिल है।	
12. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (काउंटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट ([www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)) पर उपलब्ध हैं।
  2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
  3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- \* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

## हाल के प्रकाशन

### सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:  
निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,  
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर), भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,  
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001  
टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in)
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां कहीं भी रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण [spsdepr@rbi.org.in](mailto:spsdepr@rbi.org.in) पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।
- ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
बैंक का नाम	फोर्ट, मुंबई
शाखा और पता	RBISOMBPA04
बैंक शाखा का आईएफएससी	चालू खाता
खाता प्रकार	41-8024129-19
खाता संख्या	41-8024129-19

- बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।
8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने संबंधी शिकायतें' दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।